राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 93

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, बुधवार, 11 सितंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16



कांग्रेस की आंतरिक राजनीति से आजिज उर्मिला ने पार्टी छोड़ी

>> 4

कश्मीर पर पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई

यूएनएचआरसी का 42वां सत्र ▶ भारत की दो टूक–कश्मीर पर जांच तो दूर, पाक को बोलने का भी हक नहीं

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पड़ोसी देश की झूठी दलीलों को किया खारिज

जेनेवा, प्रेट्र : जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का मुद्दा उठाने पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। मंगलवार को पाकिस्तान की झूठी दलीलों और अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग पर भारत ने कहा कि जांच तो दूर, कश्मीर पर पड़ोसी को बोलने का भी हक नहीं। भारत ने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना भारतीय संसद द्वारा किया गया एक संप्रभु निर्णय है। भारत अपने आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप स्वीकार नहीं कर सकता।

यूएनएचआरसी के 42वें सत्र में पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बयान पर भारत के प्रतिक्रिया के अधिकार का प्रयोग करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रथम सचिव विमर्श आर्यन ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, 'इस मंच को झूठी दलीलों के साथ राजनीतिक रंग देने और ध्रुवीकरण की कोशिश में दिए गए पाकिस्तान के बौखलाहट भरे बयान पर हमें कोई आश्चर्य नहीं है। पाकिस्तान समझ गया है कि हमारे फैसले ने सीमापार से आतंकवाद को लगातार पोषित करने की राह में बाधा पैदा करते हुए उसके पैरों तले से जमीन खींच ली है।' आर्यन ने पाक प्रधानमंत्री इमरान खान के भारत विरोधी बयानों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'कुछ पाकिस्तानी नेता जम्मू-कश्मीर में हिंसा भड़काने के लिए जेहाद की अपील भी करने लगे हैं। वो दूसरे देशों के सामने नरसंहार की तस्वीर पेश करने में लगे हैं, जबकि उन्हें भी पता है कि यह सच से कोसों दूर है।' आर्यन ने कहा कि पाकिस्तान यहां मानवाधिकारों का वैश्विक पैरोकार बनने की कोशिश में है लेकिन दुनिया मूर्ख नहीं बन सकती है। पाक की वाहियात कोशिशों से उसके यहां अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति से दुनिया का ध्यान हट नहीं जाएगा।

इससे पहले विदेश मंत्रालय के पूर्वी मामलों की सचिव विजय ठाकुर सिंह ने भी इशारों में पाकिस्तान को लताड़ लगाई थी। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों के बहाने दुर्भावनापूर्ण राजनीतिक एजेंडे के लिए वैश्विक मंचों का दुरुपयोग करने वालों की निंदा होनी चाहिए। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर उन्होंने कहा, 'हम दोहराना चाहते हैं कि संसद द्वारा पारित अन्य कानूनों की तरह यह एक संप्रभु निर्णय है, जो पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला है। कोई भी देश अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप स्वीकार नहीं कर सकता है। भारत तो बिल्कुल भी नहीं।' असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को भी सिंह ने भारत के सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उठाया गया वैधानिक, पारदर्शी और बिना भेदभाव के उठाया गया कदम बताया।

पिटता ही रहा है पाक : जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने से बौखलाया पाक इस मसले पर दुनिया के विभिन्न मंचों पर पिटता ही रहा है। तबसे किसी देश का साथ नहीं मिला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर पाक व चीन अकेले पड़ गए थे। मुस्लिम देशों ने भी साथ नहीं दिया। हाल में मालदीव की संसद में भी पाक को मुंह की खानी पड़ी थी।



स्विटजरलैंड के जेनेवा में मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बयान पर विदेश मंत्रालय के प्रथम सचिव विमर्श आर्यन (बाएं) ने जवाब दिया। एएनआइ

पाक की दलील

- कश्मीर मामले पर यूएनएचआरसी को चुप नहीं बैठे रहना चाहिए।
- कश्मीर के लोगों को नहीं मिल रहे मूलभूत व जरूरी मानवाधिकार।
- भारत ने ऐसे मानवाधिकार नियमों का उल्लंघन किया, जिसमें पाक भी पक्ष है।

भारत का जवाब

- वैश्विक मंचों पर अपना एजेंडा फैलाने वालों की निंदा की जानी चाहिए।
- दूसरे देशों के मामले में टांग अड़ाने वाले अपने गिरेबां में झांकें।
- वास्तव में जो खुद षड्यंत्रकारी होते हैं, वे स्वयं को ही पीड़ित बताने लगते हैं।

पड़ोसी देश ने माना, कश्मीर भारत का हिस्सा

यूएनएचआरसी की बैठक में पहुंचे पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'भारत दुनिया को यह दिखाने की कोशिश में है कि जीवन सामान्य हो गया है। अगर सब सामान्य है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि भारत क्यों अंतरराष्ट्रीय मीडिया, संगठनों, एनजीओ व अन्य को भारतीय राज्य जम्मू-कश्मीर में सच जानने के लिए नहीं जाने दे रहा।' अब तक पाक आधिकारिक बयानों में जम्मू-कश्मीर को 'भारत अधिकृत कश्मीर' कहता रहा है।

पाक का सहारा बने राहुल गांधी और उमर के बयान

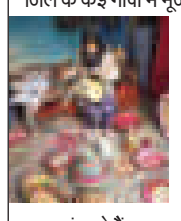
नई दिल्ली, एएनआइ : पाकिस्तान ने यूएनएचआरसी में अपना पक्ष रखने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के बयानों का सहारा लिया। पाक डोजियर के लीक हुए शुरुआती पन्नों से यह बात सामने आई है।

(संबंधित खबरें पेज-13 पर)

सरोकार

मूंज से लिख रहीं ग्राम्य स्वावलंबन की सुंदर पटकथा

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के कई गांवों में मूंज उत्पादों का निर्माण कुटीर उद्योग की शक्ल ले चुका है। ग्रामीण महिलाओं द्वारा मूंज से तैयार किए गए सुंदर उपयोगी सामान देश के बड़े शहरों तक पहुंच रहे हैं। (पेज-11)



जागरण विशेष

अवैध शराब भट्ठियों के लिए बदनाम गांव की बदली पहचान

अलीगढ़ : उप्र का गांव मिरगौला अवैध शराब कारोबार के लिए बदनाम था। 50 परिवार 70 साल से शराब बना और बेच रहे थे, लेकिन अब सभी ने इससे तौबा कर ली है। गांव नशा-मुक्ति की ओर बढ़ चला है। (पेज-11)



न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

कांग्रेस में ज्यादातर पदों के लिए चुनाव कराना जरूरी : थरूर

नई दिल्ली : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा है कि कार्यसमिति सहित पार्टी में ज्यादातर पदों के लिए चुनाव जरूरी हैं। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में जल्द ही पार्टी के अंदर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 5

मुहर्रम पर भी शांत रही कश्मीर घाटी, मुस्तैद रहे सुरक्षाबल

श्रीनगर : कश्मीर में आतंकियों और अलगाववादियों की धमकियों के बावजूद मुहर्रम पर भी कश्मीर शांत रहा। कहीं से भी हिंसा का कोई समाचार नहीं मिला। हालांकि प्रशासन ने वादी में हिंसा भड़काने के आतंकी मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए पहले से ही पाबंदियां लगा दी थीं।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

आसियान के साथ एफटीए की समीक्षा पर बनी सहमति

नई दिल्ली : भारत की चिंताओं को देखते हुए आसियान देश मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की समीक्षा पर सहमत हो गए हैं। आसियान ने माना है कि आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए एफटीए ब्र को ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली बनाने की जरूरत है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह संगठन एक संयुक्त समिति बनाने को भी राजी हो गया है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

ब्रिटिश संसद में मध्यावधि चुनाव का प्रस्ताव फिर गिरा

लंदन : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मध्यावधि चुनाव कराने की मांग पर संसद में फिर हार का सामना करना पड़ा है। इस झटके के बावजूद उन्होंने वादा किया कि वह ब्रेक्जिट समझौते के लिए प्रयास करना जारी रखेंगे। संसद की कार्यवाही निलंबित होने से पहले सोमवार देर रात तक चली बहस के बाद हुए मतदान में मध्यावधि चुनाव कराने की मांग वाला प्रस्ताव गिर गया।

अब नेपाल को मिलेगा सस्ता ईंधन

नई दिल्ली, प्रेट्र : अच्छे पड़ोसी से पक्की और फायदा पहुंचाने वाली दोस्ती की मिसाल पेश करते हुए भारत-नेपाल के बीच मंगलवार को तेल पाइपलाइन शुरू कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष केपी ओली ने संयुक्त रूप से इस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। दक्षिण एशिया में यह इस तरह की पहली सुविधा है। इससे नेपाल को सस्ता ईंधन मिलेगा। बिहार के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज तक यह लाइन बिछाई गई है।

वीडियो लिंक से किया शुभारंभ : नेपाल स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी बयान के अनुसार, दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने अपनी-अपनी राजधानियों में बैठकर वीडियो लिंक से इसका शुभारंभ किया। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आइओसीएल) ने नेपाल ऑयल कारपोरेशन के साथ तालमेल कर 324 करोड़ रुपये की लागत से यह लाइन बिछाई है। इस बारे में दोनों देशों के बीच अगस्त 2014 में एमओयू पर दस्तखत किए गए थे। दोनों पक्ष नेपाल के अमलेखगंज में पेट्रोल के भंडारण के लिए 75 करोड़ रुपये की लागत से अतिरिक्त स्टोरेज सुविधा भी बनाएंगे।

30 माह तय थे, 15 माह में कर दी तैयार : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नेपाल के विकास के प्रति वचनबद्ध है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय परियोजनाओं पर काम तेजी से जारी है, वह जल्द ही ओली के साथ इनका शुभारंभ करेंगे। पाइपलाइन रिकॉर्ड समय में तैयार की गई है। इसकी समय सीमा 30 माह तय थी, लेकिन पिछले साल प्रधानमंत्री ओली की भारत यात्रा के दौरान शिलान्यास के मात्र 15 माह में यह तैयार कर दी गई। हर साल इस पाइपलाइन से नेपाल को 20 लाख टन स्वच्छ पेट्रोलियम उत्पाद सस्ते दामों पर मिलेंगे। अब तक नेपाल को ट्रकों और टैंकरों से ईंधन की सप्लाई की जाती थी।



पीएम नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइप लाइन का उद्घाटन किया। एएनआइ

- भारत-नेपाल तेल पाइपलाइन का मोदी-ओली ने किया उद्घाटन
- दक्षिण एशिया में पहली बार दो देशों के बीच तेल पाइपलाइन चालू

कश्मीरी फल उत्पादकों से सेब खरीदेगा नैफेड

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

कश्मीर घाटी में राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा जबरन कराए जा रहे बंद से सेब उत्पादकों को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए नैफेड (राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संगठन) किसानों से सीधे सेब खरीदेगा। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (एमआइएस) के तहत नैफेड 15 दिसंबर 2019 तक खरीद प्रक्रिया को पूरा करेगा। इस दौरान दो हजार करोड़ की लागत से 12 लाख मीट्रिक टन सेब की खरीद होगी। इससे करीब सात लाख किसान लाभान्वित होंगे।

पांच अगस्त से कश्मीर में कानून व्यवस्था की उपजी स्थिति के मद्देनजर सेब उत्पादक अपनी तैयार फसल को समय रहते देश की विभिन्न मंडियों में नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसके अलावा उनकी फसल का एक हिस्सा बागों में खराब हो रहा है। जो सेब उत्पादक अपना माल किसी तरह मंडियों या देश के अन्य भागों में भेज रहे हैं, उन्हें आतंकियों द्वारा धमकाया जा रहा है।

आतंकी वारदात के बाद प्रशासन ने लिया संज्ञान : आतंकियों ने सोपोर मंडी बंद कराने के लिए गत शुक्रवार रात सोपोर में ढाई वर्षीय आसमा जान समेत चार लोगों को गोली मारी थी। इसे देखते हुए राज्य प्रशासन ने नैफेड की मदद लेने का फैसला किया है। नैफेड ने कश्मीर में कुल उत्पादन का आधे से ज्यादा सेब खरीदने का फैसला किया है।

मोल समिति तय करेगी क्रय मूल्य : नैफेड कश्मीर के सेब उत्पादकों से ए, बी और सी समेत हर ग्रेड का सेब खरीदेगा। सेब की गुणवत्ता और ग्रेडिंग के आधार पर ही किसानों को फसल के दाम मिलेंगे।

कार्यान्वयन, समन्वय समिति की अध्यक्षता करेंगे मुख्य सचिव : खरीद योजना के कार्यान्वयन और संबंधित विभागों में तालमेल के लिए मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रहमण्यम की अध्यक्षता में कार्यान्वयन व समन्वय समिति होगी। कृषि मंत्रालय, गृह मामलों व अन्य केंद्रीय एजेंसियां इस योजना के कार्यान्वयन की समग्र निगरानी करेंगी।

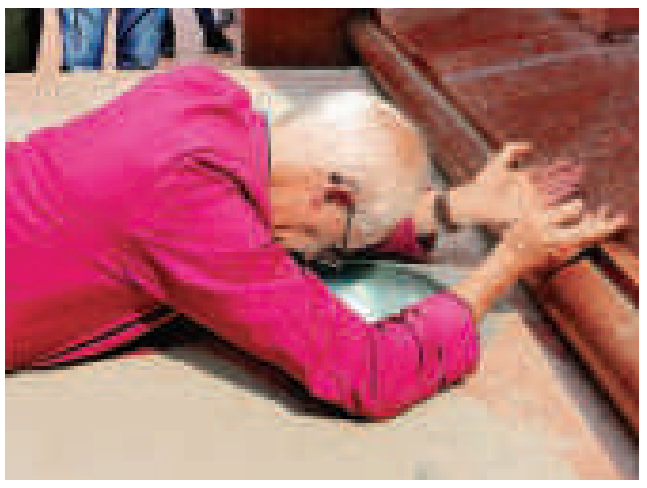
सीधे बैंक में आएगा भुगतान : मंडलायुक्त बसीर अहमद खान ने बताया कि यह योजना सिर्फ जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए चलाई जा रही है। शुरू में श्रीनगर, सोपोर और शोपियां के सेब उत्पादकों को इसके दायरे में लाया जाएगा। उत्पादकों को मौजूदा समय में मिल रहे दाम से कहीं ज्यादा दाम इस योजना के तहत मिलेंगे। किसानों को उनके आधार कार्ड के नंबर के मुताबिक बैंकों में उनकी फसल का भुगतान किया जाएगा।

- सात लाख किसान होंगे लाभान्वित, दो हजार करोड़ से 12 लाख मीट्रिक टन सेब खरीदे जाएंगे
- प्रशासन ने किसानों को राष्ट्र विरोधी तत्वों और बिचौलियों से बचाने के लिए उठाया यह कदम



प्रतीकात्मक

कैंटरबरी के आर्कबिशप ने कहा, जलियांवाला बाग कांड के लिए शर्मिंदा हूं, माफ करें



इंग्लैंड के कैंटरबरी के आर्कबिशप जस्टिन वेल्बी ने मंगलवार को धार्मिक नगरी अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में शहीदी स्मारक पर चिलचिलाती धूप में तपते पत्थर पर दो बार पेट के बल लेटकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा उन्होंने यहां हुए नरसंहार के लिए प्रायश्चित किया। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए हो रही सभा में अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थीं, जिसमें 400 से अधिक लोग शहीद हुए थे और दो हजार से ज्यादा घायल हुए थे। कैंटरबरी के आर्क बिशप इंग्लैंड के चर्च के वरिष्ठ बिशप और प्रमुख नेता हैं, जो दुनिया भर में एंग्लिकन कम्युनियन के प्रतीकात्मक प्रमुख हैं। (खबर पेज-6 पर)

एएफपी

गुजरात सरकार ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना घटाया

शत्रुघ्न शर्मा, गांधीनगर

गुजरात सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम-2019 की 50 धाराओं में संशोधन करते हुए जुर्माने की राशि 50 फीसद तक घटा दी है। नई जुर्माना राशि 16 सितंबर से प्रभावी होगी। साथ ही राज्य सरकार ने वाहनों की रफ्तार भी निर्धारित कर दी है। गांवों में यह 50, शहर में 60 और महानगरों में 70 किमी प्रति घंटा होगी।

मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मंगलवार को बताया कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण हर साल हजारों निर्दोष लोगों को जान गंवानी पड़ती है। केंद्र सरकार ने हाल ही में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करते हुए भारी भरकम जुर्माना राशि घोषित की थी, लेकिन राज्य सरकार ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए जुर्माना राशि में संशोधन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क पर तेज रफ्तार, खतरनाक ढंग से और नशे में वाहन चलाने पर 1,500 से लेकर 5,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा। वाहन चलाते वक्त ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी), पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) नहीं होने और मोबाइल पर बात करने जैसे अपराध के लिए जुर्माना राशि केंद्र के समान 500 रुपये ही रखी गई है, लेकिन बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने पर जुर्माना राशि 1,000 से घटाकर 500 रुपये कर दी गई है। हालांकि दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना राशि 1,000 रुपये ही रखी गई है। गलत तरीके से और यातायात में बाधा उत्पन्न करते हुए पार्किंग और शीशों पर डार्क फिल्म चढ़ाने पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय कानून में दोपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठने की अनुमति नहीं है, लेकिन राज्य सरकार इसमें सख्ती नहीं बरतेगी। साथ ही केंद्रीय कानून में दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट अनिवार्य है, लेकिन इस मामले में भी राज्य सरकार सख्ती नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि डिजी लॉकर मान्य होगा। साथ ही वाहन चालक 15 दिन में कभी भी दस्तावेज दिखाकर जुर्माना राशि से बच सकेंगे।

जुर्माना राशियों में बदलाव

अपराध	केंद्रीय कानून	गुजरात सरकार	पहले जुर्माना
ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना	5,000	2,000-3,000	500
बिना हेलमेट	1,000	500	100
बिना पीयूसी	5,000-10,000	500-5,000	5,000
डेंजर व रांग ड्राइविंग	5000-10000	1,500-5,000	--
एंबुलेंसको साइड नहीं देना	10,000	1,000	100
रोड रेस, स्पीड ट्रायल	5,000-10,000	5000	500
ओवरलोडिंग	20,000	1,000-4,000	1,000

छत्तीसगढ़ में 82 फीसद आरक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका

नईदुनिया, बिलासपुर : छत्तीसगढ़ में सरकार ने जातिगत आरक्षण के दायरे में बदलाव करते हुए इसकी सीमा 82 फीसद पहुंचा दी है। पिछले सप्ताह ही सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की है। आरक्षण में की गई वृद्धि को चुनौती देते हुए एक वकील ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता ने आरक्षण को असंतुलित बताते हुए इसे चुनौती दी है।

बिलासपुर के अधिवक्ता आदित्य तिवारी ने हाई कोर्ट में पहली याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि आरक्षण प्रदेश के विकास के लिए ठीक नहीं है। 82 फीसद आरक्षण लागू होने के बाद अनारक्षित वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। इससे अनारक्षित वर्ग के युवकों की पढ़ाई से लेकर शासकीय नौकरी के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। ज्ञात हो, प्रदेश में 82 फीसद आरक्षण लागू करने के सरकार के निर्णय का विरोध किया जा रहा है। सवर्णों ने इसके खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग की। इससे सोशल मीडिया में भी बहस छिड़ गई है। इसी के साथ अब आरक्षण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी भी शुरू हो गई है। ज्ञात हो, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त को राज्य में लागू जाति आरक्षण में बदलाव की घोषणा की थी।

वित्त मंत्री बोलीं

निर्मला सीतारमण ने रेडियो टैक्सी सेवाओं को ऑटो सेक्टर की सुस्ती बताकर शुरू की नई बहस

ओला-उबर भी ऑटो सेक्टर में मंदी का कारण

जेएनएन, नई दिल्ली

लगभग एक दशक पहले देश के विभिन्न शहरों में रेडियो टैक्सी की शुरुआत से ऑटो सेक्टर को जिस तरह के नुकसान की बात कही जा रही थी, सरकार ने एक तरह से उसकी तस्दीक कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चेन्नई में कहा कि इस सदी में पैदा हुई नई पीढ़ी कार खरीदने की जगह ओला और उबर जैसी रेडियो टैक्सी सेवाओं को तरजीह दे रही है, और वाहनों की मांग में कमी का यह भी एक बड़ा कारण है।

हालांकि उन्होंने देश के वाहन उद्योग पर सुस्ती के मौजूदा संकट के और भी कई कारण गिनाए हैं। लेकिन जिस तरह से देशभर के छोटे-बड़े शहरों में ओला और उबर जैसी बड़ी कंपनियों के अलावा भी स्थानीय स्तर पर रेडियो टैक्सी कंपनियां पैर पसार रही हैं, उसे देखते हुए वित्त मंत्री के बयान के मुताबिक ऑटो सेक्टर को इसका एक स्थायी समाधान खोजने की जरूरत है।

ऐसा नहीं कि वित्त मंत्री ने अकेले रेडियो टैक्सी सर्विस पर ऑटो सेक्टर की सुस्ती का ठीकरा फोड़ा हो। उन्होंने यह भी कहा कि अगले वर्ष अप्रैल से बीएस-6 मानक लागू होने वाले हैं, जिसे देखते हुए कुछ ग्राहक इंतजार करना चाह रहे हैं। कंपनियां भी बीएस-6 मानकों के हिसाब से वाहनों को अपग्रेड कर रही हैं। असल में ओला और उबर जैसी रेडियो टैक्सी सेवाओं के प्रति ग्राहकों के आकर्षण की न तो बात नई है, और न इसकी वजहें अनोखी हैं। दिल्ली-एनसीआर जैसे शहरों में कार खरीदने के लिए पहले पार्किंग स्पेस होने की गारंटी देने जैसे नियम देश के अन्य हिस्सों से आकर यहां महज नौकरी करने वाले युवाओं के लिए माकूल नहीं हैं।

दूसरी तरफ, बढ़ते प्रदूषण और जाम की समस्या से निपटने के लिए सरकार कार पूलिंग जैसे उपायों को बढ़ावा दे रही है, जिसके चलते ग्राहक रेडियो टैक्सी सेवाओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हर सुविधा अपने मोबाइल फोन पर खोजने वाली नई पीढ़ी कार रखने और उस पर कई अन्य तरह के खर्च वहन करने के मुकाबले जरूरत के हिसाब से कभी भी और कहीं भी रेडियो टैक्सी को बुला लेना मुफीद मान रहा है।

गौरतलब है कि बीते कुछ महीनों से देश का ऑटो सेक्टर मांग की समस्या से जूझ रहा है। पिछले अगस्त में घरेलू यात्री वाहनों (स्कूटर, बाइक और कार) की बिक्री में लगातर 10वें महीने गिरावट दर्ज की गई। अगस्त 2018 में 2,87,198 यूनिट की तुलना में इस साल अगस्त में सिर्फ 1,96,524 यूनिट ही बिकीं।

- इस वर्ष की शुरुआत से ही ऑटो सेक्टर की बिक्री में लगातार आ रही कमी
- अनौपचारिक रूप से ऐसी दलील नई नहीं, मगर सरकार का ऐसा मानना अलग संकेत



चेन्नई में मंगलवार को प्रेसवार्ता करतीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। प्रेट्र

चिन्मयानंद मामले का वीडियो वायरल, आश्रम पहुंची एसआइटी

शाहजहांपुर : दुष्कर्म के आरोपों में घिरे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक लड़की व कथित तौर पर स्वामी चिन्मयानंद आपत्तिजनक स्थिति में बातें करते नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो सही है या नहीं इसकी जांच होना बाकी है। इस बीच एसआइटी ने पीड़िता संग चिन्मयानंद के आश्रम पहुंचकर सात घंटे तक छानबीन की। (पेज-6)

बीतता जा रहा है विक्रम से संपर्क स्थापित करने का समय

बेंगलुरु : चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम से संपर्क स्थापित करने का समय तेजी से बीत रहा है। दरअसल, यान के लैंडर-रोवर का मिशन 14 दिन के लिए ही तय किया गया था जो चंद्रमा के एक दिन के बराबर है। जैसे-जैसे मिशन की तय की हुई अवधि बीत रही है, वैसे-वैसे संपर्क स्थापित करने की संभावना कम होती जा रही है। ज्ञात हो, छह-सात सितंबर की रात को चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की दूरी परइसरो ने लैंडर से संपर्क खो दिया था। (पेज-7)

भीड़ की हिंसा में नहीं दिल का दौरा पड़ने से हुई थी तबरेज की मौत

जागरण संवाददाता, सरायकेला

झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में उन्मादी भीड़ के हाथों पिटाई के कुछ दिन बाद जेल में दम तोड़ने वाले तबरेज अंसारी मामले में पुलिस ने चार्जशीट सौंप दी है। इसमें उसकी मौत हृदयाघात (हार्ट अटैक) से होनी बताई गई है। भीड़ के हमले से मौत होने की बात से पुलिस ने इन्कार कर दिया है। इस मामले में जेल में बंद 13 आरोपितों पर अब हत्या के बदले गैर इरादतन हत्या की धारा के तहत कार्रवाई होगी।

पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तबरेज की मौत की वजह हृदयाघात व फ्रैक्चर बताया गया है। इसलिए आरोपितों पर हत्या के बदले गैर इरादतन हत्या की धारा लगाई गई है। एसपी ने बताया कि पुलिस ने डॉक्टरों की टीम से जब दोबारा राय ली तो उन्होंने हृदयाघात को ही मौत की वजह बताई। सिर में लगी चोट को डॉक्टरों ने बहुत गंभीर नहीं माना और इस कारण तबरेज की मौत से इन्कार किया। एसपी ने बताया कि इस मामले में 13 लोग आरोपित हैं। सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें 11 के खिलाफ जांच कर रिपोर्ट अदालत को सौंप दी गई है। पिटाई से संबंधित वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है।

ज्ञात हो, 17 जून को सरायकेला के धातकीडीह में बाइक चोरी के आरोप में उन्मादी भीड़ ने तबरेज की जमकर पिटाई की थी। 22 जून को जेल में उसकी हालत बिगड़ गई और इलाज के दौरान मौत हो गई। वायरल वीडियो में तबरेज से भीड़ 'जय श्रीराम' के नारे लगवाती दिखाई दे रही थी। गत 30 अगस्त को तबरेज की पत्नी शाइस्ता परवीन जांच रिपोर्ट मांगने के लिए जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंची थी। उसने आवेदन देकर एसडीओ डॉ. बशारत कयूम की जांच रिपोर्ट व बिसरा की दूसरी जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि मुहैया कराने की मांग की थी।

- झारखंड के सरायकेला-खरसावां में उन्मादी भीड़ की हिंसा का मामला
- पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, आरोपितों पर अब नहीं चलेगा हत्या का केस

4788 वकील अनुत्तीर्ण हुए हैं वकालत करने की मान्यता देने वाली अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआइबीई) में। वकालत करने के लिए यह परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) ने सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को पत्र लिखकर यह जानकारी दी है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 11 सितंबर 2019

न्यूज गैलरी

दिल्ली पुस्तक मेला आज से, प्रवेश रहेगा नि:शुल्क

नई दिल्ली : 25वां दिल्ली पुस्तक मेला बुधवार से प्रगति मैदान में शुरू हो जाएगा। 15 सितंबर तक चलने वाले मेले में प्रवेश नि:शुल्क होगा। मेले का शुभारंभ सुबह साढ़े 11 बजे भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद के कार्यकारी निदेशक राजेश अग्रवाल करेंगे। पुस्तक मेले के साथ ही स्टेशनरी मेला, आफिस ऑटोमेशन मेला और कॉरपोरेट उपहार मेले का भी अवलोकन किया जा सकेगा। भारतीय प्रकाशक संघ (एफआइपी) के कोषाध्यक्ष एवं मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने बताया कि मेले में 120 से अधिक स्टॉल रहेंगे। मेला हॉल नं. सात में होगा। (जासं)

14 को रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी रवाना होगी पहली ट्रेन

नई दिल्ली : दिल्ली में मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना के तहत बुधवार को सफदरजंग रेलवे स्टेशन से ट्रेन अजमेर के लिए रवाना होगी। इस पर करीब 1000 बुजुर्ग यात्री अजमेर दर्शन करने जाएंगे। इसके तीन दिन बाद बुजुर्गों को लेकर 14 सितंबर को ट्रेन रामेश्वरम रवाना होगी। ट्रेन जगन्नाथपुरी के लिए बुजुर्गों का जत्था 19 सितंबर को लेकर जाएगी। दिल्ली तीर्थयात्रा विकास समिति के अध्यक्ष कमल बंसल ने बताया कि सितंबर के लिए रूट तय हो गए हैं। नवरात्र से ठीक पहले 23 सितंबर को बुजुर्गों को लेकर ट्रेन वैष्णोदेवी दर्शन कराने के लिए भी जाएगी। इसके अलाव दक्षिण भारत की ओर पहली बार बुजुर्गों को तिरुपति बाला जी का दर्शन कराने के लिए ट्रेन 27 सितंबर को रवाना होगी। इसके साथ ही ट्रेन उज्जैन के लिए 29 सितंबर को सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। सितंबर में करीब 7000 हजार तीर्थयात्रा योजना का लाभ ले सकेंगे। (जासं)

मोदी सरकार के कदमों से कम हुआ प्रदूषण : मनोज तिवारी

नई दिल्ली : दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम होने के दावे के साथ ही इसका श्रेय लेने की होड़ भी शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि उनके प्रयास से राजधानी की हवा पहले से साफ हुई है। वहीं, भाजपा इसका श्रेय केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को देते हुए मुख्यमंत्री पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी का कहना है कि लोगों को गुमराह करने व झूठ बोलने के बजाय आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार के मुखिया को राजधानी की बेहतरी के लिए कुछ काम करना चाहिए। वह सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाओं का श्रेय खुद लेने में लगे रहते हैं। दिल्ली के लोग उनकी हकीकत जान गए हैं और अब वह उनके झांसे में नहीं आएंगे। वह प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। (जासं)

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बढ़ेंगे 13,899 बेड

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अस्पतालों के विस्तार से संबंधित योजनाओं की स्टेटस रिपोर्ट मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सौंपी। जिसमें दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 13 हजार 899 बेड बढ़ाने का जिक्र है। 17 अस्पतालों का विस्तार भी होगा। तीन नए अस्पताल छह माह में बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा छह नए अस्पतालों का भी निर्माण होगा। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बेड क्षमता 120 फीसद बढ़ जाएगी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यह स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए दुनिया की सबसे बड़ी विस्तार परियोजना है। बात सिर्फ बेड की संख्या की नहीं है। इसका मकसद दिल्ली के लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करना है। इलाज में आर्थिक आधार पर लोगों से भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 तक सभी परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी।

वर्ष 2015 में केजरीवाल सरकार ने अस्पतालों में दोगुना बेड बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों



सत्येंद्र जैन। (फाइल)

के विस्तार की योजना बनाई थी। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग से इन परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। इसके मद्देनजर सत्येंद्र जैन ने उन्हें रिपोर्ट सौंपी है। इस समय दिल्ली सरकार के 38 अस्पतालों में 11 हजार 353 बेड उपलब्ध हैं। इनमें 13 हजार 899 बेड और जोड़े जाएंगे।

द्वारका, बुराड़ी और आंबेडकर नगर में तीन अस्पतालों का निर्माण चल रहा है। इन तीन अस्पतालों में 2613 बेड होंगे। आंबेडकर नगर में अस्पताल का भवन काफी हद तक बनकर तैयार है। द्वारका में मार्च 2020 तक अस्पताल बनकर तैयार होगा। वहीं बुराड़ी में

गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर

- सत्येंद्र जैन ने योजनाओं की स्टेटस रिपोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सौंपी
- 17 अस्पतालों का विस्तार होगा, तीन नए अस्पताल छह माह में बनकर हो जाएंगे तैयार

छह अस्पताल जिनके विस्तार का शुरू हुआ काम

अस्पताल	बेड बढ़ाने का प्रस्ताव	कुल
दीपचंद बंधु	281	565
भगवान महावीर	553	744
अरुणा आसफ अली	51	151
राव तुलाराम	270	370
आचार्य भिक्षु	270	420
संजय गांधी अस्पताल	362	662

पांच अस्पताल जिनके विस्तार के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी

अस्पताल	बेड बढ़ाने का प्रस्ताव	कुल बेड
गुरु गोबिंद सिंह	472	572
अंबेडकर अस्पताल	463	963
दादा देव	116	180
एलबीएस	460	660
लोकनायक इमरजेंसी	383	574

नवंबर के अंत तक अस्पताल बनकर तैयार होगा। रिपोर्ट के अनुसार 17 अस्पतालों के विस्तार की प्रक्रिया चल रही है। इन अस्पतालों में 8 हजार 986 बेड जुड़ेंगे।

एलबीएस में बनेगा मातृ व शिशु ब्लॉक : खिचड़ीपुर स्थित एलबीएस अस्पताल में 460 बेड का मातृ व शिशु ब्लॉक बनेगा। इसके लिए टेंडर हो गया है। इसके अलावा सरिता विहार, मादीपुर, हस्तसाल व ज्वालापुरी में अस्पताल बनाने की योजना की फाइल आगामी सप्ताह वित्त कमेटी में रखी जाएगी। इसके अलावा बिंदापुर व सिरसपुर में नए अस्पताल बनाए जाएंगे। बिंदापुर में 100 बेड के अस्पताल के निर्माण के लिए सलाहकार की नियुक्ति हो गई है। नए अस्पतालों में कुल 2300 बेड होंगे। संजय गांधी स्मारक अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर बनेगा।

अस्पतालों में नहीं मिलेगी प्राइवेट वार्ड की सुविधा : दिल्ली सरकार के अस्पतालों में वीवीआइपी मरीजों को प्राइवेट वार्ड की सुविधा नहीं मिलेगी। आम आदमी हो या खास सभी को एक जैसी सुविधा मिलेगी। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अस्पतालों की नई योजनाओं को जब स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष रखा तो उन्होंने प्राइवेट वार्ड के प्रावधान को हटाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हम अस्पतालों में एक समान सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।

अस्पताल जिनके विस्तार के लिए टेंडर होना बाकी

अस्पताल	प्रस्तावित बेड	कुल बेड
राजा हरिश्चंद्र	573	773
जग प्रवेश	329	560
लोकनायक	1575	4363

इन अस्पतालों के विस्तार के लिए सलाहकार नियुक्त

अस्पताल	प्रस्तावित बेड	कुल बेड
जीटीबी	806	1687
हेडगेवार	360	550
डीडीयू	1000	650
बीजेआरएम	662	862

नए अस्पताल जिसके निर्माण के लिए सलाहकार नियुक्त

अस्पताल	प्रस्तावित बेड
सरिता विहार	394
मादीपुर	602
ज्वालापुरी	602
हस्तसाल	602
सिरसपुर	--

तीन निर्माणाधीन अस्पताल जो जल्द होने वाले हैं तैयार

अस्पताल	प्रस्तावित बेड
अंबेडकर नगर	600
बुराड़ी	768
द्वारका	1241

डीयू प्रोफेसर के फ्लैट पर पुणे पुलिस की छापेमारी

कार्रवाई ▶ एल्गार परिषद मामले में संदिग्ध प्रोफेसर हनी बाबू एमटी के फ्लैट पर पहुंची थी पुलिस

पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच के डीसीपी के नेतृत्व में सेक्टर 78 में करीब छह घंटे तक हुई जांच

जागरण संवाददाता, नोएडा

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की जांच कर रही पुणे पुलिस ने मंगलवार सुबह नोएडा पुलिस की मदद से सेक्टर-78 स्थित सोसायटी में रहने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हनी बाबू एमटी के फ्लैट पर छापेमारी की। हनी बाबू के फ्लैट पर 2017 के एल्गार परिषद मामले में जांच हुई है। करीब छह घंटे तक छानबीन करने वाली जांच टीम में पुणे पुलिस के डीसीपी क्राइम ब्रांच बच्चन सिंह, एसीपी शिवाजी पवार (मामले के आइओ) के अलावा अन्य साइबर एक्सपर्ट मौजूद थे।

एसएसपी गौतमबुद्ध नगर वैभव कृष्ण ने बताया कि पुणे पुलिस की टीम ने प्रोफेसर के घर पर छानबीन की व कुछ आवश्यक सामान जब्त कर ले गई है। इस प्रकरण में कोई गिरफ्तारी



दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर हनी बाबू एमटी। जागरण

नहीं हुई है। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी की गई है।

मालूम हो कि पुणे के ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा में 31 दिसंबर 2017 को कोरेगांव भीमा युद्ध की 200वीं वर्षगांठ से पहले एल्गार सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान दिए गए भाषणों के बाद जिले के भीमा-कोरेगांव के आसपास एक जनवरी 2018 को जातीय हिंसा भड़क गई थी। इसमें काफी लोगों को चोट लगी थी व एक शख्स की मौत भी हो गई थी।

उधर, सेक्टर 78 स्थित हाइड पार्क सोसायटी में रहने वाले डीयू के प्रोफेसर हनी बाबू एमटी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पुणे में दर्ज एक मामले की जांच को लेकर मेरा घर सर्च करने पुलिस आई थी। सुबह करीब साढ़े छह बजे टीम आई थी व करीब साढ़े 12 बजे तक रही है। वह लोग किताब देखने में इंट्रस्टेड थे। लैपटॉप, पेन ड्राइव, हार्डडिस्क सीज कर दी है व ईमेल अकाउंट भी चेक किया है। पहली बार इस मामले में पुलिस ने मुझसे संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि पूछने पर पुलिस ने बताया कि वे लोग केवल सर्च व सीजर के लिए वह लोग आए हैं। बीच में किसी के बाहर जाने की इजाजत नहीं थी।

हनी बाबू के समर्थन में आया डूटा

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में कथित आरोपित डीयू के अंग्रेजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हनी बाबू के नोएडा स्थित निवास पर भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में पुणे पुलिस द्वारा मारे गए छापा की निंदा की है। डूटा अध्यक्ष राजीब रे ने हनी बाबू का समर्थन करते हुए आरोप लगाया है कि पुणे पुलिस ने छह घंटे तक हनी बाबू के निवास पर बिना किसी सर्च वॉरंट छापा मारा है। पुलिस ने घर की तलाशी ली और सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस साथ में ले गई। हनी बाबू की पत्नी भी डीयू की अंग्रेजी विभाग की शिक्षका हैं और मिरांडा हाउस कॉलेज में पढ़ाती हैं। इधर, हनी बाबू ने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिये अपना बयान जारी कर कहा कि मैं डीय के अंग्रेजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर एक दशक से पढ़ा रहा हूं। मेरे घर मंगलवार सुबह 6.30 बजे पुलिस पहुंची और 20 लोग मेरे दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने दावा किया कि वह पुणे की क्राइम ब्रांच से हैं। वह मेरे घर की तलाशी लेना चाहते थे। मैंने उन्हें उनके आइडी कार्ड मांगे। छह घंटों तक मेरे घर पर तलाशी ली गई। उन्होंने मेरे सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड को बदलने के लिए कहा और मैंने ऐसा ही किया। लेकिन, अब वह मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर जा सकते हैं। मेरे लैपटॉप और इसकी हार्डडिस्क में मेरे कई रिसर्च के काम मौजूद हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे लैपटॉप में जो मेरा काम है, उसे जब्त कर दिया गया है। सरकारी संस्थाएं कैसे मेरे काम को जब्त कर सकती हैं। बिना किसी वजह के कैसे यह ऐसा कर सकते हैं। उनके पास कोई सर्च वॉरंट नहीं था। उन्होंने मेरी पत्नी और बेटी के भी फोन जब्त कर लिए।

अभ्यास में ऐसी मारी किक, तबाह हो गया करियर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक पुरुष खिलाड़ी ने बदला लेने के लिए राज्य स्तर की वुशू (किक बॉक्सिंग) खिलाड़ी के पेट में ऐसी किक मारी कि उनका करियर ही बर्बाद हो गया।



हनी। सौजन्य: परिजन

घायल खिलाड़ी को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि वह अब कभी यह खेल दोबारा नहीं खेल सकेंगी। मामला दो जनवरी का है। परिजनों ने घटना की शिकायत आइपी एस्टेट थाने में की। वरिष्ठ अधिकारी के हस्तक्षेप पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। उनका कहना है कि इस मामले में डॉक्टर की राय लेने की वजह से मुकदमा दर्ज करने में देरी हुई। दो खिलाड़ियों के बीच अभ्यास करते वक्त यह चोट लगी थी। लिहाजा इसकी प्राथमिक जांच जरूरी थी। वहीं शिकायत के बाद आरोपित खिलाड़ी द्वारा फोन पर परिवार को धमकी भी दी जा रही है। पीड़ित महिला खिलाड़ी हनी के मुताबिक इसी साल दो जनवरी को वह अभ्यास के लिए स्टेडियम गई थीं। वहां कोच ने उनकी फाइट ज्यादा उम्र के खिलाड़ी सौरभ से करा दी, जो उनके प्रदर्शन से ईर्ष्या भाव रखता था। इसी बात पर कुछ दिनों पूर्व सौरभ से उनका झगड़ा भी हुआ था। हनी का कहना है कि कोच के कहने पर वह सौरभ के साथ अभ्यास करने लगीं। उस दौरान हनी ने सेफ्टी गार्ड नहीं पहने थे। आरोप है कि सौरभ ने जानबूझकर कर खेल के नियमों के विरुद्ध उनके पेट में जोरदार किक मारी। किक लगते ही वह गिर पड़ीं। बाद में उन्हें लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 11 जनवरी को उन्हें छुट्टी दी गई। उनके अंदरूनी अंग में गंभीर चोट लगी थी। लिहाजा डॉक्टरों ने उन्हें पूरे जीवन वुशू खेलने से मना कर दिया। डॉक्टर ने हल्का खेल ही खेलने का सुझाव दिया। इसका पता चलने पर परिजनों ने इसकी शिकायत आइपी एस्टेट थाने में की। पिता जय प्रकाश का कहना है कि वह हनी को राष्ट्रीय स्तर पर खेलते देखना चाहते थे, लेकिन इस घटना के बाद परिवार का सपना टूट गया।

हनी दरियागंज में परिजनों के साथ रहती हैं। केंद्रीय विद्यालय में 12वीं कक्षा की छात्रा हनी पिछले साल राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। वह अभ्यास के लिए इंदिरा गांधी स्टेडियम जाती थीं। उनके पिता जय प्रकाश ट्रांसपोर्ट कारोबारी हैं। हनी का कहना है कि पिछले साल दिसंबर में सौरभ और उसके भाई आशीष का त्यागराज स्टेडियम में झगड़ा हुआ था। हनी ने दोनों का बीच बीच-बचाव कराया था। उसी वक्त उसने देख लेने की धमकी दी थी। हनी ने उस वक्त मामले को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन चोट लगने के बाद उसे अहसास हुआ कि जानबूझकर उसे मारा गया।

आइआइटी दिल्ली की टीम ने पचास इमारतों का किया सुरक्षा ऑडिट

अरविंद मिश्रा, ग्रेटर नोएडा

आइआइटी दिल्ली की टीम ने शाहेबरी में बनी अवैध इमारतों का (स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट) सुरक्षा ऑडिट शुरू कर दिया है। रोजाना चार घंटे सुरक्षा ऑडिट किया जा रहा है। आइआइटी की दो सदस्यीय टीम शाहबेरी में शुक्रवार से इमारतों का ऑडिट करने में जुटी है। पिछले पांच दिनों में 20 घंटे में करीब पचास इमारतों का ऑडिट कार्य पूरा भी हो चुका है। पंद्रह दिनों में ऑडिट का काम पूरा कर आइआइटी अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण को सौंप देगी। इस रिपोर्ट को शासन को भेजा जाएगा। इसके आधार पर ही शाहबेरी की इमारतों का भविष्य तय होगा।

शाहबेरी का जमीन अधिग्रहण रद होने के बाद वहां अवैध इमारतों का जाल बिछ चुका है। पिछले साल जुलाई में दो इमारतों के जमींदोज होने से उसमें नौ लोगों की दबकर मौत हो गई थी। इसके बाद से शाहबेरी की अवैध इमारतें शासन से लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की गले की हड्डी बनी हुई हैं। अवैध रूप से बनी इन इमारतों को ध्वस्त करने के निर्देश हैं। लेकिन लोगों के विरोध को देखते हुए पहले इन इमारतों का सुरक्षा ऑडिट कराने का फैसला किया गया।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आइआइटी दिल्ली को सुरक्षा ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए प्राधिकरण अगस्त 2019 में आइआइटी



ग्रेनो के शाहबेरी में खड़ीं इमारतें। आर्काइव

शाहबेरी मामला

- शुक्रवार से रोजाना चार घंटे चल रहा है शाहबेरी में अवैध बनी इमारतों का सुरक्षा ऑडिट

बिल्डरों के खिलाफ एनएसए व गैंगस्टर की कार्रवाई

शाहबेरी में अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ 84 एफआइआर दर्ज हो चुकी हैं। इसमें डेढ़ सौ से अधिक आरोपित हैं। प्रशासन पांच के खिलाफ गैंगस्टर व सहाबुद्दीन के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई कर चुका है। शाहबेरी में अवैध इमारतों के निर्माण के दौरान बिसरख कोतवाली में तैनात 22 पुलिसकर्मियों व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारी एवं अधिकारियों की सूची शासन को कार्रवाई के लिए भेजी जा चुकी है।

को पचास लाख रुपये का भुगतान कर चुका है।

सूत्रों के मुताबिक आइआइटी की टीम ने शुक्रवार से सुरक्षा ऑडिट शुरू कर दिया है। ऑडिट करने वाली टीम में दो सदस्य शामिल हैं। पिछले पांच दिनों में 20 घंटे में टीम पचास इमारतों का सुरक्षा ऑडिट कर चुकी है। आइआइटी की टीम शाहबेरी में 426 इमारतों का सुरक्षा ऑडिट करेगी। ये सभी इमारतें बहुमंजिला हैं। अगले पंद्रह दिनों में सुरक्षा ऑडिट का काम पूरा कर टीम अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण को सौंप देगी।

टीम की सुरक्षा के लिए लगाई गई पुलिस : सुरक्षा ऑडिट कर रही आइआइटी की टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस को तैनात किया गया है। ऑडिट कार्य के दौरान पुलिस लगातार टीम के सदस्यों के साथ रहती है।

टीम बताएगी सुरक्षा के लिहाज से कितनी सुरक्षित हैं इमारतें : शाहबेरी में बनीं इमारतें अवैध होने के साथ-साथ सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक बताई जा रही हैं। बिल्डरों ने इन इमारतों के निर्माण और इनमें लगाई गई सामग्री में मानकों की पूरी तरह से अनदेखी की है। आइआइटी दिल्ली की टीम स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑडिट कर यह बताएगी कि इमारतों का ढांचा कितने लोगों के रहने के लिए कितना सुरक्षित है।

चेकिंग के दौरान नोकझोंक में युवक की मौत मामले में रिपोर्ट दर्ज

जागरण संवाददाता, इंदिरापुरम : चेकिंग के दौरान नोकझोंक में सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत गौरव शर्मा की मौत के मामले में मंगलवार रात इंदिरापुरम थाना में अज्ञात यातायात पुलिसकर्मी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस रात को परिजन के साथ घटना स्थल भी पहुंची। घटना स्थल इंदिरापुरम थाना क्षेत्र का निकला है। मंगलवार रात करीब नौ बजे मृतक के परिजन इंदिरापुरम थाना पहुंचे। मृतक के पिता मूलचंद शर्मा ने पुलिस को तहरीर दी। इंदिरापुरम थाना प्रभारी निरीक्षक दीपक शर्मा ने बताया कि मृतक के पिता मूलचंद शर्मा का आरोप है कि यातायात पुलिसकर्मी (सफेद शर्ट व नीली पैंट पहने) ने कार पर डंडा मारकर रुकवाया। इसको लेकर हुई नोकझोंक के दौरान उनके बेटे गौरव शर्मा (34) को दिल का दौरा पड़ गया। अस्पताल में उनकी मौत हो गई। उनका आरोप है कि यातायात पुलिसकर्मी यदि समय से गौरव को उपचार कराने अस्पताल ले जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। दीपक शर्मा की तहरीर पर अज्ञात यातायात पुलिसकर्मी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांच शुरू कर दी गई है।

नोएडा सेक्टर - 52 निवासी गौरव शर्मा 34 रविवार को अपने पिता मूलचंद शर्मा और मां के साथ कार से इंदिरापुरम जा रहे थे। आरोप है कि एनएच-नौ पर वाहन चेकिंग के दौरान यातायात पुलिसकर्मी से नोकझोंक हुई। इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी।

बूढ़ा बनकर नौकरी के लिए जाना चाहता था न्यूयार्क

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ गुजरात के रहने वाले आरोपित को एयरपोर्ट पुलिस ने किया था गिरफ्तार

युवा अक्सर रोजगार की तलाश में अपना घर, शहर और राज्य भी छोड़ देते हैं, लेकिन आइजीआइ एयरपोर्ट पर सीआइएसएफ ने ऐसे युवक को पकड़ा, जो बूढ़ा बनकर नौकरी करने के लिए न्यूयार्क जाना चाह रहा था। उसने एजेंट की मदद से फर्जी पासपोर्ट तैयार कराया और वीजा भी प्राप्त कर लिया। विदेश में नौकरी के लिए उसकी यह तरकीब काम नहीं आई और उसे सोमवार को आइजीआइ एयरपोर्ट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान अहमदाबाद (गुजरात) में जीएसटी रोड न्यू रेनिप के रहने वाले जयेश कुमार पटेल के रूप में हुई। वह अमरीक सिंह नाम से बने फर्जी पासपोर्ट के जरिये न्यूयार्क जाना चाह रहा था।

आइआइजी एयरपोर्ट के डीसीपी संजय भाटिया ने बताया कि जयेश (32) से पूछताछ कि गई तो उसने बताया कि उसे डर था कि न्यूयार्क में जाकर नौकरी करने के लिए वीजा नहीं मिलेगा। उसने पड़ोस में रहने वाली एक महिला से बातचीत की। महिला ने उसे एक एजेंट का नंबर दिया। एजेंट से संपर्क करने पर जयेश अपने पिता के साथ अहमदाबाद के कलोल में एक पार्लर में एजेंट से मिला। उसने उसे अमेरिका भेजने के लिए कागजों की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। उसके साथी एजेंट ने जयेश को फोन कर दिल्ली के करोल बाग इलाके में बुलाया। यहां आने पर मेकअप आर्टिस्ट ने जयेश का मेकअप कर 81 वर्ष का बूढ़ा बना दिया। उसकी मूंछ-दाढ़ी और सिर के बाल रंग करके सफेद किए गए और पगड़ी पहनाई गई। एजेंट ने उसे सलाह दी कि वह एयरपोर्ट से बूढ़े के रूप में व्हील चेयर पर जाए। एजेंट ने कालकाजी में रहने वाले अमरीक के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनाने के साथ वीजा प्राप्त करके जयेश को अमेरिका जाने के लिए दिल्ली बुलाया। उसे पासपोर्ट, वीजा और अन्य कागज देकर एयरपोर्ट पर छोड़ा और व्हील चेयर की व्यवस्था की।

ऐसे आया पकड़ में

एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी जांच के दौरान उसे सुरक्षाकर्मियों ने व्हील चेयर से उठने के लिए कहा। जांच के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने देखा कि 81 वर्ष के बूढ़े के चेहरे, गले और हाथ की त्वचा युवाओं जैसी लग रही है। दाढ़ी-मूंछ के बाल सफेद थे, लेकिन हाथ के बाल काले थे। सिर पर सफेद बाल थे, लेकिन उनकी जड़ें काली थी। सुरक्षाकर्मियों को संदेह हुआ। सिर और दाढ़ी-मूंछ के बालों की जांच करने पर पता चला कि उसने बालों पर डाई लगाई है।

छात्र राजनीति

आज चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे उम्मीदवार, 13 को होगी मतगणना और इसी दिन घोषित हो जाएंगे नतीजे

डूसू चुनाव में थम गया प्रचार, कल होगा मतदान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव प्रचार मंगलवार रात आठ बजे थम गया। डूसू चुनाव समिति के अनुसार नियमों के तहत उम्मीदवार बुधवार को प्रचार नहीं कर सकते हैं। गुरुवार को मतदान होगा। सुबह के कॉलेजों में सुबह 8.30 से दोपहर एक बजे तक और इवनिंग कॉलेजों में दोपहर बाद तीन बजे से शाम 7.30 बजे तक मतदान होगा। शुक्रवार सुबह 8.30 बजे से मतगणना शुरू होगी और इसी दिन डूसू चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं, मंगलवार को कॉलेजों में मुहर्रम की छुट्टी थी, इसलिए सभी छात्र संगठनों के उम्मीदवारों ने प्रचार के लिए हॉस्टल की ओर रुख किया।

एबीवीपी ने निकाली छह किलोमीटर की पदयात्रा : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने मंगलवार को नॉर्थ कैंपस में 200 छात्रों के साथ पदयात्रा निकाली। पदयात्रा कमलानगर, हडसन लेन होते हुए निकाली गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील करते हुए उनके समर्थन में नारे भी लगाए। एबीवीपी के दिल्ली प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ यादव ने कहा कि पदयात्रा के दौरान शाम को छात्र-छात्राओं से संवाद किया गया। हमने 5पी मॉडल का एजेंडा छात्रों के सामने रखा। इसमें हमने संकल्प लिया है कि हम परिसर, पाठ्यक्रम, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम को ठीक करेंगे। डूसू में बेहतर नेतृत्व हो, इसके लिए एबीवीपी के प्रत्याशियों को चुनने की छात्रों से अपील की गई।

सोशल मीडिया से भी किया प्रचार : छात्र संगठनों ने सोशल मीडिया के जरिये भी प्रचार किया। एबीवीपी के उम्मीदवारों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर और संगठन ने अधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर छात्रों से लाइव संवाद किया। उन्होंने छात्र संगठनों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपना पक्ष रखा।



एबीवीपी के प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए (बाएं से) अक्षित दहिया, उपाध्यक्ष प्रदीप तंवर, सचिव योगित राठी और संयुक्त सचिव शिवांगी खरवाल दाएं। (फाइल)



एनएसयूआइ के प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए (दाएं से) चेतना त्यागी, उपाध्यक्ष अंकित भारती, सचिव आशीष लांबा और संयुक्त सचिव अभिषेक। (फाइल)

जेएनयू छात्रसंघ चुनाव समिति को जीआरसी ने भेजा नोटिस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की ग्रीवांस रिड्रेसल सेल (जीआरसी) के अध्यक्ष प्रो. उमेश अशोक कदम ने जेएनयू छात्र संघ चुनाव समिति को नोटिस भेजा है। उनका कहना है कि समिति ने लिंग्दोह समिति की सिफारिशों और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए छात्रसंघ चुनाव नहीं कराया है। नियमों का उल्लंघन किया गया है। जीआरसी ने नियमों का पालन करने के लिए कहा था। नोटिस के अनुसार चुनाव समिति ने 10 बिंदुओं पर नियमों का उल्लंघन किया है। उसे बुधवार सुबह 10 बजे तक दस्तावेजों के साथ जवाब देने के लिए कहा है।

जीआरसी ने नोटिस में लिखा कि जेएनयू छात्र संघ चुनाव नियमों के तहत नहीं कराया गया। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के संविधान के तहत विश्वविद्यालय के सभी स्कूलों और विशेष केंद्रों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। चुनाव प्रक्रिया की समयावधि दस दिनों से ज्यादा की थी, जो कि लिंग्दोह समिति की सिफारिश का उल्लंघन है। चुनाव समिति ने 26 अगस्त को नामांकन दाखिल करने और आठ सितंबर को नतीजे घोषित करने की तिथियों का निर्धारण किया था। इसमें कुल 14 दिन हैं, जबकि लिंग्दोह समिति की सिफारिशों के तहत दस दिनों के अंदर ही चुनाव कराने होते हैं। चुनाव समिति ने सभी प्रत्याशियों की घोषणा करने से पहले यह जांच नहीं की कि उन प्रत्याशियों का कोई अकादमिक बकाया तो नहीं है। यह भी नियम का उल्लंघन है। सभी प्रत्याशियों का हाजिरी रिकॉर्ड उनके स्कूलों से चेक किए बिना ही घोषित कर दिया गया। जेएनयू के चीफ प्रॉक्टर कार्यालय से प्रत्याशियों के संदर्भ में यह जानकारी नहीं ली गई कि क्या उन पर किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। छात्र संघ चुनाव में काउंसिलर की एक सीट पार्ट टाइम छात्र को आवंटित की गई। यह भी लिंग्दोह समिति की सिफारिशों का उल्लंघन है। नियम के अनुसार विश्वविद्यालय के स्थायी छात्र ही चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं।

1.20 करोड़ पक्के रियायती दरों के मकान बनाए जाने हैं देश के शहरी इलाकों में सरकार द्वारा 2022 तक। 80 लाख मकान बनाने के मसौदे को मोदी सरकार की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है।

पीएम आवास योजना को मिलेगी रफ्तार

सबको आवास ▶ सवा दो करोड़ से अधिक पक्के मकान के निर्माण का है लक्ष्य

आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रयोग से समय से पहले पूरी हो सकती है योजना

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

देश में सबको आवास मुहैया कराने के उद्देश्य से चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना को समय से पहले पूरा करने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। योजना की सफलता के लिए ग्रामीण विकास और शहरी आवासीय विकास मंत्रालय ने आवासीय परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है, ताकि रियायती दर के उच्च गुणवत्ता वाले मकानों के निर्माण किए जा सकें।

पिछले दिनों शहरी विकास मंत्रालय ने एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर आवासीय परियोजनाओं में वैश्विक स्तर की टेक्नोलॉजी के उपयोग पर जोर दिया था। इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली दुनिया की लगभग दो दर्जन कंपनियों ने हिस्सा लिया था। इसी दौरान घरेलू आवासीय परियोजनाओं में हिस्सा लेने के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से पेशकश की गई। शहरी विकास सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बताया कि टेक्नोलॉजी के उपयोग से कम लागत में गुणवत्ता वाले मकानों का निर्माण किया जा सकेगा।


प्रतीकात्मक

शहरों में 80 लाख मकान बनाने के मसौदे को मिल चुकी है हरी झंडी

शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2022 तक 1.20 करोड़ पक्के रियायती दरों के मकान बनाए जाने हैं। फिलहाल 80 लाख मकान बनाने के मसौदे को हरी झंडी मिल चुकी है, जिन पर अमल शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि यह लक्ष्य अगले साल तक पूरा कर लिया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में बनाए जा रहे पक्के मकानों में आधुनिक आर्किटेक्चर और उन्नत मैटीरियल का उपयोग किया जा रहा है, जिसके लिए स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और बिल्डिंग मैटीरियल टेक्नोलॉजी प्रोमोशन काउंसिल की मदद ली जा रही है। शहरीकरण के होते तीव्र प्रसार के चलते मकानों की जरूरतें तेजी से बढ़ रही हैं। इसके लिए सरकारी एजेंसियों के साथ प्राइवेट एजेंसियों की सहायता लेने की योजना है।

गुणवत्ता वाले मकान बनाने के लिए राजमिस्त्री को किया जाएगा प्रशिक्षित

ग्रामीण क्षेत्रों में पक्का मकान बनाने की रफ्तार पिछले पांच सालों में कई गुना बढ़ी है, जिसे और तेज करने की योजना है। पिछले पांच सालों में देश में कुल 1.5 करोड़ आवासों का निर्माण किया गया है। जबकि वर्ष 2022 तक कुल 1.95 करोड़ और मकान बनाने का लक्ष्य है, जिसे प्राप्त करने के लिए निर्माण की रफ्तार को तेज करना होगा। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र तोमर का कहना है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विविधता को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि पारंपरिक मकान बनाए जा सकें। स्थानीय मैटीरियल के उपयोग के साथ वहीं के राजमिस्त्री को गुणवत्ता वाले मकान बनाने के लिए प्रशिक्षण का बंदोबस्त किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण पर दिया जा रहा पूरा जोर

दरअसल, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों के निर्माण की जिम्मेदारी लाभार्थी को ही सौंपी गई है। अब बनाए जाने वाले मकानों के साथ शौचालय, बिजली कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन और मनरेगा के तहत 90 दिनों का काम भी देने का प्रावधान किया गया है। तोमर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण में भी गुणवत्ता पर पूरा जोर दिया जा रहा है। भूकंप, चक्रवाती तूफान, भूस्खलन और बाढ़ जैसी विभीषिका से बचाव वाले मकानों की जरूरत है। इसीलिए एक जैसी योजना पूरे देश में लागू करने की जगह जिला और ब्लाक विशेष के हिसाब से योजनाएं बन रही हैं। स्थानीय मैटीरियल के उपयोग से मकानों की गुणवत्ता बढ़ जाएगी।

खाली प्लास्टिक की बोतल मशीन में डालने पर फोन होगा रिचार्ज

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को नकारने की पहल के तहत रेलवे ने नायाब पहल की है। इसके मुताबिक अगर कोई यात्री स्टेशन पर लगी प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीन का उपयोग करता है तो रेलवे उसके फोन को रिचार्ज करने में मदद करेगा। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में पीएम मोदी ने राष्ट्र से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को खत्म करने और प्राथमिकता पर पानी वाली प्लास्टिक की बोतलों का विकल्प खोजने की अपील की थी।

रेलवे ने निर्देश जारी किया है कि इस वर्ष दो अक्टूबर से उसके परिसर में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने कहा कि स्टेशनों पर 400 प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीन लगाई जाएंगी। अगर कोई यात्री उपयोग करना चाहता है तो उसे मशीन में अपना फोन नंबर डालना होगा और उसका फोन रिचार्ज हो जाएगा। हालांकि कितनी राशि का रिचार्ज यात्री को मिलेगा, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। बता दें कि वर्तमान में 128 स्टेशनों पर 160 क्रशिंग मशीनें लगी हैं। उन्होंने यह भी कहा, सभी रेलवे कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्टेशनों पर इस्तेमाल की जाने वाली सभी प्लास्टिक की बोतलों को एकत्र करें और उन्हें री-साइक्लिंग के लिए भेजें। इससे पहले मंत्रालय ने अपने कर्मियों को निर्देश दिए थे।

महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मियां तेज

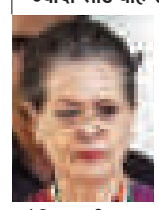
सीट बंटवारे को लेकर सोनिया से मिले पवार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

महाराष्ट्र में कांग्रेस-राकांपा नेताओं के दल बदलने के लिए मची भगदड़ के बीच राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से अहम मुलाकात की। सोनिया-पवार की इस बैठक में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीटों के तालमेल पर खास बातचीत हुई। कांग्रेस की कमजोर सियासी जमीन को देखते हुए राकांपा विधानसभा चुनाव में इस बार बड़े भाई की भूमिका निभाने का दावा जताते हुए अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है।

कांग्रेस-राकांपा के शीर्ष नेतृत्व में सीटों के बंटवारे पर हुई चर्चा के बीच कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव के अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के चयन के लिए बनी कांग्रेस की स्क्रीनिंग समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुआई में मंगलवार को पहली बैठक में कई सीटों पर नाम भी तय कर दिए गए। इस लिहाज से दस जनपथ पर सोनिया गांधी से शरद पवार की हुई लंबी मंत्रणा महत्वपूर्ण रही। पार्टी सूत्रों ने बताया कि भले राकांपा इस बार अधिक सीटों पर दावेदारी कर रही है मगर सोनिया और पवार के बीच सीधी चर्चा के बाद उम्मीद है कि लगभग बराबर-बराबर सीटों पर लड़ने को लेकर सहमति बन जाएगी। कांग्रेस-राकांपा के करीब दो दशक पुराने गठबंधन में कांग्रेस हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सूबे में हुई करारी शिकस्त के बाद पार्टी के कई बड़े नेता शिवसेना या भाजपा में शामिल हो चुके हैं। राकांपा के भी कई बड़े नेता भी सूबे में अपने गठबंधन की कमजोर सियासी हालत देख भाजपा या शिवसेना में शामिल हो चुके हैं।

▶ महाराष्ट्र में कांग्रेस की कमजोर सियासी जमीन देखते हुए इस बार ज्यादा सीटें चाह रही राकांपा


सोनिया गांधी


शरद पवार फाइल फोटो

महाराष्ट्र में कांग्रेस 123 व राकांपा 125 सीटों पर ठोकेगी ताल

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तथा राकांपा ने सीटों के बंटवारे का मसला सुलझा लिया गया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने मंगलवार को बताया कि राज्य की 288 सीटों में से कांग्रेस 123 और राकांपा 125 सीटों पर ताल ठोकेगी। शेष 41 सीटे गठबंधन के अन्य सहयोगियों के लिए छोड़ी गई हैं।

कांग्रेस में ज्यादातर पदों के लिए चुनाव कराना जरूरी : थरूर

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा है कि कार्यसमिति सहित पार्टी में ज्यादातर पदों के लिए चुनाव जरूरी हैं। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में जल्द ही पार्टी के अंदर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी।

अपनी पुस्तक 'द हिंदू वेः एन इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदूइज्म' के लोकार्पण से पहले एक साक्षात्कार में थरूर ने कहा, 'मैंने कई बार कहा है कि कांग्रेस कार्यसमिति समेत नेतृत्व के ज्यादातर पदों के लिए कार्यकर्ताओं के बीच चुनाव जरूरी हैं।' पार्टी में आंतरिक चुनाव से भविष्य के नेताओं को सफलतापूर्वक काम करने में मदद मिलेगी और पार्टी के भीतर नई ऊर्जा का संचार होगा। थरूर ने कहा, 'इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव जल्द होंगे और मुझे विश्वास है कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में पार्टी इस दिशा में काम करेगी।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जयराम रमेश के बयान का समर्थन करने के संदर्भ में पूछे जाने पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि वह ऐसा कहने वाले पहले व्यक्ति हैं कि मोदी सरकार में बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं हैं जिन्हें सकारात्मक रूप में देखा जाए। थरूर ने कहा कि पिछले साल प्रकाशित हुई अपनी किताब 'द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर' में मोदी सरकार की कमियों के बारे में बताया है, इसलिए इस मुद्दे पर मैं और मेरे दोस्त सलमान खुर्शीद की सोच एक जैसी है। उल्लेखनीय है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने गत दिनों पत्रकारों से बातचीत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की कुछ योजनाओं की जहां प्रशंसा की थी, वहीं पूर्व विदेश मंत्री और प्रख्यात अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कहा था कि मोदी सरकार की उपलब्धियों को खोजना भूसे में सुई ढूंढने के बराबर होगा।

▶ सोनिया गांधी के नेतृत्व में जल्द ही चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जताई


शशि थरूर फाइल फोटो

मानना होगा कि मोदी ने वोटरों के लिए कुछ काम किया है

शशि थरूर ने कहा, मोदी इस चुनाव में वोट फीसद 31 से 37 करने में सफल रहे हैं जबकि कांग्रेस का वोट फीसद 19 फीसद ही रहा। ऐसी स्थिति में हमें यह समझने का प्रयास करना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। भाजपा को बढ़ा हुआ मत फीसद बताता है कि मोदी ने मतदाताओं के लिए कुछ काम किया है और हमें इसे स्वीकारना होगा। हालांकि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में रह गईं कमियों को हम जरूर उजागर कर सकते हैं। यह बात ठीक है कि मोदी सरकार ने शौचालयों का निर्माण कराया, लेकिन 60 फीसद में पानी नहीं है। गरीब ग्रामीण महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया गया, लेकिन 92 फीसद ने सिलेंडर दोबारा नहीं भराया। अब अगर कांग्रेस कहती है कि मोदी ने कुछ नहीं किया और लोगों ने फिर भी उसे वोट दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों को मूर्ख समझते हैं। थरूर ने कहा कि वह चाहते हैं कि कांग्रेस, प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी दलों के साथ मिलकर सत्ता में वापस आए। ऐसा सिर्फ कोर कांग्रेस समर्थकों के भरोसे संभव नहीं हो सकेगा। हमें उन लोगों का विश्वास और वोट पाना होगा जो पिछले दो लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा के साथ चले गए हैं।

मप्र के घमासान पर सोनिया से नहीं मिल पाए सिंधिया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मध्य प्रदेश कांग्रेस में जारी घमासान का समाधान निकालने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की बैठक नहीं हो पाई। इस वजह से मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में बाहरी दखल को लेकर पार्टी में चल रही खींचतान के हल का फार्मूला अभी तय नहीं हो पाया है।

मध्य प्रदेश सरकार में बाहरी दखल की शिकायत वैसे तो सिंधिया गुट के नेताओं ने आलाकमान को पहले ही भेज दी है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस पर हाईकमान से सीधी बात नहीं हुई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की अपने खिलाफ कथित लामबंदी के मसले पर अपनी बात रखने के लिए मंगलवार को सिंधिया को सोनिया गांधी से मिलना था। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष की व्यस्तता और फिर सिंधिया के महाराष्ट्र की स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक में शामिल होने के कारण मुलाकात टल गई।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि सिंधिया अब बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष से मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के खुले घमासान को लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पहले ही अलग-अलग सोनिया गांधी से मिल कर अपना पक्ष रख चुके हैं।


ज्योतिरादित्य सिंधिया फाइल फोटो

▶ सोनिया के समक्ष ज्योतिरादित्य संधिया को रखना है अपना पक्ष

▶ दिग्विजय सिंह पर राज्य सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा रहे हैं मंत्री

सोनिया गांधी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में खेमेबंदी और नेताओं के बीच खुले तौर पर जारी घमासान पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए इससे जुड़े सभी पक्षों की शिकायतें पार्टी केंद्रीय अनुशासन समिति के अध्यक्ष एके एंटनी को सौंप दी थी। साथ ही एंटनी समिति से सरकार में बाहरी दखल की शिकायतों से लेकर नेताओं के बड़बोले बयानों पर गौर कर उचित कदम उठाने को कहा गया है। ज्ञात हो, कमलनाथ के मंत्री दिग्विजय सिंह पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा रहे हैं।

135 सीटों पर मान सकती है शिवसेना पर भाजपा को है सहयोगियों की चिंता

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन को लेकर शिवसेना के सुर नरम होने लगे हैं। शिवसेना के एक नेता की बातों पर यकीन करें तो आनेवाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी राज्य की कुल 288 विधानसभा सीटों में से 135 पर राजी हो सकती है। हालांकि, भाजपा चाहती है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के छोटे दलों का भी समुचित समायोजन हो। इससे पहले शिवसेना 144 सीटों और ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग पर अड़ी हुई थी।

पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा, '135-135 सीटों पर चुनाव लड़ने के फॉर्मूले को स्वीकार करते हुए शिवसेना 18 सीटों को गठबंधन के दूसरे दलों-आरपीआइ (ए), राष्ट्रीय समाज पक्ष व शिव संग्राम पार्टी के लिए छोड़ सकती है।' हालांकि, शिवसेना चाहती है कि सहयोगी दलों के लिए 18 और सीटों का आवंटन भाजपा अपने हिस्से से करे, क्योंकि वे उसके साझीदार हैं। इस प्रस्ताव पर भाजपा की सहमति की गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन ऐसा हुआ तो पार्टी को सिर्फ 117 सीटों पर प्रत्याशी उतार पाएगी।

पीएम मोदी के समक्ष गठबंधन को अटल बता चुके हैं उद्धव

पिछले ही शनिवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के साथ एक कार्यक्रम में मंच साझा किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन अटल है। वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां अलग-अलग चुनाव लड़ी थीं। इसमें भाजपा को 122 व शिवसेना को 63 सीटों पर जीत मिली थी।

भाजपा के सहयोगी दलों ने इस समस्या को और जटिल कर दिया। आरपीआइ (ए) के नेता व केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, आरएसपी नेता और राज्य के मंत्री माधव जानकर तथा एसएसपी के नेता विनायक मेटे ने भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने से इन्कार कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि दूसरे दलों से आए नेता और बढ़ती राजनीतिक ताकत को समायोजित करने के लिए भाजपा के चुनाव प्रबंधक 135 से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं।

निकाह अमान्य ठहराने के फैसले को नाबालिग लड़की ने दी चुनौती

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट एक शादीशुदा नाबालिग मुस्लिम लड़की की याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है जिसने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने उसके निकाह को अमान्य घोषित करते हुए उसे अयोध्या स्थित शेल्टर होम भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को सही ठहराया था।

जस्टिस एनवी रमना, इंदिरा बनर्जी और अजय रस्तोगी की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता लड़की 16 साल की है। उसने अपने वकील दुष्यंत पराशर के जरिये दायर याचिका में कहा है कि हाई कोर्ट ने इस तथ्य पर तवज्जो नहीं दी कि उसका निकाह मुस्लिम कानून के मुताबिक है। उसने कहा है कि उसके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। उसकी दलील है कि जिस व्यक्ति से उसने निकाह किया है, वह उससे प्यार करती है और उन्होंने इसी साल जून में मुस्लिम कानून के मुताबिक निकाह किया है।

डीके शिवकुमार की बेटी को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया

नई दिल्ली, आइएएनएस : कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग के मामले में उनकी बेटी एश्वर्य (22) को भी पूछताछ के लिए समन किया है। एश्वर्य मैनेजमेंट में स्नातक हैं।

ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एश्वर्य को 12 सितंबर को पूछताछ के लिए दिल्ली में जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने को कहा गया है। उन्होंने कहा, शिवकुमार के वित्तीय लेनदेन की जांच के दौरान एजेंसी को एक ट्रस्ट से जुड़े कागजात मिले थे। शिवकुमार के बनाए इस एजुकेशन ट्रस्ट में उनकी बेटी एश्वर्य ट्रस्टी हैं। इस ट्रस्ट का करोड़ों का कारोबार और संपत्तियां हैं और यह कई इंजीनियरिंग व अन्य कॉलेजों का संचालन करता है। ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और उसके वित्तीय लेन-देन का विवरण जानने के लिए ही एश्वर्य को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उम्मीद है कि इस दौरान प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज किया जाएगा और उनसे शिवकुमार के उस बयान और दस्तावेजों के बाबत पूछताछ भी की जाएगी जो उन्होंने बेटी संग 2017 में की गई सिंगापुर यात्रा के बारे में दिया है। जरूरत पड़ी तो एश्वर्य व शिवकुमार का आमना-सामना भी करा सकती है।


डीके शिवकुमार फाइल फोटो

जांच एजेंसी के समक्ष एश्वर्य को गुरुवार को होना होगा हाजिर

ज्ञात हो, इस मामले में दो दिन तक पूछताछ करने के बाद ईडी ने शिवकुमार को तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था। एक दिन बाद दिल्ली की अदालत ने शिवकुमार को 10 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। दरअसल, 2016 में नोटबंदी के बाद से ही शिवकुमार आयकर विभाग और ईडी की रडार पर थे। दो अगस्त, 2017 को दिल्ली स्थित उनके फ्लैट की आयकर विभाग ने तलाशी ली थी जहां 8.59 करोड़ की अघोषित नकदी मिली थी। इसके बाद विभाग ने उनके और के चार सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।

एनआरसी से एक भी भारतीय नहीं छूटेगा : स्मृति

जागरण संवाददाता, कोलकाता : केंद्रीय कपड़ा एवं महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर से एक भी भारतीय नहीं छूटेगा। हम देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। मंगलवार को कोलकाता में मीडिया से मुखातिब स्मृति ने एनआरसी का विरोध करने पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। ईरानी ने साफ किया कि अवैध घुसपैठ से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा।



ममता पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह अवैध घुसपैठ पर उनके रुख के विरोधाभास को दर्शाता है। ममता द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं का विरोध जगजाहिर है। उनका आक्रामक रवैया राज्य के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा मुहैया कराए जाने वाले लाभ से वंचित रख रहा है, जो कि किसानों, महिलाओं और बच्चों को मिल सकते थे। उन्होंने आगे कहा-'बंगाल सरकार द्वारा उद्योगों की स्थापना रोक दी गई है। बंगाल में लोकसभा चुनाव के नतीजों ने दिखा दिया है कि राज्य की जनता बदलाव चाहती है।'

स्कूली शिक्षा के लिए यूजीसी जैसे नियामक की तैयारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस पर गंभीरता से शुरू किया काम

स्कूली शिक्षा को राज्यों के मकड़जाल से बाहर निकालकर नई ऊंचाई पर ले जाने में जुटी केंद्र सरकार जल्द ही इसके लिए यूजीसी जैसे नियामक के गठन को मंजूरी दे सकती है। इसमें स्कूली शिक्षा का पूरा तानाबाना शामिल होगा। फिलहाल मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस पर काम कर रहा है। वह इसे लेकर अंतिम नतीजे पर पहुंच गया है। ऐसे में कभी भी इसका एलान किया जा सकता है।

प्रस्तावित नई शिक्षा नीति में भी स्कूली शिक्षा को मजबूती देने के लिए नियामक बनाने का प्रस्ताव है। इसके बावजूद मंत्रालय में स्कूली शिक्षा से जुड़े कई संस्थानों ने स्कूली शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) जैसे नियामक की जरूरत पर जोर दिया है। पिछले दिनों एनआइओएस (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान) ने भी सरकार को खुले रूप में कुछ ऐसा ही सुझाव दिया था। इसमें कहा गया था कि देश में यदि आज उच्च शिक्षा को ऊंचाई मिली है, तो उसके पीछे यूजीसी की अहम भूमिका है। इसके दायरे में मौजूदा समय में केंद्र व राज्य के सभी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान आते है। स्कूली शिक्षा में ऐसा कोई नियामक नहीं है। सारा कुछ राज्यों पर छोड़ रखा गया है। जो इसे अपने-अपने हिसाब से चलाते रहते है। यही वजह है कि ज्यादातर राज्यों में स्कूली शिक्षा का बुरा हाल है। लर्निंग आउटकम की स्थिति बेहद खराब है।

सूत्रों के मुताबिक स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में जुटे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा से जुड़े संस्थानों के इन सुझावों को गंभीरता से लिया है। साथ ही इस दिशा में तेजी से काम भी शुरू कर दिया है। इस बीच यूजीसी के नियमों पर भी नजरें दौड़ाई गई है। इसके चलते वह राज्यों के विश्वविद्यालयों पर भी अपनी दखल रखता है। स्कूली शिक्षा के बनने वाले इस नियामक को स्कूली शिक्षा आयोग (एसईसी) जैसा नाम दिया जा सकता है। साथ ही शिक्षक शिक्षा (टीचर एजुकेशन) को भी इनमें शामिल किया जा सकता है।

हाई कोर्ट ने मांगी कार्ति केस के ट्रांसफर आदेश की प्रति

चेन्नई, प्रेट्र : मद्रास हाई कोर्ट ने अभियोजन को कार्ति चिदंबरम के खिलाफ मामले को विशेष कोर्ट में ट्रांसफर करने के निचले अदालत के आदेश की प्रति पेश करने को कहा है। निचली कोर्ट ने सांसदों-विधायकों के मामले की सुनवाई के लिए गठित विशेष कोर्ट में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है।

आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई आपराधिक प्रक्रिया को विशेष कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस पीडी अउदिकेसवालु ने सोमवार को यह निर्देश दिया। कार्ति और उनकी पत्नी श्रीनिधि के खिलाफ आयकर विभाग का मामला एग्मोरे एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में लंबित है। निर्देश के बाद न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई एक हफ्ते बाद तय कर दी।

हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने मामला स्थानांतरित किए जाने को न्यायसंगत ठहराया है। जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि स्थानांतरण सुप्रीम कोर्ट के 12 सितंबर 2018 के आदेश के अनुरूप है। याची द्वारा किया गया कथित अपराध आयकर अधिनियम की धारा 279 ए के तहत आता है।

श्रद्धांजलि सभा

प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने दिवंगत नेता को किया याद, शाह ने कहा, कठिन दौर में चट्टान की तरह उनके साथ खड़े थे जेटली

मन पर जेटली के अंतिम दर्शन नहीं करने का बोझ : पीएम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व वित्तमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी। अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि में मोदी ने कहा, इतने लंबे कालखंड तक अभिन्न मित्र रहने वाले जेटली का अंतिम दर्शन नहीं कर पाने का बोझ उनके मन पर हमेशा बना रहेगा। वहीं जीवन के कठिन समय में जेटली के चट्टान की तरह साथ खड़े होने का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि उनके विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने में जेटली का अभिन्न योगदान था। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाजपा और उसके सहयोगी दलों के साथ विपक्षी दलों के नेताओं ने जेटली को याद किया।

विदेश यात्रा के कारण अरुण जेटली की अंत्येष्टि में भाग नहीं ले सके मोदी ने कहा, कैबिनेट में उनकी कमी हमेशा खलेगी। जेटली की कितनी बड़ी कमी उन्हें महसूस होती है, उसे शब्दों में नहीं बता सकते हैं। उन्होंने कहा, छात्र राजनीति की नर्सरी में पैदा हुए एक पौधे का भारत की राजनीति के विशाल फलक में एक वट वृक्ष बनकर उभरना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मोदी ने कहा, उन्हें दुनिया की हर चीज की जानकारी थी। सरकार के अहम फैसलों में जेटली के योगदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें संसदीय कार्यप्रणाली का इनसाइक्लोपीडिया बताया। पीएम ने कहा कि वे सर्वमित्र थे, वे सर्वप्रिय थे और प्रतिभा, पुरुषार्थ के कारण जिसको जहां भी उपयोगी हो सकते थे, वे हमेशा उपयोगी होते थे। मोदी ने कहा, सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा कि उन्हें अपने दोस्त को श्रद्धांजलि देने के लिए आना पड़ेगा।

विचारधारा के प्रति अरुण जेटली के लगाव का उदाहरण देते हुए अमित शाह ने बताया कि किस तरह संसद से अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद वे पीएमओ पहुंचे थे। वहां प्रधानमंत्री पहले से ही जेटली से बात कर रहे थे। इस दौरान यह अहसास ही नहीं हुआ कि वे बीमार हैं। शाह ने बताया कि किस तरह जेटली उनके जीवन के कठिन समय में एक बड़े भाई के समान चट्टान की तरह साथ खड़े रहे। उन्होंने दिल्ली में गुजरात की कमी महसूस नहीं होने दी। सार्वजनिक जीवन में पार्टी लाइन से बाहर जाकर ढेर सारे लोगों से दोस्ती रखना उनकी विशेषता थी। इस अवसर पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने 1980 के दशक से जेटली के साथ संबंधों को याद करते हुए कहा, जो भी उनसे मिलता था, उनका कायल हो जाता था। यही उनके साथ भी हुआ और पहली मुलाकात में ही वे जेटली की योग्यता और कार्यक्षमता के कायल हो गए थे। उन्होंने बताया कि किस तरह वाजपेयी सरकार में वाणिज्य मंत्री के रूप में अरुण जेटली ने विश्व व्यापार संगठन में भारत के किसानों के मुद्दे की पुरजोर पैरवी की थी।

इस अवसर पर तृणमूल के दिनेश त्रिवेदी, बसपा के सतीश मिश्रा, सपा के रामगोपाल वर्मा, भाकपा के डी. राजा, राकांपा के शरद पवार, कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी, बीजद के पिनाकी मिश्रा, लोजपा के रामविलास पासवान, अकाली दल के सुखबीर बादल ने भी जेटली को श्रद्धांजलि दी।


नई दिल्ली में मंगलवार को अरुण जेटली की स्मृति में आयोजित सभा में पीएम नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल हुए। इस दौरान संगीता जेटली की आंखें पति अरुण जेटली को याद कर नम हो गईं। प्रेट्र

कह के रहेंगे माधव जोशी



15 सितंबर से जदयू ने मध्य प्रदेश में दुष्कर्म पीड़िताओं को न्याय दिलवाने के लिए सड़कों पर उतरने की घोषणा की है। पार्टी 'देश की बेटी, मेरी बेटी- जिम्मेदारी ले सरकार' जन आंदोलन शुरू कर रही है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 11 सितंबर 2019

भीड़ की हिंसा के पीड़ितों को तत्काल आर्थिक मदद देगी उप्र सरकार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कैबिनेट ने लिया निर्णय
- प्रारंभिक जांच के बाद हो जाएगा क्षतिपूर्ति की 25 फीसद राशि का भुगतान

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर योगी कैबिनेट ने भीड़ की हिंसा (मॉब लिंचिंग) समेत अन्य जघन्य अपराधों में पीड़ितों को तत्काल अंतरिम आर्थिक सहायता देने को मंजूरी दे दी है। राज्य पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत अब आरंभिक जांच के बाद ही क्षतिपूर्ति राशि की 25 फीसद रकम अंतरिम राशि के तौर पर पीड़ित को दे दी जाएगी। अब तक किसी मामले की जांच पूरी होने के बाद पीड़ित को क्षतिपूर्ति राशि एक साथ दिये जाने की व्यवस्था थी।

राज्य सरकार के प्रवक्ता व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार भीड़ की हिंसा, दुष्कर्म, तेजाब फेंकने की घटना समेत अन्य अपराधों में अंतरिम राहत प्रदान देने की व्यवस्था कर दी गई है। उत्तर प्रदेश क्षतिपूर्ति योजना-2014 यथा संशोधित-2016 में संशोधन कर भीड़ की हिंसा/हत्या के पीड़ित को अंतरिम राहत प्रदान किए जाने के लिए प्राविधान जोड़ा गया है। अब भीड़ की हिंसा समेत अन्य मामलों में आरंभिक जांच के बाद जिलाधिकारी की संस्तुति पर क्षतिपूर्ति राशि की 25 फीसद रकम अंतरिम राहत के तौर पर पीड़ित अथवा उसके परिवारीजन को दी जा सकेगी।

राज्य पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत ऐसे पीड़ितों तथा उनके आश्रितों को जोड़ा गया है, जिन्हें किसी अपराध के कारण क्षति अथवा हानि हुई है और पुनर्वास की जरूरत है। बताया गया कि क्षतिपूर्ति योजना के तहत दुष्कर्म पीड़ित के लिए क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा दो लाख रुपये, मानसिक संताप के कारण हुई हानि या क्षति के मामलों में एक लाख रुपये, ज्वलनशील पदार्थ के हमले के मामले में तीन लाख रुपये, भीड़ की हिंसा में किसी परिवार के गैर कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर डेढ़ लाख रुपये व कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर दो लाख रुपये तथा मानव तस्करी से पीड़ित को दो लाख रुपये क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित है।

अनुच्छेद 370 पर दल छोड़ने वाले पहले कांग्रेसी बने कृपाशंकर

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई


कृपाशंकर सिंह। फाइल फोटो

महाराष्ट्र विधानसभा के लिए राजनीतिक बिसात बिछाने में जुटी कांग्रेस के लिए मंगलवार का दिन झटका देने वाला साबित हुआ। मुंबई कांग्रेस के तीन नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया। राज्य के पूर्व गृह राज्यमंत्री और हिंदी भाषी समुदाय में गहरी पैठ रखने वाले नेता कृपाशंकर सिंह ने अनुच्छेद 370 पर पार्टी के रुख का विरोध करते हुए प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस मुद्दे पर पार्टी छोड़ने वाले वह पहले कांग्रेसी नेता बन गए हैं। मंगलवार को ही उनसे पहले अभिनेत्री से राजनेता बनीं उर्मिला मातोंडकर और हर्षवर्धन पाटिल ने भी पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी।

कृपाशंकर सिंह ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि अनुच्छेद 370 पर संसद के दोनों सदनों में चली बहस के बाद से ही वह अपनी पार्टी के रुख से आहत हैं। जिस मुद्दे पर देश की आम जनता एकजुट होकर सरकार के साथ खड़ी दिखाई दे रही है उसी मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं का नासमझी भरा बयान समझ से परे है। कांग्रेस के इसी रुख से आहत होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र भेजकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपनी भावी योजना के बारे में कुछ भी नहीं कहा है।

बता दें कि विलासराव देशमुख सरकार में गृह राज्यमंत्री रह चुके कृपाशंकर सिंह मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह मूलतः उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के रहने वाले हैं। पिछला विधानसभा चुनाव हारने के बाद से ही वह पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे थे। हालांकि उन दिनों उन पर तमाम तरह के आरोप लगे थे। माना जाता है कि विभिन्न एजेंसियों से जांच में आरोपों से मुक्त होने के बावजूद पार्टी में उनकी क्षमताओं का उपयोग नहीं हो पा रहा था। पिछले कुछ समय से भाजपा नेताओं के साथ उनका मेलजोल बढ़ा दिखाई दे रहा है।

पिछले सप्ताह ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस एवं महाराष्ट्र में सह चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी निभा रहे उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य उनके घर स्थापित गणपति प्रतिमा का दर्शन करने गए थे। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी गणपति उत्सव के दौरान सिंह के घर गए थे। मुंबई में कभी पूरी तरह कांग्रेस का वोटबैंक माना जाता रहा उत्तर भारतीय समाज आज भले भाजपा के साथ खड़ा दिख रहा है, लेकिन उसके पास कोई कद्दावर हिंदीभाषी नेता नहीं है। कृपाशंकर सिंह भाजपा में यह कमी दूर करने का माध्यम बन सकते हैं।

आंतरिक राजनीति से आजिज उर्मिला ने पार्टी छोड़ी


उर्मिला मातोंडकर। फाइल फोटो

करीब पांच माह पहले उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस की सदस्य बनीं अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने मंगलवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि वह पार्टी की आंतरिक राजनीति में इस्तेमाल होना नहीं चाहती हैं। इसी वर्ष मार्च में कांग्रेस में शामिल हुई अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि पहले तो उनके द्वारा 16 मई को भेजे गए पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऊपर से वह पत्र मीडिया को लीक भी कर दिया गया। जबकि वह पत्र उन्होंने सीधे तत्कालीन मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा को भेजा था।

उर्मिला ने यह पत्र अपने चुनाव के दौरान पार्टी के हितों के विपरीत काम करने वाले कांग्रेसियों पर कार्रवाई के लिए लिखा था। अपने पत्र में उन्होंने मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम के करीबी संदेश कोंडविलकर और भूषण पाटिल के व्यवहार की आलोचना की थी। उनका मानना है कि पार्टी में कोई भी हार के लिए फिक्रमंद नहीं है।

देवड़ा बोले-उत्तर मुंबई के नेता हैं जवाबदेह : उर्मिला के इस्तीफे के कुछ ही घंटे बाद पार्टी नेता मिलिंद देवड़ा ने संजय निरुपम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर मुंबई के नेता इसके लिए जवाबदेह हैं। निरुपम 2009 में उत्तर मुंबई से सांसद चुने गए थे और 2014 में पराजित हुए थे।

आजम के रिसॉर्ट में नलकूप लगाने के मामले में होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, रामपुर : सपा सांसद आजम खां के रिसॉर्ट में नलकूप लगाने के मामले में पूर्व पालिकाध्यक्ष और तत्कालीन ईओ की गर्दन फंस गई है। जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा रिसॉर्ट में बिजली चोरी के मामले में भी डीएम ने अधिशासी अभियंता को दोषी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए कहा है।

सपा सांसद के हमसफर रिसॉर्ट में पिछले दिनों अधिकारियों ने छापा मारा था। इसमें 30 लाख रुपये की बिजली चोरी पकड़ी गई थी। इस पर आजम की पत्नी व राज्यसभा सदस्य डॉ. तजीन फात्मा के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सरकारी नलकूप भी रिसॉर्ट में लगा मिला था। इसके अलावा पानी की टंकी भी बनी थी। इनका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा था। इसके साथ ही यहां पर सरकारी जमीन भी मिली थी, जिस पर वाद भी दायर किया गया है। प्रशासन ने इस मामले में अब शिकंजा कस दिया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि योजनाबद्ध तरीके से लाभ लेने वाले तथा उस योजना में लाभ देने वाले दोषी कार्मिकों के विरुद्ध भी वैधानिक एवं विभागीय कार्रवाई के लिए अधिशासी अभियंता नलकूप खंड को निर्देशित किया गया है।

प्रधानमंत्री कल झारखंड से देश को देंगे तीन योजनाओं की सौगात

तैयारी ▸ आदिवासी बहुल क्षेत्रों में 462 एकलव्य मॉडल विद्यालय का करेंगे शिलान्यास

किसान मानधन योजना, खुदरा दुकानदार पेंशन योजना का मिलेगा तोहफा

राज्य ब्यूरो, रांची


नरेंद्र मोदी। फाइल फोटो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर को झारखंड से पूरे देश को तीन बड़ी योजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को सूचना भवन में इस बाबत विस्तारपूर्वक जानकारी दी। बताया कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, खुदरा व्यापारिक एवं स्वरोजगार पेंशन योजना और एकलव्य मॉडल विद्यालय का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही वह झारखंड विधानसभा के नए भवन व साहिबगंज में मल्टीमॉडल बंदरगाह का उदघाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 1238 करोड़ की लागत से बनने वाले झारखंड सचिवालय के नए भवन का भी शिलान्यास करेंगे।

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस उद्देश्य के साथ झारखंड को अलग राज्य बनाया था, उन्हीं के सपनों का झारखंड बनाने के लिए प्रधानमंत्री यहां से ही कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने साहिबगंज में मल्टी माडल टर्मिनल का शिलान्यास किया था। अब उन्हीं के हाथों इसका शुभारंभ हो रहा है। टर्मिनल शुरू होने से संताल परगना इलाके में औद्योगिक और व्यापारिक विकास के नए दरवाजे खुलेंगे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। संताल के साथ पूरे राज्य में विकास की गति तेज होगी।

आजादी के बाद पहली बार किसानों को पेंशन

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि किसानों के जीवन में सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने के लिए मासिक पेंशन के रूप में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के किसानों का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।

झारखंड में 69 एकलव्य विद्यालय

प्रधानमंत्री गुरुवार को देश के जनजातीय क्षेत्रों में 462 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का आनलाइन शिलान्यास करेंगे। इसमें झारखंड के 13 जिलों में 69 एकलव्य विद्यालय खोले जा रहे हैं।

दुकानदारों के लिए पेंशन योजना

रघुवर दास ने कहा कि पहली बार किसी सरकार ने खुदरा व्यापार करने वाले दुकानदारों और स्वरोजगार करने वालों को पेंशन योजना से जोड़ने की पहल की है। इसके तहत 18 से 40 वर्ष के खुदरा व्यापारियों एवं दुकानदारों को भी 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।

पीएम मोदी आज मथुरा में

जासं, मथुरा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मथुरा आ रहे हैं। वह यहां वेटरनरी यूनिवर्सिटी में आयोजित समारोह में नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। आगरा, हापुड़, मुरादाबाद के लिए करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे।

बड़ा नेता बनना है तो कलेक्टर व एसपी का कॉलर पकड़ो : लखमा

नईदुनिया, जगदलपुर

- बेबाक बयानों से चर्चा में रहने वाले कवासी लखमा का वीडियो वायरल

छत्तीसगढ़ में अपने बेबाक बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहने वाले प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में वह स्कूली बच्चों से कहते नजर आ रहे हैं कि अगर बड़ा नेता बनना है तो कलेक्टर और एसपी का कॉलर पकड़ो।

बताया जा रहा है कि मंत्री लखमा शिक्षक दिवस के दिन सुकमा जिले के पावारास गांव में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। वीडियो में बच्चों के बीच लखमा कहते नजर आ रहे हैं कि एक बार किसी बच्चे ने उनसे पूछा कि बड़ा नेता कैसे बनें, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर बड़ा नेता बनना है तो कलेक्टर और एसपी का कॉलर पकड़ो। मंत्री लखमा जिन लोगों को यह बात बता रहे हैं, वे लोग वीडियो में नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनकर वहां मौजूद बच्चों और अन्य की हंसी छूट पड़ी। हालांकि, अब लखमा कह रहे हैं कि उनकी बात को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है। उनके कहने का तात्पर्य था कि अगर बड़ा नेता बनना है तो जनता की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लखमा का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था। मीडिया ने उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया है।

लखमा राज्य के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग की कोंटा सीट से चुनकर आते हैं। लगातार पांचवीं बार विधायक बने हैं। यही वजह है कि ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं होने के बाद भी राज्य मंत्रिमंडल में उन्हें स्थान दिया गया है। लेकिन, उनके बार-बार बिगड़ते बोलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। मंत्री के ताजा बयान ने राज्य के नौकरशाह नाराज हैं। मंत्री बनने के बाद से लखमा तीसरी बार अपने बयान की वजह से चर्चा में हैं। इससे पहले वे प्रधानमंत्री और उद्योगपतियों को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। बार-बार हो रही ऐसी घटनाओं से सरकार को अब अपनी छवि की चिंत सताने लगी है।

पहले कहा था उद्योगपतियों को घुसने नहीं देंगे : इससे पहले मंत्री लखमा उद्योगपतियों को बस्तर में घुसने नहीं देने की धमकी दे चुके हैं। सूत्रों के अनुसार इसके बाद सत्ता पक्ष के लोगों ने उन्हें समझाया था कि इस तरह का बयान देने से सरकार की छवि बिगड़ेगी और निवेश भी प्रभावित हो सकता है। इसके बाद जगदलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान एक पत्रकार के सवाल पूछने पर लखमा ने कहा था, पत्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भाषा बोलने लगे हैं।

अनपढ़ को मंत्री बनाएंगे तो यही होगा : मंत्री लखमा के विवादित बयान पर केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि जब अनपढ़ को मंत्री बनाएंगे तो ऐसे ही बयानों की उम्मीद रहेगी। जिन्हें कार्यपालिका का ज्ञान नहीं है, उनसे ऐसे ही बयान की उम्मीद की जा सकती है।

मप्र में नेता पुत्रों की लांचिंग से भाजपा ने खींचे हाथ, वंशवाद नहीं बढ़ाएगी

नईदुनिया, भोपाल

- भाजयुमो ने बनाई थी नेता पुत्रों के नेतृत्व में आंदोलन समिति
- संगठन ने कहा- नेता पुत्र बतौर कार्यकर्ता ही हो सकते हैं शामिल

> भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। पार्टी में कार्यकर्ता के नाते सभी को आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। वंशवाद के आधार पर किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार पार्टी ने किसी को नहीं दिया है। भाजपा का कोई मोर्चा-प्रकोष्ठ नेता पुत्रों का लांच पैड नहीं बन रहा है, न ही ये भाजपा की रीति-नीति है।
>
> -रजनीश अग्रवाल, प्रवक्ता, मप्र भाजपा

मध्य प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) द्वारा नेता पुत्रों की लांचिंग की तैयारी पर पानी फिर गया है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि न तो वह वंशवाद को बढ़ाएगी और न ही नेता पुत्रों की लांचिंग की कोई नीति तैयार की है। दरअसल, भाजयुमो ने घंटानाद आंदोलन के जरिये नेता पुत्रों की एक आंदोलन समिति बना दी थी, जिससे यह संदेश जा रहा था कि भाजयुमो द्वारा नेता पुत्रों का लांचिंग पैड तैयार किया गया है। कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया तो संगठन ने कहा कि नेता पुत्र कार्यकर्ता के तौर पर ही आंदोलन में शामिल हो सकते हैं।

भाजयुमो ने पार्टी के आधा दर्जन दिग्गज नेताओं के बेटों के नेतृत्व में आंदोलन समिति बनाकर प्रदेशभर में अलग-अलग स्थानों पर आंदोलन का नेतृत्व करने की बागडोर भी सौंप दी थी। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा के बेटे तुष्मुल झा, पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार के बेटे मुदित शेजवार, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण मिश्रा, दीपक जोशी के बेटे जयवर्द्धन जोशी, अर्चना चिटनीस के बेटे समर्थ चिटनीस, नंदकुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्द्धन सिंह चौहान और पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया के बेटे सौरभ बावरिया को शामिल किया गया था। भाजयुमो की इस आंदोलन समिति में 31 सदस्य थे, जिनमें से एक दर्जन नेता पुत्र शामिल थे।

सूत्रों का कहना है कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने मामले में संगठन के नेताओं के सामने विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ही वंशवाद का विरोध कर रहा है तो फिर स्थानीय नेतृत्व किस आधार पर वंशवाद को प्रश्रय दे रहा है। कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेताओं से पूछा कि क्या वे सिर्फ दरी-फट्टा उठाने के लिए और नेता पुत्र मलाई खाने के लिए हैं। कई स्तर पर विरोध के बाद संगठन ने कहा कि पार्टी की ऐसी कोई मंशा नहीं कि नेता पुत्रों की लांचिंग की जाए।

विपक्ष में आने के 10 महीने बाद आज से भाजपा का 'घंटानाद' आंदोलन

विधानसभा चुनाव के 10 महीने बाद बतौर विपक्ष भाजपा पहली बार 11 सितंबर से 'घंटानाद' आंदोलन के जरिये कमलनाथ सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। पार्टी का दावा है कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने से अराजकता की स्थिति है। किसान परेशान हैं। कर्जमाफी के नाम पर किसानों से छलावा किया गया। अब उन पर 14 फीसद जुर्माने के साथ कर्ज के भुगतान का दबाव बनाया जा रहा है। तबादलों ने गवर्नेंस को चौपट कर दिया है। जन समस्याओं के निपटारे पर किसी का ध्यान नहीं है। इन सारे मुद्दों को लेकर भाजपा बुधवार को सड़कों पर उतरेगी।

पूर्वांचल और बुंदेलखंड में बुनियादी ढांचे पर 80 हजार करोड़ खर्च करेगी सरकार

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : पूर्वी पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लगभग 40 जिलों में केंद्र सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर अगले पांच वर्षों में 80 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करेगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि इसके लिए योजना बना ली गई है।

प्रयागराज आए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दैनिक जागरण को बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल संरक्षण, सौर ऊर्जा परियोजनाओं, पुलों, डैम निर्माण पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से अंतर मंत्रालय कार्य बल का गठन किया गया है, जो परियोजनाओं की मॉनीटरिंग करेगा। इस पहल से पूर्वांचल और बुंदेलखंड इलाके में विकास को नई गति , मिलने और नौकरियों का सृजन होने की उम्मीद है। बताया कि गंगा एक्सप्रेस-वे के जरिए पश्चिमी यूपी, दिल्ली एनसीआर से पूर्वी उत्तर प्रदेश सीधे जुड़ेगा। मेरठ से प्रयागराज के बीच लगभग सात सौ किमी लंबे इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण पर साढ़े छह हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। केंद्र व राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए नोडल एजेंसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने सर्वे भी शुरू करा दिया है।



मुहर्रम पर दुआ मांगी...

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित सरायममरेज थाना क्षेत्र में मंगलवार को मुहर्रम पर अपने पैतृक गांव भदारी से करीब एक किलोमीटर दूर साथर में दुआ करते केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। जागरण

मप्र सरकार आयोजित करेगी संतों का समागम

नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार भोपाल में 17 सितंबर को संत समागम आयोजित करेगी। इसमें मध्य प्रदेश से दो-ढाई हजार साधु-संत जुटेंगे और मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने अपनी बात रखेंगे। मठ, मंदिर से संबंधित संतों की अपेक्षाओं और समस्याओं के समाधान की रूपरेखा भी इसी समागम में तय की जाएगी।

प्रदेश के अध्यात्म मंत्री पीसी शर्मा ने पत्रकारवार्ता में समागम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, मठ-मंदिर सलाहकार समिति के अध्यक्ष स्वामी सुबुद्धानंद, नर्मदा न्यास के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा उपस्थित रहेंगे। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि कमलनाथ सरकार धर्म के साथ चल रही है।

सेक्स रैकेट कांड में राजद विधायक की होगी गिरफ्तारी

जागरण संवाददाता,आरा : भोजपुर और पटना के चर्चित सेक्स रैकेट कांड में पीड़िता के कोर्ट में दिए गए कलमबंद बयान के बाद राजद विधायक अरुण यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। पीड़ित किशोरी ने बयान में विधायक का नाम लिया है। पुलिस कोर्ट में गिरफ्तारी वारंट के लिए अर्जी देगी। फिलहाल विधायक भूमिगत हो गए हैं। मंगलवार को मामले में जांच से जुड़े पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि दो दिनों से सुराग नहीं मिल पा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब पीड़िता ने अपने बयान में सीधे आरोप लगाया है तो पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है।

सोमवार शाम ही मामले के आइओ इंस्पेक्टर चंद्रशेखर गुप्ता ने कोर्ट से सील बंद लिफाफे में बयान की कॉपी प्राप्त की थी। अभी तक इस मामले में पुलिस संचालिका अनीता, उसके दलाल संजीत और अभियंता अमरेश के अलावा सेक्स रैकेट के संचालक संजय यादव उर्फ जीजा को जेल भेज चुकी है। सीआइडी भी अलग से केस की तफ्तीश कर रही है।बताते चलें कि छह सितंबर को पीड़ित किशोरी का दोबारा बयान आरा कोर्ट में दर्ज कराया गया था। 18 जुलाई को पटना में संचालित सेक्स रैकेट गिरोह के चंगुल से भागकर भोजपुर पुलिस के पास पहुंची किशोरी ने इंजीनियर समेत विधायक के आवास पर भेजे जाने की बात कही थी।

हरियाणा का हाल

बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा- अकेले के दम पर 90 सीटों पर लड़ेगी पार्टी, मायावती से मुलाकात की खबरों को हुड्डा और सैलजा ने गलत ठहराया

बसपा और कांग्रेस के बीच नहीं होगा समझौता

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली


सतीश चंद्र मिश्रा। फाइल फोटो

जननायक जनता पार्टी (जजपा) से चुनावी समझौता टूटने के बाद बहुजन समाज पार्टी (बसपा) हरियाणा में किसी अन्य राजनीतिक दल से चुनावी गठबंधन नहीं करेगी। बसपा नेता और राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र मिश्रा ने पार्टी की तरफ से साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी हरियाणा में सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही कांग्रेस और बसपा के बीच समझौते की कोशिशों पर ब्रेक लग गया है।

अकेले चुनाव लड़ने के मिश्रा के बयान से पहले दिल्ली से लेकर हरियाणा तक यह चर्चा आम हो गई थी कि राज्य कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष कुमारी सैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी समझौता करने के लिए बसपा प्रमुख मायावती से मिले थे। लेकिन, मिश्रा ने इन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया है कि जजपा से गठबंधन टूटने के बाद बसपा प्रमुख की हरियाणा के किसी भी नेता से मुलाकात नहीं हुई। इतना ही नहीं बसपा प्रमुख से मुलाकात की खबरों को खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी गलत ठहराया था।

कांग्रेस भी अकेले चलेगी

2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने गठबंधन के अनेक प्रयास किए, मगर तब वहां की तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित ने अपनी पार्टी के अजय माकन जैसे अन्य नेताओं का सुझाव दरकिनार करते हुए अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया था। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि बसपा से गठबंधन करने पर पार्टी को भविष्य में काफी राजनीतिक नुकसान हो सकता है। इसलिए हरियाणा में कांग्रेस अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी।

हुड्डा चाहते थे समझौते की बात चलाना, सैलजा ने किया विरोध

सूत्र बताते हैं कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस और बसपा के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव में उतरना चाहते थे, मगर हुड्डा की इस रणनीति का नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने प्रबल विरोध किया। सैलजा ही नहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ .अशोक तंवर ने भी मायावती से समझौता करने से इन्कार कर दिया था। सैलजा और तंवर दोनों ही कांग्रेस में अनुसूचित जाति के बड़े चेहरे हैं। सैलजा और मायावती के बीच तो व्यक्तिगत संबंध भी नहीं हैं, जबकि दोनों राज्यसभा व लोकसभा में एक साथ सांसद भी रहे चुकी हैं।

उप्र से बाहर रहने वाले मूल बाशिंदों के लिए लखनऊ में बनी विशेष डेस्क

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

- उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के कार्यालय से करेगी काम
- टेलीफोन नंबर और ई-मेल आइडी भी जारी

विभिन्न राज्यों में रह रहे उत्तर प्रदेश मूल बाशिंदों की समस्याओं का निस्तारण अब उत्तर प्रदेश में बनाई गई एक विशेष डेस्क करेगी। यह डेस्क उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के कार्यालय से अपना काम करेगी। यह जानकारी मुंबई में मंगलवार को केशव मौर्य ने खास बातचीत में दी।

मुंबई में बड़ी संख्या में रह रहे उत्तर प्रदेश मूल के लोग यहां उत्तर प्रदेश का निवासी आयुक्त नियुक्त करने की मांग लंबे समय से करते रहे हैं। मायावती के शासनकाल में उत्तर भारतीयों की अग्रणी सामाजिक संस्था अभियान के संयोजक अमरजीत मिश्र ने यह मांग उठाई थी। पिछले वर्ष लखनऊ में हुए इन्वेस्टर समिट के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रवासी उद्यमियों एवं राज्य सरकार के बीच सेतु का काम करने वाली संस्था उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट फोरम ने भी विभिन्न मंचों पर यह मांग उठाई थी। कोशिश थी कि उत्तर प्रदेश मूल के निवेशकों को पुनः उनके गांव-जनपद से जोड़ने में सुविधा हो। तब सरकार की ओर से उद्योग मंत्री सतीश महाना एवं उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने इस विचार को अमल में लाने का आश्वासन भी दिया था।

अब केशव मौर्य पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के सह प्र भारी बनाए गए हैं। इस बार उनके मुंबई आगमन पर अमरजीत मिश्र ने दोबारा इस मांग की याद दिलाई। बता दें कि मिश्र अब मुंबई भाजपा के महासचिव होने के साथ-साथ महाराष्ट्र सरकार में राज्यमंत्री भी हैं। मौर्य ने इस बार मामले की गंभीरता को समझते हुए लखनऊ सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में एक विशेष डेस्क बनाने का तत्काल निर्णय लिया। इस डेस्क के लिए उनके कार्यालय के टेलीफोन नंबर 0522-2239990 को अधिकृत किया गया है। साथ ही दो अतिरिक्त कर्मचारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे किसी भी प्रदेश से आई किसी शिकायत के निस्तारण में उत्तर प्रदेश के प्रवासियों की मदद करें। इसके लिए एक विशेष मेल आईडी- dycmkmpmh@gmail.com भी बनाई गई है।

मुंबई में उप्र के एक जिम्मेदार अधिकारी की नियुक्ति की जरूरत : मौर्य

केशव मौर्य ने कहा कि मुंबई जैसे बड़े महानगर में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश मूल के लोग रहते हैं। मुंबई में उत्तर प्रदेश के एक जिम्मेदार अधिकारी की नियुक्ति होनी ही चाहिए, ताकि लोग सीधे उसके पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। उत्तर प्रदेश गए बिना ही उनकी समस्याओं का समाधान भी हो सके। जब तक यह निर्णय नहीं हो पाता, तब तक मेरे कार्यालय में बनी विशेष डेस्क इस कमी को दूर करने का पूरा प्रयास करेगी।

19 वर्ष में उत्तराखंड के नैनीताल जिले में बरामद 440 अज्ञात शवों की नहीं हो सकी शिनाख्त। राज्य बनने के बाद अब तक नैनीताल जनपद में बरामद हुए 539 अज्ञात शव, लेकिन शिनाख्त सिर्फ 99 की हो सकी।

कश्मीर में जल्द आएगी बहार, खिलखिला उठेंगे 'फूल'

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- घाटी के बच्चों और किशोरों को तनाव व नकारात्मक प्रभाव से बचाने के लिए बनाए जा रहे चाइल्ड फ्रेंडली सेंटर
- खुद को व्यक्त करने और सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रहने के लिए किया जा रहा प्रेरित

कश्मीर में जल्द बहार आएगी और मुरझाए फूल फिर खिलखिला उठेंगे। कश्मीर के 'फूल' यानी बच्चे। मौजूदा हालात का अगर सबसे ज्यादा असर हुआ है तो वह हैं मासूम बच्चे व किशोर। कश्मीर घाटी के इन्हीं बच्चों और किशोरों को तनाव व नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव से बचाने के लिए प्रशासन ने अनूठी पहल की है। घाटी के प्रत्येक जिले में चाइल्ड फ्रेंडली सेंटर (सीएफसी) स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों में बच्चों को अवसाद, अनिश्चितता और खौफ से निजात पाने के साथ खुद को व्यक्त करने और सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बाल मनोविज्ञान से विशेषज्ञ और प्रतिष्ठित मनोचिकित्सक इन बच्चों की मदद कर रहे हैं। पहले चरण में 36 सीएफसी बनाए गए हैं।

सायको-सोशल ट्रामा का शिकार हो सकते हैं बच्चे : गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस (आइएमएचएनएस) के एक डॉक्टर ने बताया कि वादी में जो हालात चल रहे हैं, उससे बच्चे सायको-सोशल ट्रामा का शिकार हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि विशेषकर छह से 16 साल के किशोर इससे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। उनकी मनोदशा पर मौजूदा हालात के नकारात्मक असर से इन्कार नहीं किया जा सकता।

बच्चों पर बंदिशों से पैदा हो जाती हैं मानसिकत दिक्कतें : आइएमएचएनएस में वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ. जैयद अहमद ने कहा कि व्यस्क किसी हद तक हालात के अनुकूल अपने आप को बना लेते हैं। बच्चों और किशोर इस मामले में थोड़े अलग होते हैं। वयस्क लोग आपस में बातचीत कर, दोस्तों में गप्पबाजी और बहस कर अपने भीतर की हताशा, निराशा को निकाल लेते हैं। विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय भी व्यक्त कर लेते हैं। बच्चे ऐसा नहीं कर पाते। जो बच्चा रोज सुबह छह-सात बजे उठता हो, स्कूल जाता हो, दोपहर को आकर खाना खाता है। स्कूल में दोस्तों के साथ और बाद में गली मोहल्ले में पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता है, टीवी देखता है, पढ़ता है। वह अचानक पूरा दिन घर में बंद रहे। टीवी भी न देख सके, टेलीफोन और मोबाइल पर अपने परिचितों से बातचीत न कर सके, स्कूल न जाए और घर से बाहर खेलने न जाए, उसके लिए कई तरह की मानसिकत दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। घर वाले भी उसे बाहर जाने से रोकते हैं। इससे उसमें कई तरह के विकार पैदा हो सकते हैं। ऐसे बच्चे कई बार सामान्य नजर आते हैं, लेकिन जब वयस्क होते हैं तो हिंसक प्रवृति के बन जाते हैं या बिल्कुल खामोश।

पहले चरण में कुलगाम, शोपियां, अनंतनाग, पुलवामा को चुना गया

आइएमएचएनएस ने ऐसे बच्चों की मदद के लिए एक कंटिनजेंसी प्लान बनाया है। पहले चरण में कुलगाम, शोपियां, अनंतनाग और पुलवामा में 16 साल तक के बच्चों तक पहुंच बनाने के लिए सीएफसी बनाए जा रहे हैं। आइएमएचएनएस में यूनीसेफ द्वारा संचालित चाइल्ड एंड गाइडेंस एंड वेलबिइंग सेंटर के बाल मनोचिकित्सक डॉ. करार हुसैन ने बताया कि प्रत्येक जिला अस्पताल में भी हम इस तरह के केंद्र बना रहे हैं। इसके अलावा हम स्कूलों, स्थानीय नागरिकों के मकानों और आंगनबाड़ी केंद्रों में सीएफसी स्थापित कर रहे हैं। इन केंद्रों में हम स्वयंसेवकों को सायकोलाजिकल फर्स्ट एड की जानकारी भी दे रहे हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि वह अवसाद और सोशल ट्रामा से पीड़ित बच्चों से कैसे बात कर उनकी भावनाओं को उभारकर उनमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं।

पाक से सिर्फ गुलाम कश्मीर पर होगी बात

- उपराष्ट्रपति ने पंच-सरपंचों से मुलाकात के दौरान राज्य में विकास की गति तेज होने की उम्मीद जताई
- कहा-देश के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और देश की अखंडता सर्वोपरि है

नई दिल्ली, प्रेट्र : उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रत्येक भारतीय की सुरक्षा और देश की अखंडता को सर्वोपरि बताते हुए मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता अब गुलाम कश्मीर के मुद्दे पर ही होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अनुच्छेद- 370 के खत्म होने के बाद जम्मू-कश्मीर में विकास की गति जहां तेज होगी, वहीं कई केंद्रीय योजनाएं और कानून लागू हो सकेंगे, जिन्हें पहले लागू नहीं किया जा सकता था। लागू होने वाले नए कानूनों में स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करना भी शामिल है।

नायडू ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित हुए पंच-सरपंचों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कहा कि अनुच्छेद-370 संविधान में एक अस्थायी प्रावधान था और इसके खत्म होने से राज्य में विकास की गति को बढ़ावा मिलेगा। जनप्रतिनिधियों से बातचीत के बाद उपराष्ट्रपति के सचिवालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि देश के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और देश की अखंडता सर्वोपरि है, इसलिए पाकिस्तान के साथ वार्ता अब केवल गुलाम कश्मीर के मुद्दे पर होगी।

उपराष्ट्रपति ने लंबे समय बाद राज्यपाल शासन के दौरान जम्मू-कश्मीर में हुए पंचायत चुनावों पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने विश्वास जताया कि अनुच्छेद-370 खत्म होने के बाद पंचायतें और अधिक स्वतंत्र रूप से काम कर सकेंगी। बातचीत के दौरान उपराष्ट्रपति ने यह भी सुझाव दिया कि हर पांच साल में स्थानीय निकायों का चुनाव कराना अनिवार्य किया जाना चाहिए और इसे स्थगित करने और आगे बढ़ाने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।



नई दिल्ली में मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के पंच-सरपंचों से मुलाकात करते उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। एएनआइ

बंगाल की खाड़ी में भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास शुरू

नई दिल्ली, आइएएनएस : भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के विजाग बंदरगाह से बंगाल की खाड़ी में जाकर संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू किया। अभ्यास में भाग ले रहे दोनों देशों की नौसेनाओं के चार जहाजों ने अभ्यास के 'सी-फेज' में समन्वित समुद्री संचालन शुरू कर दिया है। 'सी-फेज' से पहले, विजाग बंदरगाह पर दोनों देशों की नौसेनाओं ने पेशेवर संवाद किया। साथ ही प्रशिक्षण गतिविधियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया।

छह दिवसीय संयुक्त अभ्यास 'स्लीनेक्स 2019' की औपचारिक शुरुआत सात सितंबर को विजाग बंदरगाह पर हुई थी। मंगलवार से चार जहाज और उनके क्रू समुद्र में विमान ट्रैकिंग, क्रास डेक फ्लाइंग, गोलीबारी, विजिट बोर्ड सर्च और जब्ती प्रक्रियाओं, अंडरवे रिप्लेनिशमेंट और नौसैनिक युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। श्रीलंका ने आधुनिक गश्ती जहाज एसएलएनएस सिंधुराला और एक अन्य जहाज एसएलएनएस सूरानीमाला को अभ्यास के लिए भेजा है। एसएलएनएस सिंधुराला को भारत की सरकारी रक्षा कंपनी गोवा शिपयार्ड ने बनाया है। वहीं भारतीय नौसेना ने युद्धाभ्यास में मिसाइल जंगी जहाज आइएनएस खुकरी और गश्ती जहाज आइएनएस सुमेध को भेजा है। भारत ने अभ्यास में जल के मध्य गश्ती समुद्री विमान के अतिरिक्त हेलीकॉप्टरों की तैनात की है।

कश्मीर में मुहर्रम पर भी कायम रही शांति

सख्त सुरक्षा व्यवस्था ▶ मुहर्रम के जुलूस, ताजिए, अलम और जुलजुना पर थी रोक

संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- शिया बहुल इलाकों के भीतरी हिस्सों में मुहर्रम की मजलिसों पर कोई पावंदी नहीं

कश्मीर में आतंकियों और अलगाववादियों की धमकियों के बावजूद धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहे जनजीवन की रफ्तार मंगलवार को फिर थम गई। प्रशासन ने वादी में हिंसा भड़काने के आतंकी मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए पाबंदियां लगा दी थीं। ऐसे में सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त करते हुए बड़ी संख्या में केंद्रीय और अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया था।

सभी मुख्य सड़कों पर ताजिया जुलूस निकालने पर थी रोक : सभी प्रमुख सड़कों और संवेदनशील इलाकों में प्रशासन ने मुहर्रम के जुलूस, ताजिए, अलम और जुलजुना पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि शिया बहुल इलाकों के भीतरी हिस्सों में मुहर्रम की मजलिसों को इस पाबंदी के दायरे से बाहर रखा गया है। लाल चौक, जहांगीर चौक, हब्बाकदल, डलगेट और डाउन-टाउन समेत सभी संवेदनशील इलाकों में सुबह से ही प्रशासन ने निषेधाज्ञा को सख्ती से लागू रखा। विभिन्न सड़कों और चौराहों पर सुरक्षाबलों की टुकड़ियां और कंटीले तारों के अवरोधक नजर आए।

जुलूस निकालने की कोशिश, सुरक्षा बलों ने लौटाया : दोपहर को दो जगहों पर शिया मातमियों ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर जुलूस निकालने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षाबलों ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इस दौरान शिया मातमियों और सुरक्षाबलों के बीच छिटपुट हिंसक झड़पें भी हुईं। अलबत्ता, बडगाम और जडीबल के अलावा पट्टन के भीतरी हिस्सों में 10 मुहर्रम के अवसर पर अशूरा के जुलूस निकले।

जनजीवन रहा प्रभावित : अधिकारियों ने बताया कि प्रशासनिक पाबंदियों के चलते कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित रहा। हालांकि स्कूल और कई दफ्तरों में छुट्टी थी। लेकिन तनाव के बावजूद स्थिति नियंत्रण में रही। मुहर्रम के दौरान शरारती तत्व हिंसा फैलाना चाहते थे। इसलिए प्रशासनिक पाबंदियों को दोबारा लागू करना पड़ा।



लद्दाख में मंगलवार को ताजिए के साथ मुहर्रम का जुलूस निकालते लोग। एएनआइ

अगला लक्ष्य गुलाम कश्मीर में तिरंगा फहराना : जितेंद्र सिंह

राज्य ब्यूरो, जम्मू

- अनुच्छेद 370 हटाना मोदी सरकार के 100 दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि
- पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ बुरा व्यवहार, भारत में हैं सुरक्षित

प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाना मोदी सरकार के पहले 100 दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इससे देश के साथ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का संपूर्ण एकीकरण हो गया है। ऐसे में हमारा अगला लक्ष्य गुलाम कश्मीर में तिरंगा लहराना है।

मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस में मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए जितेंद्र ने पाकिस्तान को भी आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने का राग अलापने वाला पाकिस्तान अब खुद पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। मानवाधिकार की बातें करने वाले अमेरिका से ही सबसे ज्यादा नशे और ई सिगरेट की तस्स्करी हो रही है। कश्मीर में आतंकवादियों के नागरिकों को निशाना बनाने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि कश्मीर में आतंकवाद अब चंद दिनों का है। अब सीमा के अंदर और सीमा के पार देश के दुश्मनों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो रही है। सीमा पर पाकिस्तान की गोलाबारी पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में और बंकर बनाने का मुद्दा केंद्र सरकार के सामने उठाया गया है। उन्होंने बताया कि सीमांत क्षेत्रों के दौरे के दौरान सुनिश्चित किया गया कि अच्छे बंकर बन रहे हैं। इनमें रसोई और शौचालय भी है।

18 महीने से ज्यादा नहीं रहना होगा जेल में : वहीं, कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि जो 72 सालों में नहीं किया, हमने वह तीन महीने में कर दिखाया। हम 72 घंटे में केंद्र शासित प्रदेश को फिर से राज्य बना सकते हैं। सिंह ने कहा कि इस समय एक सवाल अहम है कि नेता कब तक नजरबंद रहेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह 18 महीनों से कम ही होगा।



जम्मू में मोदी सरकार के 100 दिनों के कामों की जानकारी देते जितेंद्र सिंह। एएनआइ

यासीन मलिक की टाडा कोर्ट में आज पेशी

जागरण संवाददाता, जम्मू

- रूबिया के अपहरण और एयरफोर्स के चार अधिकारियों की हत्या का मामला
- 30 साल से बच रहा था पेशी से, बाद न्याय की जगी आस, तिहाड़ जेल में बंद है मलिक
- 22 अगस्त को जारी किया गया था तीसरी बार गैर जमानती वारंट



यासीन मलिक। फाइल फोटो

श्रीनगर में एयरफोर्स के चार अधिकारियों और एक नागरिक की आतंकियों द्वारा हत्या के मामले में 30 साल बाद न्याय जल्द मिलने की उम्मीद जगी है। हत्या के इस मामले में जेकेएलएफ के चीफ यासीन मलिक को बुधवार को जम्मू की टाडा अदालत में पेश किया जा सकता है। मलिक पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री व तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी डॉ. रूबिया सईद के अपहरण का मामला भी चल रहा है। मलिक नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद है।

यासीन मलिक पिछले 30 साल से टाडा अदालत में पेश होने से बचता फिर रहा है। इसके पहले उसे दो बार पेश होने का आदेश दिया गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुआ। एक न्यूज एजेंसी के अनुसार अब जम्मू की टाडा अदालत ने बुधवार को उसकी पेशी के लिए तीसरी बार गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट 22 अगस्त को जारी किया गया था। न्यूज एजेंसी के अनुसार टाडा अदालत ने तिहाड़ जेल के प्रभारी को यासीन मलिक की पेशी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

रूबिया अपहरण केस में सीबीआइ चालान के मुताबिक श्रीनगर के सदर पुलिस स्टेशन में आठ दिसंबर 1989 को रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसके अनुसार रूबिया मिनी बस से लललदेद अस्पताल श्रीनगर से नौगाम स्थित अपने घर जा रही थी। इसी दौरान कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने उसका अपहरण कर लिया। सीबीआई ने जांच पूरी करने के बाद 18 सितंबर 1990 को जम्मू की टाडा अदालत में आरोपितों के खिलाफ चालान पेश किया।

सीबीआइ के दूसरे चालान के मुताबिक 25 जनवरी 1990 की सुबह करीब सवा सात बजे श्रीनगर के रावलपोरा में किराये पर रह रहे एयरफोर्स अधिकारी गाड़ी के लिए सनत नगर क्रासिंग पर खड़े थे, तभी आतंकवादियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मौके पर एक महिला समेत करीब 40 एयरफोर्स के अधिकारी मौजूद थे जो गंभीर रूप से घायल हुए। दो अधिकारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अधिकारियों और एक नागरिक ने बाद में दम तोड़ दिया। सीबीआई ने जांच पूरी करने के बाद यासीन मलिक व अन्य के खिलाफ टाडा कोर्ट जम्मू में चालान पेश किया था।

तीस साल बाद पति की शहादत को न्याय की उम्मीद : निर्मल

25 जनवरी 1998 की सुबह आतंकी हमले में एयरफोर्स के शहीद अधिकारियों में स्क्वार्डन लीडर रवि खन्ना भी शामिल थे। उनकी पत्नी निर्मल खन्ना का कहना है कि यासीन मलिक पिछले 30 सालों से आरामदायक जिंदगी जीता रहा, लेकिन अब उम्मीद जगी है कि उनके पति की शहादत को न्याय मिलेगा। उनका कहना है कि पिछले तीस सालों में शहीदों के परिवारों को न जाने कितनी परेशानियां झेलनी पड़ीं। यहां तक कि पेंशन के मामले में मुझे खुद दिल्ली से जम्मू के बीच कई बार आना जाना पड़ा। मुझे अपने दो बच्चों को पालने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक न्यूज एजेंसी को 69 वर्षीय निर्मल खन्ना बताती हैं कि पति को खोने के बाद मेरा जीवन तनाव भरा हो गया। मैं पिछले कुछ सालों से ब्रेन स्ट्रोक से जूझ रही हूं।

जैश के हमले की आशंका के बीच सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

जागरण संवाददाता, जम्मू : पाकिस्तान में जैश-ए-मुहम्मद के सरगना अजहर मसूद की गुपचुप रिहाई के बाद जम्मू के धार्मिक और सैन्य इलाकों में हमले की आशंका के बीच मंगलवार को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। सोमवार रात सुंजवां व कालूचक्क में संदिग्ध व्यक्तियों के देखे जाने के बाद शहर भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

मुहर्रम को लेकर मंगलवार सुबह सुरक्षा प्रबंधों की दोबारा समीक्षा करने के बाद शहर के प्रवेश द्वारों पर चौकसी बढ़ा दी गई। संवेदनशील क्षेत्रों में तैनाती बढ़ाने के साथ होटलों में ठहरे लोगों पर भी नजर रखी गई। पुराने शहर में मुहर्रम का जुलूस निकलना था। इसकी सुरक्षा को लेकर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही अलर्ट पर थीं। सुबह से ही शहर में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई थी। इस दौरान पुराने शहर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा को लेकर ज्यादा तैयारी की गई थी ताकि शरारती तत्व माहौल बिगाड़ने में कामयाब न हो पाएं। सुरक्षा एजेंसियों को पहले ही सूचना मिल गई थी कि आतंकी अजहर मसूद और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ जम्मू में किसी बड़े हमले की फिराक में हैं। वे धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर माहौल खराब कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों के लिए मुहर्रम के जुलूस की सुरक्षा एक चुनौती बन चुकी थी। पुराने शहर के पीर मिट्ठा स्थित इमामबाड़ा से मुहर्रम का जुलूस निकलना था, जिसको लेकर पुलिस ने वहां पर सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी।

दिल्ली में कम कीमत पर मिलेंगी पश्मीना शॉलें

माला दीक्षित, नई दिल्ली

बाजार से करीब 30-40 फीसद कम कीमत पर लेह लद्दाख की हस्तनिर्मित पश्मीना शॉलें, स्टोल और अन्य सामान नवंबर से दिल्ली के ट्राइफेड शोरूम में उपलब्ध होंगे। वास्तविकता और शुद्धता की सौ फीसद गारंटी वाला यह सामान लेह लद्दाख से आम उपभोक्ताओं तक लाएगा आदिवासियों के उत्थान में लगा ट्राइफेड इंडिया। लगभग एक करोड़ के कारोबार में लेह लद्दाख के आदिवासियों को 70 फीसद हिस्सा जाएगा।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद लेह लद्दाख के आदिवासियों के उत्थान की सौगात लेकर सबसे पहले केन्द्रीय जनजातीय मंत्रालय वहां पहुंचा था और 95 फीसद आदिवासियों वाले लेह लद्दाख में आदि महोत्सव आयोजित किया था। इसी आदि महोत्सव के दौरान जनजातीय मंत्रालय के तहत आने वाले ट्राइफेड ने वहां के आदिवासियों का सामान पूरे देश के उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए वहां के आदिवासियों के स्वयं सहायता समूह से सामान आपूर्ति का करार किया था। ट्राइफेड के एमडी प्रवीण कृष्णा बताते हैं कि गत अगस्त में लेह में आयोजित आदि महोत्सव मे लेह लद्दाख के करीब सौ स्वयं सहायता समूह चिन्हित किये गए जो कि सामान की आपूर्ति करेंगे। चिन्हित किये गये सप्लायर ट्राइफेड को पश्मीना शॉलें, स्टोल, हाथ से बुने स्वैटर, मोजे के अलावा हर्बल दवाएं व अन्य उत्पाद आपूर्ति करेंगे। इसके अलावा वहां के आदिवासियों के बनाए पीतल के बर्तन भी ट्राइफेड की दुकानों पर उपलब्ध होंगे। प्रवीर कहते हैं कि लेह लद्दाख के कारीगरों की बनाई शुद्ध पश्मीना शॉलें 4000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये की कीमत पर उपलब्ध होंगी। यह फिलहाल अनुमानित कीमत है। साथ ही उनके हस्तनिर्मित होने की सौ फीसद गारंटी होगी। वह कहते हैं कि इतना निश्चित है कि कीमत बाजार की कीमत से करीब तीस-चालीस फीसद कम होगी। ये सारा सामान दिल्ली सहित देश भर के 104 ट्राइफेड शोरूम पर उपलब्ध होगा। ट्राइफेड ने अभी तक वहां करीब एक करोड़ रुपये के सामान का आर्डर दिया है। इस एक करोड़ के कारोबार में 70 फीसद हिस्सा आदिवासियों को जाएगा क्योंकि ट्राइफेड का नियम है कि वह सत्तर फीसद लाभ मूल आपूर्तिकर्ता आदिवासियों को देता है। प्रवीर कहते है कि ट्राइफेड अपना कोई लाभ नहीं कमाता वह सिर्फ चीज को बाजार तक पहुंचाने और उसकी पैकेजिंग व ब्रांडिंग में आए खर्च को ही लेता है। उसका उद्देश्य आदिवासियों को सक्षम बनाना, उनकी कलाकृतियों और उत्पादों की पैकेजिंग और ब्रांडिंग करके बाजार तक पहुंचाना है ताकि आदिवासियों को उनकी चीजों की बेहतर कीमत और पहचान मिले। प्रवीर कहते हैं कि पहले भी लेह लद्दाख का सामान ट्राइफेड की दुकानों पर मिलता था लेकिन बहुत कम होता था क्योंकि वहां के सप्लायर इतने नहीं थे। आदि महोत्सव के बाद ट्राइफेड ने वहां के सौ सप्लायर को अपने पैनल में शामिल किया है। इनसे ज्यादा मात्रा में विविधिता का सामान उपलब्ध होगा।

पाक ने फिर रिहायशी क्षेत्रों पर दागे मोर्टार, 10 मकान क्षतिग्रस्त

जागरण संवाददाता, पुंछ : पाकिस्तानी सेना ने पुंछ के मेंढर व बालाकोट सेक्टर में भारी गोलाबारी की। सोमवार देर रात शुरू हुई गोलाबारी मंगलवार सुबह तक जारी रही। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने रिहायशी क्षेत्रों को भी निशाना बनाया। इस गोलाबारी में करीब दस मकान क्षतिग्रस्त हो गए और आठ मवेशी भी मारे गए। भारतीय सेना ने भी पाक सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके बाद पाक सेना ने गोलाबारी बंद कर दी।

पाक सेना ने सोमवार रात करीब एक बजे बालाकोट व मेंढर सेक्टर के रिहायशी क्षेत्रों को निशाना बनाकर मोर्टार दागने शुरू कर दिए। पाक सेना ने दोनों सेक्टरों में जमकर गोलाबारी की। इससे सीमावर्ती लोग सहम गए। इसके बाद मोर्टार लोगों के घरों के ऊपर व आंगन में गिरने लगे। इससे कई घरों को नुकसान पहुंचा और पशु भी मारे गए। इसके बाद भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। पाक गोलाबारी सुबह छह बजे बंद हुई। इससे पहले रविवार को भी पाक सेना ने नौशहरा के कलाल, डींग व सेरी सेक्टर में रिहायशी क्षेत्रों को निशाना बनाकर गोलाबारी की थी, जिसमें लोगों के घरों का काफी नुकसान हुआ था।

संकट के बादल

ऊना से हमीरपुर रेललाइन पहुंचाने का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ड्रीम प्रोजेक्ट लटक सकता है। हिमाचल सरकार ने इसके लिए फंडिंग से इन्कार कर दिया है।

हिमाचल का पैसा देने से इन्कार, केंद्र चाहे तो निर्माण करे

राज्य ब्यूरो, शिमला

ऊना से हमीरपुर रेललाइन पहुंचाने का केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का ड्रीम प्रोजेक्ट लटक सकता है। हिमाचल सरकार ने इसके लिए फंडिंग से इन्कार कर दिया है। केंद्र के पत्र के जवाब में हिमाचल सरकार का कहना है कि वित्तीय संसाधनों की कमी के चलते ऊना-हमीरपुर रेललाइन में राज्य सरकार किसी भी प्रकार की हिस्सेदारी नहीं कर सकती। केंद्र सरकार चाहे तो इस रेललाइन का निर्माण कर सकती है। केंद्र सरकार ने हिमाचल से पूछा था कि इस रेललाइन के लिए कितना खर्च वहन किया जाएगा।

केंद्रीय रेलवे मंत्रालय आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नई रेललाइनों का निर्माण करवाता है। अन्यथा राज्य सरकारों को रेलवे परियोजनाओं के मामलों में हिस्सेदारी वहन करने के लिए कहा जाता है। एनडीए सरकार के पहले कार्यकाल से ऐसी व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकार को रेलवे परियोजनाओं के लिए तय राशि अग्रिम जमा करवानी होगी। उसके बाद ही निर्माणाधीन परियोजनाओं में कार्य आगे चलेगा।

50.3 किलोमीटर प्रस्तावित है रेललाइन : ऊना से हमीरपुर रेललाइन 50.3 किलोमीटर प्रस्तावित है। इस रेललाइन में 11 सुरंगों का निर्माण प्रस्तावित है। एक सुरंग आठ किलोमीटर लंबी होगी जो बंगाणा से हमीरपुर की ओर निर्मित होगी। 15 बड़े पुलों का निर्माण किया जाएगा। इनमें एक पुल 2.45 किलोमीटर लंबा होगा। जो इस रेललाइन पर सबसे लंबा पुल होगा। जो बड़े पुल बनेंगे उनकी अधिकतम ऊंचाई 90 मीटर होगी। एक समय इस रेललाइन की निर्माण लागत 2850 करोड़ रुपये थी। अब संशोधित निर्माण लागत बढ़कर छह हजार करोड़ रुपये हो गई है। फाइनल सर्वेक्षण के मुताबिक ऊना से हमीरपुर तक कुल छह स्टेशन बनाए जाने की प्रस्तावित हैं। ऊना रेलवे स्टेशन को जंक्शन और हमीरपुर में रेल टर्मिनल बनाने का प्रस्ताव है।

पत्र का जवाब दे दिया : राज्य सरकार ने केंद्र के पत्र का जवाब दे दिया है। केंद्र सरकार की ओर से ऊना-हमीरपुर रेललाइन के लिए राज्य की हिस्सेदारी के संबंध में पूछा था। राज्य सरकार फंडिंग करने की स्थिति में नहीं है। राज्य के पास वित्तीय संसाधन पर्याप्त नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार इस रेललाइन का खर्च नहीं उठा सकती।

बंडारू दत्तात्रेय आज लेंगे राज्यपाल पद की शपथ

राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मंगलवार सायं शिमला पहुंचे। बुधवार को सुबह 11 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल के राज्यपाल के तौर पर शपथ लेने वाले 27वें राज्यपाल होंगे। मंगलवार को सायं छह बजे राजभवन पहुंचे बंडारू दत्तात्रेय व उनकी पत्नी वसंथा का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में 300 से अधिक मेहमानों के शामिल होने की संभावना है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश से बाहर से आने वाले मेहमानों की संख्या 200 से अधिक है। राजभवन में नए राज्यपाल के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अतिरिक्त संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज, मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू, नगर निगम महापौर कुसुम सदरेट सहित जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे।

> ऊना-हमीरपुर रेललाइन का सर्वेक्षण और डीपीआर बनाने का कार्य पूरा हो चुका है। इसके बाद रेलवे मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार को पत्र आया है, सरकार की ओर से उसका जवाब नहीं मिला है। उसके बाद ही इस रेललाइन को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।
>
> -अनुराग ठाकुर, केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट राज्यमंत्री

जेएमबी का संदिग्ध आतंकी चेन्नई से गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कोलकाता

कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के एक और संदिग्ध आतंकी को चेन्नई से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उसके पास से जाली दस्तावेज और जिहादी पुस्तकें बरामद की गई हैं। उसे ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार बिहार के गया से जेएमबी के संदिग्ध आतंकी एजाज अहमद से पूछताछ में असादुल्ला शेख उर्फ राजा का नाम सामने आया था। इसके बाद ही एसटीएफ उसकी तलाश में जुट गई थी। वहीं एसटीएफ ने जेएमबी के आतंकी मंसूबों के बाबत जानकारी हासिल करने के लिए उससे कड़ी पूछताछ कर रही है।

मुखबिर की सूचना पर मंगलवार सुबह एसटीएफ ने चेन्नई के निलनगड़ाई जिला अंतर्गत सेनालपुरम गांव में छापेमारी कर जेएमबी के संदिग्ध आतंकी असादुल्ला को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि असादुल्ला बंगाल के बर्धमान विस्फोट के मुख्य आरोपित कौसर और जेएमबी के मुखिया सलाउद्दीन सलाहे का करीबी था। बंगलुरु से कौसर की गिरफ्तारी के बाद व भूमिगत हो गया था। गत माह गया से आतंकी एजाज की गिरफ्तारी के वक्त वह भी वहां था।

जेएमबी का कश्मीर में पाक आतंकियों के साथ कनेक्शन!

जागरण संवाददाता, कोलकाता : मालदा से एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार आतंकियों से जब्त पेन ड्राइव और लैपटॉप की जांच में जेएमबी के कश्मीर में पाक आतंकियों के साथ लिंक होने के सनसनीखेज राज सामने आए हैं। पेन ड्राइव में कश्मीर में सुरक्षा बल के हाथों ढेर किए गए कई आतंकियों के नाम भी मिले हैं। कश्मीर में किस जगह सेना के कितने जवान तैनात हैं इसका भी लेखाजोखा है।

925 यात्रियों ने किए हैं कैलास मानसरोवर के दर्शन इस साल, वहीं, एक यात्री की मौत भी हुई है। 12 जून को शुरू हुई यात्रा के अंतिम 18वें दल के दिल्ली पहुंचते ही यात्रा का होगा समापन

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 11 सितंबर 2019

चिन्मयानंद से जुड़े मामले का वीडियो वायरल, आश्रम पहुंची एसआइटी

छानबीन ▶ पीड़ित छात्रा को लेकर मुमुक्ष आश्रम में सात घंटे की जांच-पड़ताल

जांच के बाद ही पता चल सकेगी वीडियो की सच्चाई

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर

दुष्कर्म के आरोपों में घिरे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक लड़की व कथित तौर पर स्वामी चिन्मयानंद आपत्तिजनक स्थिति में बातें करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में कितनी सच्चाई है, यह जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन, इस बीच एसआइटी ने पीड़ित छात्रा के साथ चिन्मयानंद के मुमुक्ष आश्रम पहुंचकर सात घंटे से ज्यादा वक्त तक छानबीन की।

मंगलवार दोपहर कुछ आपत्तिजनक फोटो वायरल हुए और उसके कुछ देर बाद 16 वीडियो क्लिप। एक वीडियो क्लिप नौ मिनट 58 सेकंड का है, जबकि बाकी 15 क्लिप एक मिनट से लेकर तीन मिनट तक के हैं। उनमें दिख रहा है कि कथित तौर पर स्वामी चिन्मयानंद एक कमरे में लेटे हैं, वहीं कोई लड़की है। उसका चेहरा नहीं दिख रहा, सिर्फ आवाज सुनाई दे रही। लड़की को परीक्षा के बाबत जानकारी देते हुए कहा जा रहा है कि एक, तीन, चार मई को पेपर है, दो को नहीं है। तुम्हारा पहला पेपर किस विषय का है, सवाल पर लड़की उसके बारे में बता रही है। बाद में उससे जुड़ी निजी जानकारियां ली जा रहीं। लड़की उनका भी जवाब दे रही है। 16 में चार वीडियो क्लिप को छोड़कर बाकी में कथित रूप से स्वामी चिन्मयानंद आपत्तिजनक स्थिति में लेटे दिखाई दे रहे हैं। लड़की बगल में बैठकर हाथ-पैर दबाते हुए बात कर रही है।


स्वामी चिन्मयानंद (फाइल)

कॉलेज के पूर्व छात्र के पेन ड्राइव में था वीडियो

आपबीती का वीडियो 24 अगस्त को वायरल करने के बाद छात्रा लापता हुई थी। 30 अगस्त को वह राजस्थान के एक होटल में संजय सिंह नाम के युवक के साथ मिली थी। संजय सिंह एसएस लॉ कॉलेज का पूर्व छात्र है। कॉलेज में उसका अभी भी आना-जाना रहता है। उसका कहना था कि छात्रा से परिचय था। पता चला कि उसके साथ गलत किया जा रहा, इसलिए उसे इंसाफ दिलाने के लिए मदद के लिए आगे आया। सोमवार को पीड़िता ने अपनी बातचीत का वीडियो वायरल कर स्वामी चिन्मयानंद पर गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था कि उनके खिलाफ पर्याप्त सुबूत हैं। उसी दोपहर संजय ने एसआइटी को एक पेन ड्राइव सौंपी। बताया जा रहा कि उसमें वीडियो था। इसके बाद मंगलवार को एक वीडियो वायरल भी हुआ। वहीं सोमवार को जब छात्रा से संजय सिंह के बाबत पूछा गया था तब उसने बताया था कि वह मुंहबोला भाई है।

एसआइटी ने खुलवाया हॉस्टल : मंगलवार को करीब साढ़े 11 बजे एसआइटी स्वामी चिन्मयानंद के मुमुक्ष आश्रम पहुंची। उसी परिसर में एसएस लॉ कॉलेज है। कुछ ही देर में आरोप लगाने वाली छात्रा को भी बुला लिया गया। वह जिस हॉस्टल में रहती थी, उसका ताला उसी के सामने खुलवाया गया। वहां पर टीम ने काफी देर तक पड़ताल की। छात्रा से जानकारियां हासिल कर साक्ष्य एकत्र किए।

छात्रा ने एक दिन पहले लगाए थे गंभीर आरोप : पीड़ित छात्रा ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस कर स्वामी चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। कहा था कि पर्याप्त सुबूत होने के बावजूद उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। एसआइटी ने मुझसे लंबी पूछताछ की। इसके बावजूद अभी कोई नतीजा नहीं दिख रहा। छात्रा के पिता ने डीएम पर अभद्रता और उत्तर प्रदेश पुलिस से जान का खतरा बताया था।

भारत में हमले की फिराक में नेपाल में घुसे सात पाक आतंकी

जासं, पूर्वी चंपारण : पड़ोसी देश नेपाल में सात पाकिस्तानी आतंकियों के प्रवेश की सूचना है। जैश-ए-मुहम्मद से जुड़े ये आतंकी भारत में अपने नापाक इरादों को अंजाम देने की फिराक में हैं। इस तरह के मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इससे सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। भारत -नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है। वायरल मैसेज के मुताबिक, कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाक आतंकी भारत में बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश में हैं। खुफिया सूत्र बताते हैं कि स्थिति सामान्य होने के बाद इन्हें एक-एक कर बॉर्डर पार कर भारत के विभिन्न स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। भारत में इनके एजेंट और स्लीपिंग सेल्स ने जहां रेकी की है, वहां दशहरा और दीपावाली के बीच हमले की आशंका है।

बताया गया कि नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पर इन आतंकियों की संदिग्ध गतिविधियों को देखकर नेपाली सुरक्षकर्मियों ने पीछा भी किया। लेकिन सफलता नहीं मिली। सातों के काठमांडू में अलग-अलग लोगों से मिलने के बाद नेपाल के सीमावर्ती जिले पर्सा और बारा तक आने की सूचना है। हालांकि, रक्सौल (बिहार) और वीरगंज (नेपाल) के सुरक्षाकर्मी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। वीरगंज (नेपाल) आने के बाद सभी आतंकी सुरक्षा एजेंसियों की नजर में आने के बाद भूमिगत हो गए। रक्सौल के डीएसपी संजय कुमार झा ने बताया कि लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

पूर्व न्यायिक अधिकारी को 20 लाख का मुआवजा दिया

अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड भोग चुके अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप गलत निकले

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने एक पूर्व न्यायिक अधिकारी को 20 लाख रुपये का मुआवजा दिया है जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी। बाद में आरोप गलत निकले। शीर्ष कोर्ट ने गौर किया कि गुजरात हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि पूर्व न्यायिक अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं बनता।

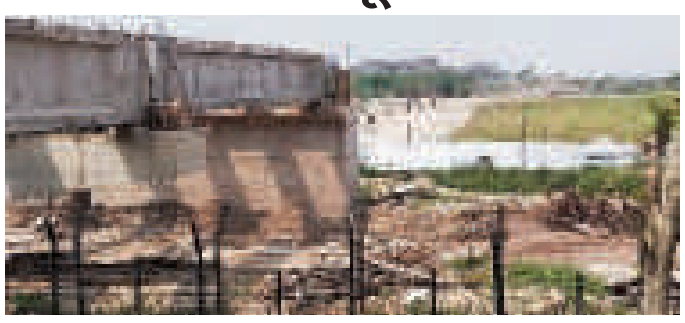
जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ हालांकि हाई कोर्ट के इस मत से सहमत नहीं हुई कि चूंकि 53 वर्षीय अधिकारी आठ साल तक नौकरी से दूर रहे हैं, इसलिए इतने अधिक समय बाद उन्हें सेवा में वापस नहीं लाया जा सकता। पीठ ने अपने फैसले में कहा, 'हाई कोर्ट ने एक बार जब यह व्यवस्था दे दी कि अपीलकर्ता (न्यायिक अधिकारी) के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए हैं तो उनके सम्मान और गरिमा को ध्यान में रखते हुए उन्हें सेवा में वापस लाया जाना चाहिए। हम व्यवस्था देते हैं कि अपीलकर्ता (अधिकारी) ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो न्यायिक अधिकारी को शोभा नहीं देता।'

कोर्ट ने कहा कि उन्हें सेवा में वापस नहीं लाया जा सकता क्योंकि वह पहले ही सेवानिवृत्ति की उम्र को पार कर चुके हैं। पीठ ने कहा, 'हमारा मत है कि क्योंकि अपीलकर्ता (अधिकारी) ने इन आठ वर्षों में काम नहीं किया है और यह तय करने में वाद का एक और दौर शुरू हो जाएगा कि इन वर्षों में कितनी आमदनी हो रही थी। वेतन वापस देने की जगह हम उन्हें एकमुश्त 20 लाख रुपये की राशि प्रदान किए जाने का निर्देश देते हैं।'


सुप्रीम कोर्ट (फाइल)

पीठ ने कहा कि उन्हें छह महीने के भीतर यह राशि मिल जानी चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने यह आदेश पूर्व न्यायिक अधिकारी की याचिका पर दिया जो नवंबर 1981 में सेवा में नियुक्त हुए थे। जून 1992 से जून 1994 तक वह गुजरात में दीवानी न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रहे थे। उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों में कहा गया कि उन्होंने सात जमानत आदेश ऐसे दिए जो कानूनी प्रावधानों के खिलाफ थे। जांच के बाद उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिसने व्यवस्था दी कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं बनता।

भारत ने करतारपुर कॉरिडोर का 75 फीसद काम पूरा किया


भारत की तरफ चल रहा करतापुर कॉरिडोर का निर्माण कार्य। जागरण

महेंद्र सिंह अर्लीभन्न, गुरदासपुर

पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के लिए भारत-पाक के बीच बनाए जा रहे कॉरिडोर का काम पूरी रफ्तार से चल रहा है। भारत ने 75 फीसद तक काम पूरा कर लिया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कॉरिडोर के 50 फीसद हिस्से में गांव मान से चंदू नंगल, पक्खोके, टाहली साहिब और डेरा बाबा नानक और हरुवाल चौक तक प्रीमिक्स भी डाल दिया है। बीएसएफ की टाउन पोस्ट क्षेत्र में जीरो लाइन पर भारत पुल के निर्माण को मुकम्मल करने में लगा है। उधर, पाकिस्तान ने भी अपनी संधू पोस्ट क्षेत्र में करतारपुर टर्मिनल कांप्लेक्स से सीमा तक सर्विस लेन का काम शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि भारत-पाक अधिकारियों की पिछले दिनों अटारी बॉर्डर पर हुई बैठक में पाकिस्तान ने जीरो लाइन पर ब्रिज बनाना स्वीकार कर लिया था। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व तक अगर पाकिस्तान पुल का निर्माण पूरा नहीं कर पाता है तो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सर्विस लेन तैयार की जा रही है।

नेशनल हाईवे अथॉरिटी आफ इंडिया के अधिकारी जतिंदर सिंह का कहना है कि भारत ने अब तक 75 फीसद काम पूरा कर लिया है। कुछ दिन में लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान ने भी अपनी ओर सीमा तक सर्विस लेन का काम शुरू कर दिया है।

'लाल इश्क' देख श्रेयांशी ने उठाया जोखिम

जासं, भदोही : एंड टीवी चैनल पर प्रसारित हो रहे सीरियल लाल इश्क को देख छात्रा श्रेयांशी ने आग लगाने जैसा जोखिम ले लिया। यह कहना है उप्र के भदोही स्थित सेंट जांस स्कूल के शौचालय में खुद पर केरोसिन डालकर झुलसी कक्षा तीन की छात्रा श्रेयांशी के पिता संगीत बरनवाल व विद्यालय के प्रधानाचार्य एजे मैथ्यू का। दोनों की ओर से दिए गए बयान ने भले ही यह साफ कर दिया है कि छात्रा ने खुद आग लगाई थी लेकिन यह भी बड़ा सवाल है कि सीरियल में उसने ऐसा कौन सा सीन देखा, जिससे ऐसा कदम उठाया। इसका जवाब आना बाकी है। उधर, वाराणसी के अस्पताल में भर्ती छात्रा की हालत में सुधार होने लगा है। मंगलवार को दिए गए बयान में संगीत ने बताया कि वह एंड टीवी चैनल पर आने वाले धारावाहिक लाल इश्क को देखती थी। उसी में तंत्र-मंत्र के जरिए एनर्जी बढ़ाने के लिए कोई सीन उसके दिमाग में गहरे से घर कर गई और उसने ऐसा जोखिम ले लिया। यह बात श्रेयांशी ही बता सकती है कि उसने कौन का सीन व कब देखा था।

एंड टीवी चैनल पर प्रसारित हो रहे लाल इश्क सीरियल में आठ सितंबर को जो प्रस्तुति दी गई थी, उसका सारांश यह था कि एक स्कूल के क्लास में एक कमजोर बच्ची को साथी छात्र हमेशा परेशान किया करते थे। इससे तंग आकर उसने सुसाइड कर लिया। इसके बाद उसने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली थी।

इमरान को सिद्धू से ज्यादा जानता हूं, पाक को बनाना चाहते हैं टेररिस्ट स्टेट : बलदेव

सचिन आनंद, लुधियाना

पाकिस्तान से जान बचाकर भारत आए इमरान खान की पार्टी के पूर्व विधायक बलदेव कुमार ने मंगलवार को नवजोत सिंह सिद्धू को भी सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू इमरान खान को नहीं जानते। इमरान को मैं ज्यादा अच्छे से जानता हूं। क्योंकि मैं उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) का विधायक रहा हूं। बलदेव ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान को आतंकी देश बनाना चाहते हैं। अगर यह नया पाकिस्तान है, तो यह पाकिस्तान इमरान को ही मुबारक।

पाकिस्तानी गायक ने दी धमकी : खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा में बारीकोट सीट से पूर्व विधायक बलदेव कुमार को अब पाकिस्तानी गायक जस्सी लयलपुरिया ने फोन पर धमकी दी है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की पोल खोलने और खुद इसका शिकार होने पर बलदेव कुमार ने भारत में राजनीतिक शरण की मांग की है। मीडिया में बलदेव का मामला उठाए जाने के बाद इसका असर पाकिस्तान में भी दिखाई दिया। पाकिस्तान के मशहूर सिख पंजाबी गायक जस्सी लयलपुरिया ने वाट्सएप के जरिए कॉल

पाक गायक जस्सी ने दी बलदेव कुमार को धमकी, कहा- भुगतना पड़ेगा अंजाम


पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा के पूर्व विधायक बलदेव कुमार। जागरण

कर बलदेव कुमार को मंगलवार की शाम को धमकी दी। दोनों में फोन पर तीखी बहस हुई।

इस दौरान जस्सी ने बलदेव को पाकिस्तान और वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ दिए बयानों को गलत बताया और कहा कि तुम ठीक नहीं कर रहे। उन्हें इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। इस पर गुस्से में आए बलदेव ने जस्सी को फटकारा और कहा कि वह (जस्सी) पाकिस्तान की सरकार के हाथों इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन्हें जो करना है कर लें।

जिस लड़की का धर्म परिवर्तन हुआ, क्या सिद्धू उसे बेटी नहीं मानते : बलदेव कुमार ने कहा कि जिस सिख लड़की का अपहरण कर पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन किया गया, क्या उसे नवजोत सिद्धू अपनी बेटी नहीं मानते। अगर यही सिद्धू की बेटी के साथ होता तो क्या वे इसी तरह इमरान का गुणगान करते। बलदेव ने इमरान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें शादियों से फुर्सत मिलेगी, तभी देश और जनता के मुद्दे उठाएंगे।

बलदेव कुमार ने कहा कि पाकिस्तान के गुरुद्वारों में ग्रंथी भी आइएसआइ के इशारे पर भर्ती होते हैं। करतारपुर कॉरिडोर भारत के सिखों के लिए अच्छी पहल है, लेकिन पाकिस्तान की फितरत को देखते हुए इसमें साजिश दिखाई दे रही है। बलदेव ने भारतीय सिखों को भी संदेश दिया। किसी धर्म विशेष का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि भारत के सिखों को यह समझना चाहिए कि जो लोग हमारे गुरुओं के नहीं हुए, वे हमारे क्या होंगे। बलदेव ने कहा कि गुरुद्वारों में पाठ और अरदास के दौरान बिजली सप्लाई बंद करने वाली पाकिस्तानी कौम अल्पसंख्यकों को निम्न दर्जे के नागरिक के तौर पर देखती है।

भारत दशहरे पर लेगा फ्रांस से पहला राफेल लड़ाकू विमान

नई दिल्ली, आइएएनएस : भारत फ्रांसीसी कंपनी दासौ एविएशन से पहला राफेल लड़ाकू विमान आठ अक्टूबर को दशहरे के मौके पर फ्रांस में हासिल करेगा। हालांकि इन लड़ाकू विमानों की पहली खेप अगले साल मई में ही भारत पहुंच पाएगी।

रक्षा सूत्रों ने बताया कि पहला राफेल विमान हासिल करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वरिष्ठ अधिकारियों की टीम के साथ फ्रांस जाने का कार्यक्रम है। भारत ने दासौ एविएशन के साथ भारतीय वायुसेना के लिए 36 राफेल विमान खरीदने का सौदा किया है। पूर्व की योजना के मुताबिक भारत को पहला राफेल विमान सितंबर के आखिरी सप्ताह में सौंपा जाना था। राजनाथ सिंह के साथ वायुसेना अध्यक्ष बीएस धनोआ का जाने का कार्यक्रम था। लेकिन इस कार्यक्रम के लिए आठ अक्टूबर की तिथि इसलिए चुनी गई है क्योंकि इस दिन वायुसेना दिवस होने के साथ-साथ दशहरा भी है। बता दें कि राफेल की पहली स्क्वाड्रन अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात की जाएगी जो भारत-पाक सीमा से 250 किमी दूर है। जबकि दूसरी स्क्वाड्रन बंगाल के हासिमारा बेस पर तैनात की जाएगी जो भारत-भूटान सीमा के नजदीक है।

सोनिया ने हरियाणा में गठित कीं चुनाव व प्रचार कमेटियां

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी भी तेज गति से आगे बढ़ने लगी है। राज्य कांग्रेस में बड़े बदलाव के बाद अब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चुनाव कमेटी और चुनाव प्रचार अभियान कमेटी का गठन कर दिया है। सैलजा को प्रदेश कांग्रेसाध्यक्ष होने के नाते चुनाव कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। उनके साथ 20 वरिष्ठ नेताओं को जोड़ा गया है। इसके अलावा कैप्टन अजय यादव को चुनाव प्रचार अभियान कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। कैप्टन के साथ पूर्व विधायक दिलू राम बाजीगर को कमेटी का संयोजक बनाया गया है। 25 अन्य नेताओं को भी बतौर सदस्य इस कमेटी में शामिल किया गया है।

सैलजा के साथ चुनाव कमेटी में विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ.अशोक तंवर, विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई, पूर्व मंत्री एचएस चड्ढा, कैप्टन अजय यादव, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष फूलचंद मुलाना, विधायक डॉ.रघुबीर सिंह कादयान, पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह, कुलदीप शर्मा, पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा, विधायक आनंद सिंह डांगी, करण सिंह दलाल,

सैलजा प्रदेश अध्यक्ष के नाते होंगी चुनाव कमेटी की पदेन चेयरपर्सन

अजय यादव को बनाया चुनाव प्रचार अभियान कमेटी का अध्यक्ष

पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल, आफताब अहमद, शादी लाल बतरा, बजरंग दास गर्ग, विधायक जयबीर वाल्मीकि और जयपाल सिंह लाली को सदस्य बनाया गया है। इस कमेटी में हुड्डा समर्थकों का ही दबदबा है। दो सदस्यों को छोड़ दें तो बाकी सभी हुड्डा समर्थक हैं।

कैप्टन अजय यादव के साथ चुनाव प्रचार अभियान कमेटी में संयोजक पद पर दिलूराम बाजीगर भी हुड्डा समर्थक हैं। इसके अलावा प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा, विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी, डॉ.अशोक तंवर, रणदीप सिंह सुरजेवाला, एसी चौधरी, फूलचंद मुलाना, कुलदीप बिश्नोई, कुलदीप शर्मा, दीपेंद्र हुड्डा, रणजीत सिंह, आजाद मोहम्मद, गीता भुक्कल, चक्रवती शर्मा, धर्मपाल मलिक, श्रुति चौधरी, अनीता यादव, जयवीर वाल्मीकि, उदयभान, धर्मबीर गाबा, पंडित रामलीलाल, परमवीर सिंह, शमशेर सिंह गोगी, अनिल धंतोड़ी, रणजीता मेहता को इस कमेटी में शामिल किया गया है। युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, एनएसयूआइ के प्रदेशाध्यक्ष सहित सेवादल के एक प्रतिनिधि भी इस कमेटी में शामिल रहेंगे।

सूत्रों के अनुसार अभी और भी कमेटियां गठित की जाएंगी। सोनिया गांधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पहले ही चुनाव प्रबंधन कमेटी का चेयरमैन घोषित कर चुकी हैं।

इनेलो छोड़ने वाले पांच विधायकों की सदस्यता रद

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल (इनेलो) के टिकट पर चुनाव जीतकर दलबदल करने वाले पांच विधायकों की विधानसभा से सदस्यता रद कर दी गई है। इनमें जननायक जनता पार्टी (जजपा) में शामिल हुए चार विधायक नैना सिंह चौटाला, पिरथी नंबरदार, अनूप धानक और राजदीप फौगाट तथा पहले कांग्रेस और उसके बाद भाजपा में शामिल हुए नसीम अहमद शामिल हैं। हालांकि, ये सभी पहले ही विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर खुद ही पूर्व हो चुके हैं। नसीम अहमद के अध्यक्ष पीठ के सामने पेश नहीं होने के कारण एक्स पार्टी मानते हुए उनकी विधानसभा से सदस्यता रद की गई है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने मंगलवार को पांचों विधायकों (पूर्व) की विधानसभा से सदस्यता रद करने संबंधी फैसला सुनाया। 3 सितंबर को दोनों पक्षों की अंतिम बहस के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला की शिकायत पर इन विधायकों के विरुद्ध दलबदल कानून के तहत कार्रवाई की गई है। डबवाली से विधायक नैना सिंह चौटाला, चरखी दादरी से राजदीप सिंह फौगाट, नरवाना से पिरथी नंबरदार और उकलाना से विधायक रहे अनूप धानक पूर्व सांसद दुष्यंत सिंह चौटाला के नेतृत्व वाली जननायक जनता पार्टी का समर्थन कर रहे थे। इसी साल 25 मार्च को फतेहाबाद से इनेलो विधायक रहे बलवान सिंह दौलतपुरिया ने इन विधायकों के खिलाफ दलबदल कानून के तहत कार्रवाई के लिए स्पीकर की कोर्ट में याचिका दायर की। दौलतपुरिया खुद जब विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए तो अभय चौटाला ने 26 जुलाई को अध्यक्ष पीठ में अलग-अलग याचिकाएं दायर कीं।

दोबारा शादी के चार साल बाद फिर तलाक चाहते हैं डॉक्टर पति-पत्नी

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश के भोपाल में कुटुंब न्यायालय में तलाक के लिए अनूठा मामला पहुंचा है। इसमें डॉक्टर पति-पत्नी दो बार शादी करने के बाद फिर से तलाक लेना चाहते हैं। दो बार की शादी में 14 फेरे लेने के बाद भी उनका रिश्ता टूटने की कगार पर है।

भोपाल के डॉक्टर दंपती ने हिंदू रीति-रिवाज से 13 साल पहले 2006 में शादी की थी। दोनों के बीच कुछ साल तक सबकुछ ठीक रहा, जब उनकी बेटी चार साल की हुई तो पति-पत्नी में झगड़े होने लगे और आपसी सहमति से दोनों ने 2011 में तलाक ले लिया। बेटी की परवरिश के कारण दोनों ने 2015 में दोबारा शादी की, लेकिन अब फिर रिश्ते में दरार पड़ गई है और तलाक की नौबत आ गई है।

धूमधाम से की थी दूसरी शादी

पत्नी ने बताया कि पहली बार तलाक के बाद तीन-चार साल अलग रहे तो बेटी की

भोपाल के कुटुंब न्यायालय में पहुंचा मामला

वर्ष 2006 में पहली बार की थी शादी

वर्ष 2011 में सहमति से लिया तलाक

वर्ष 2015 में दूसरी बार किया था विवाह

मेरे सामने कुटुंब न्यायालय में इस तरह का पहला केस आया है। जब बच्चे के भविष्य को देखकर एक महिला ने उसी व्यक्ति से दोबारा विवाह किया, लेकिन दोनों के बीच मतभेद के कारण मामला फिर से तलाक तक पहुंच गया है। दोनों को फिर से काउंसिलिंग के लिए बुलाया है।

- नूरून्निशां खान, काउंसलर, कुटुंब न्यायालय

परवरिश के कारण फिर से शादी करने का फैसला किया। हमारी पहली शादी का वीडियो देखकर बेटी अक्सर अपने बारे में पूछती थी। जब उसे पता चला कि हम दोनों फिर से शादी कर रहे हैं तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। हमने कोर्ट मैरिज करने का फैसला लिया था, लेकिन बेटी की खातिर सभी रीति-रिवाजों के साथ धूमधाम से शादी करनी पड़ी। इसमें आठ से 10 लाख रुपये खर्च हुए।

पत्नी का यह भी कहना है कि बेटी की खातिर सब कुछ भुलाकर पति को दोबारा मौका दिया, लेकिन अब फिर हर दिन झगड़े हो रहे हैं। इससे बेटी पर गलत असर पड़ रहा है। बेटी की खातिर हम एक हुए थे, लेकिन फिर से उसके लिए अलग हो रहे हैं। उसने बताया कि दोनों व्यस्त रहते हैं। पति ने दूसरे शहर में अपनी पदस्थापना ले ली। वे बेटी को बिलकुल समय नहीं देते हैं। वहीं, पति का कहना है कि वह तलाक नहीं चाहता। पत्नी छोटी-छोटी बातों पर बेटी को लेकर मायके पहुंच जाती है। कुटुंब न्यायालय में इस तरह के कई मामले आ रहे हैं जिनमें पति-पत्नी के बीच छोटे-छोटे विवाद तलाक का कारण बन रहे हैं। इसका खामियाजा बच्चों को उठाना पड़ता है।

प्रायश्चित

जलियांवाला बाग पहुंचे कैंटरबरी के आर्च बिशप जस्टिन वेल्बी ने नरसंहार पर जताया दुख, शहीदी स्मारक पर चिलचिलाती धूप में दो बार हुए दंडवत

चर्च प्रमुख हुए जलियांवाला स्मारक पर दंडवत

जासं, अमृतसर

इंग्लैंड के सभी चर्चों के प्रमुख और कैंटरबरी चर्च के आर्च बिशप जस्टिन वेल्बी ने मंगलवार को जलियांवाला बाग पहुंचकर शहीदी स्मारक पर चिलचिलाती धूप में दो बार दंडवत होकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा यहां हुए नरसंहार के लिए प्रायश्चित किया।

जस्टिन वेल्बी ने कहा कि ठीक 100 साल पहले जलियांवाला बाग में जो क्रूरता हुई थी, उसके लिए वह बेहद दुखी हैं। उनकी दुआएं हमेशा जलियांवाला बाग नरसंहार में शहीदों के परिजनों के साथ रहेंगी। वे उम्मीद करते हैं कि जलियांवाला बाग की तरह मानवीय क्रूरता को दोहराया न जाए। उन्होंने कहा कि वह किसी सरकार की तरफ से नहीं बल्कि एक धार्मिक नेता होने के नाते अमृतसर आए हैं।

जलियांवाला बाग की विजिटर बुक में उन्होंने लिखा है कि नरसंहार में शहीद हुए लोगों के बच्चों के लिए भी वह विशेष प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वह जलियांवाला बाग में प्रायश्चित करने आए हैं, क्योंकि कैंटरबरी में इसे प्रायश्चित कहते हैं। इसके बाद वह श्री दरबार साहिब में पहुंचे, जहां दर्शन करने के बाद उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सिख कौम बहुत ही गर्म जोशी से समाज की सेवा और शांति के लिए प्रयासरत है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि उनका खुद का मकसद भी यही है विश्व में अमन-शांति का माहौल बने, जिसका वह संदेश लेकर आए हैं। इस मौके पर उनकी धर्मपत्नी कैरोलीन वेल्बी, एलिशा जेन, डॉ. रेवरेंड विलियम जोनाथान और अन्य मौजूद थे।


अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग शहीदी स्मारक में शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करते इंग्लैंड के कैंटरबरी के आर्च बिशप जस्टिन वेल्बी। राघव शिकारपुरिया

ताज में लहराया भगवा झंडा, वीडियो वायरल

जासं, आगरा : ताज महल में भगवा झंडा लहराते युवक का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। यह वीडियो मंगलवार को एक वाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किया गया। इससे स्मारक की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने जांच कराने की बात कही है।

वाट्सएप ग्रुप 'भगवाधारी राम के वंशज' में यह वीडियो पोस्ट किया गया। वीडियो में नजर आ रहा है कि ताजमहल के उद्यान में बेंच पर एक युवक बैठा हुआ है। उसके पीछे खड़ा युवक अपने दोनों हाथों में भगवा झंडा लहरा रहा है। वीडियो को संपादित कर गाना जोड़ा गया है। करीब एक मिनट 14 सेकंड का यह वीडियो पोस्ट होने के बाद सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। ताजमहल में किसी भी तरह का झंडा, पोस्टर, बैनर या ऐसी किसी सामग्री को ले जाने पर रोक है। ऐसे में सवाल उठता है कि जांच के बाद भगवा झंडे स्मारक में कैसे चले गए। ताज के संरक्षण सहायक अंकित नामदेव ने बताया कि इसकी जांच कराई जा रही है। जांच के बाद ही इस मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी।

ईडी पहुंचा हाई कोर्ट, एजेएल और वोरा को नोटिस जारी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

पंचकूला में एसोसिएट जर्नल लिमिटेड (एजेएल) को आवंटित किए गए प्लॉट को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अटैच करने पर यथास्थिति बनाए रखने के अपीलीय अधिकरण, दिल्ली के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट ने एजेएल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न अपीलीय अधिकरण के आदेश पर रोक लगा दी जाए।

गौरतलब है कि ईडी के अपीलीय अधिकरण ने चार जून को एजेएल को आवंटित प्लाट पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ ईडी की ओर से याचिका दाखिल करते हुए कहा गया कि 1982 में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल ने हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (संक्षेप में जो हुडा कहा जाता था। अब इसका नाम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है) का प्लॉट एजेएल को आवंटित किया था। 10 साल तक यहां कोई निर्माण नहीं हुआ तो हुडा ने प्लॉट वापस ले लिया। 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1982 की कीमत पर ही प्लॉट एजेएल को फिर आवंटित कर दिया। इस कारण ईडी ने 15 जुलाई 2016 को केस दर्ज किया। केंद्र सरकार के वकील सत्यपाल जैन ने कोर्ट को बताया कि ईडी ने गत वर्ष एक दिसंबर को पंचकूला के इस प्लॉट को अटैच करने के अंतरिम आदेश दे दिए थे।

न्यायिक प्राधिकरण ने इसी वर्ष 21 जून को अपनी मंजूरी दे दी थी। इस प्लॉट को अटैच करने के आदेश को एजेएल ने दिल्ली अपीलीय अधिकरण में चुनौती दी थी, जिस पर चार जून को वहां से यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए गए थे। जैन ने कहा कि अधिकरण को ऐसा आदेश पारित करने का अधिकार ही नहीं है।

मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा-26 के तहत अपीलीय अधिकरण अंतरिम आदेश जारी नहीं कर सकता। वह आदेश में संशोधन और उन्हें रद कर सकता है।

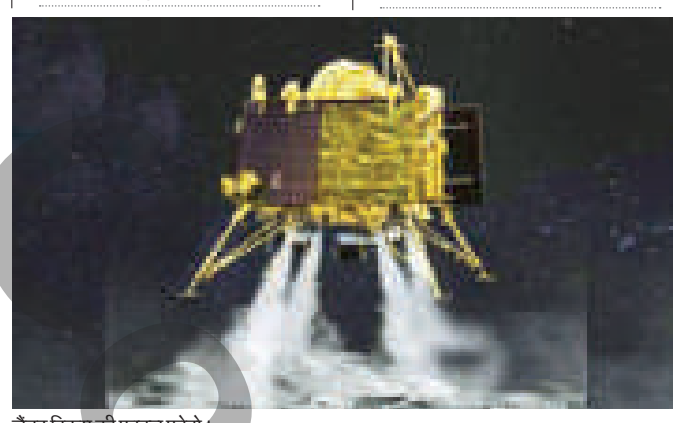
6 सितंबर की देर रात इसरो के चंद्रयान-2 मिशन के तहत लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था, लेकिन अंतिम समय में महज 2.1 किलोमीटर पहले लैंडर से इसरो का संपर्क टूट गया था।

विक्रम से संपर्क स्थापित करने में फिसल रहा समय

बेंगलुरु, प्रेट्र : भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम से संपर्क स्थापित करने का समय तेजी से बीत रहा है। छह व सात सितंबर की दरम्यानी रात को चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की दूरी पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने लैंडर से अपना संपर्क खो दिया था। शनिवार को चांद की सतह पर विक्रम की स्थिति का पता चल गया था। इसके बाद इसरो प्रमुख के. सिवन ने 14 दिन तक लैंडर से संपर्क करने की कोशिश किए जाने की बात की थी। दरअसल, यान के लैंडर-रोवर का मिशन केवल 14 दिन के लिए ही तय किया गया था जो चंद्रमा के एक दिन के बराबर है। जैसे-जैसे मिशन की तय की हुई अवधि बीत रही है, वैसे-वैसे संपर्क स्थापित करने की संभावना भी कम होती जा रही है।

इसरो ने सोमवार को कहा कि विक्रम ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हार्ड लैंडिंग की है। मंगलवार को एजेंसी ने चांद पर विक्रम की स्थिति पता चलने की दोबारा पुष्टि की। इसरो ने ट्वीट कर यह भी कहा कि वैज्ञानिक संपर्क स्थापित करने की हरसंभव कोशिश कर रहे हैं। इसरो के कुछ अधिकारियों के अनुसार विक्रम चांद की सतह पर पहले से तय जगह से 500 मीटर की ही दूरी पर पड़ा है। वह टूटा नहीं है, बस तिरछा हो गया है। जानकारों के मुताबिक, वैज्ञानिकों की टीम संपर्क साधने के लिए लैंडर के एंटीना को सही स्थिति में लाने की कोशिश कर रही है। हालांकि, इसरो ने इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। विक्रम की विफल सॉफ्ट लैंडिंग के कारणों पर भी इसरो ने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है। इसरो के पूर्व अधिकारी ने कहा, 'उनके पास जो डाटा आए होंगे उससे लैंडिंग में चूक का पता पहले ही चल जाना चाहिए। इसरो का अब भी चुप रहना अजीब है।'

- लैंडर और रोवर का मिशन केवल 14 दिन के लिए ही हुआ था तय
- ऑर्बिटर पर टिकी हैं इसरो की उम्मीदें, उसके जरिये मिलेगी जानकारी


लैंडर विक्रम की फाइल फोटो।

संपर्क बनाने के लिए चंद्रमा की जा रही पूजा

तंजावुर : लैंडर विक्रम से संपर्क स्थापित करने की कामना करते हुए श्रद्धालुओं ने यहां के श्री कैलासनाथ मंदिर में भगवान चंद्रमा की पूजा की। मंदिर के अधिकारी वी. कनन ने कहा कि पूजा के दौरान पहले भगवान चंद्र का अभिषेक किया गया। सोमवार को हुई इस पूजा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया था। कनन ने कहा, 'संपर्क टूटने के बाद हमने पूजा करने का निर्णय लिया था ताकि चंद्र देव हमारी मदद कर सकें।' एक दशक पहले चंद्रयान-1 की लांच और हाल में चंद्रयान-2 की सॉफ्ट लैंडिंग से पहले भी मंदिर में पूजा कराई गई थी।

भारत का महत्वाकांक्षी चंद्रयान-2 अभियान इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ट्रेंडिंग हैशटैग है। एक अध्ययन के अनुसार एक से नौ सितंबर के बीच इस हैशटैग से 67,554 ट्वीट किए जा चुके हैं। वहीं अब तक इस अभियान से संबंधित कुल 2,39,109 ट्वीट किए गए हैं।

ऑनलाइन जुए के लिए कंपनी को लगा दिया 38 करोड़ का चूना

बेंगलुरु, प्रेट्र : वैश्विक निवेश कंपनी गोल्डमैन सैक्श के वाइस प्रेसिडेंट ने ऑनलाइन जुए में मोटी रकम हारने के बाद उसकी भरपाई के लिए अपनी कंपनी के 38 करोड़ रुपये का गबन कर लिया। लेकिन इस धांधली में उसने अपने तीन अधीनस्थ कर्मचारियों के कंप्यूटर का इस्तेमाल करके उनको ही इसमें फंसा दिया।

बेंगलुरु में व्हाइटफील्ड क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त एमएन अनुचेत ने मंगलवार को बताया कि कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट अश्विनी झुनझुनवाला को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक 38 वर्षीय झुनझुनवाला का साथी वेदांत अब भी फरार है।

वैश्विक निवेश कंपनी गोल्डमैन सैक्श के लीगल हेड अभिषेक परशीरा ने कंपनी की ओर से आइपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत इन दोनों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। एफआइआर के मुताबिक झुनझुनवाला ने अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए कंपनी में अपने तीन कनिष्ठ कर्मचारियों गौरव मिश्रा, अभिषेक यादव और सुजीत अप्पैया को जरिया बनाया। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट पर आरोप है कि उसने इन तीनों के आफिस में रखे कंप्यूटरों पर लॉग इन करके हेराफेरी की। यह तीनों ही कंपनी में नए कर्मचारी थे और इनका प्रशिक्षण चल रहा था। जब यह लोग अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे थे तो उसने उन्हें पानी लाने या किसी और काम से कहीं भेजकर उनके कंप्यूटरों पर लॉग इन किया। उसके बाद झुनझुनवाला ने दो किस्तों में कंपनी के 38 करोड़ रुपये को इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना में अवैध तरीके से ट्रांसफर कर दिया।

ऐसी ही धांधलियों के लिए कंपनी से निकाले जा चुके वेदांत पर आरोप है कि उसने ही उसे कंपनी की रकम का गबन करने के लिए उकसाया था। यह मामला तब सामने आया जब छह सितंबर को कंपनी ने इंटरनल ऑडिट कराया।

- घपले में अपने तीन जूनियर कर्मियों के कंप्यूटर का किया इस्तेमाल
- रकम इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना को की ट्रांसफर

नए कर्मियों को ट्रेनिंग में फंसाया : पुलिस सूत्रों के अनुसार मिश्रा ने कंपनी के अधिकारियों को बताया कि झुनझुनवाला ने हाल ही में उससे एक पेमेंट के लिए एक सेटिलमेंट रीकांसिलेशन सर्विस (एसआरएस) बनाने को कहा था। लेकिन उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था क्योंकि वह कंपनी में नया आया है। यह चार सितंबर का वही समय था जब झुनझुनवाला ने उसके कंप्यूटर को अपने कब्जे में लेकर रकम की हेराफेरी की थी।

लाखों के कर्ज में डूबा था : कंपनी ने अपनी शिकायत में कहा है कि ऑनलाइन पोकर खेलते हुए कंपनी के पदाधिकारी झुनझुनवाला ने 70,000 डॉलर (करीब 49 लाख रुपये) गंवा दिए थे। इसके अलावा भी उसने 25 लाख रुपये का कर्ज भी लिया हुआ है और कुछ अन्य लोगों से भी कर्ज ले रखा है। उस पर कर्ज बढ़ने पर उसने इस बारे में वेदांत से सलाह ली। आरोप है कि वेदांत ने ही उसे घपला करने का तरीका बताया था।

आवास घोटाले के वकील से आरोपितों के परोक्ष संबंध : अन्ना

अहमदनगर, प्रेट्र : प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने मंगलवार को घरकुल आवास घोटाले की पैरवी के लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अमोल सावंत की बतौर विशेष लोक अभियोजक नियुक्ति पर ऐतराज जताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विशेष लोक अभियोजक सावंत पूर्व में उस वरिष्ठ वकील के सहयोगी रह चुके हैं जो आरोपितों की तरफ से इस मामले की पैरवी बांबे हाई कोर्ट में करेंगे, इसलिए सावंत आरोपितों से परोक्ष तौर पर जुड़े हुए हैं।

यह मामला वर्ष 1996 में कम कीमत वाले 11 हजार आवासों के निर्माण के लिए जलगांव नगर निगम की तरफ से निकाली गई निविदा में अनियमितता से संबंधित है। धुले जिला अदालत इस मामले में 31 अगस्त को दो पूर्व मंत्रियों सुरेश जैन व गुलाबराव देवकर को सात साल की सजा सुना चुकी है। ट्रायल कोर्ट में अधिवक्ता प्रवीण चवाण ने मामले की पैरवी की थी। सजा पा चुके कुछ लोगों की तरफ से बांबे हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर बहस के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अमोल सावंत को नियुक्त किया है। रालेगण सिद्धि में अन्ना ने मीडिया से कहा कि सावंत की नियुक्ति में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अन्ना इस घोटाले की जांच के लिए आंदोलन भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि चवाण ने अभियोजक के तौर पर बेहतर काम किया और उन्हें ही हाई कोर्ट में मौका दिया जाना चाहिए था। अन्ना ने कहा, 'मैं इस मामले में पांच सितंबर को मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस से बात कर चुका हूं। वह हमसे सहमत थे, फिर भी सावंत को नियुक्त कर दी।'

दुष्कर्म के मामले में डिनोबली स्कूल के उप प्राचार्य व नर्स को जेल भेजा गया

शर्मनाक प्रकरण ▶ धनबाद में इस स्कूल में किया गया था आठ साल की छात्रा से दुष्कर्म

मनो रोग चिकित्सक एवं बाल कल्याण समिति के सामने छात्रा ने लिया उप प्राचार्य का नाम

जागरण संवाददाता, धनबाद

आठ साल की मासूम छात्रा के साथ स्कूल के सिक रूम में दुष्कर्म के मुकदमे में कतरास एरिया के डिनोबली स्कूल के उप प्राचार्य फादर पॉल जूलियन एक्का (54) और नर्स इमरेंसिया लोमडा (35) को मंगलवार को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में पेश किया। मजिस्ट्रेट ने दोनों को तत्काल जेल भेजने का आदेश दिया। छात्रा ने 164 के बयान में सिर्फ नर्स का नाम लिया था। मेडिकल जांच के बाद मनो रोग चिकित्सक ने छात्रा से बातचीत की। फिर उसे बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया। दोनों जगहों पर बातचीत के दौरान छात्रा ने उसके साथ गलत होने के लिए उप प्राचार्य पर ही संदेह जताया। मुकदमे में क्लास टीचर भी नामजद है। अनुसंधान में अभी तक उनके खिलाफ ठोस साक्ष्य नहीं मिला है। पुलिस अभी डिनोबली के और लोगों से पूछताछ करेगी।

चार साल पहले निर्मला सदन से डिनोबली गई थी नर्स

जेल गई नर्स इमरेंशिया सिमडेगा में बानो की रहने वाली है। उसने जमशेदपुर में नर्सिंग की पढ़ाई की है। धनबाद की पार्क क्लिनिक में उसने कैरियर शुरू किया था। फिर गोविंदपुर के निर्मला सदन में कार्य किया था। 2015 में उन्होंने डिनोबली में बतौर नर्स योगदान दिया था।

छात्रा के परिजन ने कतरास थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उनकी पुत्री के साथ स्कूल के भीतर दुष्कर्म किया गया है। इसमें उप प्राचार्य, क्लास टीचर एवं नर्स को नामजद किया गया है। इसके बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। डीसी के आदेश पर सात सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने छात्रा की मेडिकल जांच की। पुष्टि हुई कि उसके साथ गलत हुआ है। फिर मनो रोग चिकित्सक ने छात्रा की काउंसलिंग की। इस दौरान छात्रा ने जो कुछ बताया, वह चौंकाने वाला था। उसे धमका दिया गया था जिस कारण वह 28 दिन तक खामोश थी। रक्तस्त्राव होने और तकलीफ बढ़ने के बाद उसने परिजनों को हकीकत बयां की थी।

परीक्षा में नंबर काटने की धमकी देकर किया था खामोश : छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के बाद परीक्षा में नंबर काटने की धमकी देकर उसे खामोश किया गया था। बाल कल्याण समिति एवं मनो रोग चिकित्सक की काउंसलिंग के दौरान यह बात सामने आई। पुलिस को जानकारी मिली कि आठ अगस्त को क्लास में छात्रा की तबीयत खराब हुई थी। उसे उल्टी हो गई थी। कुछ देर बाद लंच ब्रेक होने को था। लंच ब्रेक के बाद क्लास टीचर ने छात्रा को सिक रूम भेज दिया था। वहां छात्रा को सफेद रंग की छोटी दवा दी गई थी। दवा खाने के बाद छात्रा तनिक अचेत हो गई थी तो उसके साथ गलत काम किया गया था। होश में आने के बाद छात्रा ने नर्स से सवाल किया कि उसके अंतःवस्त्र क्यों खुले हैं, शरीर के नाजुक हिस्से में दर्द क्यों हो रहा है तो नर्स ने धमकी दी थी कि ये बातें अपने घरवालों या किसी और को बताने पर परीक्षा में नंबर कट जाएंगे। इसके बाद मासूम बच्ची दर्द सहती रही। 23 अगस्त को स्कूल में अधिक रक्तस्त्राव हुआ था। बच्ची को अपने अंतःवस्त्र स्कूल में फेंकने पड़े थे।

एसएसपी के सामने कबूला कि डेढ़ घंटा सिक रूम में थी छात्रा : धनबाद एसएसपी किशोर कौशल ने सोमवार की रात 11 बजे से भोर साढ़े तीन बजे तक डिनोबली के उप प्राचार्य एवं नर्स से पूछताछ की। नर्स ने बताया कि किसी की तबीयत खराब होने पर 15 से 20 मिनट सिक रूम में रखने के बाद परिजनों को सूचना दे दी जाती है। एसएसपी ने पीड़ित छात्रा के मामले में पूछताछ शुरू की। चार घंटे तक पूछताछ में नर्स ने स्वीकार किया कि छात्रा डेढ़ घंटा तक सिक रूम में थी और इस दौरान कुछ देर के लिए वह सिक रूम से दूसरी ओर गई भी थी।

यह भी स्वीकारा कि सिक रूम में उप प्राचार्य छात्रा को देखने गए थे। साढ़े चार घंटे की पूछताछ के दौरान नर्स और उप प्राचार्य के विरोधाभासी बयान सुनने के बाद एसएसपी ने दोनों को जेल भेजने का आदेश दिया।

चाईबासा, सोनुवा और बारीपदा में रह चुके हैं उप प्राचार्य : डिनोबली के उप प्राचार्य फादर पॉल जूलियन एक्का मूलतः लोहरदगा के हैं। वे पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल में हॉस्टल वार्डन थे। फिर सोनुवा के सेंट जॉन में प्राचार्य रहे। इसके बाद बारीपदा के लोयला स्कूल में प्राचार्य की जवाबदेही संभाली। 2018 में उन्होंने डिनोबली में बतौर उप प्राचार्य योगदान दिया।

उत्तरकाशी में 26 दिन बाद भी पटरी पर नहीं लौटी जिंदगी

शैलेंद्र गोदियाल, उत्तरकाशी

उत्तरकाशी जिले के आराकोट क्षेत्र में आपदा को आए 26 दिन बीत चुके हैं, पर अभी भी सुदूरवर्ती गांवों में जिंदगी हिचकौले खा रही है। अभी भी 11 गांवों में यातायात सुचारू नहीं हो पाया है, जबकि दस गांवों में लोग बिजली का इंतजार कर रहे हैं। स्थिति यह है कि ग्रामीण अभी भी जरूरी सामान के लिए जान जोखिम में डाल मीलों पैदल चलकर टिकोची पहुंच रहे हैं। हालांकि, टिकोची तक सड़क मार्ग सुचारू हो चुका है।

जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से करीब 220 किमी दूर आराकोट क्षेत्र में 18 अगस्त की सुबह कुदरत का कहर काल बनकर टूटा था। इस तबाही में जन हानि और पशु हानि के साथ सड़क, पेयजल, विद्युत व संचार व्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचा जिससे ग्रामीण गांवों में ही कैद होकर रह गए। प्रशासन ने युद्ध स्तर पर बचाव व राहत अभियान भी चलाया, लेकिन फिर भी सड़क, संचार और बिजली की व्यवस्था अभी तक सुचारू नहीं हो पाई है। इसका सीधा-सीधा असर ग्रामीणों की आर्थिकी पर पड़ रहा है। स्थिति यह है कि अभी तक सड़क टिकोची तक ही पहुंच सकी है। टिकोची के पास दुचाणू, किराणू और सिरतोली को जोड़ने वाले पुल के पुनर्निर्माण की भी अभी तैयारी नहीं हुई है। इन जगहों पर बेली ब्रिज बनाने का प्रस्ताव है, लेकिन इसमें समय लगना तय है। इसलिए कोटीगाड में हयूम पाइप डालकर सड़क खोलने में लोनिवि पुरोला की टीम जुटी है।

इसके अलावा अभी तक चिवां, खकवाड़ी, मोंडा, बलावट, गमरी, मैंजाणी, माकुड़ी व डंगोली गांव को जोड़ने वाले सड़क मार्ग भी सुचारू नहीं हो पाए हैं। इसमें अभी भी कम से कम दस दिन और लगेंगे। यही वजह है कि ग्रामीणों को जरूरी कार्यों के लिए दस से 15 किमी की दूरी पैदल नापकर टिकोची पहुंचना पड़ रहा है। इसके अलावा डगोली, बरनाली, माकुड़ी, गोकुल, झोटाड़ी, जागटा, चिंवा, बलावट, मोंडा व खकवाड़ी गांव में अभी भी विद्युत आपूर्ति ठप है, जिससे ग्रामीणों को खासी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं।

- आपदा प्रभावित आराकोट क्षेत्र के 11 गांवों को अब भी सड़क खुलने का इंतजार
- जरूरी कार्यों के लिए भी दस से 15 किमी की दूरी पैदल नापकर टिकोची पहुंच रहे ग्रामीण
- क्षेत्र के दस गांवों में अभी तक सुचारु नहीं हो सकी विद्युत आपूर्ति, लोगों की मुश्किलें बढ़ीं

मोंडा गांव निवासी अब्बल सिंह चौहान कहते हैं कि चिवां-मोंडा-बलावट-खकवाड़ी मार्ग जगह-जगह टूटा पड़ा है। इससे ग्रामीण गांव से बाजार तक भी नहीं जा पा रहे हैं। इसका सबसे बुरा असर सेब की फसल पर पड़ रहा है। बताया कि कि डगोली, बरनाली, माकुड़ी, गोकुल, झोटाड़ी, जागटा, चिंवा, बलावट, मोंडा, खकवाड़ी आदि गांवों में सेब की फसल बर्बाद हो चुकी है। यहां अगस्त में सेब तैयार हो चुका था, लेकिन उसे अभी तक बाजार नहीं पहुंचाया जा सका।

कंकाल शशिनाथ झा का नहीं, दावा करने वाले को सौंप सकती है सीबीआइ

मनोज कुमार सिंह, रांची

- हबीबुल्लाह अंसारी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कंकाल सौंपने की मांग की है
- याचिका में कहा, वर्ष 1998 में बरामद कंकाल उसके भाई मोहम्मद अलीम का

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के प्रमुख शिबू सोरेन के पीए रहे शशिनाथ झा के कंकाल पर दावा करने वाले हबीबुल्लाह अंसारी को सीबीआइ कंकाल सौंप सकती है। सीबीआइ इसके लिए तैयार है, उसे इंतजार है झारखंड हाई कोर्ट के आदेश का। केंद्रीय जांच एजेंसी का मानना है कि इस मामले में अब विवाद करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि शशिनाथ झा के तथाकथित कंकाल का डीएनए उनके परिजनों से नहीं मेल खाने पर ही दिल्ली हाई कोर्ट ने शिबू सोरेन सहित अन्य आरोपितों को बरी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसपर अपनी मुहर लगाई है। ऐसे में दावा करने वाले हबीबुल्लाह का डीएनए मैच हो जाने पर बरामद कंकाल उसे सौंप दिया जाएगा। इस बाबत सीबीआइ के अधिवक्ता राजीव नंदन प्रसाद ने कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, सीबीआइ उसका अनुपालन करेगी।

यह है मामला

शशिनाथ झा शिबू सोरेन के पीए थे। दिल्ली स्थित कार्यालय से 22 मई 1994 को घर के लिए निकले थे, लेकिन घर नहीं पहुंचे। उनके भाई अमरनाथ झा ने 25 मई 1994 को थाने में आवेदन दिया था। वर्ष 1996 में मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी गई थी। बाद में इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने शिबू सोरेन सहित अन्य आरोपितों को बरी कर दिया था।

बरामद कंकाल को बताया मोहम्मद अलीम का : दरअसल, रांची के पिस्का बगान के रहने वाले हबीबुल्ला अंसारी ने झारखंड हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर शशिनाथ झा के तथाकथित कंकाल पर दावा जताया है। याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए उसने कंकाल को अपने भाई अलीम अंसारी का बताया है।

हबीबुल्ला ने यह दावा तब किया है, जब शशिनाथ झा का मामला पूरी तरह से समाप्त हो गया है। सीबीआइ सूत्रों की मानें तो बरामद कंकाल अभी भी सुरक्षित रखा गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता जेजे सांगा ने बताया कि वर्ष 1998 में सीबीआइ ने आरोपितों के निशानदेही पर पिस्का बगान से एक कंकाल को बरामद किया था। कंकाल में सिल्वर कलर का नकली दांत, टोपी, बेल्ट और हाथ में कड़ा मिला था। इसके आधार पर हबीबुल्लाह ने कंकाल की पहचान अपने भाई मोहम्मद अलीम के रूप में की थी। हालांकि, सीबीआइ ने इस बात से इन्कार किया है कि मामले में जांच और ट्रायल के दौरान हबीबुल्लाह ने कोई दावा किया था। यह मामला झारखंड में राजनीतिक रूप से काफी चर्चित रहा। अभी भी यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि शशिनाथ झा के कंकाल के पीछे पूरा सच क्या है।

ओएचई ने फिर दगा दिया, 1.34 घंटे खड़ी रही वंदे भारत

जागरण संवाददाता, वाराणसी : देश की हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत की रफ्तार मंगलवार दोपहर फिर से थम गई। राजा तालाब एवं हरदत्तपुर के बीच मंगलवार को ओएचई (ओवर हेड इक्यूपमेंट) का करंट कम होने से परेशानी हुई। ट्रेन के 1.34 घंटे तक खड़ी रहने से यात्री परेशान हो उठे। इंजीनियरों को भनक लगी तो उनकी नींद उड़ गई, असल में 72 घंटे में ओएचई फेल होने की यह दूसरी घटना रही। लेटलतीफी का असर अप की ट्रेन पर पड़ा। दो घंटे की देरी से शाम पांच बजे रवाना की जा सकी।

नई दिल्ली से वाराणसी आ रही 22436 वंदे भारत एक्सप्रेस हरदत्तपुर रेल खंड से गुजर रही थी। किमी संख्या 217/7 पर अचानक ट्रेन के पहिए थम गए। चालक ने इंजन की गड़बड़ी समझ उसे दुरुस्त करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। इंजीनियर मशक्कत में जुटे तो पूरे 1.34 घंटे बाद सफल हो सके। लेटलतीफी के कारण ट्रेन कैंट रेलवे स्टेशन (वाराणसी) 4.15 बजे पहुंची। स्टेशन प्रशासन ट्रेन के पहुंचते ही उसकी रवानगी कराने में जुट गया क्योंकि नई दिल्ली जाने को यात्रियों की भीड़ प्लेटफार्म पर उमड़ी थी।

बिहार : वीडियो में एके-47 लहराने वाले गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पटना

- कोलकाता भागने की फिराक में थे दोनों, स्टेशन पर पकड़े गए
- एएसपी दोनों से पूछताछ में कुछ अहम सुराग हाथ लगने का किया दावा

वायरल वीडियो में एके-47 राइफल लहराने वाले मोकामा विधायक अनंत सिंह के विरोधी विवेका पहलवान के सहयोगी चंदन और विक्की को पुलिस ने सोमवार की रात मोकामा स्टेशन से धर दबोचा। दोनों को सोमवार की रात मोकामा स्टेशन के पास स्थित चाय की दुकान से गिरफ्तार किया गया। एसएसपी गरिमा मलिक को सूचना मिली कि चंदन और विक्की मोकामा रेलवे स्टेशन के पास चाय की दुकान पर हैं। दोनों कोलकाता भागने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही एसएसपी ने टीम को निर्देश दिए। तीन थानों की पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर चंदन और विक्की को चाय की दुकान से धर दबोचा।

मंगलवार को एएसपी लिपि सिंह ने बताया कि दोनों से पूछताछ में कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। इसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सूत्रों की मानें तो पूछताछ में चंदन और विक्की ने एके 47 से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हैं। मसलन हथियार किसका था, कहां से आया था, फिलहाल कहां है।

यह है मामला

29 अगस्त को एक वीडियो वायरल हुआ था। यह वीडियो विवेका पहलवान के लदमा स्थित घर का बताया गया था। पुलिस ने वीडियो के आधार पर उसमें दिख रहे शख्स की शिनाख्त विवेका के भतीजे कर्मवीर, अथमलगोला थाने के फुलेलपुर निवासी चंदन और विक्की के रूप में की थी। मोकामा विधायक अनंत सिंह के समर्थकों का कहना था कि हाथ में एके-47 लिए दिख रहे शख्स चंदन और विक्की विवेका पहलवान के काफी करीबी हैं। वे आपराधिक मामलों में आरोपित रहे हैं। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस पर दबाव बढ़ गया था।

सीबीआइ ने मुंबई जेल में इंद्राणी से पूछताछ की

नई दिल्ली, प्रेट्र : सीबीआइ अधिकारियों की एक टीम ने आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में इंद्राणी मुखर्जी से जेल में पूछताछ की। इसी मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया है। इंद्राणी अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या करने के आरोप में जेल में बंद हैं। यह जानकारी मंगलवार को सूत्रों ने दी।

सूत्रों ने बताया कि इंद्राणी से यह पूछताछ भायखला जेल में लगभग एक घंटे चली। उन्होंने बताया कि एजेंसी को कंपनी द्वारा किए गए कुछ विदेशी लेनदेन के बारे में इंद्राणी से कुछ स्पष्टीकरण चाहिए थे। जांच एजेंसी ने आइएनएक्स समूह की कंपनियों के वित्तीय लेनदेन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पांच देशों को 'अनुरोध पत्र' भेजे थे। बता दें कि एजेंसी ने सोमवार को मुंबई की एक विशेष अदालत को बताया था कि जिन देशों को अनुरोध पत्र भेजे गए थे, उनमें से एक ने स्पष्टीकरण मांगा है, जिसके लिए सीबीआई इंद्राणी से पूछताछ करना चाहती है।

इंद्राणी का नाम सीबीआइ के आरोपपत्र में था। उस पर आरोप है कि उसने अपने दूसरे पति और ड्राइवर के साथ मिलकर अपनी बेटी शीना बोरा की कथित रूप से हत्या के लिए साजिश रची।

आस्था का प्रश्न

वामन द्वादशी पर अपनी मां मूर्ति से मिलने माणा गांव गए भगवान बदरी नारायण, सैकड़ों लोग बने इस पावन क्षण के साक्षी, पांच घंटे बंद रहे बदरीनाथ धाम के कपाट

भाव-विह्वल कर गया नारायण का माता मूर्ति से मिलन

संवाद सूत्र, बदरीनाथ

श्री बदरीनाथ धाम के निकट देश के अंतिम गांव माणा वामन द्वादशी के मौके पर आयोजित माता मूर्ति मेले में भगवान नारायण का अपनी मां मूर्ति से भाव-विह्वल कर देने वाला मिलन हुआ। इस पावन क्षण के सैकड़ों लोग साक्षी बने। इस दौरान स्थानीय लोगों ने लोकरंग की मनोहारी छटा बिखेरी। बाद में भंडारे का आयोजन भी हुआ, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने भोग लगाया। परंपरा के अनुसार माता मूर्ति मेला संपन्न होने के बाद अब बदरीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी धाम में कहीं भी आवाजाही कर सकते हैं।

भाद्रपद शुक्ल द्वादशी पर हर साल माणा गांव स्थित माता मूर्ति मंदिर में भव्य मेले का आयोजन होता है। मंगलवार को भी सुबह 9.30 बजे बदरीनाथ मंदिर में भगवान नारायण को दोपहर का राजभोग लगाने के बाद उद्धवजी को गर्भगृह से बाहर निकाला गया। ठीक दस बजे मंदिर के कपाट बंद किए गए और फिर भगवान के उत्सव विग्रह उद्धवजी की डोली माता मूर्ति मंदिर के लिए रवाना हुई। इस दौरान भगवान नारायण की जै-जैकार से पूरी बदरीशपुरी नारायणमय हो गई।


चमोली के माणा गांव में मंगलवार को मूर्ति मेला धूमधाम के साथ मनाया गया। बदरीनाथ धाम से माता मूर्ति से मिलने माणा गांव जाती भगवान नारायण की डोली। जागरण

धाम के मुख्य पुजारी रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी के नेतृत्व में उत्सव डोली यात्रा नाग-नागिन, गजकोटी व इंद्रधारा होते हुए तीन किमी की पैदल दूरी तय कर माणा गांवा स्थित माता मूर्ति मंदिर पहुंची। यहां पर रावल ने माता मूर्ति की पूजा-अर्चना की और फिर भगवान को दोपहर का राजभोग लगाया गया। मंदिर में जब भगवान नारायण का मां मूर्ति से भावपूर्ण मिलन हुआ तो भक्तों की आंखें भी छलछला आईं। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से लोकजीवन के रंग बिखेरे। माणा गांव की महिलाओं ने झुमैलो व पौणा नृत्य का मनोहारी झांकी प्रस्तुत की।

दोपहर दो बजे उद्धवजी की डोली ने माणा गांव से बदरीनाथ धाम के लिए प्रस्थान किया और तीन बजे मंदिर के कपाट खोल दिए गए। इस मौके पर श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के सीईओ बीडी सिंह, मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी, धर्माधिकारी भुवनचंद्र उनियाल, चारधाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष शिव प्रसाद ममगाईं, डिमरी धार्मिक पंचायत के अध्यक्ष आशुतोष डिमरी, राकेश कुमार डिमरी, राजेंद्र डिमरी, पीतांबर मोलफा समेत सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे। माता मूर्ति मंदिर में भगवान को राजभोग लगाने के बाद फिर उसे माणा गांव के हक-हकूकधारियों और श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। यहां पर सेना, आइटीबीपी (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस) व विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं की ओर से भंडारे भी लगाए गए थे। भगवान के अपनी मां से मिलन के बाद अब धाम के रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी नर-नारायण पर्वत समेत संपूर्ण बदरीशपुरी में कहीं भी आ-जा सकते हैं।

बंजर भूमि को दुरुस्त करने के लिए इसी साल शुरू होगा सेंटर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

बंजर भूमि को सुधारने के लिए देहरादून स्थित भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आइसीएफआरई) में प्रस्तावित उत्कृष्ट सेंटर इसी साल से शुरू हो जाएगा। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही इसे लेकर आइसीएफआरई से सेंटर को लेकर पूरी योजना भी मांगी है। देश में अपनी तरह के इस पहले सेंटर को खोलने की घोषणा सरकार ने हाल ही में की है। सोमवार को यूएनसीसीडी की सीओपी-14 में प्रधानमंत्री ने दुनिया के साथ भी इसे साझा किया।

इस घोषणा के साथ ही आइसीएफआरई अपनी इस नई भूमिका को लेकर सक्रिय हो गया है। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए ग्रेटर नोएडा में चल रहे यूएनसीसीडी (यूनाइटेड नेशन कंजरवेशन टू कॉम्बेट डेजर्टीफिकेशन) के सीओपी (कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज)-14 के अंतिम दिन 13 सितंबर को उसने इसमें शिरकत करने का फैसला लिया है। हालांकि इसका मकसद कांफ्रेंस में आए दुनिया के करीब 200 देशों के प्रतिनिधियों को इस सेंटर की उपयोगिता सहित इसके जरिये उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी देना भी है। इसके साथ सेंटर का फोकस बंजर भूमि के संकट से घिरे दुनिया के देशों को विशेषज्ञ प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराना है, जिसकी मदद से भारत अपनी बंजर जमीन को सुधारने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रहा है।

सीओपी-14 में भारत ने अपनी इसी विशेषज्ञता को दुनिया के सामने मजबूती से रखा है। साथ ही बताया है कि उसने कैसे अपनी विशेषज्ञता से तेजी से घट रहे जंगल को बचाते हुए उन्हें बढ़ाने में भी कामयाबी हासिल की है। इसके साथ ही भूमि की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया है। खास बात यह है कि सरकार ने यूएनसीसीडी की सीओपी-14 शुरू होने से पहले ही बंजर भूमि को संवारने के लिए जिन बड़े कदमों को उठाने की घोषणा की है, उनमें 260 लाख हेक्टेयर भूमि को सुधारना और देहरादून में एक उत्कृष्ट सेंटर खोलना शामिल है।

दैनिक जागरण

अपनी खुशी के निर्धारक हम स्वयं होते हैं

पाकिस्तान का बेसुरा राग

यह हास्यास्पद है कि बलूचिस्तान, और सिंध में मानवाधिकार उल्लंघन के संगीन आरोपों से दो-चार हो रहे पाकिस्तान ने जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कश्मीर का राग अलापा। ऐसा करते हुए उसने हमेशा की तरह छल-कपट का सहारा लिया, लेकिन उसकी पोल खुद उसके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने तब खोल दी जब उन्होंने जम्मू-कश्मीर का उल्लेख भारतीय राज्य के तौर पर किया। पाकिस्तान के झूठ के जवाब में भारतीय प्रतिनिधि ने उसे न केवल खरी-खरी सुनाई, बल्कि उसे आतंकवाद का गढ़ कहकर भी रेखांकित किया। चूंकि दुनिया भी पाकिस्तान को आतंक के गढ़ के रूप में ही देखती है इसलिए इसकी उम्मीद नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उसे कोई समर्थन मिलने वाला है। पाकिस्तान को इसके पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी मुंह की खानी पड़ी थी। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस शरारती पड़ोसी का आगे भी यही हश्र हो। इस क्रम में यह भी ध्यान रखने की जरूरत होगी कि कश्मीर मसले के बहाने कोई देश अनुचित दबाव बनाने की कोशिश न करे। भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ब्रिटेन की भूमिका कोई बहुत अच्छी नहीं रही और अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर यह कह दिया कि अगर भारत और पाकिस्तान चाहें तो वह कश्मीर पर मध्यस्थता को तैयार हैं। यह एक गैर जरूरी बयान है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले भारतीय प्रधानमंत्री ने उनके समक्ष दो-टूक कहा था कि भारत अपने और पाकिस्तान के बीच के मामलों में किसी तीसरे देश को कष्ट नहीं देना चाहता।

आखिर जब अमेरिका इससे अच्छी तरह अवगत है कि भारत पाकिस्तान से जुड़े मसलों पर किसी की मध्यस्थता के पक्ष में हर्गिज नहीं तब फिर इस तरह की बातों का क्या मतलब कि अगर भारत-पाकिस्तान चाहें तो...? चूंकि इस तरह की बातें भारत के न चाहने के बावजूद हो रही हैं इसलिए यही लगता है कि अमेरिका और साथ ही कुछ अन्य पश्चिमी देश कश्मीर के बहाने भारत को परेशान करना चाह रहे हैं। शायद इन देशों और खासकर अमेरिका को यह पच नहीं रहा कि भारत हर मामले में उसकी हां में हां मिलाने को तैयार नहीं। यह स्वाभाविक है कि अमेरिका को यह रास न आ रहा हो कि भारत उसके साथ ही रूस को भी बराबर महत्व दे रहा है, लेकिन भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर अडिग रहना चाहिए। इसी के साथ उसे अपनी आर्थिक प्रगति को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। वास्तव में आर्थिक रूप से और मजबूत होकर ही भारत हर तरह की अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों का सामना कहीं आसानी से कर सकने में समर्थ होगा।

गांवों का विकास

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम यानी जीपीडीपी से उत्तराखंड के गांवों की तस्वीर बदलने की उम्मीद बंधती दिख रही है। आगामी दो अक्टूबर से देश के अन्य राज्यों की भांति उत्तराखंड में भी इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा। हरिद्वार जिले से इसकी शुरुआत होगी। प्रदेश के अन्य 12 जिलों में पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के फलस्वरूप इन दिनों चुनावों की तैयारी चल रही हैं जो नवंबर तक पूरी होने का अनुमान है। उसके बाद ही इन जिलों को योजना में शामिल किया जाएगा। जैसा कि प्रचारित किया जा रहा है कि जीपीडीपी गांवों के समेकित विकास पर केंद्रित है। इसमें विभागों की जिम्मेदारी तय होने के साथ ही योजनाओं की प्राथमिकताओं का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख है। योजनाओं का चयन पारदर्शी तरीके से गांव की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है, सीधा सा अर्थ यह कि मनमाफिक कुछ भी नहीं होने वाला। उत्तराखंड के संदर्भ में इसके काफी फायदे नजर आ रहे हैं। यहां गांवों की तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है। सोलह हजार से अधिक गांवों वाले उत्तराखंड में बड़ी संख्या में ऐसे गांव हैं जहां अभी तक बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का टोटा बना हुआ है। सरकारों की बेरुखी और स्थानीय स्तर पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी इसके कारक के रूप में सामने आते रहे हैं, लेकिन अब जो व्यवस्था की गई है उसमें इन वजह से गांव का विकास रुकने की गुंजाइश कम रहेगी। जीपीडीपी योजना पलायन के लिहाज से भी उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। राज्य अरसे से पलायन की मार झेल रहा है, इसके पीछे भी बुनियादी सुविधाओं की कमी बड़ा कारण रही है। पलायन आयोग की ताजा रिपोर्ट तस्दीक कर रही है कि प्रदेश में 203 गांवों से लोगों ने पीने के पानी की दिक्कत, 510 गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं न होने, 367 गांव में रोड कनेक्टिविटी न होने और 120 गांवों में बिजली न होने की वजह से लोगों ने पलायन किया। निःसंदेह यह चिंताजनक है कि बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते लोगों को अपनी जड़ों से दूर होना पड़ रहा है। जीपीडीपी पलायन पर अंकुश लगने की भी उम्मीद जगा रहा है। बस, जरूरत योजना को लेकर सरकारी तंत्र की मानसिकता बदलने की है। यह बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि ग्राम विकास की योजनाओं के प्रति विभागों का नजरिया अभी तक बहुत अच्छा नहीं दिखा है।

भूले-बिसरे फिरोज गांधी



ए. सूर्यप्रकाश

देश में फिरोज गांधी की स्मृति में कोई खास आयोजन नहीं होते, जबकि हमें कई बातों के लिए उनका अवश्य ही स्मरण करना चाहिए



अवधेश राजपूत

आठ सितंबर को फिरोज गांधी की पुण्यतिथि थी, लेकिन शायद ही किसी और यहां तक कांग्रेसी नेताओं ने उनका स्मरण किया हो। 12 सितंबर को उनकी जन्म तिथि है। देखना है कि तब भी उनका स्मरण होता है या नहीं? जो भी हो, ऐसा विरले ही देखने को मिलता है कि सत्तापक्ष का कोई सांसद अपनी ही सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के खुलासे और पारदर्शिता लाने के लिए अड़ जाए। फिरोज गांधी कांग्रेस पार्टी के ऐसे ही सांसद थे। वह भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले और निःसंदेह भारत के सबसे पहले बेहतरीन खोजी सांसद थे। देश में उनकी स्मृति में कोई खास आयोजन नहीं होते, जबकि हमें कई बातों के लिए फिरोज गांधी का अवश्य ही स्मरण करना चाहिए। मसलन स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी जिसके चलते उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। सार्वजनिक जीवन में शुचिता एवं पारदर्शिता के लिए बड़ी मेहनत से की गई उनकी तफ्तीश और प्रतिबद्धता को भी याद करना होगा जिसके चलते नेहरू सरकार में वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। बीमा कारोबार का राष्ट्रीयकरण हुआ और एक ऐसा कानून बना जिसमें मीडिया को संसदीय कार्यवाही की रिपोर्टिंग के मामले में मानहानि और दूसरे अभियोगों को लेकर राहत मिली।

चूंकि कांग्रेस पार्टी कभी उनका नाम नहीं लेती तो शायद युवा पीढ़ी को यह नहीं मालूम कि वह इंदिरा गांधी के पति, सोनिया गांधी के ससुर और राहुल गांधी के दादा थे। यह 1920 के दशक के आखिरी दौर की बात है जब कमला नेहरू से प्रेरित होकर फिरोज स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने भूमिगत रहकर भी आजादी के लिए अभियान चलाया। 1950 में वह अस्थाई संसद के सदस्य बने और 1952 एवं 1957 में लोकसभा के लिए चुने गए। सांसद के रूप में फिरोज शुरुआत में बहुत मुखर नहीं थे, लेकिन दिसंबर 1955 में लोकसभा में अपने पहले भाषण के साथ ही उन्होंने सदन में अपनी धाक जमा ली। जब वह बीमा (संशोधन) विधेयक पर बोल रहे थे हर कोई अपनी सीट से चिपककर उन्हें एकटक सुन रहा था। अपने भाषण से उन्होंने सदन को जकड़कर रख दिया। निजी बीमा कंपनियों की संदिग्ध गतिविधियों का भंडाफोड़ करते हुए उन्होंने जीवन बीमा कारोबार के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में पुख्ता दलीलें पेश कीं। उन्होंने सार्वजनिक धन के बेजा खर्च को रोकने की पुरजोर तरीके से पैरवी की जो पैसा इन कंपनियों में निवेश किया जा रहा था। जब उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया तब तक प्रत्येक सदस्य को यह महसूस हुआ कि निजी बीमा कंपनियां अपराधी हैं। उनके तर्क इतने अकाट्य थे कि दो महीनों के भीतर ही राष्ट्रपति ने बीमा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण से जुड़ा अध्यादेश जारी कर दिया। फिरोज का भाषण निजी बीमा कंपनियों के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। राष्ट्रीयकरण के साथ ही जीवन बीमा निगम यानी एलआइसी अस्तित्व में आई। एक सांसद के लिए यह विशिष्ट उपलब्धि थी, लेकिन अभी और भी कुछ बाकी था। 1957 की दूसरी छमाही में उन्हें वित्त मंत्रालय में घोटाले की भनक लगी। उनके सुनने में आया कि एलआइसी ने एकाएक एचडी मूंदड़ा की कंपनियों के शेयर खरीदे। ये शेयर भी ऊंची कीमतों पर खरीदे गए थे। मूंदड़ा कांग्रेस के करीबी कारोबारी थे। फिरोज ने प्रश्न काल के दौरान इस मुद्दे को उठाया और इस पर विशेष चर्चा की मांग की। वित्त मंत्री के ढुलमुल जवाब ने फिरोज को और सतर्क कर दिया। उन्होंने कहा, 'मेरे भीतर उथल-पुथल ने मुझे इस मुद्दे को उठाने पर मजबूर किया। इतने बड़े पैमाने पर होने वाली चीजों को लेकर मौन साधना एक अपराध बन जाता है।'

मूंदड़ा संदिग्ध रिकॉर्ड वाले कारोबारी थे जिन्होंने कांग्रेस को बड़ा चुनावी चंदा दिया था। जब वह वित्तीय संकट में फंसे तो चाहते थे कि नेहरू सरकार उन्हें उबार ले। उन्होंने सरकार से उनकी कंपनियों में करोड़ो रुपये के शेयर खरीदने के लिए कहा। उनकी सभी कंपनियों की हालत खस्ता थी, फिर भी सरकार एलआइसी के जरिये शेयर खरीदारी के लिए तैयार हो गई। इसी दौरान मूंदड़ा ने कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनियों के शेयर खरीदकर कृत्रिम रूप से उनका भाव बढ़ा दिया। ऐसे में जब एलआइसी ने शेयर खरीदे तो उनके दाम उससे ज्यादा बढ़ गए थे जब मूंदड़ा ने सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। यही एलआइसी-मूंदड़ा घोटाला था।

सरकारी गड़बड़ का खुलासा करने के लिए फिरोज गांधी ने एक पखवाड़े के दौरान इन कंपनियों के शेयरों के भाव की पड़ताल की। वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी ने एलआइसी द्वारा अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने की दुहाई देते हुए इस सौदे का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन फिरोज इससे आश्वस्त नहीं हुए। उन्होंने-आपने मूंदड़ा की कंपनियों पर ही नजरें इनायत क्यों कीं और क्यों शेयर ऊंचे भाव पर खरीदे गए? सार्वजनिक धन को ऐसे कैसे खर्च किया जा सकता है? एलआइसी द्वारा खरीदारी के बाद ये शेयर क्यों गिरावट के शिकार हो गए? जैसे कई तल्ख सवाल किए। सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। नेहरू को जांच आयोग गठित करने पर मजबूर होना पड़ा। जांच में वित्त मंत्री को नैतिक रूप से दोषी पाया गया। फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा।

अपने संसदीय करियर में फिरोज गांधी की कई उपलब्धियां रहीं। इनमें संसदीय रिपोर्टिंग के दौरान प्रेस को सांसदों के कोप से बचाने वाला कानून बनाना भी शामिल है। पत्रकारों ने उन्हें बताया था कि संसद में मुखर रूप से बोलने के लिए सांसदों को तो विशेषाधिकार हासिल हैं वहीं पत्रकारों को संसदीय रिपोर्टिंग के दौरान मानहानि और अन्य कानूनी परेशानियों का जोखिम झेलना पड़ता है। लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता में अपनी अगाध आस्था के चलते उन्हें महसूस हुआ कि संसदीय रिपोर्टिंग के दौरान मीडिया के समक्ष कोई बाधा नहीं होनी चाहिए और लोगों को विधायी कार्यवाही का वास्तविक ब्योरा मिलना चाहिए।

उन्होंने इससे जुड़ा विधेयक संसद में रखा। इन सभी मामलों में फिरोज गांधी ने तथ्यों और आंकड़ों पर अपनी पकड़ से लगभग अकेले ही इन्हें तार्किक परिणति तक पहुंचाया। तमाम ऐसे कारक थे जिन्होंने फिरोज गांधी को सच्चा जनप्रतिनिधि बनने के लिए प्रेरित किया। एक तो विद्रोही स्वभाव और जन कल्याण एवं लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता थी। दूसरा उन सूचनाओं को जुटाने की कर्मठता जिससे वे अपने मामलों की पैरवी करते और सरकार में अपने सूत्रों से बेहद सहजता से जुड़ते। अंत में उनके संसदीय कौशल की बारी आती थी। यही वजह थी कि उनके साथी सांसद और नेहरू सरकार में मंत्री उन्हें 'गूढ़ जानकारियां रखने वाला खतरनाक शख्स' करार देते थे। ऐसे असाधारण सांसद के स्मरण के लिए भारत को काफी कुछ करने की दरकार है।

(लेखक प्रसार भारती के चेयरमैन एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

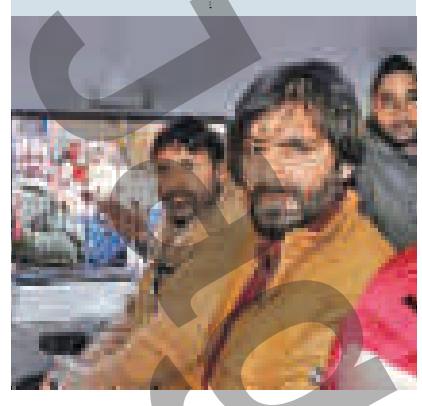
response@jagran.com

आतंक और अन्याय की अनदेखी



राजीव सचान

सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1995 से 2019 तक वायु सैनिकों की हत्या का मामला ठंडे बस्ते में क्यों पड़ा रहा?



पांच अगस्त के बाद से ही कश्मीर खबरों में छाया हुआ है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि कश्मीर से आने वाली या फिर उससे संबंधित हर खबर देश का ध्यान आकर्षित कर रही हो। इसका उदाहरण हाल में आई वह खबर है जो यह बताती है कि 30 साल बाद श्रीनगर में हत्या के एक मामले की सुनवाई शुरू होने वाली है। यह हत्या का सामान्य मामला नहीं। यह 1990 में गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को श्रीनगर के बाहरी इलाके में वायुसेना के चार कर्मियों की हत्या का मामला है। इस मामले का मुख्य आरोपी यासीन मलिक है, जो जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का मुखिया है और फिलहाल आतंकी फंडिंग के आरोप में न्यायिक हिरासत में है। उसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अनुचित तरीके से बाहर से पैसा हासिल करने और पत्थरबाजों को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। यासीन मलिक पर 1989 में केंद्रीय गृह मंत्री रहे मुफ्ती मुहम्मद सईद की बेटी के अपहरण का भी आरोप है, लेकिन पिछले दिनों जब उसके संगठन जेकेएलएफ पर पाबंदी लगाई गई तो इसका विरोध जिन लोगों ने किया उनमें मुफ्ती मुहम्मद सईद की दूसरी बेटी और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी शामिल थीं। उन्होंने इस पाबंदी को गलत बताते हुए कहा कि अगर वह सत्ता में आईं तो जेकेएलएफ पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा देंगी। पता नहीं उनकी यह इच्छा पूरी होगी या नहीं, लेकिन यासीन मलिक के मुरीद फारूक अब्दुल्ला भी हैं। वास्तव में महबूबा और फारूक , दोनों ही यह मान रहे हैं कि यासीन मलिक कश्मीर मसले का एक पक्ष है। ऐसा मानने वाले और भी हैं-न केवल कश्मीर में, बल्कि दिल्ली में भी।

वायु सेना के चार कर्मियों की हत्या के मामले की जांच करते हुए सीबीआइ ने अगस्त 1990 में ही जम्मू की टाडा अदालत में यासीन मलिक के खिलाफ आरोपपत्र दायर कर दिया था, लेकिन 1995 में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने यह कहते हुए मलिक के खिलाफ सुनवाई पर रोक लगा दी कि श्रीनगर में टाडा अदालत नहीं है। इसी के साथ रुबिया सईद के अपहरण के मामले की भी सुनवाई थम गई। इस मामले में आरोप पत्र सितंबर 1990 में दाखिल हुआ था। कोई नहीं जानता कि इसके बाद किसी ने इसकी सुध क्यों नहीं ली कि इस मामले की सुनवाई आगे बढ़े? आखिर कोई वायु सेना के चार कर्मियों की हत्या की अनदेखी कैसे कर सकता है? चूंकि यासीन मलिक पर टाडा के तहत मामले की सुनवाई पर रोक का आदेश हाईकोर्ट की एकल पीठ ने दिया था इसलिए उसे आसानी से चुनौती दी जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अगर जम्मू की टाडा अदालत में इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकती थी तो किसी अन्य अदालत में तो हो ही सकती थी। दुर्भाग्य से ऐसा भी नहीं हो सका। इस मामले की सुनवाई शायद इसलिए आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि किसी ने इसमें दिलचस्पी नहीं ली कि इस बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने वालों को यथाशीघ्र सजा मिले। बहुत संभव है कि इस मामले के ठंडे बस्ते में चले जाने के पीछे एक कारण अनुच्छेद 370 के प्रावधान रहे हों, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं कि इतनी बड़ी आतंकी घटना की कोई सुध न ले। क्या ऐसा इसलिए हुआ कि यासीन मलिक ने बाद में कथित तौर पर हिंसा का रास्ता छोड़ने का एलान कर दिया था? पता नहीं सच क्या है, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं कि कुछ लोग उसे गांधीवादी बताने लगे थे। इसके बाद वह हुर्रियत कांफ्रेंस का हिस्सा बनकर कश्मीर मसले के हल के लिए केंद्र सरकार से होने वाली वार्ताओं में भी शामिल होने लगा। ऐसा लगता है कि इस दौरान इस बात को भुलाना ही बेहतर समझा गया कि कश्मीरी पंडितों के पलायन में भी यासीन मलिक और उसके साथियों की बड़ी भूमिका थी। उसके अतीत से भली तरह परिचित होते हुए भी पता नहीं कैसे यासीन मलिक को कश्मीर समस्या के समाधान में सहायक मान लिया गया? चूंकि ऐसा मान लिया गया इसलिए उसकी एक तरह से मेहमाननवाजी होने लगी।

हत्या और अपहरण के मामले में वांछित होने के बाद भी यासीन मलिक को देश से बाहर जाने की इजाजत मिल गई। इतना ही नहीं, वह टीवी चैनलों में कश्मीर के विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित होने लगा और उसे कश्मीर के युवाओं के लिए रोल मॉडल के तौर पर भी पेश किया जाने लगा। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसे मानवाधिकारों के मसीहा के तौर पर रेखांकित करते थे। यह सही है कि जब यह सब हो रहा था तब उस पर हत्या और अपहरण के आरोप भर थे और वे साबित नहीं हुए थे, लेकिन आखिर ऐसा कौन देश है जो अपने सैनिकों के हत्यारोपी से इतनी नरमी से पेश आता है? साफ है कि इसकी जानबूझकर अनदेखी की जा रही थी कि यासीन मलिक वायुसेना के चार कर्मियों की हत्या का आरोपी है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि आखिरकार तीस साल बाद यासीन मलिक के मामले की सुनवाई होने जा रही है, क्योंकि इसी के साथ यह भी पता चलना चाहिए कि आखिर इस मामले में इतनी देरी के लिए कौन जिम्मेदार है?

1990 में श्रीनगर में मारे गए वायु सेना के चार कर्मियों में से एक स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना भी थे। उनकी पत्नी के अनुसार तीस साल बाद उन्हें उम्मीद की एक रोशनी नजर आई है, लेकिन उनके इस सवाल का जवाब शायद ही किसी के पास हो कि आखिर उनके पति का कसूर क्या था? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि 1995 से 2019 तक यह मामला ठंडे बस्ते में क्यों पड़ा रहा? वास्तव में यह देर नहीं अंधेर है। यह अंधेर उस दौरान हुई जब यह बार-बार दोहराया जा रहा था कि आतंक के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। अगर यह सख्ती थी तो फिर नरमी किसे कहते हैं? निःसंदेह यासीन मलिक का मामला एकलौता प्रकरण नहीं है। कश्मीर में इस तरह के तमाम मामले हैं जिनकी सुनवाई का अता-पता नहीं। इनमें कई मामले कश्मीरी पंडितों की हत्या के भी हैं।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडीटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सदाचार

किसी देवता को रिझाने से ज्यादा खुद देवता बन जाना ज्यादा सरल है। देवता शब्द संस्कृत के दिव् धातु से बना है, जिसका अर्थ प्रकाश है। सूर्य को प्रथम एवं प्रत्यक्ष देवता इसीलिए कहा गया है कि वह प्रकाश के साथ जड़-चेतन को ऊर्जा देता है। जब खुद के या किसी अन्य के जीवन में अंधेरा दिखाई पड़े तो उसे आत्मबल की ऊर्जा देकर कोई भी व्यक्ति देवता की श्रेणी में खड़ा हो सकता है। आप किसी एक देवता को ईष्ट बनाएं या अन्यान्य देवी-देवता की पूजा जब करें तो ध्यान दें कि जिस देवी-देवता की पूजा की जा रही है वे क्यों पूजनीय हुए? जिन कार्यों से वे पूजनीय हुए वही आचरण पूजक को अपनाकर पूजनीय व्यक्तित्व बनाने का कार्य करना चाहिए।

ऐसा नहीं कि हम पूजा तो भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा मां दुर्गा की करें और आचरण रावण या लंकिनी-डंकिनी का करें। यह तो और घातक है। रावण, कंस या धृतराष्ट्र जैसे प्रतापी राजा तक हर पल डरे-डरे रहे। डर किसी व्यक्ति के शरीर और मन पर घातक असर डालता है। कोई भी व्यक्ति छल-छद्म, धोखा-विश्वासघात, शोषण और उत्पीड़न में लगता है तो एक अज्ञात भय उसमें धीरे-धीरे समाने लगता है। जबकि सदाचार का जीवन बनाने से आत्मबल मजबूत होता है। जिंदगी में विपरीत स्थिति या अंधकार उक्त गुणों एवं मनुष्य की मनःस्थितियों की परीक्षा लेते हैं। इस हालत में सबसे पहले धैर्य बनाए रखना चाहिए। इसी के साथ सत्य एवं सदाचार को मजबूती से धारण रखना चाहिए।

इन सद्गुणों को छोड़कर आनन-फानन में बिना सोचे-समझे कोई नकारात्मक कदम उठा लेने पर उसके गंभीर परिणाम ही होंगे। उलटे-पलटे काम से मन में हमेशा डर बना रहेगा। जो सर्वाधिक कष्टदायी स्थिति होती है। यह ध्यान रखना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में सबसे उत्कृष्ट मानव ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी सिद्धांत के अनुसार मनुष्य देवता बने या दैत्य, यह उसके खुद के हाथों में है।

सलिल पाण्डेय

जीएम फसलों पर दुविधा में सरकार

फिर से

गैरकानूनी जीएम फसलें उगाने पर पांच साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है

महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों के किसान आनुवंशिक इंजीनियरिंग से दुरुस्त किए गए फसलों (जीएम) को उगाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका तर्क है कि इन्हें उगाने में कम लागत आती है, उपज अधिक होती है और इन पर कीटों और खरपतवारों का हमला भी कम होता है। सरकार ने जीएम कॉटन (कपास) की एक प्रजाति को छोड़कर बाकी जीएम फसलों पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन 19 जुलाई को संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि इस बात का कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है कि ये फसलें मानव उपभोग के लिए ठीक नहीं हैं। हालांकि इससे जीएम फसलों पर पूरी पाबंदी का मामला फिट नहीं बैठता, लेकिन पर्यावरण को लेकर चिंतित लोग और कुछ किसानों के समूह भी कहते हैं कि सरकार इस मसले पर ऐसे अध्ययनों को नजरअंदाज कर रही है जो जीएम फसलों की पैदावार को सेहत के नुकसान से जोड़कर देखते हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि जीएम फूड के इस्तेमाल से कैंसर भी हो सकता है।

अब सवाल यह भी है कि क्या आनुवंशिक इंजीनियरिंग से तैयार फसलें सेहत के लिए ठीक हैं या नहीं, इस पर निगाह कौन रखेगा? या खेती में अधिक पैदावार हासिल करने की इच्छा से हम पर्यावरण और सेहत की चिंता को ताक पर रख दें? इसके बरक्स एक सवाल यह पैदा होता है कि जीएम फसलें बदलते पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के दौर में मुफीद साबित हो सकती हैं और इससे बढ़ती आबादी का पेट भी भरा जा सकता है?

असल में बीटी कॉटन को मंजूरी मिले 17 साल बीत गए हैं। यह एकमात्र जीएम फसल है जिसे भारत में उगाने की कानूनी मंजूरी मिली हुई है। हालांकि बीटी बैंगन और जीएम सरसों को भी 2017 में सरकारी मंजूरी दी जा चुकी है। पिछली जुलाई में महाराष्ट्र में 12 किसानों को सरकारी बंदिश का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार किया गया था। ये किसान बिना मंजूरी वाले जीएम कपास के बीजों का इस्तेमाल कर रहे थे। इस बाबत 60 एफआइआर दर्ज किए गए और 1100 किलोग्राम गैरकानूनी बीज भी जब्त किया गया था। गौरतलब है कि गैरकानूनी जीएम फसलें उगाने पर पांच साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

यहां ध्यान देने वाली बात है कि देश में साल 2017-18 में 62 लाख मीट्रिक टन कपास की पैदावार हुई थी। चीन के मुकाबले यह उपज काफी अधिक थी। चीन में 60 लाख मीट्रिक टन, अमेरिका में 46 लाख मीट्रिक टन, ब्राजील में 19 लाख मीट्रिक टन और पाकिस्तान में 18 लाख मीट्रिक टन कपास उगाया गया। देश में कपास की खेती का रकबा करीबन 1.17 करोड़ हेक्टेयर है। देश के 10 राज्यों के 65 लाख कपास किसान और करीबन 6 करोड़ लोग कपास से जुड़े कामकाज से अपनी रोटी कमाते हैं। देश के कपास पैदा करने वाले इलाकों में से 15 फीसद इलाके महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हैं जहां गैर-कानूनी जीएम कपास (2017-18 में) उगाई गई थी। इसमें हर हेक्टेयर में करीबन 2800 से 5000 रुपये तक का फायदा हुआ था।

(साभार : गुस्ताख ब्लॉग में मंजित ठाकुर)

मेलबाक्स

अपने अंदर भी झांके कांग्रेस

मनीष तिवारी का आलेख 'लोकतंत्र को चाहिए सशक्त संस्थाएं' पढ़ा। इसमें उन्होंने हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन के उदाहरण दिए हैं, जिन्होंने सत्ता में आकर न्यायपालिका तथा अन्य संस्थाओं को नष्ट कर तानाशाही व्यवस्था स्थापित की। किंतु क्या इंदिरा गांधी का देश पर आपातकाल थोपकर निरंकुश बनने का प्रयास (1975- 77) कुछ कम उल्लेखनीय था, जिसका कोई जिक्र तक लेख में नहीं है? इंदिरा गांधी ने तीन न्यायमूर्तियों को हटाकर चौथे जज को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया। बाद में पुनः वरिष्ठतम जज एचआर खन्ना की जगह अपने चहेते एएन रे को कमान सौंपी। आपातकाल के दौरान प्रतिबद्ध न्यायपालिका की बात कही जा रही थी। लेखक ने जिन तानाशाहों का उल्लेख किया है, उन्होंने सत्ता पाने के बाद संवैधानिक संस्थाओं का गला घोंटा, किंतु कांग्रेस पर आरोप लगते हैं कि चाहे वह सत्ता में हो या सत्ता के बाहर, संवैधानिक एवं वैधानिक दोनों प्रकार की संस्थाओं को पंगु बनाने की कोशिशों में लगी रहती है। अभी पी चिदंबरम और रामजन्मभूमि मामलों में उसके नेताओं तथा नेता-वकीलों के न्यायपालिका-विरोधी बयान सबके सामने हैं। कैग के खिलाफ जैसा मोर्चा कांग्रेस ने तीन-चार वर्ष पहले से खोला था, उसे कौन भूल सकता है। निर्वाचन आयोग पर उसके प्रहार सर्व-विदित हैं। उसके सत्ता में रहते ही सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआइ को सरकारी तोता बताया था, इतनी कम प्रतिष्ठा एवं विश्वसनीयता इस वैधानिक एजेंसी की कांग्रस ने बना दी थी। भारतीय सेना एवं सेनाध्यक्ष को गली के गुंडे बताने की गलती भी कांग्रेस ने ही की है। देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने के भी ढेरों उदाहरण हैं। कहा जाता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा-अध्यक्ष सबका सम्मान इस पार्टी ने गिराया है। मनीष तिवारी अपने लेख में इन सब बातों का भी जिक्र करते तो अच्छा होता।

अजय मित्तल, मेरठ

प्लास्टिक का विकल्प

प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए इन दिनों देश भर में अभियान चलाया जा रहा है। 2 अक्टूबर से यह अभियान और तेज होगा। आम लोगों से लेकर दुकानदारों तक में प्लास्टिक को लेकर विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है। सरकार भी इसके विकल्प के बारे में बात नहीं कर पा रही है। आम जनों के बीच प्लास्टिक जीवन पद्धति बन चुकी है। त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है ऐसे समय में अर्थव्यवस्था में, बाजार में, दुकानदारों में एक उम्मीद जगती है। कई लोगों का व्यवसाय और कई लोगों के आर्थिक हित इससे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग फुटकर सेवाओं में प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। ऐसे में सरकार उन्हें क्या विकल्प उपलब्ध कराती है देखना होगा। सरकार विकल्प के तौर पर चाहे तो खुद इको फ्रेंडली प्लास्टिक का उत्पादन कर अफरा-तफरी के माहौल से दुकानदार और जनता दोनों को बचा सकती है।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

नजरिया बदल कर देखें

9 सितंबर, 2019 के अंक में भरत झुनझुनवाला का मंदी दूर करने के उपायों पर लेख पढ़ा। उन्होंने प्रमुखतः निजीकरण की बात कही है, यहां तक कि शिक्षा के क्षेत्र में भी। यदि हर क्षेत्र में निजीकरण ही हो जाएगा तो उनके द्वारा नियमों की अनदेखी होने में देर नहीं लगेगी और न ही गुणवत्ता की गारंटी होगी। सरकारी क्षेत्र में सहायता की उपलब्धता में अनेकों अड़चनें और अनावश्यक हस्तक्षेप भी उनकी गुणवत्ता को बहुत प्रभावित करते हैं। विकट समस्या सरकारी /अर्धसरकारी क्षेत्र के कर्मियों का हमेशा निर्वाचन में लगाए रहना भी है। वोटर कार्ड का सत्यापन भी यही कर रहे हैं, जिसमें सरकारी स्कूलों के शिक्षक भी लगे हैं। फिर भी लांछन यह कि ये सब नाकारा हैं काम नहीं करते, ऐसे में झुनझुनवाला उनके वेतन फ्रीज करने तक की बात करते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। बैंकों के विलय और निजीकरण की वकालत कर क्या घड़ी उल्टी दिशा में चलाने का प्रयास नहीं होगा। बैंकों के विलय का मकसद एनपीए की प्रतिशत को कम करके दिखाना है। इसी से बैंकों का चयन हुआ है। अधिक अच्छा होता कि बैंकों को अपना कर्जा स्वयं वसूल करने के लिए बाध्य किया जाता। निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र की संस्थाओं का अस्तित्व चेक्स और बैलेंस की दृष्टि से अपरिहार्य है। जरूरत है तो केवल नजरिया बदलने की।

शैलेंद्र सक्सेना, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दि

1999 में पेश किया गया था करतारपुर कॉरिडोर बनाने का विचार, जब अटल बिहारी वाजपेयी बस से लाहौर गए थे, लेकिन पिछले साल जाकर ही इसकी नींव डल पाई।

आजकल

करतारपुर के बहाने अमन की बात



भवदीप कांग
वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और ऐसे में करतारपुर कॉरिडोर का महत्व कहीं ज्यादा बढ़ गया है। वास्तव में दोनों देशों के मध्य फिलहाल संवाद की यही एक कड़ी बची है, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही बौखलाहट में भारत से संबंधों को काफी हद तक बिगाड़ चुका है। ऐसे में यदि पाक चाहे तो यह कॉरिडोर ऐसा अहम पड़ाव बन सकता है, जहां से दोनों देशों के बीच संबंध सुधार की नई राह खुले



करतारपुर कॉरिडोर को भारत और पाकिस्तान के मध्य शांति के मार्ग के रूप में निरूपित किया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 को भारत सरकार द्वारा निष्प्रभावी किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है और ऐसे में इस परियोजना का महत्व कहीं ज्यादा बढ़ गया है। वास्तव में, दोनों देशों के मध्य फिलहाल संवाद की यही एक कड़ी बची है, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही बौखलाहट में भारत से राजनयिक संबंधों को काफी हद तक घटा चुका है और रेल एवं बस सेवा को रोकने के अलावा उसने आपसी कारोबार को भी बंद कर दिया है।

ऐसे माहौल में बीते दिनों अटारी सीमा पर दोनों देशों के बीच करतारपुर कॉरिडोर (जो डेरा बाबा नानक को पाकिस्तान में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब से जोड़ेगा) को लेकर तीसरे दौर की वार्ता हुई। इसमें कोई अंतिम सहमति तो नहीं बन सकी, चूंकि पाकिस्तान हरेक सिख श्रद्धालु से 20 डॉलर फीस लेने पर अड़ गया और साथ ही साथ उसने श्रद्धालुओं की सहायता के लिए भारतीय प्रोटोकॉल अधिकारी की इजाजत देने से भी इन्कार कर दिया। फिर भी अच्छी खबर यह है कि मुख्य मसले सुलझ गए हैं। यह कॉरिडोर सालभर खुला रहेगा और रोज 5000 सिख श्रद्धालु बगैर वीजा के करतारपुर साहिब तक जा सकेंगे। इसके साथ यह भी तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान मिलकर रावी नदी के दोनों ओर पुल बनाएंगे और पाकिस्तान लंगर एवं प्रसाद वितरण के लिए जरूरी व्यवस्थाएं करेगा।

पाकिस्तान ने इस कॉरिडोर को गुरु नानक जी के 550वें प्रकाश पर्व (जो 12 नवंबर को आ रहा है) से पूर्व खोलने का वादा किया है। एक अस्थायी सड़क बनाई जाएगी, ताकि निर्धारित समयसीमा का पालन हो सके। इस संदर्भ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम बाहर से आने वाले सिख श्रद्धालुओं को हरसंभव सुविधाएं मुहैया कराएं। उन्होंने ऑन-अराइवल वीजा देने का वादा किया और कहा- करतारपुर सिखों का मदीना है और ननकाना साहिब मक्का है। हम (मुस्लिम) किसी को मक्का या मदीना से दूर करने की कल्पना भी नहीं कर सकते।

यहां पर यह समझना होगा कि इमरान ने यह वादा इसलिए नहीं किया कि उन्हें सिख समुदाय की फिक्र है या वे सिखों की धार्मिक भावनाओं का आदर करते हैं। ऐसा तो उन्होंने पाकिस्तान की छवि सुधारने की कोशिश के तहत किया, जो सिख लड़कियों के अपहरण, जबरन धर्मांतरण और निकाह की हालिया घटनाओं के चलते काफी कलंकित हो चुकी है। वैश्विक समुदाय को इस बारे में कोई भ्रम नहीं कि पाकिस्तानी सत्तातंत्र का अपने यहां के सिखों (या कहें कि समूचे अल्पसंख्यक समुदाय) के प्रति कैसा रवैया है। यदि सिख समुदाय की ही बात करें तो इस संदर्भ में पाकिस्तान का मानवाधिकार रिकॉर्ड हैरान करने वाला है। पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मुताबिक वहां सिख समुदाय तेजी से घट रहा है। बीस साल पहले पाकिस्तान में 40,000 सिख मौजूद थे, जो अब घटकर महज 8000 रह गए हैं। इनमें अफगानिस्तान से आए सिख शरणार्थी भी शामिल हैं। आखिर बाकी सब कहां गायब हो गए? सिखों के तेजी से घटते आंकड़ों की एक ही वजह हो सकती है-जबरन धर्मांतरण।

पाकिस्तान के सशस्त्र बलों और सरकार में सिखों का प्रतिनिधित्व नगण्य है (मेजर हरचरण सिंह ऐसे पहले सिख थे, जो वर्ष 2007 में पाकिस्तानी सैन्य अफसर बने)। इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी छोटी-सी सिख आबादी को खालिस्तान के नारों को हवा देने के लिए इस्तेमाल करने से बाज नहीं आता। इसकी हालिया मिसाल एक पाकिस्तानी सिख लीडर का वह वीडियो है, जिसमें वह तमाम सिखों से कश्मीर पर पाकिस्तानी रुख का समर्थन करने और अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का विरोध करने की अपील कर रहा है।

ये पाकिस्तान के हताश-निरर्थक प्रयास हैं, क्योंकि खालिस्तानी भावनाएं तो कब की दफ्न हो चुकीं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह राष्ट्रवादी शख्स हैं, जो जंग में भी हिस्सा ले चुके हैं। वे असंतुष्टों को एक इंच भी जगह देना गवारा नहीं कर सकते। पर वे एक सिख भी हैं और इस नाते इस बात को लेकर बेहद उत्सुक हैं कि करतारपुर कॉरिडोर इस साल गुरुपर्व (12 नवंबर) तक बनकर तैयार हो जाए।

गौरतलब है कि भारत-पाकिस्तान का विभाजन करने वाली रेडक्लिफ रेखा ने गुरुनानक की जन्मस्थली ननकाना साहिब और उनके अंतिम दिनों का ठिकाना रहे करतारपुर के दरबार साहिब को भारत से जुदा कर दिया। सरहद से महज 4-5 किमी की दूरी पर स्थित गुरुद्वारा भारत से भी साफ नजर आता है। बीएसएफ ने तो इसके लिए दस फुट ऊंचा एक चबूतरा भी तैयार किया है, जिस पर चढ़कर श्रद्धालु इसके दर्शन कर सकते हैं। 1960 के दशक में जमीन की अदला-बदली की बात भी चली थी, ताकि करतारपुर भारत का हिस्सा बन सके, पर दोनों देशों में तनाव बढ़ने के कारण यह विचार ठंडे बस्ते में चला गया।

बहरहाल करतारपुर कॉरिडोर बनाने का विचार सबसे पहले वर्ष 1999 में पेश किया गया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी बस से लाहौर गए थे, लेकिन पिछले साल जाकर ही इसकी नींव डल पाई। यह प्रस्तावित गलियारा भले ही महज 6 किमी का हो, लेकिन इसका महत्व भौगोलिक दायरों से कहीं बढ़कर है।

इस कॉरिडोर परियोजना के बहाने पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष यह दिखाना चाहता है कि वह भारत से संबंध सामान्य करने की दिशा में पहला कदम आगे बढ़ाने की सियासी मंशा रखता है। हालांकि उसे यह एहसास हो चुका है कि वह भारत से कोई सौदेबाजी करने या किसी तरह की रियायत पाने के लिए कॉरिडोर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। भारतीय पक्ष ने यह साफ कर दिया कि पाकिस्तानी जमीन से आतंकवाद का निर्यात पूरी तरह रुकने के बाद ही द्विपक्षीय संवाद की राह खुल सकती है। भारत ने कश्मीर को अपना अंदरूनी मामला करार देते हुए इस पर किसी भी तरह की बातचीत से स्पष्ट इन्कार किया है।

भारत सरकार का करतारपुर कॉरिडोर पर बातचीत को द्विपक्षीय संवाद के दायरे से अलग रखने का रवैया बार-बार सही साबित हुआ है। पाकिस्तान एक ओर तो करतारपुर पर बातचीत करता है तो दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले होते हैं। बीते बुधवार को भी जहां अटारी में करतारपुर को लेकर दोनों पक्षों में बातचीत चल रही थी, वहीं लंदन में पाकिस्तानी प्रदर्शनकारी भारतीय दूतावास को घेरते हुए नारेबाजी कर रहे थे, यातायात अवरुद्ध कर रहे थे और खिड़कियों के कांच फोड़ रहे थे। यह स्पष्टतः पाकिस्तान का दोहरा रवैया है और भारत इसके झांसे में नहीं आने वाला।

पाकिस्तान कश्मीर मसले पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का समर्थन जुटाने में नाकाम रहते हुए लगभग पूरी तरह अलग-थलग पड़ चुका है। तमाम देश इस पर सहमत हैं कि ये भारत का अंदरूनी मामला है। यदि इमरान खान अक्ल से काम लें तो वे धार्मिक कूटनीति का इस्तेमाल शांति की दिशा में कदम बढ़ाने और संबंध सुधार के प्रति गंभीरता दर्शाने के रूप में कर सकते हैं। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान, दोनों ही परमाणु शक्ति-संपन्न देश हैं, जिनके मध्य छोटी-बड़ी लड़ाइयों, गहरे असंतोष और अविश्वास का स्याह इतिहास रहा है। करतारपुर कॉरिडोर एक ऐसा अहम पड़ाव बन सकता है, जहां से दोनों देशों के मध्य संबंध सुधार की नई राह खुले। पाकिस्तान इसका लाभ उठाए तो बेहतर है।

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर कहर

अरविंद जयतिलक

1947 में भारत विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने पहले भाषण में कहा था कि 'हमें अपने व्यवहार और विचार से अल्पसंख्यकों को यह जता देना चाहिए कि हम उनकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं और उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है।' लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत जिन्ना के वादे पर खरा नहीं रही। जिन्ना के समय से ही पाकिस्तान में गैर-मुसलमानों विशेष रूप से हिंदुओं और सिखों पर कहर जारी है। गत रोज पहले जिस तरह ननकाना साहिब में गुरुद्वारा तंबू साहिब के ग्रंथि भगवान सिंह की नाबालिग बेटी को अगवाकर उसका जबरन धर्मांतरण कराकर बलपूर्वक निकाह किया गया, उससे साफ है कि पाकिस्तान अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा करने में विफल है। यह उचित है कि इन घटनाओं को लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। याद होगा कि कुछ महीने पहले सिंध प्रांत में अल्पसंख्यक समुदाय की दो नाबालिग हिंदू बहनों रवीना और रीना के साथ भी ऐसा ही हुआ था। गौर करें तो पाकिस्तान में हर साल 1000 से अधिक हिंदू लड़कियों को अगवाकर उनका जबरन धर्मांतरण कराकर शादी की जाती है। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष की मानें तो सिर्फ सिंध राज्य में ही हर महीने 20 से 25 हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराकर मुसलमानों से शादी कराई जाती है।

पाकिस्तान में हिंदू और सिख लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कोई नई बात नहीं है। भारत विभाजन के बाद से ही पाकिस्तान में हिंदुओं को खत्म करने की साजिश चल रही है। विभाजन के समय पाकिस्तान में 15 फीसद हिंदू थे जो आज उनकी आबादी घटकर 1.6 फीसद रह गई है। 1947 में पाकिस्तान में 428 हिंदू मंदिर थे। आज सिर्फ 26 मंदिर शेष बचे हैं। यानी अन्य मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया है। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग (एचआरसीपी) की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में हिंदू और सिख समुदाय के लोगों की स्थिति भयावह है। पाकिस्तान में सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें भारत के संबंध में नकारात्मक टिप्पणियों से अटी पड़ी हैं। पाकिस्तानी स्कूलों में हिंदुओं के प्रति नफरत पैदा करने का ही नतीजा है कि आज पाकिस्तान का आम जनमानस भारत को घृणा की नजर से देखता है। गत वर्ष अमेरिकी संगठन प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण से जाहिर हुआ कि पाकिस्तान में हर चार में से तीन नागरिक भारत के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। इसी नफरत का कारण है कि वहां के हिंदू लगातार पलायन कर रहे हैं। पाकिस्तानी हिंदू काउंसिल के संस्थापक डॉक्टर रमेश कुमार बंकवानी की मानें तो पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान से 50,000 से अधिक हिंदू परिवार पलायन किए हैं जिनमें से अधिकांश भारत आए हैं। उनकी मानें तो आज पाकिस्तान में हालात ऐसे बन गए हैं कि हिंदू और सिख परिवारों विशेष रूप से लड़कियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। भारत सरकार को चाहिए कि वह पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनाए। अगर आवश्यक हो तो इस मसले को संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उठाए।

खरी-खरी

मंदी पर अफलातून

जवाहर चौधरी

इधर मंदी का सुन रहे हैं जी। कहते हैं कि आ रही है, आपने भी सुना होगा? चिंतित सिक्का जी बोले। मंदी!! कहां से आ रही है? अफलातून जी ने चौंककर पूछा। कहां से!! ये तो नहीं पता। जहां होगी, वहीं से आ रही होगी। जैसे लड़कियां आती हैं मायके। सिक्का ने मजाक किया। अफलातून अपनी रौ में थे, लड़कियां तो ससुराल से आती हैं, बल्कि भाई लेने जाते हैं तब आती हैं। मंदी को लेने कौन गया? मैं नहीं गया भियाजी, मंदी मेरी भेन नहीं है।

फिर देखो यार, किसकी बहन है। मंदी का आधार कार्ड तो होगा ही। आप गलत समझ रहे हो। मंदी का आधार कार्ड नहीं बनता है!! तो पासपोर्ट बनता होगा? पता तो चले किधर से आ रही है। किसी के घर नहीं आती है, बाजार में आती है मंदी। बाजार में! अकेली आती है क्या? आजकल बाजार में पैर रखने की जगह नहीं होती है! सोने तक की दुकान पर भीड़ इतनी होती है कि लगता है फिरी में बंट रहा है। ऐसा नहीं है, जानकार बताते हैं कि जब मंदी आने वाली होती है, तब सोने की बिक्री तो और ज्यादा बढ़ जाती है।

तो यों कहिए ना कि मंदी बहू है नवेली। परंपरा है अपने यहां, शादी ब्याह के मौसम में सोने की खरीदी बढ़ जाती है। चार साल पहले हमारे यहां बड़ी वाली आई थी, तब दो लाख का सोना खरीदा था हमने और पिछले साल छोटी मंदी के टाइम तीन लाख का, लेकिन मंदी किसी की भी हो, इज्जत होती है घर की। उसे अकेले-दुकेले बाजार में नहीं आना चाहिए। पूरा शहर युवा हृदय सम्राट गुंडों से भरा पड़ा है।

अरे अफलातून जी, आप कहां से कहां निकल जाते हैं! कैसे बताएं आपको...मंदी जो है आती है और छा जाती है बस...जैसे बादल आते हैं और छा जाते हैं। जब वह ठीक से छा जाती है तो सरकार को चिंता करना पड़ती है।

पूरी सरकार चिंता करती है या उनका कोई अलग से चिंता-मंत्री होता है? सब करते हैं, पूरी सरकार करती है, और रात-दिन करती है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर; पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दस कबीर। चिंता-मंत्री ही करते हैं चिंता। दरअसल अंदर से वह चिंता-मंत्री होता है, लेकिन उसको कहते वित्त-मंत्री हैं। सिक्का जी ने विस्तार समझाया। तो मतलब, अपन लोगों को क्या करना है? और अभी करना है या मंदी ढंग से छा जाए तब करना है? कुछ नया नहीं करना है जी। राजा की जै-जै कार जैसे पहले किया करते थे ना, वही करते रहिए बस।

ट्वीट-ट्वीट

चुनाव के बाद से राफेल लड़ाकू विमान का नाम शायद पहली बार सुर्खियों में आया है। आठ अक्टूबर को भारत को पहला राफेल मिल सकता है। उस दिन वायुसेना दिवस भी है। साथ ही, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी या दशहरा भी।
अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

जब उर्मिला मातोंडकर ने लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया तो मैंने उनका पुरजोर समर्थन किया। उन्हें राजनीति में लाने वाले भी जब उनसे किनारा करने लगे, मैं तब भी उनके साथ खड़ा था। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं कि मुंबई नॉर्थ के नेताओं की जवाबदेही तय होनी ही चाहिए।
मिलिंद देवड़ा@milinddeora



गुजरात ने हेलमेट से जुड़े चालान की दर घटा दी है। आखिर कितने और राज्य उसकी देखादेखी ऐसा करेंगे? अगर दूसरे राज्य भी यही करेंगे तो मुझे हैरानी नहीं होगी और हम खुशी-खुशी पुरानी व्यवस्था की ओर वापस लौट जाएंगे।
आकाश चोपड़ा@cricketaakash

छत्तीसगढ़ डायरी

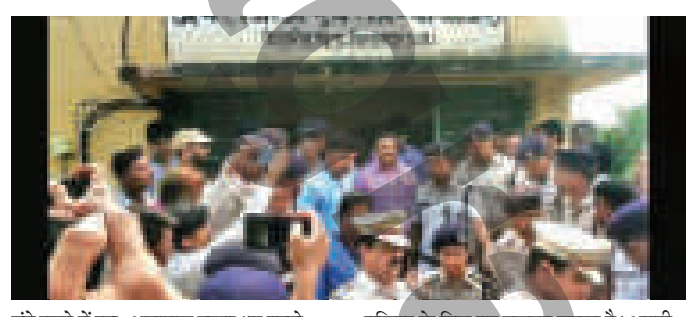
विपक्षियों के लिए आफत बने पुराने मामले

आलोक मिश्रा
राज्य संपादक, नईदुनिया, छत्तीसगढ़



छत्तीसगढ़ में इस समय भले ही झमाझम बारिश के चलते मौसम सुहाना हो, लेकिन सियासी पारा बेहद गरम हो चला है। इस बार इस गरमी का कारण तल्ख बयानबाजी, आंदोलन आदि नहीं, बल्कि पुराने कानूनी मामले हैं, जिसके लपेटे में विपक्ष है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी एवं उनके पुत्र अमित जोगी के साथ ही भाजपा के रमन सिंह सरीखे नेता इसके कारण बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। बड़े जोगी की जाति दिक्कत बन गई है तो छोटे जोगी का जन्मस्थान, रमन सिंह अंतागढ़ चुनाव की खरीद-फरोख्त में लपेटे में आ गए हैं तो राजेश मूढ़त अपने बंगले में रकम देने के मामले में, जबकि हवा देकर दूर बैठी कांग्रेस मजे ले रही है।

जोगी परिवार की मुसीबत तब शुरू हुई जब अजीत जोगी की जाति की जांच कर रही उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने उन्हें कंवर आदिवासी मानने से इन्कार कर दिया। जोगी इसे मानने को तैयार नहीं, लेकिन जोगी के गांव जोगीसार के बगल के गांव में एकत्र हुए कंवर समाज के लोगों ने इस फैसले के कारण उन्हें समाज से बाहर करने का एलान कर दिया। जोगी भला इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने समाज के अध्यक्ष को कानूनी नोटिस भेज दिया। बहरहाल जोगी की जाति प्रकरण को लेकर भाजपा तो चुप रही, लेकिन कांग्रेस चुटकी लेने लगी कि जोगी की जाति क्या है? इधर बड़े जोगी जाति में फंसे तो उधर छोटे जोगी (अमित जोगी) दो जन्मस्थान को लेकर जेल पहुंच गए। मामला 2013 के मरवाही विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। उनके दो जन्मस्थान को लेकर भाजपा नेत्री समीरा पैकरा हाईकोर्ट गई थीं। इसी बीच चुनाव हो गए और मरवाही से अमित जोगी विधायक बन गए। हाईकोर्ट में हलफनामा दे दिया कि उनका जन्म अमेरिका के टेक्सास में हुआ है। इसके आधार पर तब हाईकोर्ट ने मामला खारिज कर दिया तो इसी वर्ष 2 फरवरी को समीरा ने उसी हलफनामा के आधार पर बिलासपुर में एफआइआर करा दी। छह महीने मामला ठंडे बस्ते में रहा, अचानक हफ्ता भर पहले समीरा थाने पहुंचीं और कार्रवाई करने को लेकर हंगामा मचा दिया। छोटे जोगी ने सोशल मीडिया पर चुटकी ले ली कि जब हाईकोर्ट में नहीं चली तो अब क्या चलेगी। इसने आग में घी का काम किया और जोगी जी धर लिए गए 14 दिन की रिमांड पर। जेल पहुंचने पर तबीयत नासाज हो गई। अब अस्पताल में हैं, देखरेख हो रही है। इस मुसीबत से बड़े जोगी को भी सदमा लगा और वे भी भर्ती हैं।

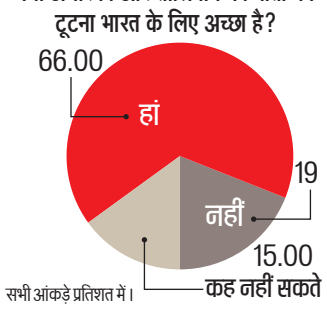


कहा जाता है कि मुसीबत जब आती है तो हर तरफ से आती है। आजकल जोगी परिवार के लिए यह एकदम दुरुस्त है। अपनी जाति और बेटे को जेल मामले में झूल रहे दोनों जोगी के लिए अंतागढ़ टेपकांड में पूर्व विधायक मंतूराम पंवार की गवाही बड़ा झटका दे गई। इसमें दोनों जोगी के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, उनके दामाद एवं पूर्व मंत्री राजेश मूढ़त वगैरह भी लपेटे में आ गए। मंतूराम ने कह दिया कि साढ़े सात करोड़ रुपये में मुझे बैठाने का सौदा हुआ था। इस विस्फोटक बयान से खलबली मच गई। फंसे नेता कह रहे हैं कि मंतू झूठ बोल रहे हैं। मंतूराम भाजपा में ही हैं और अब कांग्रेस कह रही है कि मंतू अगर पार्टी में आना चाहेंगे तो विचार किया जाएगा। मामला 2014 में हुए अंतागढ़ उपचुनाव से जुड़ा है। उस समय भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन भरने वाले एक प्रत्याशी को छोड़ कर सभी ने नाम वापस ले लिया था। इनमें उस समय कांग्रेस प्रत्याशी रहे मंतूराम पंवार ने भी ऐन वक्त पर नाम वापस ले लिया था। कांग्रेस ने प्रत्याशी खरीदने का आरोप लगाया था। उसी मामले में मंतूराम ने अपनी गवाही में साढ़े सात करोड़ रुपये में डील का हवाला दिया। अब भाजपा और जोगी उन्हें झूठा करार दे रहे हैं। बहरहाल आगे जो भी हो, लेकिन यह गवाही दिक्कत खड़ी करती तो जरूर नजर आ रही है।

मंतूराम की गवाही को भाजपा दंतेवाड़ा उपचुनाव से जोड़ कर इसे सियासी रूप देने में जुट गई है। दंतेवाड़ा विधानसभा का उप चुनाव हो रहा है। सीट भाजपा की है और उसने इस सीट पर लोकसभा चुनाव के दौरान नक्सली हिंसा में शहीद हुए विधायक भीमा मंडावी की पत्नी को उतारा है। जिनका मुकाबला है कांग्रेस के टिकट पर उतरीं स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की पत्नी देवती कर्मा से, जो भीमा से गत चुनाव हारी थीं। कांग्रेस चाहती है इस सीट को जीतकर भाजपा मुक्त बस्तर का संदेश देना, जबकि भाजपा की मंशा है अपनी सीट बचाकर कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव को रोकना। ऐसे हालात में मंतूराम की गवाही भाजपा को भारी पड़ रही है। इसलिए भाजपा इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस एक तीर से दो निशाने लगाने के मूड में है। उसकी कोशिश है विपक्ष को बैकफुट पर लाना और सीट कब्जाना। इसलिए कांग्रेस पर्दे के पीछे से इसे तूल देने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में यह पखवारा कानूनी दांव-पेच में ही उलझा रहा। इन दोनों प्रकरणों के अलावा एसआइटी जांच में फंसे स्पेशल डीजी मुकेश गुप्ता का मामला भी सुर्खियों में रहा। उसमें उन पर शिकंजा कसने में जुटी सरकार की तब किरकिरी हो गई। जब हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन पर चल रहे भ्रष्टाचार के तीनों मामलों पर स्टे ले लिया।

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या अमेरिका और तालिबान की वार्ता का टूटना भारत के लिए अच्छा है?



सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या मौजूदा दौर में आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y**, **N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

ताऊ जी अब छोड़ दो पंचायत का राग,
याद करो तुम भी जरा 'नौ-ग्यारह' की आग।
'नौ-ग्यारह' की आग हुआ आतंकी हमला,
अमरीका पर टूट पड़ा जब दानव अमला।
आप बनें 'मध्यस्थ' बात ये लगे उबाऊ,
खत्म करो आतंक साथ में आकर ताऊ।
- ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

सड़क पर सुशासन की चाह

सुशील कुमार सिंह
निदेशक, वाईएस रिसर्च फाउंडेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन



यह सही है कि अधिक जुर्माना वाहन चालकों को खौफजदा करेगा। इसका फायदा यह होगा कि वे नियमों का पालन करने के प्रति उन्मुख होंगे, मगर इससे पहले सरकार को यह भी सोचना चाहिए था कि इसे चरणबद्ध ढंग से लागू किया जाता तो कहीं बेहतर होता



भारत में हर साल लाखों लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं के कारण होती है, जिसका सबसे बड़ा कारण यातायात नियमों का ज्ञान नहीं होने के साथ-साथ खतरनाक ड्राइविंग को माना जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2018 की रिपोर्ट भी कहती है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं भारत में ही होती हैं। यहां तक कि सर्वाधिक आबादी वाला देश चीन भी इस मामले में पीछे है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 2017 की रिपोर्ट भी यह पुष्टि करती है कि सड़क कानूनों को सही मंशा से लागू कर लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है।

लगातार बढ़ रहीं सड़क दुर्घटनाओं और उनके परिणाम स्वरूप होने वाली मौतों को रोकने के लिए सरकार ने नया मोटर वाहन कानून बीते एक सितंबर से लागू किया है जिसमें जुर्माने की राशि कई मामलों में बढ़ाकर 10 गुना तक कर दी गई है। इस उम्मीद में कि आर्थिक दबाव के चलते वाहन चालक होशोहवास में रहेंगे और दुर्घटनाएं थमेंगी। हालांकि मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों ने अभी इसे नहीं लागू करने का फैसला किया है। इसके पीछे जुर्माने की राशि का अधिक होना भी हो सकता है। साथ ही ये दोनों राज्य भाजपा शासित नहीं हैं। 10 गुना चालान के पीछे तर्क है कि इससे वाहन चालाक सड़क पर अनुशासन में रहेंगे ही साथ ही ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए भी बाध्य होंगे। परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाएं भी घटेंगी। चूंकि जुर्माने की राशि अधिक है, ऐसे में कइयों की गलतियां उनके भौतिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर सकती हैं।

हालांकि यह आरोप उचित नहीं है कि सरकार ने मनमाने ढंग से अपनी वित्तीय शक्ति बढ़ाने के लिए वाहन चालकों से जुर्माने के नाम पर उगाही करने का मन बनाया है। मगर भारी भरकम जुर्माना यह सवाल जरूर खड़ा करता है कि बिना ट्रैफिक जागरूकता फैलाए नए नियम कइयों के लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं। देश के कई हिस्सों से यह खबर है कि वाहन चालकों को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ रहा है जिसके चलते प्रशासन और जनता के बीच संबंध बिगड़ रहे हैं। वैसे भी देश में हर चौथा व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है और अशिक्षित भी। इतना ही नहीं जहां गरीबों को रसोई गैस के सिलेंडर करोड़ों की संख्या में मुफ्त दिए जाते हों और अनाज भी सस्ती दरों पर उपलब्ध कराए जाते हों, वहां उनके द्वारा सड़कों पर की गई एक गलती उन्हें 10 गुने अधिक चालान की चपेट में ले सकती है और उनके जीवन को कठिनाई में डाल सकती है। हालांकि अमीर हों या गरीब नियमों का पालन सभी के लिए आवश्यक है।

अब यह भी समझना सही रहेगा कि नए मोटर वाहन कानून में जुर्माने की राशि कहां, कितनी और किस पैमाने पर तय की गई है? गौरतलब है कि नाबालिग के गाड़ी चलाने पर जुर्माना 25 हजार रुपये है। साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद हो जाएगा और उसका ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल तक नहीं बनेगा। जाहिर है यहां कोई एतराज नहीं होना चाहिए। बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों से अब 5 सौ से 15 सौ रुपये के बीच वसूली की जाएगी जो पहले एक सौ से तीन सौ रुपये के बीच था। यदि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं होगा तो 5 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना वसूला जाएगा। गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करना और खतरनाक ड्राइविंग के लिए जुर्माने की राशि भी एक हजार से बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दी गई है। इतना ही नहीं गलत दिशा में ड्राइविंग करने पर अब 11 सौ के बजाय 5 हजार रुपये देने होंगे। रेड लाइट जंप करने पर जुर्माना पहले एक सौ रुपये था अब वह 10 हजार रुपये कर दिया गया है। बिना सीट बेल्ट और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर भी जुर्माने की राशि में भारी वृद्धि की गई है। इमरजेंसी गाड़ियां मसलन एंबुलेंस और दमकल को साइड ना देने पर जुर्माने की राशि 10 हजार निश्चित की गई है। इसके अलावा भी कई ऐसे ट्रैफिक नियम हैं जिन पर जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है।

सरकार का इरादा भले ही भारी जुर्माने के चलते वाहन चालाकों को पटरी पर लाने का हो, पर बिना सड़क और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किए केवल जुर्माने पर जोर देना कई सवाल खड़े करता है। सवाल यह भी है कि क्या पहले लगाए गए जुर्माने की राशि कम थी या फिर वाहन चालकों में जागरूकता का आभाव था जो अब अधिक जुर्माने के कारण समस्या हल हो जाएगी। हां, यह सही है कि अधिक जुर्माना वाहन चालकों में अधिक डर का प्रवेश कराएगा। फलस्वरूप नियमों का पालन करने के प्रति वे आतुर होंगे, मगर इसे जनता पर थोपी गई मात्र एकतरफा जिम्मेदारी ही कही जाएगी।

जब जुर्माना इतना अधिक है कि इसकी भरपाई करने वाले की आर्थिकी बिगड़ सकती है तो फिर ऐसे में सड़कों के रखरखाव के प्रति क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? बेशक सरकार सड़क परिवहन से लेकर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिम्मेदार है, परंतु इस नियम को लागू करने से पहले क्या उसे एक से तीन महीने तक जागरूकता अभियान नहीं चलाना चाहिए था? लोकतंत्र में लोक कल्याण से भरे सरकार का यह दायित्व है कि अपने नागरिकों के प्रति संवेदनशील रहे और उनकी आर्थिक प्रगति को लेकर कहीं अधिक उदार रहे। साथ ही इंस्पेक्टर राज को कम करने का प्रयास करे, पर जुर्माने की राशि देखकर थोड़ी आशंका बढ़ जाती है। देखा जाए तो सरकार और प्रशासन को केवल चालान काटने के लिए ही नहीं आतुर रहना चाहिए, बल्कि एक अच्छी मंशा के साथ लोगों में ट्रैफिक चेतना भी बढ़ानी चाहिए। व्यापक पैमाने पर वाहन चालक जागरूक बनें इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जाहिर है कि देश की जनता जनाधिकार रखती है इस नाते उस पर आर्थिक भार इतना न लादें कि उसका जीवन ही दूभर हो जाए।

डाटागीरी

ठोस कचरे के निपटान में छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आगे

भारत के किसी भी हिस्से में चले जाएं, शहरी इलाके में दाखिल होते ही कचरे के पहाड़ (डंपिंग ग्राउंड) दिखाई पड़ जाते हैं। यह स्थिति सिर्फ भारत की ही नहीं दुनिया के तमाम देशों में है। मौजूदा समय में दुनिया के तकरीबन सभी देश ठोस कचरा प्रबंधन की समस्या से जूझ रहे हैं। विकासशील देशों में यह स्थिति ज्यादा भयावह इसलिए होती जा रही है, क्योंकि कचरा निपटान की तकनीक प्रभावशाली ढंग से काम नहीं कर रही है।



जेएनएन, नई दिल्ली

भारत में ठोस कचरे के निपटान के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि स्थिति पूरी तरह से भले ही दुरुस्त नहीं हो सकी है, लेकिन कुछ राज्यों ने इस दिशा में बेहद सकारात्मक परिणाम दिए हैं। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ने अद्भुद प्रदर्शन किया है।

कचरे का 85 फीसद तक निपटान कर रहा छत्तीसगढ़ : छत्तीसगढ़ में प्रति वर्ष तकरीबन 601,885 मीट्रिक टन कचरा उत्पन्न होता है। प्रदेश इस कचरे का 85 फीसद तक निपटान करने में संभव है। वहीं, तेलंगाना में प्रति वर्ष 2,690,415 मीट्रिक टन ठोस कचरा निकलता है और यहां पर 73 फीसद तक कचरे का निपटान कर लिया जाता है। पिछले दिनों लोकसभा सत्र के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने एक सवाल के जवाब में यह जानकारी उपलब्ध कराई है।

बंगाल और जम्मू-कश्मीर फिसड्डी : बड़े राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर ही ऐसे राज्य हैं जहां सबसे कम निपटान किया जाता है। ये प्रदेश अपने यहां निकले ठोस कचरे का सिर्फ पांच और आठ फीसद ही निपटान करते हैं।

महाराष्ट्र में निकलता है सबसे ज्यादा ठोस कचरा : सबसे ज्यादा ठोस कचरा महाराष्ट्र में निकलता है। यहां प्रति वर्ष निकलने वाले 8,22,38,050 मीट्रिक टन ठोस कचरे का 44 फीसद निपटान किया जाता है। इसके बाद दिल्ली में 38,32,500, गुजरात में 37,02,925 और कर्नाटक में 36,50,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष ठोस कचरा निकलता है। दिल्ली में 55, गुजरात में 57 और कर्नाटक में 32 फीसद तक कचरे का निपटान होता है। 2016-17 में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में रोजाना तकरीबन 1,50,000 मीट्रिक टन कचरा निकलता है, जिसका 90 फीसद (1,35,000) इकट्ठा किया जाता है। एकत्रित कचरे में 20 फीसद (27,000 मीट्रिक टन) का निपटान किया जाता है, जबकि शेष 80 फीसद (10,8000 मीट्रिक टन) डंप साइटों पर चला जाता है। 2016-17 की रिपोर्ट के अनुसार 71.7 लाख टन खतरनाक अपशिष्ट का उत्पादन किया गया था, जिसमें से 36.8 लाख टन (49.46 फीसद) को रिसाइकिल किया गया।

8.22 करोड़ मीट्रिक टन ठोस कचरा सालाना निकलता है भारत में

38.32 लाख मीट्रिक टन कचरा निकलता है दिल्ली में

नवंबर 2018 तक ठोस कचरे का निपटान

वेहतर प्रदर्शन वाले राज्य	
राज्य	निपटान (% में)
छत्तीसगढ़	84
तेलंगाना	73
मध्य प्रदेश	65
केरल	60
उप्र और गुजरात	57
खराब प्रदर्शन वाले राज्य	
राज्य	निपटान (% में)
बंगाल	5
जम्मू-कश्मीर	8
ओडिशा	12
हरियाणा	17
आंध्र प्रदेश	29

वन्यजीवों से संघर्ष रोकने को बनेगा प्लान

तैयारी ▶ उत्तराखंड के ऋषिकेश में तैयार होगी नेशनल एक्शन प्लान की रूपरेखा

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इस सिलसिले में 18-19 को बुलाई है बैठक

- नीति, क्षमता विकास, लैंडस्केप स्तर के प्रोजेक्ट व जनसहभागिता होंगे बिंदु
- सभी राज्यों के सीडब्ल्यूएलडब्यू समेत अन्य वनाधिकारी करेंगे इसमें शिरकत

केदार दत्त, देहरादून

उत्तराखंड समेत देश के विभिन्न राज्यों में बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष से केंद्र सरकार भी चिंतित है। इस संघर्ष से पार पाने के लिए अब 'नेशनल एक्शन प्लान' तैयार किया जा रहा है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने एक्शन प्लान को लेकर मंथन के लिए 18 व 19 सितंबर को ऋषिकेश में बैठक बुलाई है। इसमें देश के सभी राज्यों के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक (सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू) समेत अन्य वनाधिकारी शिरकत करेंगे। एक्शन प्लान के तहत नीति, क्षमता विकास, लैंडस्केप स्तर पर पायलट प्रोजेक्ट, संघर्ष थामने को नवीन तकनीकी का उपयोग, जनसहभागिता जैसे बिंदुओं पर गहनता से मंथन होगा।

71 फीसद वन भूभाग वाले उत्तराखंड में मानव व वन्यजीवों के बीच छिड़ी जंग अब चिंताजनक स्थिति में पहुंच गई है। गुलदार, बाघ, हाथी, भालू जैसे जानवर जहां खतरे का सबब बने हैं, वहीं बंदर, लंगूर, वनरोज जैसे जानवरों ने भी नींद उड़ाई हुई है। मनुष्य और वन्यजीवों के बीच चल रहे इस संघर्ष में दोनों को ही कीमत चुकानी पड़ रही है। ऐसी ही स्थिति देश के अन्य राज्यों में भी है।

हालांकि, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में इस संघर्ष को थामने के लिए प्रयास हुए हैं, मगर इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक्शन प्लान नहीं बन पाया है। अब इसके लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पहल की है।



प्रतीकात्मक

नेशनल एक्शन प्लान की रूपरेखा तय करने के लिए मंत्रालय ने उत्तराखंड को चुना है। इसी कड़ी में 18 व 19 सितंबर को ऋषिकेश में मंत्रालय ने उत्तराखंड समेत सभी राज्यों के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालकों समेत अन्य वनाधिकारियों के साथ ही विशेषज्ञों की बैठक बुलाई है। उत्तराखंड के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजीव भरतरी ने इसकी पुष्टि की।

नेशनल एक्शन प्लान के मद्देनजर विभिन्न राज्यों में मानव-वन्यजीव संघर्ष थामने को हुई पहल के क्रम में राष्ट्रीय स्तर पर समग्र कार्ययोजना की रूपरेखा पर विचार किया जाएगा।

इसके अलावा संघर्ष थामने को नीति, क्षमता विकास, नवीनतम तकनीकी का इस्तेमाल, आमजन की सहभागिता जैसे बिंदुओं पर विमर्श होगा। मंथन में निकले बिंदुओं को राष्ट्रीय स्तर पर मानव- वन्यजीव संघर्ष थामने को तैयार किए जाने वाले एक्शन प्लान में शामिल किया जाएगा। फिर इसी के आधार पर राज्यों में कदम उठाए जाएंगे। मानव और वन्यजीव संघर्ष में नुकसान दोनों तरफ होता है। सरकार अब इसे कम करने के लिए पूरे प्रयास कर रही है।

पर्यटन बढ़ाने के लिए 12 नए अभयारण्य खोलेगी मप्र सरकार

- डीएफओ से स्थान तलाशने को कहा, 200 हेक्टेयर की जरूरत

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए राज्य सरकार पर्यटन पर विशेष ध्यान दे रही है। वन विभाग ने हाल ही में 12 नए अभयारण्य खोलने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। संबंधित जिलों के डीएफओ (जिला वन अधिकारी) से अभयारण्य के लिए स्थान का चयन करने को कहा गया है। एक अभयारण्य के लिए कम से कम 200 हेक्टेयर भूमि की जरूरत है।

वर्तमान में प्रदेश में 10 नेशनल पार्क और 25 अभयारण्य हैं। इनसे सरकार को हर साल करीब 27 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है। इस राशि को 200 करोड़ रुपए तक ले जाने की तैयारी है। वन विभाग ने प्रारंभिक तौर पर श्योपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, शहडोल, डिंडौरी, सागर, खंडवा, जबलपुर, इंदौर, सिवनी और होशंगाबाद में वाइल्ड लाइफ अभयारण्य खोलने का प्रस्ताव दिया है। जबकि रातापानी और मानधाता को नेशनल पार्क बनाने की तैयारी है। इनके भी प्रस्ताव शासन को भेज दिए गए हैं।

वाइल्ड लाइफ के अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक जेएस चौहान ने बताया कि नए अभयारण्य बनने से शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ेगी और उन पर निर्भर बाघ, तेंदुओं की संख्या में भी वृद्धि होगी। नए अभयारण्यों के लिए तैयारी की जा रही है।

अब पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए ऑनलाइन पिंडदान

कमल नयन, गया : वर्षों से चली आ रही पिंडदान की परंपरा भी समय के साथ बदल रही है। 15 दिनों का पितृपक्ष गया में दो दिनों बाद शुरू हो रहा है। गया तीर्थ आने वाले श्रद्धालु की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। वैसे पर्यटन विभाग ने इस वर्ष 'ई-पिंडदान' का पैकेज लांच किया है। पर्यटन विभाग के इस नये पैकेज को तीर्थ पुरोहित धर्म के साथ मजाक बता रहे हैं।

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने ई-पिंडदान के पैकेज को लांच किया है, जो 12-28 सितंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान देश-विदेश के श्रद्धालु अपने पितरों को पैकेज के माध्यम से घर बैठे तर्पण और पिंडदान का कर्मकांड संपन्न करेंगे। इसके लिए 19 हजार रुपये के साथ-साथ 950 रुपये जीएसटी व्यय करना होगा। पर्यटन विभाग ने इस पैकेज में बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट नंबर की घोषणा की है। इसमें राशि उपलब्ध कराने के बाद पंजीकृत कर गया में उनके पितरों को तर्पण और पिंडदान किया जाएगा। उक्त राशि में विष्णुपद मंदिर व अक्षयवट में पिंडदान और फल्गु में तर्पण कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त पूजन सामग्री, पंडित और पुरोहित पर होने वाला व्यय एवं कर्मकांड की वीडियो क्लीपिंग, फाटोग्राफ सभी श्रद्धालु को पिंडदान के बाद उपलब्ध कराए जाएंगे।

पर्यटन विभाग के ई-पिंडदान पैकेज का गयापाल तीर्थ पुरोहित सही नहीं ठहरा रहे हैं। यहां बता दें कि परंपरा से चली आ रही पिंडदान के मूल में पुत्र को गयाजी आकर फल्गु में स्नान और विष्णुपद में पिंडदान ही फलदायी कहा गया है। ग्रंथों में भी यही बात कही गई है। लेकिन समय के साथ काफी बदलाव आया है।

नुसरत फतेह अली की कब्र की मिट्टी लेने पंजाब के मोगा आते हैं गायक

सत्येन ओझा, मोगा

सूफी शैली के प्रसिद्ध पाकिस्तानी कव्वाल नुसरत फतेह अली खान की कब्र की मिट्टी लेने के लिए गायक पंजाब के मोगा आते हैं। इस मिट्टी को गुरुओं का आशीर्वाद मानकर गायक सहेज कर रखते हैं। पार्श्व गायक लखविंदर वडाली और फिरोज खान भी नुसरत की कब्र की मिट्टी लेने के लिए मंगलवार को मोगा शहर के गुरुद्वारा जोहड़ के पास रहने वाले सोनू नुसरत के घर पहुंचे। यह कोई पहला मौका नहीं है जब प्रसिद्ध गायक सोनू के घर पहुंचकर नुसरत साहब की कब्र की मिट्टी लेने पहुंचे हों। गायक मास्टर सलीम और नूरां सिस्टर्स भी सोनू नुसरत से नुसरत फतेह अली खान की कब्र की मिट्टी ले जा चुके हैं।

दिल की धड़कन है गुरुओं का आशीर्वाद : गायक लखविंदर वडाली ने कहा कि नुसरत फतेह अली खान जैसे संगीतकार की मिट्टी को अपने साथ रखना उनके लिए सम्मान की बात है। यह मिट्टी हमेशा उन्हें जीवन में और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी। संगीत गुरुओं के प्रति ये सम्मान भाव ही है। गुरुओं का आशीर्वाद ही कलाकार के दिल की धड़कन होता है।

पाकिस्तान के फैसलाबाद में हैं कब्र : नुसरत फतेह अली खान की कब्र पाकिस्तान के फैसलाबाद शहर में है। उनकी कब्र पर अब टाइलें लग चुकी हैं। सोनू रावल उर्फ नुसरत कहते हैं कि उनकी कब्र की मिट्टी को वह उनके आशीर्वाद के रूप में अपने साथ रखते हैं। उन्हें यह मिट्टी 15 साल पहले भारत आए उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के भांजे रिजवान उज्जमा अली खान ने सौंपी थी। तब से उन्होंने इस मिट्टी को संभाल रखा है। जब भी गायक आते हैं तो वे इस मिट्टी का कुछ हिस्सा उन्हें सम्मान स्वरूप सौंप देते हैं।



सोनू के घर उस्ताद नुसरत की मिट्टी लेने पहुंचे पार्श्व गायक फिरोजखान। जागरण

- मोगा के सोनू को 15 साल पहले नुसरत फतेह अली खान के भांजे ने सौंपी थी कब्र की मिट्टी



सूफी गायक नुसरत फतेह अली खां की कब्र की मिट्टी लेने पहुंचे लखबिंदर वडाली। जागरण

नुसरत के पहले से लेकर अंतिम गाने का रिकॉर्ड है सोनू के पास : सोनू नुसरत उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की गायकी के बचपन से शौकीन हैं। उनके पास नुसरत फतेह अली खां के पहले गाने से लेकर अंतिम गाने तक का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। नुसरत के जीवन से जुड़े कई दिलचस्प किस्सों का इतिहास भी सोनू ने संभाल रखा है। संगीत के माहौल में पले बढ़े सोनू की बहन राखी रावल रामगढ़िया गर्ल्स कॉलेज लुधियाना में संगीत लेक्चरर हैं।

गुमनाम अनीता को 'कौशल' ने दिलाया मुकाम और नाम



पटना जिले के नौबतपुर की अनीता। फाइल

नीरज कुमार, पटना

- यूनेस्को की वेबसाइट पर दुनियाभर में पढ़ी जा रही उनके संघर्ष की गाथा
- गांव की गलियों से निकल पीएम के सपने को साकार करने में जुटी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कौशल विकास योजना लोगों को गुमनामी के अंधेरे से निकाल संबल प्रदान कर रही है। अंतरराष्ट्रीय संस्था यूनेस्को (यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन) भी उन्हें रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रही है। बिहार की अनीता इसका उदाहरण है।

पटना जिले के नौबतपुर की अनीता की शादी 2012 में हुई। तब वह इंटर की पढ़ाई कर रही थी। शादी की पांचवीं सालगिरह के पहले ही पति को ब्रेन हेमरेज हो गया। पति के इलाज में काफी पैसा खर्च होने के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। दो बच्चों के साथ अनीता का गुजारा मुश्किल हो गया था। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। तानों के कारण ससुराल में रहना मुश्किल होने लगा। माता-पिता उसे घर ले आए। इलाज कराया। अनीता ने माता-पिता के सहयोग से अपने पैरों पर खड़े होने का निर्णय लिया।

ऐसे मिला मुकाम : अनीता के माता-पिता को पटना में आइसीआइसीआइ एकेडमी फॉर स्किल्स का पता चला। यहां सेल्स एवं मार्केटिंग का मुफ्त प्रशिक्षण मिलता है। परिजनों ने उसका नामांकन करा दिया। यहां उसे 72 दिनों का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान पूरी लगन से कड़ी मेहनत की। प्रशिक्षण के दौरान उसे अंग्रेजी में बात करने, कस्टमर डीलिंग, प्रोडक्ट, टॉप टेन टेबल आदि की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद रिलायंस ट्रेंड में उसे जॉब भी मिल गया।

फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वह समाज कल्याण विभाग में पर्यवेक्षिका है, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का जिम्मा उठा रही है।

बनी रोल मॉडल

उसकी सफलता की कहानी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम तक पहुंची। निगम ने अनीता की कहानी को चयनित कर यूनेस्को भेजा। यूनेस्को ने संघर्ष से मिली उसकी सफलता को अपनी वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दुनियाभर के लोग इसे पढ़कर प्रेरित हो रहे हैं। अनीता इस उपलब्धि पर खुशी जताती है और महिलाओं को संघर्ष के आगे घुटने न टेकने की सलाह देती है।

फोटो न्यूज

जलवायु परिवर्तन और वनों के अंधाधुंध दोहन के प्रति दुनिया को आगाह करते हुए ऑस्ट्रिया के क्लगेनफर्ट में एक फुटबॉल स्टेडियम में जंगल उगाया गया है। यहां अब पेड़ों की सरसराहट ने रेफरी की सीटी की जगह ले ली है। 49 साल पुराने और 32 हजार की क्षमता वाले व्योर्दरसी स्टेडियम में 300 पेड़ लगाए गए हैं। यह पहल स्विट्जरलैंड के कलाकार क्लाउस लिटमैन ने की है। दरअसल उन्होंने ऑस्ट्रिया के ऑर्टिस्ट मैक्स पिंटनर की बहुचर्चित पेंसिल स्केच 'अनइंडिंग अट्रेक्शन ऑफ नेचर' को जीवंत किया है। इस स्केच में मैक्स पिंटनर ने वनों के अतिरिक्त दोहन पर आगाह करते हुए फुटबॉल मैदान में पेड़ों की कल्पना की थी। आठ सितंबर से 27 अक्टूबर तक यह स्टेडियम जनता के लिए खुला रहेगा। इसमें आने वालों से किराया भी वसूल किया जाएगा। इस स्टेडियम ने यूरोपियन फुटबॉल प्रतियोगिता 2008 के कुछ मैचों की मेजबानी की थी। एएफपी

49 साल पुराने स्टेडियम को पर्यावरण के प्रति आगाह करते हुए जंगल में तब्दील किया गया है

300 पेड़ लगाए गए हैं विभिन्न प्रजातियों के ऑस्ट्रिया के इस स्टेडियम में, दर्शकों के लिए खुले दरवाजे



मैक्स पिंटनर के साथ क्लाउस लिटमैन।



देश में खेतों से तेजी से हो रहा मिट्टी का कटाव

सुमन सेमवाल, देहरादून

- मिट्टी कटाव की दर प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष 40 टन
- कटाव के कारण घट रही मिट्टी की उर्वरा क्षमता
- वन क्षेत्रों में हालात बेहतर, जितनी मिट्टी नष्ट हो रही, उससे अधिक है वनने की दर

देश के खेतों के लिए अच्छी खबर नहीं है। अन्न उगलते खेतों से उपजाऊ मिट्टी का तेजी से क्षरण (कटाव) हो रहा है। गंभीर यह है कि हर साल खेतों व आग लगे जंगलों में जितनी मिट्टी का निर्माण होता है, उससे करीब साढ़े तीन गुना ज्यादा मिट्टी खेतों से बाहर चली जा रही है। यह चौंकाने वाला राजफाश किया है भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान ने। संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. डी मंडल ने 'साइंस ऑफ हिमालयाज' कार्यक्रम में इस अध्ययन को साझा किया। डॉ. डी मंडल ने बताया कि देश के खातों में प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष औसतन 40 टन मिट्टी का कटाव हो रहा है। वहीं, मिट्टी के बनने की यह दर सालाना प्रति हेक्टेयर 12.5 टन ही है। यह स्थिति इतनी भयावह है कि भविष्य में खेतों की उर्वरा क्षमता को घातक रूप से प्रभावित कर सकती है। इससे इतर वन क्षेत्रों, जहां वनस्पति अच्छी मात्रा में हैं, वहां मिट्टी के बनने की दर क्षरण से अधिक पाई गई। उन्होंने बताया कि ऐसे वन क्षेत्रों में एक टन से भी कम मिट्टी का क्षरण हो रहा है, जबकि इसके बनने की दर 2.5 टन तक है।

30 हजार करोड़ के खाद्यान्न का नुकसान : भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. डी मंडल ने बताया कि खेतों की मिट्टी के क्षरण का सीधा असर खाद्यान्न की पैदावार पर पड़ रहा है। कुछ समय पहले के आंकड़ों के अनुसार इससे 30 हजार करोड़ रुपये के अनाज, तिलहन व दलहन कम पैदा हो रही है।

मिट्टी में लॉक कार्बन भी वातावरण में मिल रहा : संस्थान के वैज्ञानिक ने बताया कि विश्वभर की मिट्टी में एक मीटर की गहराई तक 200 गीगाटन कार्बन है। इसी के अनुरूप जैसे-जैसे यह मिट्टी कटती रहती है, उससे कार्बन भी मुक्त होकर वातावरण में मिल जाता है।

चीन से सीख लेने पर दिया बल : वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. मंडल ने चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी मिट्टी कटान की यह स्थिति थी, मगर वर्ष 1999 में यलो रिवर वैली में शुरू किए गए संरक्षण के प्रयास से उन्होंने 2012 तक 100 फीसद लक्ष्य को हासिल कर लिया। उन्होंने सीधी रणनीति बनाई कि जहां मिट्टी का कटान अधिक है, वहां किसी भी तरह की वनस्पति को हानि न पहुंचाई जाए। न ही ऐसे क्षेत्रों में खेती के लिए अनुमति दी गई। इससे जो किसान प्रभावित हुए, उन्हें अन्यत्र से अनाज आदि देकर उसकी भरपाई कर दी गई।



प्रतीकात्मक

इस तरह रोका जा सकता है मिट्टी का कटाव

- धरातल पर अधिक से अधिक वनस्पतियां होनी चाहिए। खासकर खेतों के ऊपरी क्षेत्रों में इसका ख्याल रखा जाए।
- किसी भी क्षेत्र में पानी का वेग अधिक होगा तो वह मिट्टी का अधिक कटान करेगा।
- खेतों के बाहरी किनारों पर मिट्टी को पकड़े रखने वाली फसल लगाई जानी चाहिए।
- फसलों के चक्रानुक्रम का ध्यान अवश्य रखा जाए।
- जिन क्षेत्रों में जल संरक्षण के कार्य होने चाहिए, सिर्फ वहीं स्रोतों को विकसित किया जाए।

बेहद पौष्टिक होता है सरसों का साग



सर्दियों में सरसों के साग का सेवन न केवल स्वाद के मामले में लज्जतदार है बल्कि सेहत से जुड़े कई फायदों से भी भरा है। इसमें मौजूद विटामिन्स, मिनिरल्स, फाइबर और प्रोटीन इसे बेहद फायदेमंद बनाते हैं। पूरे भारत में, खासकर पंजाब में तो यह मक्के की रोटी के साथ बहुत ही चाव से खाया जाता है। ये सर्दी-जुकाम से लेकर हृदय रोगों और कैंसर के खतरे तक को भी कम करता है।

पौष्टिक तत्वों से भरपूर

डाइटिशियन मोनिशा सिक्का के अनुसार सौ ग्राम साग से हमें 30.35 कैलोरी एनर्जी मिलती है। इसके साथ ही कार्बोहाइड्रेट 2.41 ग्राम, कैल्शियम 191 मिलीग्राम, जिंक 0.68 मिली ग्राम, विटामिन सी 60.32 मिली ग्राम, आयरन 2.84 मिलीग्राम, प्रोटिन 3.52 ग्राम, टोटल फैट 0.51 ग्राम, फासफोरस 71.62 मिलीग्राम, बीटा कैरोटिन 2619 आइयू, विटामिन बी9 110 मिलीग्राम मात्रा में पाए जाते हैं।

(जालंधर से जगदीश कुमार का इनपुट)

मिट्टी की हांडी में बनता था स्वादिष्ट साग

किसी समय कच्ची मिट्टी के बने चूल्हे में लकड़ी की आंच पर मिट्टी की हांडी में सरसों का साग बनाया जाता था। समय में तेजी से बदलाव और मिट्टी हांडी, कच्चे चूल्हे व लकड़ी की आंच का प्रचलन तकरीबन खत्म हो गया। अब तो गैस पर कुकर में बने सागे का वो पुराना स्वाद नहीं रहा। महिलाएं भी अब सरसों का साग बनाने में अधिक समय लगने की वजह से कतराती हैं।



सरसों का साग पौष्टिक गुणों का खजाना है। इसके सेवन से अच्छी खासी एनर्जी शरीर को मिलती है। इसके सेवन से शरीर में खून व कैल्शियम की कमी दूर होती है। यह लीवर और खून की सफाई करता है। हाई फाइबर युक्त होने की वजह से पेट को भी ठीक रखता है। बढ़े कोलेस्ट्रॉल वाले मरीजों के लिए यह लाभदायक है।

डॉ. कपिल गुप्ता, सदस्य पंजाब मेडिकल काउंसिल

रोगों को रखता है दूर

- सरसों के साग में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। इसके सेवन से ब्लैडर, पेट, ब्रेस्ट, फेफड़े, प्रोस्टेट और ओवरी के कैंसर से बचाव में मदद मिलती है।
- इसके सेवन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर घटता है।



- इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जो शरीर की मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रित रखने में मदद करता है। इसके सेवन से पाचन ठीक रहता है।
- इसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। यह हड्डियों से जुड़े रोगों के उपचार में भी फायदेमंद माना जाता है।
- इसमें विटामिन ए अच्छी मात्रा में होता है, जो आंखों की मासंपेशियों को किसी भी तरह की क्षति से बचाता है और आंखों की रोशनी बढ़ाता है।

1047 महिलाएं हैं केरल में प्रति हजार पुरुषों में। केरल लिंगानुपात में भारत का सबसे अच्छी स्थिति वाला राज्य है। वहीं, सबसे ज्यादा खराब हालात सिक्किम के हैं यहां हजार पुरुषों में केवल 809 महिलाएं हैं।

मूंज से लिख रहीं ग्राम्य स्वावलंबन की सुंदर पटकथा

प्रयागराज के कई गांवों में बड़े पैमाने पर हो रहा मूंज से उपयोगी उत्पाद बनाने का काम, सुधर रही आर्थिक हालत

राजकुमार श्रीवास्तव, प्रयागराज

प्रयागराज, उप्र के कई गांवों में मूंज उत्पादों का निर्माण कुटीर उद्योग की शक्ल ले चुका है। ग्रामीण महिलाओं द्वारा मूंज से तैयार किए गए सुंदर उपयोगी सामान देश के बड़े शहरों तक पहुंच रहे हैं। उप्र सरकार की एक जनपद एक उत्पाद (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी) योजना में मूंज शिल्प के शामिल हो जाने से इस विधा से जुड़े परिवारों में नई उम्मीद जग गई है। खास तौर पर महिलाओं के लिए यह अपने पैरों पर खड़े होने का बड़ा जरिया बनने लगा है।

जनसंख्या नियोजन

प्रयागराज के नैनी क्षेत्र में मौजूद कई गांवों में महिलाएं घर बैठे मूंज के खूबसूरत उत्पाद बना रही हैं। अभी तक उनके उत्पाद की बिक्री स्थानीय बाजार में होती थी। लेकिन अब बड़ा बाजार उपलब्ध होने लगा है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार की कोशिश पर खुलने वाले कॉमन फैसिलिटी सेंटर और शोरूम से उनकी जिंदगी बदल जाएगी।

नैनी क्षेत्र के मड़ौका, पिपरसा, इंदलपुर, डांडी, महेवा पूरब पट्टी और महेवा पश्चिम पट्टी, भड़ए समेत कई गांवों में महिलाएं मूंज से ब्रेड बॉक्स से लेकर तरह-तरह के



उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मूंज से टोकरी बनाती महिला। जागरण

सजावटी सामान तैयार करती हैं। पहले इन्हें अपने सामानों को बेचने के लिए शहर में चौक और कोतवाली का बाजार ही उपलब्ध था। लेकिन जब से मूंज ओडीओपी में शामिल हुआ है, तब से इन्होंने सरकार की कोशिशों के बीच अपने कार्य और हुनर का दायरा बढ़ाया है। पिकनिक बैग के लिए जनवरी 2019 में राज्य पुरस्कार पा चुकीं महेवा पूरब पट्टी की फिरोजा बेगम बताती हैं कि बाहरी जिलों के व्यापारी थोक में आर्डर देते हैं, जिसमें ज्यादा मुनाफा मिल जाता है। मुरादाबाद के एक कारोबारी ने 90 हजार का आर्डर दिया, लेकिन समय के अंदर 50 हजार का ही सामान दे पाए। सबीना, शहाना और तनीजा बताती हैं कि शादी-विवाह और त्योहार के समय महीने की बिक्री 20-25 हजार रुपये तक हो जाती है। मूंज से झोले, टोकरी, ब्रेड बॉक्स, फ्लावर पॉट, पर्स, नाइट लैंप, वॉल हैंगिंग, पेपरवेट, पेन होल्डर, टी-कोस्टर एवं अन्य घरेलू सजावटी सामान तैयार हो रहे हैं।

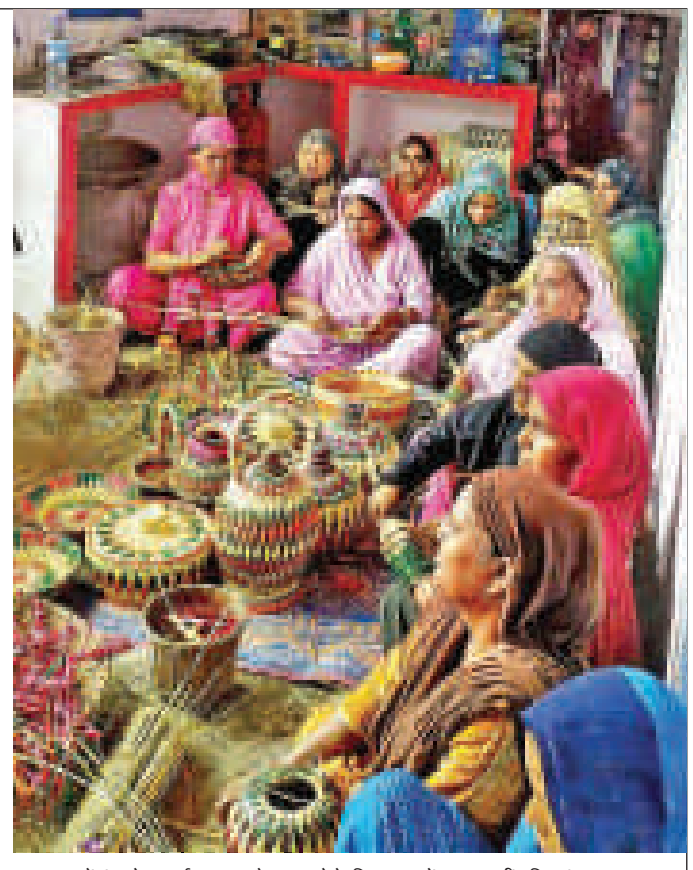
- कुटीर उद्योग की शक्ल ले चुका है मूंज उत्पादों का कारोबार, देश के बड़े शहरों तक हो रही आपूर्ति
- एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत ग्रामीण उद्यमिता को दिया जा रहा है बढ़ावा

मूंज से बनी सामग्रियों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार शोरूम खोलने पर लोन और उस पर सब्सिडी दे रही है। इस कारोबार से जुड़े लोग खुद शोरूम खोल सकते हैं। इसमें ऐसे लोगों को शोरूम खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो सक्षम हैं। उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी नैनी क्षेत्र में जल्द स्थापित होगा।

- अजय कुमार चौरसिया, उपायुक्त उद्योग, प्रयागराज, उप्र

क्या है एक जनपद एक उत्पाद : यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य राज्य की उन विशिष्ट शिल्प कलाओं और उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाना है, जो देश में कहीं और उपलब्ध नहीं हैं। जैसे प्राचीन एवं पौष्टिक कालानमक चावल, दुर्लभ गेहूं डंठल शिल्प, विश्व प्रसिद्ध चिकनकारी, कपड़ों पर जरी-जरदोजी का काम, मृत पशु से प्राप्त सींगों व हड्डियों से अति जटिल शिल्प कार्य जो हाथी दांत का विकल्प है... इत्यादि। इनमें से बहुत से उत्पाद जीआइ टैग (भौगोलिक पहचान पट्टिका धारक) हैं। ये वे उत्पाद हैं, जिनसे स्थान विशेष की पहचान होती है।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news



प्रयागराज में मूंज से आकर्षक उत्पाद तैयार करने के लिए समूह में काम करतीं महिलाएं। जागरण

काश! मैंने दिखाई होती समझदारी तो आज होश में होता बेटा

जरा देख के चलो...

- हेलमेट न लगाने पर बेटा पांच साल से कोमा में, पिता ने गंवाए दो करोड़
- 14 साल के बेटे को दे रखी थी बाइक चलाने की छूट, हेलमेट पर भी नहीं देते थे ध्यान, सड़क हादसे का शिकार हो गया बेटा



घर में मारूफ की सेवा करते उनके पिता मकसूद। जागरण

मुस्लेमीन, रामपुर

हेलमेट पहनकर या सीट बेल्ट बांधकर वाहन चलाना आपकी अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, न कि पुलिस के लिए। यातायात पुलिस चालान इसीलिए काटती है ताकि आप अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत रहें। जुर्माना कई गुणा बढ़ाने के पीछे भी यही मंशा है। ताकि आपको अपनी लापरवाही की इससे कहीं बड़ी कीमत न चुकानी पड़ जाए।

ऐसी ही एक लापरवाही ने रामपुर, उप्र निवासी रुखसाना की जिंदगी को नासूर बना दिया है। दरअसल, 27 नवंबर 2014 को उनका 14 साल का बेटा मारूफ सड़क हादसे का शिकार हो गया था। कक्षा नौ का छात्र था। अभिभावक ने उसे इतनी कमउम्र में भी बाइक चलाने की अनुमति दे रखी थी। यही नहीं, हेलमेट लगाने के लिए भी हिदायत नहीं दी थी। मारूफ बिना हेलमेट लगाए बाइक से कहीं जा रहा था। बाइक फिसल गई। मारूफ का सिर डिवाइडर से टकरा गया। गंभीर चोट आई। मुरादाबाद के अस्पताल में फायदा नहीं होने पर उसे दिल्ली के फोर्टिस अस?पताल में ले जाया गया। जहां वह 70 दिन तक आइसीयू में रहा। इसके बाद आज वह जिंदा तो है लेकिन होश में नहीं है, कोमा में है। पांच साल से वह बिस्तर पर है, न कुछ बोल सकता है और न ही हिल सकता है। मां रुखसाना और पिता मकसूद पांच साल से उसकी सेवा में लगे हैं। अब तक उसके खर्च पर दो करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हो चुका है। इसके बाद भी पांच से उनके बेटे के शरीर में कोई हलचल नहीं होने का दर्द जो रुखसाना और मकसूद के सीने में है, उसे वही समझ सकते हैं। पर



14 साल के मारूफ की फाइल फोटो।

एक उम्मीद है कि बेटे को होश आएगा। इसी के सहारे उसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ रहे।

पापा को है मलाल : मारूफ पिछले पांच साल से खामोश है। बेड पर ही वह जवान हो गया है। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, तब उसका चेहरा साफ था, लेकिन अब दाढ़ी-मूछ भी निकल आई हैं। उसके पापा मकसूद को इस बात का अफसोस है कि उन्होंने बेटे को बाइक चलाने की अनुमति क्यों दी। उसकी तो बाइक चलाने की उम्र भी नहीं थी। उन्हें इस बात का भी मलाल है कि बेटा हेलमेट लगाए होता तो सिर में चोट नहीं लगती। अब वह दूसरों को नसीहत देते हैं कि कमउम्र बच्चों को वाहन न चलाने दें। हेलमेट या सीट बेल्ट का इस्तेमाल वाहन चलाते समय अवश्य करें और यातायात नियमों का पूरी तरह पालन करें।

शराब भट्ठियों के लिए बदनाम गांव की बदली पहचान

नई तस्वीर ▶ उप्र के अलीगढ़ के गांव मिरगौला में बीते 70 साल से अवैध शराब का धंधा कर रहे थे 50 परिवार

जागरण विशेष

सभी की सहमति के चलते गांव में कार्रवाई करना पुलिस के लिए नहीं होता था आसान

राहुल वार्ष्णेय, अलीगढ़

अलीगढ़, उप्र का गांव मिरगौला अवैध शराब कारोबार के लिए बदनाम था। करीब 50 परिवार बीते 70 साल से अवैध शराब बना और बेच रहे थे। लेकिन अब सभी ने इससे तौबा कर ली है। गांव नशा-मुक्ति की ओर बढ़ चला है। इस बदलाव की वजह बना एक थप्पड़।

अलीगढ़ जिले के गंगीरी क्षेत्र स्थित मिरगौला की तस्वीर ही बदल गई। जुआ और शराब के लिए पूरे क्षेत्र में बदनाम रहा यह गांव अब अनुकरणीय उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है। गांव में 200 परिवार रहते हैं। आजादी के वक्त से ही यहां अवैध शराब के धंधे का चलन था। एक चौथाई परिवार शराब के काम से जुड़े थे। गांव में कार्रवाई करना पुलिस के लिए आसान नहीं होता था। यदि कभी काम रुकवाती तो कुछ ही दिन असर होता। दिनभर माफिया दबंगई करते थे। सस्ती शराब खरीदने के लिए आसपास के गांवों के लोगों की भीड़ लगी रहती। शाम होने के बाद गलियों में नशे में धुत लोगों का उपद्रव शुरू हो जाता था। इस बीच, तीन दिसंबर 2018 को एक घटना घटी। नशे में धुत एक शराब माफिया ने ग्रेजुएशन कर रहे गांव के युवक नरेंद्र कुमार को थप्पड़ मार दिया। यह गांव के पढ़े-लिखे अन्य युवाओं को नागवार गुजरा। सब एकजुट होने लगे। रात होने से पहले ही तय कर लिया कि अब गांव में नशे का खेल खत्म कर दिया जाएगा। फैसले पर अमल को तुरंत 25 युवाओं की टीम बना दी, जिसने घर-घर जाकर शराब से दूर रहने का आग्रह किया। बुजुर्गों से मशविरा कर पांच दिसंबर को पंचायत की गई, जिसमें शराबबंदी का प्रस्ताव पारित हो गया। पंचायत में शराब पीने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना और भट्ठी चलाने पर बहिष्कार की बात तय हुई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से भी प्रस्ताव पर सहमति की मुहर लगवा ली गई।



उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के गांव मिरगौला में शराबबंदी को लेकर बैठक करते ग्रामीण। जागरण

इसके बाद शराब के खिलाफ मुहिम छेड़ दी गई, जिसमें महिलाएं भी शामिल हुईं। अगले ही दिन से कच्ची शराब बनाने वाले ठिकानों पर रात में पहरेदारी शुरू कर दी गई। शराब पीकर आने वाले लोगों को गांव में प्रवेश करने से रोकना शुरू कर दिया। कोई विरोध करता तो सभी एकजुट होकर उसे समझाते। न मानने पर छह लोगों को तो पुलिस के हवाले कर दिया गया। दो लोगों पर जुर्माना लगाया, पर शराब न पीने की शर्त पर माफ कर दिया गया। गांव के बदले माहौल में भट्ठी चलाने की तो किसी ने हिम्मत ही नहीं की। धीरे-धीरे शराब के कारोबार से लोग पीछे हट गए। गांव की ब्रजेश कुमारी बताती हैं कि पहले बाहर निकलना तक दूभर था। अब राहत है।

सुधर रही सेहत : शराब के धंधे से जुड़े लोगों पर पहले आसानी से पैसा आता था, अब अधिकांश मजदूरी व खेती करके ही खुश हैं। सेहत और परिवार की दशा भी सुधर रही है। किसान ओमवीर सिंह ने बताया कि बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में गांव के लोग सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए गांव में हर माह बैठक होती है, जिसमें शिकायतों का भी निस्तारण मिलकर किया जाता है। युवाओं ने गांव में मुफ्त कोचिंग भी शुरू की है। इसमें गरीब परिवारों के 25 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है।

युवाओं की तारीफ करते हुए कहते हैं, इनकी इस मुहिम में पुलिस शुरू से ही साथ है। यह अन्य गांवों के लिए नजीर है। आसपास के गांव के लोगों को इससे सीख लेने की सलाह दी जा रही है।

- मणिलाल पाटीदार, पुलिस निरीक्षक, अलीगढ़ देहात

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

उप्र के प्रयागराज में टीले में दफन लाक्षागृह का खुल सकता है राज

ज्ञानेन्द्र सिंह, प्रयागराज

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के हंडिया में गंगा किनारे मिट्टी के टीले में दफन लाक्षागृह के राज से पर्दा उठ सकता है। यहां फिर पुरातात्विक महत्व के अवशेष मिलने लगे हैं। हाल ही में बारिश की वजह से प्राचीन टीले की एक दीवार ढहने के बाद उसमें पत्थर की पक्की नाली दिखाई दी।

प्रयागराज शहर से लगभग 40 किमी दूर हंडिया में गंगा किनारे स्थित किला कोट की मान्यता महाभारत कालीन लाक्षागृह के रूप में रही है। इतिहासकार व पुरातत्वविद भी इससे इन्कार नहीं करते। यहां 2001-02 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खोदाई कराई थी। क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी सुभाष यादव बताते हैं कि लगभग दो वर्षों तक हुई खोदाई के दौरान ईसा पूर्व की छठी शताब्दी से मध्यकाल में 15वीं व 16वीं शताब्दी तक के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। मतलब लगभग 24 सौ वर्षों के पुरातात्विक अवशेष मिले, जिन्हें संरक्षित किया गया है। यहां प्राचीन बस्ती और उस काल की सभ्यता के प्रमाण मिल चुके हैं। एक ऐसी गुफा भी मिली है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे निकलकर पांडवों ने अपनी जान बचाई थी। माना जाता है कि दुर्योधन ने पांडवों को जिंदा जला देने के लिए ही लाक्षागृह



हंडिया के लाक्षागृह किला कोट टीला की प्राचीन दीवार गिरने से दिखी पक्की नाली। जागरण

बनवाया था। हाल ही में बारिश के दौरान किला कोट के उत्तर में विद्यासागर वर्मा के घर के पीछे ईंट व मिट्टी की एक प्राचीन दीवार में पत्थर की नाली दिखाई दी।

नाली लगभग चार फीट तक दीवार के अंदर है। पत्थर पर नक्काशी होने से इसके प्राचीन होने का अनुमान है। इसे छोटी सुरंग माना जा रहा है। इसका छोर कहां खत्म होता है, यह जानने की उत्सुकता है। मंगलवार को भी इसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते रहे। अब पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यहां फिर अन्वेषण कार्य शुरू कर सकता है। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी का कहना है कि आवश्यकता पड़ी तो दोबारा खोदाई कराई जाएगी।

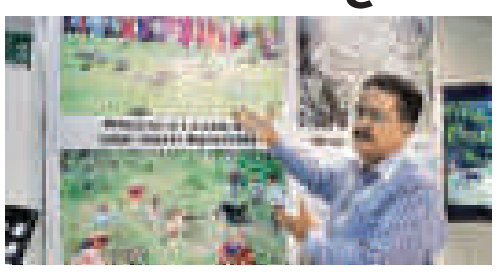
हरियाली चाहिए तो रोपण से पहले जानें बीच की जानकारी और पौधे की प्रकृति

मनीष तिवारी, ग्रेटर नोएडा

वनाच्छादित राष्ट्रों की श्रेणी में भारत दसवें पायदान पर है। देश में वन क्षेत्र लगभग 24 फीसद है। वन क्षेत्र बढ़ाने की दिशा में सरकार, संगठन व आम लोगों के द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में पौधे लगाए जाते हैं। इस वर्ष अकेले उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित कर पौधे लगाए। पौधे लगाना ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उसकी प्रकृति, प्राकृतिक वास, समुद्रतल से ऊंचाई, बीज पकने का समय आदि चीजों की जानकारी भी आवश्यक है। इंडिया एक्सपो मार्ट में चल रहे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कॉप-14 में वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी विस्तृत जानकारी लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। विदेशी प्रतिनिधियों के द्वारा अहम जानकारी को जुटाया जा रहा है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. सुबोध ऐरी का कहना है कि पर्यावरण अभियान के तहत पौधे लगा इतिश्री कर ली जाती है। पौधे की प्रकृति व

- सर्वे के बाद गोविंद बल्लभ पंत संस्थान ने तैयार की है विभिन्न प्रजाति के पौधों की प्रकृति
- पौधा रोपण अभियान में नहीं रखा जाता पौधे की प्रकृति का ध्यान



पौधरोपण के बारे में जानकारी देते वेज्ञानिक डॉ. सुबोध ऐरी। जागरण

लगाने के सही तरीके का पालन न होने से पचास फीसद तक पौधे सूख जाते हैं। संस्थान द्वारा लंबे समय तक किए गए मंथन के बाद विभिन्न प्रजाति के पौधों की प्रकृति को समझा गया। उन्होंने बताया हर पौधे के लिए अलग-अलग जलवायु अनुकूल होती है। उसे जानने के बाद पौधे लगाए जाने चाहिए। पौधे लगाने के लिए गड्ढा एक माह पूर्व खोदा जाना चाहिए। गड्ढा कम से कम डेढ़ फीट गहरा व एक फीट चौड़ा होना आवश्यक है। अमूमन दो पौधों के बीच तीन से पांच मीटर की दूरी रखनी चाहिए। गड्ढे में गोबर की सड़ी खाद व सूखी पत्तियां डालनी चाहिए। इससे गड्ढे के नीचे नमी बनी रहती है। साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। पौधा लगाने के दौरान मिट्टी व गोबर की खाद मिलाकर डालना चाहिए। पाया जाता है कि पौधे लगाने के बाद लोग उन्हें छोड़ देते हैं। देखभाल न होने से पौधे दम तोड़ देते हैं। पौधों को जिंदा रखने के लिए समय-समय पर मिट्टी की निराई-गुड़ाई करें, समय-समय पर खाद दें व तब तक पौधों को समय-समय पर पानी दें जब तक कि पौधों की जड़ों का विकास इतना न हो जाए कि वह अपनी जरूरत के अनुसार पानी की व्यवस्था स्वयं न कर लें। उन्होंने बताया सर्वे के बाद बड़ी संख्या में सरकारी महकमों ने इस पर अमल शुरू किया है।

तहकीकात

अवैध हथियार से निकली गोली ने ली एक मासूम की जिंदगी, बच्चे की मौत ने राज उगले तो ठग की प्रेमिका ने दे दी जान, प्रेमिका की मौत से टूट गए अपराधी ने खुद भी खाया जहर

झारखंड के इस साइबर ठग को जिंदगी ने कुछ ऐसे ठगा

अश्विनी रघुवंशी, धनबाद

झारखंड के धनबाद में एक साइबर ठग को जिंदगी ने कुछ ऐसे ठगा कि वह जिंदा तो है, मगर मायूसी के सिवा उसके पास कुछ नहीं बचा है। अपराध की बुनियाद पर खुशहाल जिंदगी की इमारत को बुलंद करने की उसकी ख्वाहिश ने एक मासूम को बेमौत मार दिया। बच्चे की मौत ने राज उगले तो उसकी मुहब्बत उससे छिन गई। प्रेमिका की मौत से टूट गए ठन ने भी जान देने की कोशिश की, मगर बच गया। किसी ने सच ही कहा है कि अपराध का रास्ता भले ही चकाचौंध से भरा हो, मगर वह अंधेरों में जाकर ही खत्म होता है। ऐसा ही हुआ है मनोज चौहान के साथ। अब वह सलाखों के पीछे है।

धनबाद के खास सिजुआ में रहने वाला कारू रजवार कोयला ढोकर दो वक्त की रोटी जुटाता है। उसका एक ही बेटा था आर्यन। कक्षा दो में पढ़ता था। हमेशा उसकी खिलखिलाहट मोहल्ले में गूंजती रहती थी। 16 अगस्त को उसकी मौत हो गई। पुलिस तक मामला पहुंचा तो उसने पड़ताल शुरू की। इस दौरान उसे बताया गया कि किसी नुकीली वस्तु के लगने से उसकी मौत हो गई है। तेतुलमारी पुलिस ने बारीकी से पड़ताल की तो कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आईं। इस दौरान पता चला कि नुकीली वस्तु से नहीं बल्कि गोली लगने से मौत हुई है। इसके बाद पुलिस के कान खड़े हो गए। उसने पड़ताल का एंगल बदल दिया। इस दौरान आर्यन के फुफेरे भाई राजेश ने पुलिस को पड़ोस में रहने वाले साइबर अपराधी मनोज और उसके अवैध हथियारों के बारे में जानकारी दी। उसने बताया कि मनोज एक साइबर अपराधी है, जिसने न जाने कितने लोगों को ठगा है। अपराधिक प्रवृत्ति का मनोज अवैध हथियार भी रखता था, मगर अपने घर के बजाय आर्यन के घर में। प्रतिदिन की तरह 16 अगस्त को आर्यन स्कूल से लौटा तो उसके साथ कुछ साथी भी थे। मनोज का काला बैग घर में पड़ा था। वह खेल-खेल में उसे उठा लाया। आर्यन ने पिस्टल देखी तो बैग से निकाल ली। इसी बीच अचानक तेज आवाज के साथ गोली निकली और उसके चेहरे में जा धसी।

यह पता होने के बाद पुलिस की पड़ताल की दिशा बदल दी। इस दौरान आर्यन के घर में पुलिस को साइबर अपराध में प्रयोग होने वाले कुछ उपकरण भी मिले। पुलिस ने मनोज की कॉल



जेल जाने के पहले अस्पताल में उपचाराधीन मनोज चौहान। जागरण



नेहा की फाइल फोटो।

डिटेल खंगाली तो चौंक गई। आर्यन की मौत के दिन मनोज ने पड़ोस के किराना दुकानदार अनिल बर्णवाल के मोबाइल पर नौ बार बात की थी। पुलिस ने अनिल से पूछताछ की तो उसने बताया कि मनोज से उसकी बात नहीं हुई है। कॉल डिटेल की जानकारी देने पर अनिल का जवाब था कि शायद घर वालों से बात हुई हो। अनिल ने घर आकर कॉल डिटेल के बारे में पत्नी और बेटी से पूछताछ की। इसके अगले दिन पुलिस अनिल की पत्नी और बेटी को थाने लाने के लिए पहुंची तो बेटी नेहा ने पुलिस वालों को देख खुद को कमरे में बंद कर लिया और फंदे पर झूल गई। नेहा की अर्थी सज ही रही थी कि मनोज चौहान के घर से रोने की आवाज आई। हल्ला हुआ कि मनोज ने गया (बिहार) स्थित पैतृक गांव में जहर खा लिया है। पुलिस को यकीन हो गया था कि नेहा और मनोज

आर्यन की मौत के लिए साइबर अपराधी मनोज चौहान जिम्मेदार है। उसके कारण दो जानें गईं। मनोज को कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी।

- किशोर कौशल, एसएसपी, धनबाद

के बीच कुछ है। शायद मोहब्बत। शादीशुदा मनोज से मोहब्बत का पर्दाफाश होने के डर से ही नेहा ने जान दे दी। उसकी अर्थी उठी तो मनोज टूट गया। यही वजह है कि उसने जहर खा लिया। गया में इलाज के बाद धनबाद पुलिस ने जब उससे बात की तो उसने बताया कि आर्यन को जब गोली लगी तो वह तड़प उठा। आर्यन के दोस्त डर कर भाग गए और गली में आकर शोर मचाया। उस दौरान वह भी गली में ही था। भाग कर अंदर गया तो देखा आर्यन छटपटा रहा था। नुकीली चीज से आर्यन को लगी गोली निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह निष्प्राण हो चुका था। ऐसे में कमरे में ही बोरे के नीचे शव ढका और पिस्टल लेकर भाग निकला। बाद में प्रेमिका के भी आत्महत्या करने से मेरी दुनिया ही उजड़ गई। यही वजह है कि मैंने भी जहर खाकर खुद की जान देने की कोशिश की।

साइकिल से एशियाई देशों की यात्रा पर रवाना हुए प्रदीप

संवाद सूत्र, गरुड़ (बागेश्वर) : गिनीज बुक में नाम दर्ज करा चुके गरुड़ तहसील के रिठाड़ गांव निवासी प्रदीप राणा अब साइकिल से एशियाई देशों की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। 21 वर्षीय युवा प्रदीप राणा मंगलवार को एशियाई देशों नेपाल, वर्मा, भूटान, म्यामार, मलेशिया, सिंगापुर की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा की खास विशेषता यह है कि वह इन देशों का साइकिल से भ्रमण करेंगे। साइकिल से यात्रा करने का उनका उद्देश्य यह है कि इन देशों में जाकर लोगों को अमन, शांति व मजबूत लोकतंत्र का संदेश देंगे। प्रदीप ने अपनी यात्रा पूरी करने के लिए तीन माह का लक्ष्य रखा है। मंगलवार को गरुड़ के ऐतिहासिक गांधी चबूतरे पर विभिन्न संगठनों के लोगों ने प्रदीप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देहरादून से बीएससी आईटी कर चुके प्रदीप राणा इससे पहले 18700 किमी की यात्रा साइकिल से तय कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड बना चुके हैं। तीन साल पूर्व प्रदीप भारत के 22 राज्यों में साइकिल से भ्रमण कर चुके हैं।

यस बैंक में हिस्सेदारी खरीदने के प्रयास में पेटीएम

नई दिल्ली : डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम बैंकिंग सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए यस बैंक में हिस्सेदारी खरीदने के प्रयास में है। सूत्रों के मुताबिक यस बैंक के सहायक संस्थापक राना कपूर से कंपनी की बातचीत चल रही है। यस बैंक में राना कपूर की 9.6 परसेंट हिस्सेदारी है। यह समझौता आरबीआइ के अप्रूवल पर निर्भर करेगा। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा की पहले से पेटीएम पेमेंट बैंक में हिस्सेदारी है। (प्रेट्र)



वर्ष 2040 तक देश की ऊर्जा जरूरतें दोगुनी होने वाली हैं। हम इस स्तर की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने की दिशा में काम कर रहे हैं।
— धर्मेंद्र प्रधान, पेट्रोलियम मंत्री

राहत ▶ समझौते को सभी पक्षों के लिए समान रूप से लाभकारी बनाने पर होगा काम

एफटीए की समीक्षा पर बनी सहमति

अधिकारियों की समिति गठित करने का फैसला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारत की चिंताओं को देखते हुए आसियान देश मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की समीक्षा पर सहमत हो गए हैं। आसियान ने माना है कि आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए एफटीए को ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली बनाने की जरूरत है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह संगठन एक संयुक्त समिति बनाने को भी राजी हो गया है। थाइलैंड की राजधानी बैंकॉक में दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में एफटीए की समीक्षा को लेकर सहमति बनी। भारत की ओर से वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में समीक्षा की बात को शामिल किया गया।

बयान में कहा गया है कि इंडस्ट्री और बिजनेस समूहों के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी मंत्री इस बात पर सहमत हैं कि भारत और आसियान के बीच साल 2009 में हुए इस समझौते की समीक्षा की आवश्यकता है।



भारत ने मजबूती से रखा अपना पक्ष। प्रतीकात्मक

मंत्रियों ने अब इसकी जिम्मेदारी अधिकारी स्तर पर सौंप दी है जो अगली मंत्री स्तरीय बैठक से पूर्व समझौते की समीक्षा करेंगे और अपनी रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे। आसियान में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाइलैंड, फिलिपींस, लाओस और वियतनाम शामिल हैं। भारत और आसियान देशों के बीच 2018 में 80.8 अरब डॉलर का कारोबार हुआ जो साल 2017 में 73.6 अरब डॉलर का था।

एफटीए समीक्षा की जरूरत क्यों : विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों के चलते कस्टम ड्यूटी घटने से स्टील, पेट्रोकेमिकल्स, टैक्सटाइल जैसे उत्पादों का भारत में आयात काफी बढ़ गया, जिससे घरेलू इंडस्ट्री की परेशानियां बढ़ीं।

यह होगा फायदा

आसियान के साथ बनी इस सहमति के बाद इंडस्ट्री के कई वर्गों को राहत मिलने की उम्मीद बंधेगी

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से आ रहे टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेटल इंडस्ट्री के लिए ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव की उम्मीद की जा रही है

यह है संयुक्त बयान में

संयुक्त बयान के मुताबिक दोनों पक्षों को आसियान-भारत बिजनेस काउंसिल के सुझावों से भी मदद मिलेगी और इस समझौते को दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार को ज्यादा लाभकारी बनाया जा सकेगा

समझौते के मुताबिक दोनों पक्ष आपस में होने वाले कारोबार में ज्यादातर वस्तुओं पर समयबद्ध तरीके से ड्यूटी घटाने का एक कार्यक्रम निर्धारित कर सकते हैं।

भारत स्मार्टफोन निर्यातकों में हुआ शुमार

एक वर्ष में सात गुना बढ़ा निर्यात

हरिकिशन शर्मा, नई दिल्ली

- यूएई, रूस और चीन जैसे देशों को हो रहा भारत में मैन्युफैक्चर्ड स्मार्टफोन का निर्यात
- एक साल में स्मार्टफोन के निर्यात में 700 प्रतिशत की वृद्धि

मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम का असर दिखने लगा है। इस अभियान की शुरुआत के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का उत्पादन पांच साल में दोगुना हो गया है बल्कि भारत अब स्मार्टफोन के निर्यातक के रूप में उभर रहा है। भारत से स्मार्टफोन का निर्यात संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, रूस, दक्षिण अफ्रीका और चीन को हो रहा है। स्मार्टफोन के निर्यात में एक साल में 700 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की वार्षिक रिपोर्ट, 2018-19 में इसकी जानकारी देते हुए कहा गया है कि मेक इन इंडिया के साथ ही मोबाइल फोन हैंडसेट और कंपोनेंट्स मैन्यूफैक्चरिंग एक फ्लैगशिप सेक्टर के रूप में उभरा है। घरेलू मोबाइल फोन के उत्पादन की बदौलत मोबाइल फोन का आयात कम हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2017-18 में भारत से स्मार्ट फोन का निर्यात महज 20 करोड़ डॉलर मूल्य का था, जो वित्त वर्ष 2018-19 में बढ़कर 160 करोड़ डॉलर हो गया।

इस बीच वाणिज्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के शुरुआती चार महीनों (अप्रैल-जुलाई) के दौरान भारत से स्मार्टफोन का निर्यात एक अरब डॉलर के पार जा चुका है। माना जा रहा है कि वित्त वर्ष पूरा होने तक यह बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगा।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2014-15 में देश में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का उत्पादन 31.2 अरब डॉलर मूल्य का था जो वित्त वर्ष 2018-19 में बढ़कर 65.5 अरब डॉलर हो गया है। इसमें मोबाइल हैंडसेट की हिस्सेदारी 3.1 अरब डॉलर से बढ़कर 24.3 अरब डॉलर हो गई है। गौरतलब है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की मांग का सिर्फ एक-तिहाई ही घरेलू उत्पादन से पूरा कर पाता है। शेष मांग आयात के जरिये पूरी होती है।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का उत्पादन

प्रोडक्ट	2014-15	2018-19
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स	9.1	11.0
इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स	6.4	11.6
कंप्यूटर हार्डवेयर	3.1	3.0
मोबाइल फोन	3.1	24.3
स्ट्रैटिजिक इलेक्ट्रॉनिक्स	2.6	4.0
इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स	6.5	9.7
एलईडी	0.4	1.9
कुल	31.2	65.5

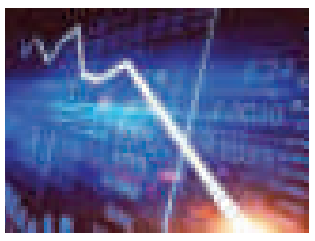
नोट : उत्पादन के आंकड़े अरब डॉलर में

देश के कुल आयात में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत के आस-पास है।

छोटे शेयरों का प्रदर्शन अब तक निराशाजनक

नई दिल्ली, प्रेट्र : चालू वित्त वर्ष में अब तक छोटो और मझोले स्तर के शेयरों ने निवेशकों को निराश किया है। अप्रैल के बाद से बीएसई के स्मॉल-कैप और मिड-कैप सूचकांक में 15.42 परसेंट तक की गिरावट दिख चुकी है। ब्लूचिप शेयरों की तुलना में इन कंपनियों के शेयर तेजी से फिसले हैं। विश्लेषकों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में बीएसई स्मॉल-कैप इंडेक्स में 2,317.4 अंक या 15.42 परसेंट की कमी दर्ज की गई। इसी दौरान मिड-कैप इंडेक्स 1,985 अंक या 12.82 परसेंट तक फिसल गया है।

हालांकि इसी अवधि में बीएसई के बेंचमार्क इंडेक्स यानी सेंसेक्स में स्मॉल या मिड-कैप जितनी निराशाजनक स्थिति नहीं रही। चालू वित्त वर्ष में अब तक 30 शेयरों वाले सेंसेक्स में 1,527.46 अंक यानी 3.94 परसेंट की ही गिरावट झलकी है। पिछले 23 अगस्त को मिड-कैप 12,914.63 अंक के निचले स्तर पर पहुंच गया, जो 52 सप्ताह की सबसे बड़ी गिरावट थी। इसी दिन स्मॉल-कैप 11,950.86 अंक के साथ एक साल के निचले स्तर पर चला गया।



प्रतीकात्मक

- पिछले 23 अगस्त को स्मॉल-कैप 11,950.86 अंक के साथ वर्ष के निचले स्तर पर आ गया
- ऑटो सेक्टर की सुस्ती और अन्य कारणों के चलते निवेशकों में निराशा देखी गई

विश्लेषकों के मुताबिक सुपर रिच लोगों और एफपीआइ पर ज्यादा टैक्स और ऑटो सेक्टर में मंदी के चलते निवेशकों में निराशा देखी गई। इसके अलावा ग्लोबल स्तर ट्रेड वार जैसे मुद्दों के चलते भी निवेशकों का हौसला कमजोर हुआ। इस दौरान सबसे ज्यादा नुकसान स्मॉल स्टॉक्स को उठाना पड़ा। जानकारों के मुताबिक स्माल स्टॉक में ज्यादातर घरेलू निवेशक किया जाता है।

मुहर्रम के उपलक्ष्य में बाजार बंद

मुंबई, एएनआइ : मंगलवार को मुहर्रम के उपलक्ष्य में घरेलू शेयर बाजार बंद रहे। छुट्टी के चलते फोरेक्स और कमोडिटी मार्केट भी बंद रहे। मेटल और सराफा बाजार में भी कोई कारोबार नहीं हुआ। पिछले कारोबारी सत्र यानी सोमवार को प्रमुख शेयर बाजार लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। इस दौरान एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी 11,000 अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया। कारोबार के आखिर में निफ्टी 56.85 अंक यानी 0.52 अंक उछलकर 11,003.05 अंक पर बंद हुआ। सोमवार को बीएसई का 30-शेयरों वाला सेंसेक्स मजबूत होकर 37,145.45 अंक पर बंद हुआ।

मंत्रिसमूह तय करेगा एयर इंडिया की रिजर्व कीमत

नई दिल्ली, आइएएनएस : कर्ज में डूबी सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया को बेचने के लिए सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मंत्रियों का समूह एयर इंडिया का कर्ज चुका दिए जाने लायक रिजर्व प्राइज तय करेगा। इसके साथ ही मंत्रियों का यह समूह कंपनी के विक्रय से संबंधित कई और मुश्किलों पर मंथन करेगा। इनमें कंपनी के कर्मचारियों की सेवा से संबंधित तकनीकी समस्याओं का निपटारा भी होगा। कंपनी के रिटायर्ड या जल्द रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को दी जा रही मेडिकल सुविधाओं को लेकर भी किसी नतीजे की तलाश की जाएगी।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सरकार एयर इंडिया की बिक्री के लिए जरूरी प्रावधानों को सुनिश्चत करने के बाद इससे पूरी तरह से अलग हो जाएगी। मंत्रियों के इस समूह में अमित शाह के अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कॉमर्स और रेल मंत्री पीयूष गोयल और नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं।

बीते एक साल में देश का एविएशन माहौल बदल चुका है। निजी विमानन कंपनी जेट एयरवेज के 18 अप्रैल से परिचालन में नहीं रहने के चलते भी चीजें बदली हैं। सेंटर ऑफ एशिया पैसेफिक एविएशन के सीईओ कपिल कौल के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस साल चीजें सकारात्मक हैं। अगर कंपनी की कुछ मूलभूत समस्याओं को दूर कर दिया गया तो निश्चित तौर पर निवेशक इसमें रुचि दिखाएंगे।

- गृह मंत्री अमित शाह करेंगे कंपनी के लिए गठित मंत्रिसमूह का नेतृत्व
- कर्मचारियों के संयोजन से संबंधित समस्याओं पर होगा मंथन



सरकार ने बिक्री के बाद कंपनी से निकल जाने का मन बनाया है। फाइल

ये भी तय होंगे बैठक में

- मंत्रियों का यह समूह कंपनी के विक्रय से संबंधित कई और मुश्किलों पर मंथन करेगा
- कंपनी के कर्मचारियों की सेवा से संबंधित तकनीकी समस्याओं का होगा निपटारा
- कर्मचारियों को दी जा रही मेडिकल सुविधाओं के मुद्दे को भी सुलझाने की कोशिश होगी

पिछली कोशिश रही थी नाकाम

इससे पहले मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में भी एयर इंडिया को बेचने का प्रयास किया था। लेकिन तब सरकार अपने प्रयास में सफल नहीं हो सकी थी। उस समय कच्चे तेल की कीमतें काफी ऊपर थीं और डॉलर के मुकाबले कमजोर रुपये के चलते निवेशकों ने इसे खरीदने को लेकर कोई उत्साह नहीं दिखाया था। उस दौरान एक भी निवेशक आगे नहीं आया था।

जैक मा हुए रिटायर, करते रहेंगे अलीबाबा का मार्गदर्शन

बीजिंग, प्रेट्र : चीन के अरबपति जैक मा ने मंगलवार को अपने 55वें जन्मदिन के मौके पर ई- कॉमर्स कंपनी अलीबाबा से रिटायरमेंट ले ली। गरीब परिवार में पैदा हुए मा ने चीन जैसे कम्यूनिस्ट देश में दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी खड़ी कर दी। 55 वर्षीय जैक मा को चीन का स्टीव जॉब्स कहा जाता है। उन्होंने कहा कि अब वे इंटरनेट के लिए पुराने हो गए हैं और अब उन्हें कुछ नया करना है।

जैक मा ने 1999 में अलीबाबा की नींव रखी थी। फोर्ब्स मैगजीन ने पिछले साल अलीबाबा की कीमत 480 बिलियन डॉलर आंकी थी, जबकि जैक मा को 39 बिलियन डॉलर के साथ चीन का सबसे बड़ा धनकुबेर बताया था।

मा ने अपनी कामयाबी से यह दिखा दिया कि करीब-करीब नियंत्रित इकोनॉमी में भी एक बड़ी कंपनी खड़ी की जा सकती है। जैक मा ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा बीते साल की थी। उनके इस फैसले को लेकर तमाम तरह की अफवाहों का बाजार गर्म रहा। यहां तक कहा गया था कि जैक मा ने चीन में खराब होते कारोबारी माहौल से निराश होकर रिटायरमेंट का फैसला लिया है। यह भी खबर थी कि चीन अपनी कंपनियों के कामकाज में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बाद में मा ने इन खबरों को कोरी अफवाह बताया था।

- अलीबाबा के डायरेक्टर के तौर पर करते रहेंगे मार्गदर्शन
- बोले, इंटरनेट के लिए पुराना हो गया हूं, कुछ अलग करना है

जैक मा का संक्षिप्त परिचय

उम्र- 55 वर्ष
संपत्ति- 39 बिलियन डॉलर
कंपनी- अलीबाबा
कंपनी की संपत्ति- 480 बिलियन डॉलर
कारोबार- चीन, अमेरिका, यूरोप समेत दर्जनों अन्य देश
उत्तराधिकारी- डेनियल झांग

मा का रिटायरमेंट ऐसे समय पर हुआ है जब कंपनी भारत में बड़े निवेश की घोषणा कर चुकी है। भारत में उसकी सीधी टक्कर अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स जैसी कंपनियों से होगी। रिटायर होने से पहले उन्होंने डेनियल झांग को कंपनी का सीईओ नियुक्त कर दिया था। वह अलीबाबा के डायरेक्टर बने रहेंगे।

नए मोटर वाहन कानून के बाद वाहनों के इंश्योरेंस में आया तेज उछाल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

इस महीने से लागू हुआ नया मोटर कानून वाहन चालकों के लिए भले ही मुसीबत का कारण हो, बीमा उद्योग के लिए यह वरदान बनकर आया है। नया मोटर वाहन कानून लागू होने के दिन से ही व्हीकल इंश्योरेंस सेक्टर गुलजार है। पिछले कुछ महीनों से ऑटो सेक्टर में आई सुस्ती के चलते कारोबार में बड़ी कमी झेल रही बीमा कंपनियों में नई जान आई है। नए कानून में थर्ड पार्टी वाहन बीमा नहीं होने पर जुर्माने की राशि एक हजार रुपये से बढ़ाकर दो हजार रुपये कर दी गई है। इस जुर्माने से बचने के लिए मोटर वाहन बीमा लेने वालों की संख्या बेहद बढ़ गई है। जानकारों के मुताबिक मोटे तौर पर देश में अभी 70 फीसद वाहन बिना बीमा के ही सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इनके बीमा कराने से साधारण बीमा कंपनियों की प्रीमियम राजस्व में अच्छी खासी वृद्धि की गुंजाइश है।

आइसीआइसीआइ लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रमुख (रिइंश्योरेंस व क्लेम) संजय दत्ता ने दैनिक जागरण को बताया कि सितंबर में अब तक वाहन बीमा कराने वालों की संख्या में आम महीनों के मुकाबले तीन गुना तक बढ़ोतरी देखी गई है। यह नए मोटर वाहन कानून का असर है। अभी तक लोग वाहन पुराना होने पर वाहनों के बीमा के रिन्यूअल में आनाकानी करते थे। लेकिन अब उनके लिए बीमा प्रोडक्ट लेना इसलिए भी मुफीद हो गया है क्योंकि दोपहिया वाहनों के मामले में अमूमन बीमा शुल्क बिना बीमा के वाहन चलाने के जुर्माने से कम है। एक तरह से नए मोटर वाहन कानून ने वाहन बीमा को लेकर जागरुकता बढ़ा दी है।



प्रतीकात्मक

- सड़कों पर दौड़ने वाली तकरीबन 70 फीसद दोपहिया गाड़ियों का बीमा नहीं
- बिना थर्ड पार्टी बीमा के वाहन चलाने पर जुर्माने की राशि दोगुनी होने का असर

बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के मोटर बीमा कारोबार के प्रेसिडेंट व कंट्री हेड गुरनीश खुराना का अनुमान है कि भारत में सड़कों पर जितने दोपहिया वाहन दौड़ते हैं उनमें से 70 फीसद का बीमा नहीं होता है। मुख्य तौर पर जागरूकता नहीं होने की वजह से लोग वाहन बीमा नहीं खरीदते हैं। कुछ लोग सिर्फ कानूनी बाध्यताओं के तहत वाहन बीमा खरीदते हैं। दुर्घटना की स्थिति में अक्सर बीमा नहीं होने की वजह से लोगों को भारी हर्जाना भरना पड़ता है, जो कई बार चालक के सामर्थ्य से बाहर होता है। नया मोटर वाहन कानून लागू होने के बाद थर्ड पार्टी बीमा नहीं होने पर जुर्माने की राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दी गई है। इसके मुकाबले बीमा की राशि काफी कम होती है। ग्राहक पांच वर्षों के लिए भी बीमा ले सकता है। खुराना कहते हैं, 'दोपहिया वाहन रखने वाले हर व्यक्ति को समग्र वाहन बीमा लेना चाहिए दुर्घटना में अगर तीसरे पक्ष को कोई क्षति हुई, तो उसकी भी भरपाई हो सके।' देश में 25 साधारण बीमा कंपनियां मोटर बीमा मुहैया करा रही हैं।

स्टार्ट-अप के लिए दिल्ली-एनसीआर देशभर में बेहतर



एनसीआर के स्टार्ट-अप किसी एक नहीं, बल्कि अनेक सेक्टर में अव्वल हैं। प्रतीकात्मक

नई दिल्ली, प्रेट्र : स्टार्ट-अप कंपनियों को बेहतर माहौल मुहैया कराने के मामले में दिल्ली-एनसीआर ने देशभर बाजी मारी है। टीआइई-दिल्ली-एनसीआर और जिन्नोव की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 7,000 से ज्यादा स्टार्ट-अप कंपनियां हैं। इनकी कुल संपत्ति 5,000 करोड़ डॉलर (करीब 3.5 लाख करोड़ रुपये) से ज्यादा है। इनमें से 10 ऐसी कंपनियां हैं, जिनमें से प्रत्येक की पूंजी एक अरब डॉलर (सात हजार करोड़ रुपये) या उससे ज्यादा है।

'टर्बोचार्जिंग दिल्ली-एनसीआर स्टार्ट-अप इकोसिस्टम' विषय पर तैयार रिपोर्ट का कहना है कि देशभर में स्टार्ट-अप की कुल संख्या में दिल्ली-एनसीआर की हिस्सेदारी 23 फीसद है, जहां कुल 7,039 ऐसी कंपनियां हैं। बेंगलुरु 5,234 कंपनियों के साथ दूसरे, मुंबई 3,829 कंपनियों के साथ तीसरे और हैदराबाद 1,940 कंपनियों के साथ चौथे स्थान पर रहा है। ये सभी कंपनियां वर्ष 2009 से 2019 के दौरान स्थापित की गई हैं।

जहां तक एनसीआर का सवाल है, तो इसमें दिल्ली में 4491, गुरुग्राम में 1,544 और नोएडा में 1,004 स्टार्ट-अप कंपनियां हैं। दिल्ली इस लिहाज से भी अन्य शहरों से आगे है कि यहां एक अरब डॉलर से ज्यादा मूल्य वाली स्टार्ट-अप कंपनियों की संख्या 10 है। इस मामले में नौ कंपनियों के साथ बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है। ऐसी दो-दो कंपनियां मुंबई और पुणे, जबकि चेन्नई में एक है।

टीआइई दिल्ली-एनसीआर के प्रेसिडेंट राजन आनंदन ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर के मामले में एक और खास बात यह है कि इस क्षेत्र ने वर्ष 2013 के बाद से अब तक हर वर्ष कम से कम एक अरबपति (डॉलर के मूल्य में) स्टार्ट-अप दिए। एक और दिलचस्प बात इस क्षेत्र की यह है कि यहां जो 10 दिग्गज स्टार्ट-अप हैं, वे सब के सब किसी एक ही क्षेत्र से नहीं हैं। इनमें फिन-टेक, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, फूड, एनर्जी और अन्य सेक्टर की कंपनियां हैं। इतना ही नहीं, देश की शीर्ष पांच स्टार्ट-अप कंपनियां भी दिल्ली-एनसीआर में ही स्थित हैं। इनमें ओयो रूम्स, पेटीएम और हाइक जैसी कंपनियां शामिल हैं।

- शीर्ष पांच स्टार्ट-अप कंपनियां दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ही
- स्टार्ट-अप की कुल संख्या में हिस्सेदारी 23 फीसद

एनसीआर का दबदबा

7,039 स्टार्ट-अप हैं इस क्षेत्र में

100 करोड़ डॉलर से ज्यादा संपत्ति वाली 10 कंपनियां

50 फीसद के करीब है देशभर की स्टार्ट-अप कंपनियों की कुल संपत्ति में हिस्सेदारी

56 अरब डॉलर तक है इस क्षेत्र की कंपनियों का कुल मूल्य

भरोसा

निवेश की स्थिति में सुधार की उम्मीद कर रहीं कंपनियां, स्मॉल अप्लायंसेज व ब्रांडेड अपैरल सेक्टर में सकारात्मक रुख

कंपनियों को दूसरी छमाही में विकास की उम्मीद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही में यानी सितंबर से अगले वर्ष मार्च तक उद्योग जगत इकोनॉमी में सुधार की उम्मीद देख रहा है। कंपनियों का मानना है कि राजनीति और नीतिगत स्तर पर स्थायित्व के चलते वित्त वर्ष के इस हिस्से में इंडस्ट्री के कुछ सेक्टर में निवेश की स्थिति में सुधार होगा। उनके मुताबिक रियल एस्टेट, स्मॉल अप्लायंसेज और ब्रांडेड अपैरल सेक्टर में सकारात्मक रुख बनेगा।

मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट रिसर्च एजेंसी सीएलएसए इंडिया की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इकोनॉमी में सुस्ती को लेकर कंपनियां चिंतित तो हैं, लेकिन दूसरी छमाही को लेकर कंपनियों का रुख सकारात्मक भी है। कंपनियों का मानना है कि दूसरी छमाही से निजी कंपनियों के निवेश की स्थिति में बदलाव आना शुरू हो सकता है। वैसे भी वित्त वर्ष की शुरुआत से शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों, खासतौर पर आइटी सेक्टर की कंपनियों में रोजगार के अवसरों को लेकर सुधार की स्थिति देखने को मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक आइटी सेक्टर के अलावा इस वित्त वर्ष में एनबीएफसी सेक्टर में भी नौकरियों के अवसर बने हैं।

सीएलएसए ने स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करीब 100 कंपनियों की सालाना रिपोर्ट का सार निकालकर यह रिपोर्ट तैयार की है। इन कंपनियों की वित्त वर्ष 2018-19 की सालाना रिपोर्ट मौजूदा आर्थिक हालात के मद्देनजर तैयार की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियों का एक सकारात्मक रुख यह है कि ये देश में राजनीतिक स्थिरता को लेकर काफी उत्साहित हैं। खासतौर पर रियल एस्टेट, स्मॉल अप्लायंसेज और ब्रांडेड अपैरल सेक्टरों से जुड़ी कंपनियां भविष्य को लेकर उत्साहित हैं। हालांकि ऑटो और ग्लोबल कमोडिटीज से जुड़ी कंपनियां सशंकित हैं।



निवेश बढ़ने और कई चुनौतियों के ढीले पड़ने की उम्मीदें बढ़ी हैं। प्रतीकात्मक

कई कंपनियों ने इस बात से सहमति व्यक्त की है कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कई ढांचागत सुधार हुए। सीएलएसए का मानना है कि कुछ कॉरपोरेट और कई सेक्टरों को इसका लाभ भी हुआ। खासतौर पर कंपनियों ने कंसोलिडेशन के जरिये इन सुधारों का लाभ भी लिया। यही सेक्टर इकोनॉमी की भविष्य की स्थिति को लेकर सकारात्मक भी हैं। इनमें डिजिटल इकोनॉमी लिंक्ड कंपनियां और नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल कंपनियां भी शामिल हैं।

पूंजी निवेश पर मिश्रित रुख

रिपोर्ट के मुताबिक पूंजी निवेश को लेकर कंपनियों का रुख मिश्रित रहा है। एलएंडटी के हवाले से कहा गया है कि वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही में निवेश के माहौल में सुधार की उम्मीद है। एलएंडटी का मानना है कि इस अवधि तक केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का कामकाज सुचारु रूप से चलने लगेगा। कंपनी का मानना है कि दूसरी छमाही में वित्तीय बाजारों और पूंजी के प्रवाह में स्थिरता आएगी।

रिपोर्ट का आधार

सीएलएसए ने अपनी इस रिपोर्ट में जिन कंपनियों को शामिल किया है उनकी मार्केट कैप 1.2 ट्रिलियन डॉलर की है। यह देश की कुल लिस्टेड कंपनियों की मार्केट कैप का 65 परसेंट है।

उल्टा चोर कोतवाल को डांटे

पाक द्वारा बलूचिस्तान में मानवाधिकार हनन की दास्तां



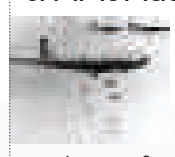
पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में कथित मानवाधिकार हनन का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय मंच पर चाहे जितना उठाता रहे, लेकिन यह सच है कि उसकी सेना बलूचिस्तान में जुल्म करने का हर रिकॉर्ड तोड़ रही है। पाकिस्तान के उदय के 72 साल बाद भी वहां के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान को सबसे तनावग्रस्त इलाका माना जाता है। आर्थिक और सामाजिक पैमानों पर बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। पाक सेना पर सालों से आजादी की मांग कर रहे बलोच लोगों को गायब करने और उनकी गुपचुप तरह से हत्या करने के आरोप लगते रहे हैं।

पाक सेना के अत्याचार



बलोच आंदोलन को पाक सेना ने हमेशा ताकत से कुचलने की कोशिश की है। 2006 को जनरल परवेज मुशर्रफ के शासनकाल में बलोच आंदोलन के नेता **नवाब अकबर बुग्ती** की सेना ने हत्या कर दी थी। तब से ले कर अब तक सेना पर बलोच अभियान के लिए लड़ रहे लोगों को गायब करने और उनकी गुपचुप हत्या के कई आरोप लगे हैं। लोगों को उठा लेना और फिर उनकी लाशें मिलना वहां आम बात है।

अपनों पर गिराए बम



1974 में जनरल टिक्का खां के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने मिराज और एफ-86 युद्धक विमानों से बलूचिस्तान के इलाकों पर बम गिराए। यहां तक कि ईरान के शाह ने अपने कोबरा हेलिकॉप्टर भेज कर बलोच आंदोलनकारियों के इलाकों पर बमबारी कराई। उन्होंने अंधाधुंध हवाई ताकत का इस्तेमाल करके बलूचिस्तान के बच्चों, बूढ़ों और लड़ाकों को मारा।

आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन

सत्तर के दशक में पाकिस्तान की जीडीपी में बलूचिस्तान की भागीदारी 4.9 फीसद थी, जो साल 2000 में गिर कर सिर्फ तीन फीसद रह गई। बलोच लोग शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़े हैं। पाकिस्तान के सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी बहुत कम है। वहां संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन साथ ही सूखे की बहुत बड़ी समस्या है। वहां के सुई इलाके से जो गैस निकली है है, वो पाकिस्तान के घरों को तो फायदा पहुंचा रही है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों की उस तक पहुंच नहीं है।

भारत से अपील

बलूचिस्तान के कई नेता भारत से भी आग्रह कर चुके हैं कि उन्हें आजादी दिलाने में मदद की जाए। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले से दिए गए अपने भाषण में



बलूचिस्तान का जिक्र किया तो पूरी दुनिया का ध्यान उस तरफ गया। यह पहला मौका था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इस तरह खुले-आम बलूचिस्तान का जिक्र किया था।

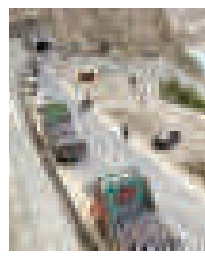
जबरन कराया विलय

अधिकतर बलोच मानते हैं कि जिस तहस से उन्हें पाकिस्तान में मिलाया गया वह गैरकानूनी था। जब अंग्रेज गए तो बलोचों ने अपनी आजादी घोषित कर दी और पाकिस्तान ने ये बात कुबूल भी कर ली। लेकिन बाद में वो इस बात से मुकर गए। बलूचिस्तान के संविधान में संसद के दो सदनों का प्रावधान था। कलात के खान (बलूच के पूर्व शासकों के शीर्षक होते थे।) ने उन दोनों सदनों पर ये फैसला छोड़ दिया कि उन्हें क्या करना चाहिए। दोनों सदनों ने इस बात को नामंजूर किया कि वो पाकिस्तान के साथ अपने देश का विलय करेंगे। इसके बाद मार्च 1948 में वहां पाकिस्तान की सेना आई और खान का अपहरण कर कराची ले आई। वहां उन पर दबाव डाल कर पाकिस्तान के साथ विलय पर उनके दस्तखत कराए गए।



चीन-पाक आर्थिक कॉरीडोर के खिलाफ

कुछ साल पहले चीन ने इस इलाके में चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरीडोर बना कर करीब 60 अरब डॉलर निवेश करने का फ़ैसला किया था। पाकिस्तान में तो इसे गेम चेंजर माना गया, लेकिन बलोच लोग इसके खिलाफ हैं। वहां के मुख्यमंत्री का कहना है कि पाक सरकार ने हमें विश्वास में नहीं लिया। बिना हमसे ही पूछे ही योजना के लिए हामी भर दी। बलोचों को डर है कि इस योजना के जरिये अगर चीनी लोग आकर रहने लगेंगे तो बलोच कहां जाएंगे।



ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन को पद से हटाया



जॉन बोल्टन। फाइल

वाशिंगटन, आइएएनएस : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) जॉन बोल्टन को पद से हटा दिया। ट्रंप ने ट्वीट कर बताया, 'मैंने जॉन बोल्टन को सोमवार रात ही सूचित कर दिया था कि अब व्हाइट हाउस में उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है। मैं और प्रशासन में अन्य लोग उनके कई सुझावों से बिल्कुल असहमत थे इसलिए मैंने जॉन से इस्तीफा देने के लिए कह दिया था। यह मुझे मंगलवार सुबह दिया गया। मैंने जॉन को उनकी सेवाओं के लिए बहुत धन्यवाद दिया है।' अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि जॉन बोल्टन की जगह नए एनएसए की घोषणा अगले हफ्ते कर दी जाएगी। मालूम हो कि बोल्टन ने पिछले साल एचआर मैकमास्टर की जगह एनएसए का पद संभाला था। ट्रंप के ट्वीट करने के कुछ ही देर बाद बोल्टन ने भी ट्वीट कर कहा, 'मैंने सोमवार रात इस्तीफा देने की पेशकश की थी और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि इसके बारे में मंगलवार को बात करेंगे।'

ईरान और उत्तर कोरिया विरोधी रुख बना विदाई का कारण : न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, ट्रंप ने बोल्टन को ईरान, उत्तर कोरिया और अफगानिस्तान से जुड़े मसलों में विदेश नीति पर बुनियादी असहमति के चलते हटाया है। बताया जाता है कि बोल्टन की एनएसए पद से छुट्टी ऐसे समय हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति उत्तर कोरिया और ईरान के साथ कूटनीतिक रिश्तों की राह खोलना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन में बोल्टन जैसे लोग इसमें बाधा बन रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर के जिक्र पर चीन और पाकिस्तान को भारत ने लगाई लताड़

दी चेतावनी ▶ कश्मीर में अनु. 370 हटने के बाद से चीन और पाकिस्तान कर रहे हैं बयानबाजी

दोनों को सीपीईसी का अनधिकृत जमीन पर निर्माण होने की याद दिलाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली



रवीश कुमार। फाइल

कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के भारत के फैसले के बाद जिस तरह से पाकिस्तान और चीन इस मुद्दे पर एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, उस पर भारत ने दोनों को लताड़ लगाई है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की तीन दिन पहले हुई इस्लामाबाद यात्रा के दौरान जिस तरह से संयुक्त बयान में कश्मीर का जिक्र किया गया है उसे भारत ने पूरी तरह खारिज किया है। भारत ने दोनों देशों को यह भी याद दिलाया है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला हिस्सा भी भारत का ही है। उस हिस्से पर चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (सीपीईसी) बनाया जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत भी आने वाले थे लेकिन भारत ने उनकी यात्रा को अंत समय में आग्रह कर स्थगित करवा दिया था।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि चीन के विदेश मंत्री की हालिया पाकिस्तान यात्रा के दौरान संयुक्त बयान में जम्मू-कश्मीर के जिक्र को हम पूरी तरह से खारिज करते हैं। जम्मू-कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। दूसरी तरफ हम चीन की व पाकिस्तान की तथाकथित आर्थिक कॉरिडोर को लेकर भी अपनी चिंता जताते हैं। यह जम्मू-कश्मीर के एक हिस्से पर बनाया जा रहा है। यह हिस्सा वर्ष 1947 से पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। भारत किसी भी दूसरे देश की तरफ से पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से में फेरबदल करने की कार्रवाई के खिलाफ है। जो भी देश ऐसा कर रहा है उसे तुरंत इन गतिविधियों को रोकना चाहिए।

चीन के विदेश मंत्री पिछले हफ्ते पाकिस्तान-चीन-अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय वार्ता में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे थे। वहां उनकी पाकिस्तान सरकार के आला अधिकारियों और विदेश मंत्री शाह मेहमूद कुरैशी के साथ अलग-अलग बातचीत हुई थी। दरअसल, जब से भारत ने अनुच्छेद 370 समाप्त किया है तभी से चीन अपने मित्र देश पाकिस्तान के साथ है। भारत के उक्त फैसले के कुछ ही दिनों बाद कुरैशी ने चीन की यात्रा की थी। उसके कुछ ही दिनों बाद चीन की शह पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर बैठक का आयोजन किया गया। चीन एक तरफ भारत से कहता है कि कश्मीर मुद्दे का समाधान पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय आधार पर करे जबकि दूसरी तरफ वह पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाता दिख रहा है।

कश्मीर पर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर चला मध्यस्थता कार्ड

वाशिंगटन, आइएएनएस : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव दूर करने के लिए एक बार फिर मध्यस्थता का इरादा जताया है। साथ ही यह भी कहा कि वह ऐसा तभी करेंगे अगर दोनों देश ऐसा चाहें। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसके लिए दो टूक मना करने के बावजूद ट्रंप ने मध्यस्थता का जिक्र किया है।

व्हाइट हाउस में सोमवार को मीडिया को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक सवाल के जवाब में कहा, 'अगर वह चाहें तो मैं उनकी मदद करना चाहता हूं। वह यह बात जानते हैं। यह विकल्प अभी भी खुला है।' उन्होंने कहा आप सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर तनाव है। मेरे विचार से अब यह तनाव दो हफ्ते पहले के हालात से कुछ कम हुआ है।

राष्ट्रपति ने कहा कि उनका भारत और पाकिस्तान दोनों से ही अच्छा तालमेल है। पिछले ही महीने फ्रांस में जी-सात सम्मेलन के इतर ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच

- **अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा-अगर भारत-पाक चाहें तो खुला है विकल्प**
- **बोले-दो हफ्ते पहले के मुकाबले दोनों देशों के बीच कम हुआ तनाव**

इस मुद्दे पर बात हुई थी और दोनों ने नेताओं से इस बात पर सहमति जताई थी कि कश्मीर द्विपक्षीय मामला है। भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे पक्ष की कोई गुंजाइश नहीं है।

उल्लेखनीय है कि ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर सबसे पहले जुलाई में मध्यस्थता की बात कही थी जब उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात के दौरान कहा था कि मोदी ने उन्हें ओसाका बैठक के दौरान यह सुझाव दिया था। लेकिन भारत ने तुरंत दो टूक स्पष्ट कर दिया था कि मोदी ने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही और कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है। इसके बाद पिछले महीने फ्रांस में मोदी से मुलाकात के दौरान ट्रंप के फिर से कश्मीर मुद्दा उठाने पर पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि हम किसी को भी कश्मीर पर कष्ट नहीं देना चाहते।

मुहाजिर नेता ने खोली गुलाम कश्मीर में पाक सेना के अत्याचार की पोल

लंदन, एएनआइ : ब्रिटेन में रहने वाले मुहाजिर नेता आरिफ आजकी ने गुलाम कश्मीर में पाकिस्तान की सेना की ओर से की जा रही बर्बरता की पोल खोली है। उन्होंने कहा कि गुलाम कश्मीर में पिछले दो दिनों से आजादी के समर्थन में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। सेना के जुल्म और मानवाधिकार उल्लघनों के खिलाफ जमकर गुस्सा जाहिर किया जा रहा है।

आजकी ने गुलाम कश्मीर के बदतर हालात का जिक्र करते हुए मंगलवार को यहां कहा, 'किसी को आवाजाही की खुली आजादी नहीं है। सेना का अभियान चल रहा है। लोगों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। यही नहीं, पत्रकारों को भी वहां की खबर देने की मनाही है। पाकिस्तान की सेना क्या कर रही है?'

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद पाकिस्तान की सेना की ओर से भारत के खिलाफ की गई टिप्पणियों का जिक्र करते हुए आजकी ने कहा, 'हम यही सोचते हैं कि वे हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन सैन्य कमांडर ट्विटर वार में व्यस्त दिख रहे हैं।'



ब्रिटेन में रहने वाले मुहाजिर नेता आरिफ आजकी। एएनआइ

- **सेना की बर्बरता के खिलाफ गुलाम कश्मीर में दो दिनों से हो रहे विरोध प्रदर्शन**
- **लोगों पर की जा रहीं है ज्यादतियां, पत्रकारों को भी है मनाही**

पाकिस्तान 72 साल से खेल रहा कश्मीर कार्ड

लंदन में बतौर मानवाधिकार कार्यकर्ता काम करने वाले आजकी ने कहा कि पाकिस्तान पिछले 72 साल से संयुक्त राष्ट्र और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (ओआइसी) जैसे वैश्विक मंचों पर कश्मीर कार्ड खेल रहा है।

भारत में हिंसा भड़काने का भी कर रहा प्रयास

आजकी के अनुसार, भारतीय क्षेत्र में हिंसा के लिए पाकिस्तान जिहाद के नाम पर लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री महमूद खान ने बीते बुधवार को कहा था कि कश्मीर के लिए अगर जिहाद का एलान कर दिया जाए तो वह इसका कमांडर बनना पसंद करेंगे।

अमेरिकी पूछताछ में जासूस ने कुबूला राष्ट्रपति चुनावों में थी पुतिन की भूमिका

वाशिंगटन, एएफपी : रूस की सरकार के एक उच्च पदस्थ सूत्र ने अमेरिकी एजेंटों के समक्ष कबूल किया है कि रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन का 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में सीधा दखल था। अमेरिकी मीडिया ने यह रिपोर्ट दी है।

सीएनएन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दशकों से जानकारी दे रहे सूत्र की पुतिन तक पहुंच थी और उसने रूस के नेता तक अनेक उच्च स्तरीय दस्तावेज पहुंचाएं हैं। हालांकि जासूस को 2017 में रूस के बाहर भेज दिया गया, क्योंकि उन्हें भय था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कैबिनेट की खुफिया जानकारियों के लगातार लीक होने से उसका भंडाफोड़ हो सकता है। वहीं अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआइए ने इसका खंडन किया है। एजेंसी में जनता से जुड़े मामलों के निदेशक ब्रिटनी ब्रेमेल ने सीएनएन से कहा, 'ऐसे भ्रामक कयास लगाना कि राष्ट्रपति चुनाव के संचालन में हमारे देश के सबसे जटिल खुफिया तंत्र में एक कथित बाहरी व्यक्ति घुस आया, उचित नहीं है।' वहीं

- **व्हाइट हाउस ने सीएनएन की खबर को गलत बताया, सीआइए ने कहा, भ्रामक कयास लगाना उचित नहीं**

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव स्टेफनी ग्रिशम ने सीएनएन की खबर को न केवल गलत बताया, बल्कि कई लोगों के जीवन को खतरे में डालने वाला बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि एजेंसी ने 2016 के अंत में उस सूत्र से जानकारी निकलवाने की पेशकश की थी, लेकिन मुखबिर ने पारिवारिक समस्याओं का हवाला देते हुए इससे इन्कार कर दिया था। समाचार पत्र में कहा गया कि इस घटना के बाद आशंका हुई कि मुखबिर डबल एजेंट हो गया है, लेकिन कई महीनों बाद वह मान गया। इसमें कहा गया कि इस अज्ञात व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारियों से अमेरिकी खुफिया एजेंसी इस नतीजे पर पहुंची कि 2016 के चुनाव में ट्रंप के पक्ष में और उनकी डेमोक्रेटिक विपक्षी हिलेरी क्लिंटन के विरोध में माहौल बनाने में पुतिन ने रूसी दखल की भूमिका तैयार की। इसी बीच अमेरिकी न्यूज नेटवर्क एनबीसी ने वाशिंगटन में रहने वाले एक व्यक्ति को खोज निकालने का दावा किया है, जिसके बारे में सीएनएन में बताया गया था। जब एनबीसी संवाददाता ने उसके घर पर सपंर्क किया तो उस रूसी को अपना दोस्त बताने वाले दो लोग अचानक निकले और पूछने लगे कि आखिर वह उससे क्यों बात करना चाहता है।

क्रेमलिन ने मंगलवार को कहा कि रूसी मीडिया द्वारा पहचाने गए और सीआइए द्वारा पकड़ा गया जासूस अमेरिका में काम करता था, लेकिन उसे निकाल दिया गया था। इतना ही नहीं, उसका राष्ट्रपति पुतिन से कोई सीधा संपर्क भी नहीं था। समाचार पत्र कोमसैंट ने सूत्रों के हवाले से कहा कि इस रूसी व्यक्ति की पहचान उच्चस्तरीय सरकारी स्रोत के रूप में की गई है और इसे 2017 में कथित तौर पर रूस से बाहर निकाल दिया गया था। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वह एक एजेंट था या नहीं है। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि जरूर कर सकता हूं कि वह राष्ट्रपति प्रशासन के तहत काम करता था।

प्रशांत महासागर में रेडियो एक्टिव पानी बहा सकता है जापान

टोक्यो, रायटर : जापान की कंपनी टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से निकले रेडियो एक्टिव जल को प्रशांत महासागर में बहा सकती है। जापान के पर्यावरण मंत्री योशिएकी हरादा ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मार्च, 2011 में भूकंप के बाद आई सुनामी से फुकुशिमा देईची स्थित परमाणु संयंत्र नष्ट हो गया था। 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में हुई दुर्घटना के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु हादसा था।

फुकुशिमा हादसे के बाद इस संयंत्र का संचालन करने वाली टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर ने संयंत्र के कूलिंग पाइपों में मौजूद दस लाख टन दूषित पानी टैंकों में इकट्ठा किया था। अब कंपनी का कहना है कि उसके पास इस पानी को रखने की जगह नहीं है। जापान सरकार इस मसले पर आखिरी निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञों की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इस बीच मंगलवार को राजधानी टोक्यो में हरादा ने पत्रकारों से कहा, पानी को समुद्र में बहाना ही एकमात्र विकल्प है। सरकार इस पर चर्चा करेगी लेकिन मैंने अपनी राय दे दी है। उन्होंने हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया कि कितनी पानी समुद्र में बहाया जाएगा। यदि रेडियो एक्टिव पानी समुद्र में बहाया जाता है तो जापान को दक्षिण कोरिया समेत कई पड़ोसी देशों के रोष का सामना करना पड़ेगा।

- **2011 में भूकंप के बाद आई सुनामी में तबाह हो गया था फुकुशिमा परमाणु संयंत्र**
- **यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में हुई दुर्घटना के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु हादसा था**

कई परमाणु संयंत्र समुद्र में ही बहाते हैं पानी

तटीय इलाके में स्थित परमाणु संयंत्र आमतौर पर ट्रिटियम युक्त पानी समुद्र में ही बहाते हैं। ट्रिटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है जो अन्य के मुकाबले कम हानिकारक है। टोक्यो इलेक्ट्रिक ने पिछले साल स्वीकार किया था कि फुकुशिमा के पानी में ट्रिटियम के अलावा भी कई अन्य हानिकारक तत्व मौजूद हैं।

पाक पुलिस स्टेशनों में क्रूरता की घटनाएं अब नहीं आएंगी सामने

लाहौर, आइएएनएस : पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कैदियों से होने वाली क्रूरता और दुर्व्यव्हार को छुपाने के लिए पुलिस स्टेशनों में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। सरकारी फरमान के अनुसार, अब एसएचओ रैंक से नीचे के अधिकारी थाने में वीडियो रिकार्डिंग करने में सक्षम स्मार्टफोन अपने साथ नहीं रख सकेंगे।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कदम ऐसी कई वीडियो क्लिप सामने आने के बाद उठाया गया, जिसमें पंजाब पुलिस की क्रूरता और बर्बरता उजागर हुई थी। पुलिस महानिरीक्षक (आइजीपी) आरिफ नवाज के अनुसार, आम लोगों को भी पुलिस स्टेशन में स्मार्टफोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी। थाने में दाखिल होने से पहले उन्हें अपना मोबाइल बाहर ही जमा कराना होगा। अधिकारियों को हालांकि ऐसे सामान्य फोन ले जाने की छूट होगी, जिनमें वीडियो रिकार्डिंग फीचर ना हो। इस संबंध में हाल में एक बैठक हुई थी, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों को लिखित में आदेश जारी किया गया है।

- **पंजाब प्रांत के पुलिस स्टेशनों में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर लगाई गई रोक**
- **कैदियों से क्रूरता की वीडियो क्लिप सामने आने के बाद उठाया गया कदम**

इसमें लोगों को अवैध रूप से हिरासत में रखने और यातनाएं देने के खिलाफ निर्देश भी दिए गए हैं। एक दिन पहले ही आइजीपी ने पुलिस हिरासत में हुई मौतों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने सीसीटीवी के जरिये पुलिस स्टेशनों की निगरानी में हो रही लापरवाही पर भी गुस्सा जाहिर किया था।

ट्रंप ने किया तालिबान से वार्ता खत्म होने का एलान

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकी संगठन तालिबान से वार्ता खत्म होने का एलान कर दिया है। साथ ही यह भी कहा कि बीते एक दशक में अमेरिका ने तालिबान को जितना बड़ा झटका नहीं दिया है उससे ज्यादा पिछले चार दिन में दिया है। इससे पहले शनिवार को ट्रंप ने तालिबान और अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ कैंप डेविड में होने वाली गुप्त बैठक रद करने की जानकारी देकर सबको चौंका दिया था।

ट्रंप ने सोमवार को ह्वाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, 'तालिबान के साथ वार्ता अब दफन हो चुकी है। अब हम अफगान सरकार और अन्य से बातचीत कर रहे हैं। देखते हैं, क्या होता है।' उन्होंने यह भी कहा कि तालिबान सोचता है कि लोगों को मारकर वह वार्ता में अपना पक्ष मजबूत कर सकता है। लेकिन उनके (ट्रंप) के साथ वह ऐसा नहीं कर सकता। उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान में करीब दो दशक से जारी संघर्ष खत्म करने के लिए अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौते के मसौदे पर सहमति बन चुकी थी। इसके तहत समझौता होने के 130 दिन के भीतर अमेरिका को अपने 5,400 सैनिक वापस बुलाने थे।

सैनिकों की वापसी का दिया संकेत : ट्रंप ने अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी के भी संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा, 'अमेरिका, अफगानिस्तान से बाहर जरूर निकलेगा लेकिन सही समय आने पर।' ट्रंप ने यह भी कहा वह कुछ निश्चित सैनिकों को वापस बुलाएंगे लेकिन सैनिकों की संख्या मीडिया को नहीं बताएंगे। ट्रंप ने कहा कि तालिबान से बातचीत की अभी कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा, 'मैंने भविष्य में तालिबान से वार्ता की संभावना पर कोई चर्चा नहीं की है।'

तालिबान ने हमले जारी रखने की धमकी दी : आतंकी संगठन तालिबान ने भी ट्रंप के एलान के जवाब में हमले जारी रखने की धमकी दी है। उसने कहा कि बातचीत रोकने के फैसले पर अमेरिका को पछतावा होगा। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा, 'हमारे पास अफगानिस्तान में युद्ध खत्म करने के दो रास्ते थे। पहला जिहाद व संघर्ष। दूसरा बातचीत और समझौता। यदि ट्रंप बातचीत बंद करना चाहते हैं तो हम पहला रास्ता अपनाएंगे।

सार्जेंट बैरेटो की मौत ने रद कराई अफगान शांति वार्ता

न्यूयॉर्क टाइम्स से

वाशिंगटन : अफगानिस्तान में करीब दो दशक से जारी संघर्ष खत्म करने के लिए अमेरिका और आतंकी संगठन तालिबान समझौते के बेहद करीब पहुंच गए थे। इसी बीच गत गुरुवार यानी पांच सितंबर को काबुल स्थित अमेरिकी दूतावास के पास तालिबान ने विस्फोटकों से लदी कार उड़ा दी। अफगान राजधानी में एक हफ्ते के भीतर तालिबान का यह दूसरा बड़ा आतंकी हमला था। इस हमले में 10 अफगान नागरिकों के अलावा एक अमेरिकी सैनिक सार्जेंट बैरेटो ऑर्टिज की भी मौत हो गई थी। तीसरी बार अफगानिस्तान में तैनात किए गए 34 वर्षीय बैरेटो की मौत से भड़के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो तालिबान के साथ कैंप डेविड में होने वाली गोपनीय बैठक रद की। बाद में उन्होंने तालिबान से पूरी तरह वार्ता खत्म करने का एलान कर दिया। सार्जेंट बैरेटो को करीब से जानने वाले बताते हैं कि उन्हें केवल दो चीजों से प्यार था। एक उनका परिवार और दूसरा सेना व देश। प्यूर्टोरिको में पले-बढ़े बैरेटो के पिता भी सैनिक थे। बैरेटो 2010 में सेना में शामिल हुए थे। अफगानिस्तान में गुप्त ऑपरेशन कर रही विशेष टीम का हिस्सा रहे बैरेटो गुरुवार को अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के कार्यालय के करीब स्थित चेक प्वाइंट पर पहुंचे थे कि तभी वहां धमाका हुआ और वह उसकी चपेट में आ गए।

बैरेटो की पत्नी लेग्ना एपोंते ने कहा, 'बैरेटो के पिता ने बहुत ही गर्व के साथ देश की सेवा की। वह भी अपने पिता की तरह ही बनना चाहते थे। वह अपने देश को बहुत प्यार करते थे और उसकी सेवा करना उनके लिए सम्मान की बात थी।' उनके एक साथी सार्जेंट सेइक ने कहा कि बैरेटो बहुत ही सकारात्मक और महान शख्सियत थे।

हवाई हमले में तालिबानी आतंकी मुल्ला इदरीस समेत 37 की मौत

हेरात, एएनआइ : युद्धग्रस्त अफगानिस्तान के बाघलान व हेरात क्षेत्र में मंगलवार को हुए हवाई हमले में तालिबानी आतंकी मुल्ला इदरीस व संगठन के 36 अन्य सदस्यों की मौत हो गई। क्षेत्रीय पुलिस प्रमुख जनरल अमीनुल्लाह अमरखिल के हवाले से टोलो न्यूज ने बताया, छह साथियों समेत इदरीस हेरात में मारा गया।

अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के हवाले से उसने बताया कि सोमवार को बाघलान क्षेत्र में अफगानी सेना के ऑपरेशन में 30 तालिबानी आतंकी मारे गए। उल्लेखनीय है कि काबुल में हुए आतंकी हमले में अमेरिकी सैनिक समेत 12 लोगों के मारे जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैंप डैविड में प्रस्तावित तालिबान के साथ शांति वार्ता को रद कर दिया था। तालिबान ने रविवार को इसे अविश्वनीय बताया था। अफगानी सेना के साथ दो दिनों के संघर्ष के बाद तालिबान ने ताखर स्थित उत्तरी प्रांत के यांगि कला जिले पर कब्जा जमा लिया।

ब्रिटिश संसद में फिर मध्यावधि चुनाव की मांग वाला प्रस्ताव गिरा

लंदन, प्रेट्र : सियासी संकट में घिरे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मध्यावधि चुनाव कराने की मांग पर संसद में फिर हार का सामना करना पड़ा है। इस झटके के बावजूद उन्होंने वादा किया कि वह ब्रेक्जिट समझौते के लिए प्रयास करना जारी रखेंगे।

संसद की कार्यवाही निलंबित होने से पहले सोमवार देर रात तक चली बहस के बाद हुए मतदान में मध्यावधि चुनाव कराने की मांग वाला प्रस्ताव गिर गया। अपना प्रस्ताव गिरने पर जॉनसन ने विपक्षी सांसदों पर नाराजगी भी जाहिर की। इसके बाद संसद की कार्यवाही 14 अक्टूबर तक के लिए निलंबित कर दी गई। संसद के निलंबन पर कई विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी कर अपना विरोध जाहिर किया। प्रधानमंत्री जॉनसन ने ही महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से संसद को निलंबित करने की मांग की थी।

जॉनसन ने कहा, 'मैं अगले महीने ब्रसेल्स में होने वाले सम्मेलन में समझौते का प्रयास करूंगा। विपक्ष समयपूर्व चुनाव कराने में बाधा खड़ी कर मुझे अपना कर्तव्य निभाने से रोक रहा है।' प्रधानमंत्री ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक की और संसद में मिली कई शिकस्त और ब्रेक्जिट को लेकर अगली रणनीति पर चर्चा की। जॉनसन ने एक दिन पहले भी कहा था कि ब्रेक्जिट को रोकने की विपक्ष की कोशिश कामयाब नहीं होगी। उनके कार्यालय ने भी साफ कर दिया था कि 31 अक्टूबर को यूरोपीय यूनियन से अलगाव तय है।

- **प्रधानमंत्री जॉनसन ने कहा, बेक्जिट समझौते का प्रयास जारी रखेंगे**

डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी की नेता से मिलेंगे जॉनसन

जॉनसन उत्तरी आयरलैंड की डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी की नेता अर्लीन फोस्टर से उन अफवाहों के बीच मिलने वाले हैं कि वह ब्रेक्जिट के बाद आयरलैंड की सीमा और कारोबार के मसले पर नरम रुख अपना सकते हैं। फोस्टर की पार्टी चाहती है कि उत्तरी आयरलैंड ब्रिटेन के साथ बना रहे। पार्टी ने जॉनसन को आगाह भी किया है कि उनका क्षेत्र वार्ता में कोई त्याग नहीं करेगा।



विश्व कप से पहले कप्तान बदल दिए जाने का असर अफगानिस्तान की टीम के प्रदर्शन पर काफी पड़ा था।
— मुहम्मद नबी, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के सदस्य

बांग्लादेश की टी-20 टीम से मेहदी और रूबेल बाहर

ढाका, एएफपी : बांग्लादेश ने अफगानिस्तान और जिंबाब्वे के खिलाफ होने वाली टी-20 त्रिकोणीय सीरीज के पहले दो मैचों के लिए ऑफ स्पिनर मेहदी हसन और तेज गेंदबाज रूबेल हुसैन को टीम में जगह नहीं दी है। ऑलराउंडर आरिफुल हक, तेज गेंदबाज अबु हैदर, स्पिनर नजमुल इस्लाम और बल्लेबाज मुहम्मद मिथुन को भी टी-20 टीम से बाहर कर दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से ब्रेक की मांग करने वाले तमीम इकबाल भी टीम का हिस्सा नहीं हैं।



अफ्रीकी टीम का ध्यान बल्लेबाजी व गेंदबाजी पर

टी-20 ▶ भारत के खिलाफ पहले टी-20 मैच के लिए मेहमान टीम ने बहाया जमकर पसीना

टीम ने फील्डिंग से ज्यादा बल्लेबाजी और गेंदबाजी का किया अभ्यास

मुनीष गारिया, धर्मशाला



धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम में मंगलवार को दोपहर बाद दक्षिण अफ्रीका टीम ने अभ्यास किया। इस दौरान अभ्यास से फुटबाल खेलकर वार्मअप होते हुए खिलाड़ी डेविड मिलर, शमसी और अन्य। जागरण

पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म में चल रही दक्षिण अफ्रीकी टीम ने धर्मशाला में भारतीय टीम के खिलाफ नई रणनीति बनाई है। सीरीज के पहले मुकाबले में टीम को जहां युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर विश्वास है, वहीं, टीम धर्मशाला में पहले खेल चुके खिलाड़ियों के अनुभव के सहारे सीरीज के पहले मैच में जीत दर्ज करने की फिराक में है। टीम ने मंगलवार को फील्डिंग से ज्यादा बल्लेबाजी और गेंदबाजी पर ध्यान दिया।

बुमराह का डर : क्विंटन डिकॉक को अच्छे से पता है कि मेजबान टीम के पास जसप्रीत बुमराह की अगुआई में बेहतरीन गेंदबाज इकाई हैं जो टीम के बल्लेबाजों की अच्छे से परीक्षा लेंगे। यॉर्कर मैन बुमराह अभी शानदार फॉर्म में है और उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में कैरेबियाई बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि डिकॉक और बुमराह आइपीएल की टीम मुंबई इंडियंस में एक साथ खेलते हैं इसलिए मेहमान टीम के कप्तान इस भारतीय गेंदबाज को खेल सकते हैं लेकिन अन्य बल्लेबाजों के लिए यह आसान नहीं रहेगा।

रबादा ने कराई डिकॉक को बल्लेबाजी : अभ्यास के लिए तीन पिचें तय की गई थीं जिसमें पहली पिच में कैगिसो रबादा ने लंबे समय तक डिकॉक को गेंदबाजी करवाई। रबादा की गेंदबाजी के दौरान टीम के कोच हर दूसरी गेंद के बाद गेंदबाजी के टिप्स दे रहे थे। वहीं, दूसरी पिच में डेविड मिलर को बबुमा गेंदबाजी करवा रहे थे। तीसरी पिच में अन्य सभी खिलाड़ी अभ्यास कर रहे थे।

पुराने खिलाड़ियों को पूरा सम्मान : दक्षिण अफ्रीकी टीम के अंतरिम निदेशक इनोक क्वे ने अभ्यास के पहले ही दिन यह स्पष्ट कर दिया है कि वे मैच में पुराने खिलाड़ियों को पूरा सम्मान एवं टीम में स्थान देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि धर्मशाला स्टेडियम की परिस्थितियां क्या हैं और अभ्यास के दौरान यहां पहले खेल चुके खिलाड़ियों की राय को भी शामिल किया जाएगा। धर्मशाला स्टेडियम में मिलर और रबादा दो अक्टूबर 2015 को हुए टी-20 मुकाबले में भारत के खिलाफ खेल चुके हैं, इसलिए इन पर सबकी निगाहें होंगी। टीम को भी इनसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

ऑलराउंडरों की बढ़ेगी जिम्मेदारी : दक्षिण अफ्रीकी टीम का यहां पुराने खिलाड़ियों को तवज्जो देने की रणनीति अगर मैच के दौरान नहीं चली तो टीम के ऑलराउंडरों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी। मेहमान टीम के पास ऑलराउंडरों की भरमार है जिसमें डुसेन, रेजा हेंड्रिक्स, ड्वेन प्रिटोरियस, जॉर्ज लिंडे और एंडिले फेलुकवायो की टीम के मौजूदगी से टीम में संतुलन है।

साढ़े तीन घंटे बहाया पसीना : अंतरिम निदेशक इनोक क्वे के नेतृत्व में मंगलवार को मेहमान टीम ने यहां अभ्यास सत्र के दौरान फुटबॉल खेली और कैच अभ्यास भी किया। टीम के खिलाड़ियों ने पांच-पांच सदस्यों की टीम बनाकर फुटबॉल खेली।

> धर्मशाला की पिच बल्लेबाजों के लिए मदद करेगी। मैं धर्मशाला की पिच पर नहीं खेला हूं। जब पिछली बार हम यहां आए थे तो पिच अच्छा खेली थी। रोहित ने पिछली बार यहां शतक जड़ा था। मुझे उम्मीद है कि यहां की पिच अच्छी होगी।
> – क्विंटन डिकॉक, कप्तान, दक्षिण अफ्रीका

हमारे पास डिकॉक के रूप में अच्छा कप्तान : इनोक क्वे

जागरण संवाददाता, धर्मशाला : दक्षिण अफ्रीका के अंतरिम निदेशक इनोक क्वे का मानना है कि फाफ डु प्लेसिस का खिलाड़ी और कप्तान के रूप में अहम योगदान रहा है लेकिन अब भविष्य को देखते हुए क्विंटन डिकॉक के कौशल पर भरोसा करना है। 35 वर्षीय डुप्लेसिस अभी राष्ट्रीय टीम के टेस्ट कप्तान हैं लेकिन क्वे ने संकेत दिए हैं कि अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 विश्व कप के लिए नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा।

क्वे ने कहा, 'फाफ ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के लिए अच्छा किया है लेकिन हमें अब भविष्य को भी देखना है और हमें डिकॉक पर भरोसा है जो टी-20 में टीम की अगुआई कर रहे हैं। हमारे पास एक अच्छा कप्तान है और उनके पास भविष्य की टीम तैयार करने का मौका है। हमारा अभी ध्यान सिर्फ भारत के खिलाफ होने वाली इस सीरीज पर है। डिकॉक ने भारत में कई मैच खेले हैं जिसका हमें फायदा मिलेगा।'

भारतीय टीम मजबूत : क्वे ने आगे कहा, 'भारतीय टीम इस समय मजबूत स्थिति में है और घरेलू परिस्थितियों एवं मैदान में यह टीम और भी खतरनाक हो जाएगी लेकिन हमारी टीम में कई नए युवा खिलाड़ी हैं, जिनके बूते पर टीम भारत को कड़ी चुनौती देगी। टीम के कई खिलाड़ियों के लिए धर्मशाला नई जगह है इसलिए टीम यहां पहले ही पहुंचकर यहां की परिस्थितियों में खुद को ढालने की कोशिश कर रही है। वहीं कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्हें धर्मशाला की परिस्थितियों का पहले से अनुभव है। यहां एक अच्छा मुकाबला गेंद और बल्ले के बीच देखने को मिलेगा। हमारी टीम में कई नए चेहरे हैं लेकिन यह टीम किसी भी टीम को पटखनी देने का दम रखती है।'

टेस्ट रैंकिंग में कोहली पर स्मिथ की बढ़त कायम

दुबई, प्रेट्र : एशेज सीरीज में अपने दमदार प्रदर्शन की बदौलत ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और गेंदबाज पैट कमिंस ने आइसीसी की जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में अपनी बादशाह को और मजबूत कर लिया।

स्मिथ और कमिंस ने इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की 185 रन की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। स्मिथ ने भारतीय कप्तान विराट कोहली पर 34 अंकों की बढ़त बना ली है और पांच मैचों की एशेज सीरीज के खत्म होने पर उनका रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार रहना लगभग तय है। मैनचेस्टर में 211 और 82 रन की पारियां खेलकर मैन ऑफ द मैच बने स्मिथ के 937 अंक हो गए हैं जो दिसंबर 2017 में उनके सर्वश्रेष्ठ रेटिंग अंक से महज 10 कम हैं। दूसरी ओर पिछले टेस्ट में 103 रन देकर सात विकेट चटकाने वाले कमिंस ने अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 914 रेटिंग अंक की बराबरी की है जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के पांचवें सर्वाधिक अंक हैं। यह ऑस्ट्रेलिया की ओर से संयुक्त रूप से सर्वाधिक रेटिंग अंक हैं। ग्लेन मैक्ग्रा ने भी 2001 में इतने ही अंक हासिल किए थे।

कमिंस ने दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कैगिसो रबादा पर 63 अंकों की बढ़त बना रखी है। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह तीसरे स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड इस साल पहली बार शीर्ष 10 में जगह बनाते हुए 12वें से आठवें स्थान पर पहुंच गए। बल्लेबाजी रैंकिंग में इंग्लैंड के जोस बटलर चार स्थान के फायदे से 37वें और रॉरी बर्न्स छह स्थान के फायदे से करियर के सर्वश्रेष्ठ 61वें स्थान पर जबकि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन छह स्थान के फायदे से 60वें स्थान पर पहुंच गए हैं। भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा चौथे और अजिंक्य रहाणे सातवें पायदान पर बने हुए हैं। चटगांव टेस्ट में बांग्लादेश पर अफगानिस्तान की 224 रन की जीत से मेहमान टीम के खिलाड़ियों को भी काफी फायदा मिला है। पूर्व कप्तान असगर अफगान 92 और 50 रन की पारियां खेलने के बाद 110वें से 63वें स्थान पर पहुंच गए हैं। पहली पारी में शतक जड़ने वाले रहमत शाह भी 93वें से 65वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

वहीं उस टेस्ट में 104 रन देकर 11 विकेट चटकाकर मैन ऑफ द मैच बने कप्तान राशिद खान 69वें से 37वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ऑलराउंडर मुहम्मद नबी ने 21 स्थान के फायदे से 85वें स्थान पर रहते हुए टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा। बांग्लादेश के बाएं हाथ के स्पिनर शाकिब-अल-हसन और ताइजुल इस्लाम एक-एक स्थान के फायदे से क्रमशः 21वें और 22वें पायदान पर हैं। ऑफ स्पिनर नईम हसन 21 स्थान की छलांग के साथ 66वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

आइसीसी टेस्ट रैंकिंग

- बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार हैं ऑस्ट्रेलिया के स्टीव
- गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने बरकरार रखी बादशाहत



भारतीय कप्तान विराट कोहली। फाइल

लंकाई क्रिकेटरों के नहीं आने पर फवाद ने भारत को कोसा

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

- भारत ने श्रीलंका को पाकिस्तान जाने से रोका : फवाद हुसैन
- बीसीसीआइ के अधिकारी ने कहा, झूठ का पुलिंदा है फवाद का बयान

पाकिस्तान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद हुसैन ने आरोप लगाया कि भारत की धमकी की वजह से 10 प्रमुख श्रीलंकाई क्रिकेटरों ने पाकिस्तान के दौरे पर जाने से इन्कार कर दिया। फवाद ने ट्वीट किया कि भारत ने प्रमुख श्रीलंकाई क्रिकेटरों को धमकाया कि यदि उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया तो उन्हें आइपीएल से बाहर कर दिया जाएगा। यह जानकारी मुझे क्रिकेट कमेंट्रेटरों से मिली है और भारत के खेल अधिकारियों के इस कदम की निंदा की जानी चाहिए। हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एक पदाधिकारी ने फवाद के बयान की निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने जो बोला है वह झूठ के सिवा कुछ नहीं है।

श्रीलंका को 27 सितंबर से पाकिस्तान का दौरा करना है लेकिन श्रीलंकाई गेंदबाज लसित मलिंगा, पूर्व कप्तान एंजेलो मैथ्यूज, निरोशन डिकवेला, कुशल परेरा, धनंजय डिसिल्वा, अकिला धनंजय, सुरंगा लकमल, दिनेश चांदीमल और दिमुथ करुणारत्ने ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। पाक दौरे में दोनों देशों के बीच तीन वनडे और तीन टी-20 मैचों की सीरीज 27 सितंबर से नौ अक्टूबर तक होने की संभावना है। क्रिकेट श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल ने कराची और लाहौर का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था और इस दौरे को हरी झंडी दिखाई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता था कि श्रीलंकाई टीम दो टेस्ट मैच खेले लेकिन तीन वनडे और तीन टी-20 मैच खेलने पर रजामंदी हो पाई थी। प्रमुख खिलाड़ियों द्वारा इन्कार करने से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड उलझन में है लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने कहा कि भले ही प्रमुख श्रीलंकाई खिलाड़ी इस दौरे पर नहीं आएंगे लेकिन यह दौरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक ही होगा। 2009 में श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकी हमले के बाद से कोई भी टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करना चाहती है।



पाक मंत्री फवाद हुसैन। फाइल फोटो

गिल शतक से चूके, भारत-ए को बड़ी बढ़त

तिरुवनंतपुरम, प्रेट्र : कप्तान शुभमन गिल शतक से चूक गए लेकिन 90 रन की उनकी पारी से भारत-ए ने दक्षिण अफ्रीका-ए के खिलाफ पहले अनाधिकृत टेस्ट मैच के दूसरे दिन मंगलवार को पहली पारी में 303 रन बनाकर 139 रन की बढ़त हासिल की। इस चार दिवसीय मुकाबले में भारत-ए के लिए जलज सक्सेना ने भी नाबाद 61 रन बनाए। दिन का खेल खत्म होने तक भारत-ए ने दक्षिण अफ्रीका-ए की दूसरी पारी में 125 रन पर पांच विकेट चटका दिए हैं। मेहमान टीम अब भी भारत ए से 14 रन पीछे है। दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 164 रन पर सिमटी थी।

इससे पहले भारत-ए ने दिन की शुरुआत दो विकेट पर 129 रन से की जब गिल 66 और अंकित बवाने छह रन पर खेल रहे थे। बवाने हालांकि सोमवार के स्कोर में बिना कोई रन जोड़े दिन के दूसरे ओवर में मार्को जॉनसन की गेंद पर बोल्ड हो गए। गिल को इसके बाद केएस भरत (33) का साथ मिला और दोनों ने चौथे विकेट के लिए 44 रन की साझेदारी की। गिल ने 153 गेंद की पारी में 13 चौके और एक छक्का लगाया। भारतीय टीम 200 रन से पहले सात विकेट गंवाकर थोड़ी मुश्किल में थी लेकिन सक्सेना और ठाकुर (34) ने टीम को संभाला।

नजरिये में अंतर को मतभेद के रूप में नहीं देखा जा सकता : रवि शास्त्री

दुबई, प्रेट्र : भारतीय कप्तान विराट कोहली और सीमित ओवरों की टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा के बीच मतभेद की अटकलों को खारिज करने की कोशिश करते हुए मुख्य कोच रवि शास्त्री ने कहा कि नजरिये में अंतर को मतभेद के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

पहले भी दोनों सीनियर खिलाड़ियों के बीच मतभेद की खबरों को बकवास करार दे चुके शास्त्री से एक बार फिर इस बारे में पूछा गया। शास्त्री ने कहा कि टीम में जब 15 खिलाड़ी होते हैं तो हमेशा ऐसा समय आता है जब नजरिये में अंतर होता है। इसकी जरूरत भी है। मैं नहीं चाहता कि सभी एक ही बात बोलें। चर्चाएं होनी चाहिए और तभी कोई किसी नई रणनीति के बारे में सोच सकता है जिसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए इसलिए आपको खिलाड़ियों को खुद को अभिव्यक्त करने का मौका देना होगा और फिर फैसला करना होगा कि क्या सबसे सही है।' शास्त्री ने कहा, 'कभी-कभी यह टीम का सबसे जूनियर खिलाड़ी हो सकता है जो ऐसी रणनीति सामने रख सकता है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं हो और हमें इस पर विचार करने की जरूरत है इसलिए इसे मतभेद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।'

भारतीय टीम के कैरेबियाई दौरे पर रवाना होने से पहले कोहली ने भी मतभेद की खबरों को खारिज किया था। टी-20 विश्व कप 2021 तक फिर से भारतीय टीम के कोच नियुक्त किए गए शास्त्री ने कहा, 'मैं पिछले पांच साल से ड्रेसिंग रूम का हिस्सा हूं। मैंने देखा है कि लड़के कैसे खेल रहे हैं और वे कैसे टीम को मजबूत बना रहे हैं और उन्हें अपने काम की नैतिकता का पता है। अगर ऐसा होता तो रोहित विश्व कप में पांच शतक कैसे बनाता? विराट वह कैसे करता जो वह कर रहा है? वे एक साथ साझेदारी कैसे बनाते?' ऐसे अफवाह से टीम पर किसी प्रकार के असर के सवाल पर शास्त्री ने कहा कि अगर टीम पिछले पांच वर्षों से इस स्तर का खेल दिखा रही है तो मुझे लगता है कि आपको टीम के साथ खड़ा होने की जरूरत है। आपको परेशानी बढ़ाने के बजाय टीम के साथ रहना चाहिए। टीम की ऐसी निरंतरता मैंने किसी समय में नहीं देखी। आप देखिए हमने टी-20, वनडे, टेस्ट और यहां तक की आइसीसी की प्रतियोगिताओं में किस तरह का प्रदर्शन किया है।

हमने हितों के टकराव का मामला आचार अधिकारी के सामने उठाया : सीओए अध्यक्ष विनोद राय

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित प्रशासकों की समिति (सीओए) के प्रमुख विनोद राय ने स्वीकार किया है कि हितों के टकराव के मसले पर बीसीसीआइ लोकपाल-आचार अधिकारी न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) डीके जैन और सीओए के अलग-अलग विचार हैं। जैन ने सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज क्रिकेटरों को नोटिस भेजे थे जिसकी क्रिकेट बिरादरी ने आलोचना की थी। राय ने कहा कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लोकपाल है और उन्होंने इस पर विचार किया।

महिला टीम के प्रदर्शन विश्लेषक की तलाश में बीसीसीआइ

नई दिल्ली : बीसीसीआइ ने महिला क्रिकेट टीम के प्रदर्शन विश्लेषक के पद के लिए आवेदन मंगाए हैं। टीम प्रबंधन ने प्रदर्शन विश्लेषक की जरूरत के बारे में बताया था। पद के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 सितंबर है। इस पद के लिए आवेदन करने वाले की उम्र सीमा 60 साल है। बीसीसीआइ ने कहा, 'बोर्ड में विश्लेषक का काम छोटे से छोटा डाटा एकत्रित करना होगा। उसे इस काम को सीनियर टीम के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रणाली के तहत करना होगा। विश्लेषक कोचिंग और तकनीकी सदस्यों को खेल की रणनीतिक तैयारियों में मदद करेगा। उसे विरोधी टीम के मजबूत और कमजोर पक्षों पर ध्यान रखना होगा।'

ऑल इंडिया रेडियो पर क्रिकेट की कमेंट्री

नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेट की पहुंच को बढ़ाने के लिए बीसीसीआइ ने मंगलवार को ऑल इंडिया रेडियो (एआइआर) के साथ रेडियो अधिकारों को लेकर दो साल का करार किया। इस करार के तहत क्रिकेट प्रेमियों को उनके पसंदीदा खेल और मैचों की कमेंट्री रेडियो पर लाइव सुनने का मौका मिलेगा। बोर्ड ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के साथ होने वाली टी-20 सीरीज के साथ रेडियो कमेंट्री शुरू हो जाएगी। सीरीज का पहला मैच 15 सितंबर को धर्मशाला में खेला जाना है। इसके अलावा एआइआर पुरुष एवं महिला घरेलू टूर्नामेंट का भी रेडियो प्रसारण करेगा। बीसीसीआइ के साथ उसका दो साल का करार इसी साल 10 सितंबर से शुरू होगा और 31 अगस्त, 2021 तक जारी रहेगा।

राहुल की जगह रोहित को सलामी बल्लेबाज के तौर पर चुनेंगे : प्रसाद

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली



मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद।

काफी समय से टीम इंडिया के टेस्ट के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल की आलोचना हो रही थी। केएल राहुल लंबे समय से भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा हैं, लेकिन वे लंबी पारी खेलने में हर बार फेल हो रहे हैं। पिछले काफी समय से वे बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे हैं और टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दिला पाए हैं। ऐसे में राष्ट्रीय चयनकर्ताओं ने भी राहुल का विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है।

दरअसल, भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने ऐसे संकेत दिए हैं कि राहुल के खराब फॉर्म की वजह से रोहित शर्मा को टेस्ट क्रिकेट में बतौर सलामी बल्लेबाज टीम में शामिल किया जा सकता है। राहुल ने पिछली 12 पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक जड़ा है। उधर, वनडे और टी-20 टीम के उपकप्तान रोहित टेस्ट टीम का हिस्सा हैं, लेकिन अंतिम 11 से बाहर हैं। ऐसे में अब टीम प्रबंधन रोहित से टेस्ट क्रिकेट में भी पारी की शुरुआत कराने के लिए मान गया है, जिसकी वकालत सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण कर चुके हैं।

एमएसके प्रसाद ने कहा कि चयन समिति के तौर पर हम वेस्टइंडीज के दौरे के बाद नहीं मिले हैं। अगली बार जब भी चयनकर्ताओं की बैठक होगी तो हम इस मामले (रोहित को टेस्ट ओपनर) पर विचार करेंगे। प्रसाद ने राहुल का बचाव करते हुए कहा कि राहुल के पास कौशल है। हां, लेकिन मौजूदा समय वह बुरे दौर से गुजर रहा है। हम उसकी फॉर्म को लेकर चिंतित हैं। राहुल को विकेट पर टिकना होगा और अपनी फॉर्म पानी होगी।

माना जा रहा है कि रोहित टेस्ट मैचों में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पारी की शुरुआत कर सकते हैं। रोहित के पास खुद को ओपनिंग बल्लेबाज साबित करना का मौका इसलिए भी है, क्योंकि राहुल, शिखर धवन और मुरली विजय जैसे खिलाड़ी पारी की शुरुआत करने में असफल रहे हैं। हालांकि, मयंक अग्रवाल ने थोड़ा बहुत अच्छा करने की कोशिश की है, लेकिन वे बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे हैं। कुलदीप यादव और युजवेंद्रा सिंह चहल वेस्टइंडीज के खिलाफ खत्म हुई टी-20 सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थे। वे आगामी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में भी टी-20 टीम का हिस्सा नहीं हैं लेकिन इसके बावजूद प्रसाद ने कहा कि ये दोनों अगले विश्व कप में टीम की रणनीतियों का हिस्सा रहेंगे।

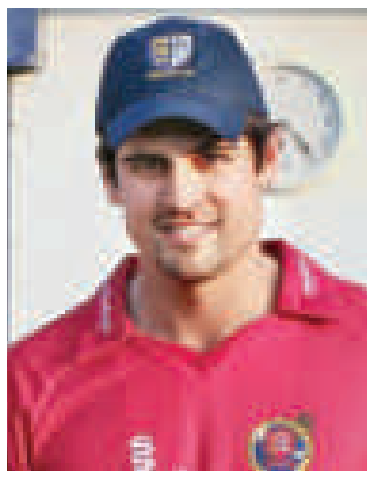
एशेज डायरी

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने किसी भी कीमत पर जीत दर्ज करने की मानसिकता को लेकर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को घेरा

अंगुलियों में बंधे टेप से गेंद से छेड़छाड़ करते थे वार्नर : कुक

लंदन, आइएएनएस : क्रिकेट में गेंद से छेड़छाड़ का मुद्दा इस खेल की प्रतिष्ठा को कई बार तार-तार कर चुका है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही एशेज सीरीज के दौरान एक बार फिर गेंद से छेड़छाड़ का विवाद सुर्खियों में आ गया है। इस बार इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज एलिस्टेयर कुक ने अपनी आत्मकथा में इसे लेकर चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन किए हैं। उन्होंने गेंद से छेड़छाड़ को लेकर ऑस्ट्रेलियाई ओपनर और धाकड़ बल्लेबाज डेविड वार्नर पर निशाना साधा है और साथ ही किसी भी कीमत पर जीत दर्ज करने की मानसिकता को लेकर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को भी घेरा है।

मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के व्यवहार से कोई सबसे ज्यादा रूबरू होता है तो वो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ऐसा इन दोनों टीमों के बीच बेहद लंबे समय से चल रही प्रतिद्वंद्विता के चलते है। यही वजह है कि सात एशेज सीरीज का हिस्सा रहे इंग्लैंड के पूर्व कप्तान कुक ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों और टीम को लेकर कई चौंकाने वाली बातें अपनी आत्मकथा में लिखी हैं। कुक ने लिखा है कि वार्नर ने बताया था कि उन्होंने एक प्रथम श्रेणी मैच में कैसे गेंद से छेड़छाड़ की थी। कुक के अनुसार वार्नर ने मुझे बताया कि कैसे एक प्रथम श्रेणी मैच में उन्होंने हाथ में बंधे टेप पर लगे मैटेरियल के जरिये गेंद से छेड़छाड़ की थी। उस समय अगर स्टीव स्मिथ दखलअंदाजी नहीं करते तो शायद वार्नर इससे जुड़े और राज भी उगल देते। कुक ने बताया कि यह वाकया 2017-2018 की एशेज सीरीज के बाद हुई एक पार्टी के दौरान का है। जैसे ही वार्नर ने इस बात का खुलासा किया, मैंने स्टीव स्मिथ की ओर देखा। उनके चेहरे का भाव ऐसा था मानो वार्नर से कह रहे हों कि तुम्हें यह बात नहीं बतानी चाहिए थी।



इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टेयर कुक। फाइल

कुक ने आत्मकथा में लिखा है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम किसी भी कीमत पर जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरती है। चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। हालांकि कुक ने सीधे तौर पर बेईमानी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन संकेतों पर साफ कर दिया कि ऑस्ट्रेलियाई टीम जीत के लिए कुछ भी कर सकती है।

कुक के अनुसार, ऑस्ट्रेलियाई के लोग अपनी टीम के हर हाल पर जीत दर्ज करने के तौर-तरीकों से संतुष्ट नहीं हैं मगर ऑस्ट्रेलियाई टीम इस मामले में बहुत दूर तक निकल गई है। हालांकि गेंद से छेड़छाड़ विवाद के बाद से ऑस्ट्रेलियाई टीम प्रशंसकों का दिल जीतने की कोशिश में लगी है। टीम के कोच जस्टिन लैंगर ने ड्रेसिंग रूम की संस्कृति बदल दी है और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैदान पर अधिक विनम्र नजर आ रहे हैं।

बॉयकॉट और स्ट्रॉस को नाइटहुड से सम्मानित किया गया

लंदन : इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटरों जेफ्री बॉयकॉट और एंड्रयू स्ट्रॉस को इंग्लैंड की पूर्व प्रधानमंत्री टेरेजा मे ने इस्तीफे के साथ अपनी सम्मान सूची में नाइटहुड के लिए शामिल किया था। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साथ शानदार करियर के बाद खेल के प्रति सेवाओं के लिए बॉयकॉट और स्ट्रॉस को सोमवार को सर की उपाधि दी गई। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी टॉम हैरिसन ने कहा कि हमें इससे अधिक खुशी नहीं हो सकती कि एंड्रयू स्ट्रॉस खेल के अन्य दिग्गज खिलाड़ियों की सूची में शामिल होंगे जिन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए नाइटहुड दी गई।

उन्होंने कहा कि सर जेफ्री बॉयकॉट को भी तहेदिल से बधाई, क्रिकेट में लंबे करियर और खेल के प्रति जुनूनी प्रतिबद्धता के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। बॉयकॉट ने इंग्लैंड की ओर से 1964 से 1982 के बीच टेस्ट क्रिकेट में 47 .72 की औसत से 8114 रन बनाए। इंग्लैंड और मिडिलसेक्स के पूर्व बल्लेबाज स्ट्रॉस ने 2004 से 2012 के बीच 100 टेस्ट में 7037 रन बनाए। स्ट्रॉस की अगुआई में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2009 और 2010-11 में एशेज सीरीज जीती।

एशेज में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के करीब पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पेन

लंदन : टिम पेन की टीम गुरुवार से शुरू हो रहे पांचवें और अंतिम टेस्ट में हार से बच जाती है तो यह विकेटकीपर बल्लेबाज इंग्लैंड की सरजमीं पर टेस्ट सीरीज जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई कप्तानों की सूची में शामिल हो जाएगा। पेन अगर यह उपलब्धि हासिल करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के कई दिग्गज कप्तानों को पीछे छोड़ देंगे जिसमें ग्रेग चैपल भी शामिल हैं। इसके अलावा रिकी पोंटिंग और माइकल क्लार्क जैसे दिग्गज बल्लेबाज और कप्तान तो दो प्रयासों में भी इंग्लैंड में एशेज नहीं जीत पाए। इंग्लैंड में पिछली बार एशेज सीरीज जीतने का सम्मान स्टीव वॉ को मिला था जिनकी अगुआई में ऑस्ट्रेलिया ने 18 साल पहले 4-1 से जीत दर्ज की थी। चैपल, पोंटिंग और क्लार्क ऑस्ट्रेलिया के महानतम क्रिकेटरों में शामिल रहे लेकिन उनकी अगुआई में टीम इंग्लैंड में एशेज सीरीज नहीं जीत पाई। पेन को बेहद मुश्किल समय में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी सौंपी गई।

मार्च 2018 में केपटाउन में गेंद से छेड़छाड़ प्रकरण में तत्कालीन कप्तान स्टीव स्मिथ से कप्तानी छीने जाने और डेविड वार्नर को उप कप्तानी से हटाए जाने और दोनों पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा 12 महीने का प्रतिबंध लगाने के बाद पेन को टीम की बागडोर सौंपी गई। पाकिस्तान के खिलाफ 2010 में लार्ड्स में ऑस्ट्रेलिया की ओर से टेस्ट पदार्पण करने वाले पेन 2017 में क्रिकेट से संन्यास लेने और इसकी जगह खेल सामान बनाने वाली कंपनी के साथ जुड़ने के करीब थे। पेन हालांकि इसके बाद टीम में वापसी करने में सफल रहे और एक साल बाद केपटाउन प्रकरण के बाद उन्हें कप्तान बनाया गया। पेन पर आरोप लगे कि वह 'दुर्घटनावश' कप्तान बने और टीम में उनका स्थान नहीं बनता लेकिन इस क्रिकेटर ने अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी और अब टीम को एशेज सीरीज जिताने की दहलीज पर ले आए हैं।



विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेंगे शंकर

नई दिल्ली : ऊंची कूद के खिलाड़ी तेजस्वनी शंकर ने इसी महीने के आखिरी में दोहा में होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप से अपना नाम वापस ले लिया है। शंकर ने इस बात की जानकारी भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआइ) को दे दी है। एएफआई ने मंगलवार को शंकर के चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेने की जानकारी दी। विश्व चैंपियनशिप कतर की राजधानी दोहा में 27 सितंबर से शुरू होगी।

हम अर्जेंटीना के स्टार फारवर्ड लियोन मेसी को 2003 में इंग्लिश क्लब में लाना चाहते थे।
– आर्सेन वेंगर, आर्सेनल के पूर्व कोच



बेल्जियम, नीदरलैंड्स और जर्मनी की आसान जीत

फुटबॉल डायरी ▶ बेल्जियम ने स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स ने इस्टोनिया जबकि जर्मनी ने उत्तरी आयरलैंड को हराया

तीनों टीमें यूरो 2020 क्वालीफाई करने के नजदीक पहुंचीं

पेरिस, एएफपी : बेल्जियम, नीदरलैंड्स और जर्मनी की टीमों ने अपने-अपने मुकाबलों में आसान जीत दर्ज करके अगले साल होने वाले यूरो 2020 क्वालीफाई करने की ओर अपना एक और कदम बढ़ा दिया है। बेल्जियम की टीम ने एकतरफा अंदाज में स्कॉटलैंड को 4-0 से शिकस्त दी जबकि नीदरलैंड्स ने इसी अंतर से इस्टोनिया को मात दी। इसके अलावा जर्मनी की टीम ने भी उत्तरी आयरलैंड को 2-0 से हरा दिया। दुनिया की नंबर एक बेल्जियम की टीम हालांकि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकी लेकिन इसके बावजूद स्कॉटलैंड को हराने में सफल रही। ग्रुप-आई में बेल्जियम की छह मैचों में यह छठी जीत है। अन्य मैचों में ग्रुप-ई में क्रोएशिया को बाकू में अजरबैजान ने 1-1 से बराबरी पर रोका जबकि स्लोवाकिया ने बुडापेस्ट में हंगरी को 2-1 से हराया।

लुकाकू ने खोला खाता : इंटर मिलान के स्ट्राइकर बेल्जियम के रोमेलु लुकाकू ने स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच के नौवें मिनट में गोल करके अपनी टीम का खाता खोला। लुकाकू अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए 50 गोल करने से सिर्फ एक कदम दूर हैं। इसके बाद डिफेंडर थॉमस वर्माएलेन ने 24वें मिनट में बॉक्स के अंदर से गोल करके बेल्जियम को मैच में 2-0 से आगे कर दिया। पहले हाफ के खत्म होने में जब खेल समाप्ति में 13 मिनट बचे थे तब टॉबी एल्डरविल्डे ने गोल करके स्कॉटलैंड की वापसी पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया। मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्डर केविन डि ब्रूने ने शुरुआती तीनों गोलों में भूमिका निभाई और 82वें मिनट में गोल करके जीत का अंतर 4-0 कर दिया।

ब्रूने ने कहा, 'यह हमारा विश्वस्तरीय प्रदर्शन नहीं था। हमने सिर्फ वही किया जो हमें करना था। पहला गोल करने के बाद हमने मैच पर नियंत्रण बना लिया और फिर स्कॉटलैंड को कोई मौका नहीं दिया।' स्कॉटलैंड की टीम छह अंकों के साथ पांचवें स्थान पर खिसक गई है और यूरो कप के लिए क्वालीफाई करने का उसका सपना लगभग खत्म हो गया।

हार से उबरा जर्मनी : ग्रुप-सी के अपने पिछले मैच में जर्मनी को नीदरलैंड्स के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन इस मैच को जीतकर वह दोबारा ग्रुप तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया। पांच टीमों के ग्रुप में उत्तरी आयरलैंड और जर्मनी के 12-12 अंक हैं, लेकिन गोल अंतर के आधार पर जर्मनी शीर्ष पर मौजूद हैं। दोनों टीमों के बीच मुकाबले के पहले हाफ में कड़ी टक्कर देखने को मिली। मेजबान टीम ने जर्मनी के खिलाफ बेहतरीन डिफेंस किया और पहले हाफ में कोई भी टीम बढ़त नहीं बना पाई। दूसरे हाफ की शुरुआत जर्मनी के लिए बेहतरीन रही। 48वें मिनट में मार्सेल हॉलस्टनबर्ग ने हाफ वॉली के जरिये बेहतरीन गोल करते हुए जर्मनी को बढ़त दिलाई। इसके बाद मेजबान टीम ने वापसी की कोशिशें तेज कर दी, लेकिन जर्मनी ने ज्यादातर समय गेंद अपने पास रखकर उसे वापसी का कोई बड़ा मौका नहीं दिया। इंजुरी टाइम (90+2वें मिनट) में सर्गी गनाबरी के गोल ने उत्तरी आयरलैंड की वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए।

बाबेल ने दागे दो गोल : नीदरलैंड्स के रियान बाबेल ने इस्टोनिया के खिलाफ मैच में सबसे ज्यादा दो गोल दागे। पहला गोल उन्होंने मैच के 17वें मिनट में किया और अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। पहले हाफ में नीदरलैंड्स और कोई गोल नहीं कर सका लेकिन दूसरा हाफ पूरी तरह से उसके नाम रहा। बाबेल ने 47वें मिनट में अपना दूसरा गोल करके नीदरलैंड्स की बढ़त को दोगुना कर दिया। इसके बाद इस्टोनिया मुकाबले से पूरी तरह बाहर हो गई। 76वें मिनट में मेंफिस डिपे ने मौके को भुनाते हुए गोल किया और स्कोर 3-0 कर दिया। मैच का आखिरी गोल जीजी वाइनाल्डम ने 87वें मिनट में किया।



गोल करने के बाद जश्न मनाते डि ब्रूने। एपी

ईरानी महिला फुटबॉल प्रशंसक की मौत

तेहरान, रायटर : एक सप्ताह पहले खुद को आग के हवाले करने वाली ईरानी महिला फुटबॉल प्रशंसक की मृत्यु हो गई। महिला ने पुरुष बनकर स्टेडियम में प्रवेश करने का प्रयास किया था लेकिन पकड़ी गई थी। उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और इसी के बाद उसने खुद को आग लगा ली थी। उसे मार्च में गिरफ्तार किया गया था।

जेम्स के गोल ने दिलाई वेल्स को जीत

कार्डिफ, आइएएनएस : युवा खिलाड़ी डेनियल जेम्स के गोल की बदौलत वेल्स ने दोस्ताना मैच में बेलारूस को 1-0 से हराया। घरेलू मैदान पर वेल्स की यह चौथी जीत है। बेलारूस के खिलाफ वेल्स की शुरुआत बेहतरीन रही। मैच के 17वें मिनट में मेजबान टीम ने आक्रमण बोला और इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर युनाइटेड से खेलने वाले जेम्स ने दमदार गोल करते हुए अपनी टीम की बढ़त दिला दी।

सिंधू बोलीं, भारत में उच्च स्तर के कोचों की जरूरत

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

▶ भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कहा, मैं हर टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करती हूं

हाल ही में विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर इतिहास रचने वाली भारत की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू ने माना कि भारत को उच्च स्तर पर अच्छे और खासकर विदेशी कोचों की जरूरत है। अच्छे कोचों के होने से खिलाड़ियों के खेल में जरूरी सुधार होगा और इससे देश को नए चैंपियन मिलने मदद मिलेगी।

सिंधू ने कहा, 'यह पूर्व खिलाड़ियों के ऊपर है कि वह कोच बनना चाहते हैं या नहीं। यह उनके ऊपर है कि वे क्या करना चाहते हैं। हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। उच्च स्तर के कोचों की जरूरत है, जो खेल के बारे में काफी अच्छे से जानते हैं और जो चैंपियन बना सकते हैं। गोपी सर एक महान खिलाड़ी और कोच हैं। इसमें कोई शक नहीं है। अब हमें विदेशों से अन्य प्रशिक्षकों की जरूरत है ताकि वे हमारे खेल में जरूरी बदलाव कर सके जिससे हमें मदद मिले।'

विश्व चैंपियन ने कहा, 'विश्व चैंपियनशिप ने मुझे काफी आत्मविश्वास दिया है। इसी आत्मविश्वास के साथ मैं आगे जाऊंगी। ओलंपिक में अभी समय है और इस दौरान मुझे काफी टूर्नामेंट भी खेलने हैं। मैं ज्यादा दूर की नहीं सोचूंगी सिर्फ जिस टूर्नामेंट में खेलूंगी उसी पर ध्यान दूंगी। जब मैं एक बार कोर्ट पर उतर जाती हूं तो कुछ दबाव नहीं रहता है और मैं सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करती हूं और आगे भी यही करूंगी। अब मुझ पर जिम्मेदारी बढ़ गई है और सभी लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। अब मुझे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मैं कुछ चीजों में बदलाव करूंगी और कुछ नया लेकर आने की कोशिश करूंगी क्योंकि हर किसी ने अब मेरा खेल देख लिया है और इसलिए अब मुझे कुछ नया करने की जरूरत है।'



पीवी सिंधू। (फाइल)

पानी, नौका और चप्पू के बिना नौकायन का अभ्यास



सिगरा स्टेडियम में शैडो अभ्यास करते नौकायान के खिलाड़ी। जागरण

जागरण संवाददाता, वाराणसी

गजब

- सिगरा स्टेडियम की सीढ़ियों पर प्रशिक्षु कर रहे शैडो अभ्यास
- बाढ़ के कारण गंगा नदी में नहीं हो पा रहा है अभ्यास

बिना पानी, नौकायन और चप्पू के नौकायन का अभ्यास करते हुए आपने किसी को देखा है? अगर नहीं देखा है तो आप वाराणसी के सिगरा में स्थित डॉ.संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम जा सकते हैं। मंगलवार को यहां तीन प्रशिक्षु सीढ़ियों में बैठकर चप्पू की जगह डंडा लेकर इसी तरह से नौकायन का अभ्यास कर रहे थे।

जब इस बारे में अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षक मनीष कुमार तिवारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गंगा नदी में बाढ़ के कारण इस समय वह वहां पर नौकायन का अभ्यास नहीं करा पा रहे हैं। प्रशिक्षुओं को नौकायन की शुरुआती जानकारी देने के लिए इस तरह का अभ्यास कराया जाता है। प्रयागराज में भी ऐसा किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण (एनआइएस) के त्रिवेंद्रम केंद्र में भी इसको प्रयोग में लाया जाता है। नौकायन के अलावा कयाकिंग और कैनोइंग में भी इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है।

उप क्रीड़ाधिकारी सुनील कुमार मांझी ने बताया कि वाराणसी में पहली बार खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश ने नौकायन और कयाकिंग एंड कैनोइंग के अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षण नियुक्त किए हैं। इस समय गंगा नदी में बाढ़ आई हुई है। प्रशिक्षुओं का नुकसान न हो इसलिए उन्हें शैडो अभ्यास कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश नौकायन संघ के सचिव सुधीर शर्मा ने बताया कि बाढ़ के कारण प्रशिक्षुओं का दिन खराब न हो इसके लिए डेमो अभ्यास करना गलत नहीं है। बनारस में पहली बार रोइंग का प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ है। जल्द ही यहां पर उपकरण उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

गर्मी, लू, सूखे के लिए बदल सकते हैं क्रिकेट के नियम

▶ जलवायु परिवर्तन की वजह से गर्मी से जुड़े नियम लागू करने का सुझाव

लंदन, एएफपी : जलवायु परिवर्तन को देखते हुए क्रिकेट में गर्मी से जुड़े नियम लागू करने के सुझाव के साथ एक शोध जारी किया गया है। इस शोध में खराब मौसम में खेल को स्थगित करने का सुझाव दिया गया है। खेल शोधकर्ताओं और पर्यावरण शिक्षाविदों के इस शोध को मंगलवार को जारी किया गया।

ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर सस्टेनेबल स्पोर्ट और दो विश्वविद्यालयों द्वारा मिलकर किए शोध के आधार पर यह सुझाव दिया गया है। इसमें युवा खिलाड़ियों पर अधिक ध्यान देने को कहा गया है और साथ ही खेल सामग्री बनाने वाली कंपनियों को ऐसी सामग्री बनाने को कहा गया है जिसमें हवा बेहतर तरीके से गुजर सके क्योंकि बेहद गर्म मौसम अब अधिक स्थानों पर देखा जा रहा है।

इस रिपोर्ट की प्रस्तावना लिखने वाले लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान के अधिकारी रसेल सेयमोर ने कहा कि यह सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि सभी खेलों के लिए इस मुद्दे पर गंभीर होना का समय है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी एक जगह खड़े नहीं रहते हैं और हमें आने वाले संकट से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। हिट फॉर सिक्स नाम की इस रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि किस तरह भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्रिकेट खेलने वाले देशों में खराब मौसम का असर पड़ रहा है, जिसमें सूखा, लू और तूफान जैसे मुश्किल मौसम का जिक्र है।

विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस तरह के मौसम सामान्य होते जा रहे हैं। इसमें बताया गया कि है कि गर्मी के कारण ऑस्ट्रेलिया में आयु वर्ग के मैचों पर असर पड़ा, पानी की कमी के कारण दक्षिण अफ्रीका दौरा प्रभावित हुआ और बाढ़ के कारण इंग्लैंड में क्रिकेट सत्र में विलंब हुआ।

यू मुंबा ने तेलुगु टाइटंस को हराया

खेल संवाददाता, जागरण : प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल-7) के सातवें सत्र में मंगलवार को रेडर अर्जुन देशवाल के शानदार खेल के दम पर यू मुंबा ने तेलुगु टाइटंस को 41-27 अंकों के अंतर से हरा दिया। अर्जुन ने 10 अंक अर्जित किए। रेडर रोहित बालियान और डिफेंडर के तौर पर खेलने वाले कप्तान फजेल अत्राचली ने भी अपनी टीम के लिए क्रमशः सात और छह अंक बटोरे। यू मुंबा का अब तक इस लीग में प्रदर्शन कमाल का रहा है।

पहले हाफ में मुकाबला बराबर का रहा। दोनों ही टीमों ने एक दूसरे को कोई मौका नहीं दिया। कभी यू मुंबा तो कभी तेलुगु टाइटंस की टीमें अंकों के मामले में ऊपर-नीचे होती रहीं। पहले हाफ का खेल खत्म होने तक दोनों टीमें 15-15 अंक से बराबरी पर थी लेकिन दूसरे हाफ में मुंबा के खिलाड़ियों ने बेहद आक्रामकता दिखाई। मुंबा ने इस बार तेजी से बढ़त बनानी शुरू की और अंकों का फासला बढ़ता चला गया और अंत में 41-27 के बड़े अंतर से मुकाबले को अपने नाम किया।

विविध

डीआरडीओ के सुरक्षाकर्मी ने रायफल से की खुदकशी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में मंगलवार की सुबह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) आवासीय परिसर में तैनात मूल रूप से पंजाब के गुरदासपुर निवासी 51 वर्षीय हरजीत सिंह नामक सुरक्षाकर्मी ने सरकारी रायफल से खुद के सिर में गोली मार कर जान दे दी। वह डीआरडीओ सेंटर में डिफेंस सर्विस कॉर्प में सुरक्षाकर्मी के पद पर तैनात थे। घटनास्थल से पुलिस को सुसाइड नोट नहीं मिला है। लिहाजा उन्होंने आत्महत्या क्यों की, इसका स्पष्ट पता अभी नहीं चल सका है।

पुलिस के अनुसार हरजीत सिंह दिल्ली में बैरक में रहते थे। उनका परिवार पंजाब के गुरदासपुर में रहता है। परिवार में पत्नी, दो शादीशुदा बेटे व एक बेटी हैं। पहले हरजीत सिंह सेना में थे। वे 2014 में सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। बाद में 2016 में उनका चयन डिफेंस सर्विस कॉर्प में सुरक्षा कर्मी के तौर पर हो गया था। उनकी तैनाती वर्तमान में सिविल लाइंस स्थित डीआरडीओ परिसर में थी। ड्यूटी के लिए उन्हें इंसास रायफल जारी की गई थी। बताया जाता है कि मंगलवार की सुबह आठ बजे ड्यूटी खत्म होने के बाद वे हथियार जमा कराने जा रहे थे। इसके काफी देर बाद एक कर्मचारी ने देखा कि हरजीत सिंह खून से लथपथ पड़े हैं। उनके सिर में गोली लगने का निशान है, जबकि पास में ही उनकी राइफल भी पड़ी थी। सुबह 10.50 बजे घटना की सूचना पुलिस को दी गई।

रांची में चोरी का आरोप लगा दो बहनों को पेड़ से बांधकर पीटा

जागरण संवाददाता, बुढ़मू (रांची)

रांची के बुढ़मू में एक शर्मनाक घटना हुई। ठाकुरगांव थाना क्षेत्र में फसल चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने सोबा गांव में दो सगी बहनों सालो देवी व बालो देवी को पेड़ से बांधकर जमकर पीटा। इस पर भी जब ग्रामीणों का मन नहीं भरा, तो मानवीय संवेदनाओं को ताक में रखते हुए दोनों के बाल काट डाले। भीड़ उन्हें मार डालने पर उतारू थी, लेकिन पुलिस ने ऐन वक्त पर मौके पर पहुंचकर दोनों की जान बचाई। इस संबंध में ठाकुरगांव थाने में मामला दर्ज किया गया है।

चोरी की अफवाह के बाद शुरू हुआ बवाल : सब्जी का कारोबार करने वाली सालो देवी कांके ब्लाक के गागी व बालो देवी बुढ़मू ब्लाक के बुतरू गांव की रहनेवाली हैं। वे दोनों रविवार को उमेडंडा साप्ताहिक हाट से सब्जी खरीदने के बाद घर लौट रही थीं। इसी बीच ठाकुरगांव के बेड़वारी पावर ग्रिड के समीप इनका ऑटो खराब हो गया। ये दोनों सोबा गांव स्थित अपने मायके आ गईं और रात वहीं रुक गईं। सोमवार की सुबह हाथ में सब्जी का थैला लेकर जा रही थीं।

इसी बीच ग्रामीणों के बीच अफवाह उड़ गई कि महिलाएं खेतों से सब्जी चोरी कर ले जा रही हैं। इस दौरान दोनों महिलाएं रातू चट्टी स्थित बाजार चली गईं। पीछे वहां दर्जनों ग्रामीण पहुंचे और मारपीट करते हुए सोबा गांव लेकर आए। ग्रामीणों ने दोनों की पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई की। इसी दौरान सूचना पाकर ठाकुरगांव के ग्रामीण भी पहुंचे और पिटाई करते हुए दोनों को अधमरा कर दिया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को भीड़ से छुड़ाते हुए रिम्स भेजा।

प्राथमिकी दर्ज, लोगों ने किया विरोध

महिलाओं के बयान के आधार पर मंगलवार को ठाकुरगांव थाना में 19 नामजद व दो दर्जन अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की कार्रवाई के बाद मंगलवार को दर्जनों महिला-पुरुषों ने थाना पहुंचकर विरोध प्रकट किया। साथ ही महिलाओं के खिलाफ सब्जी चोरी करने का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया। थाना प्रभारी नवीन कुमार ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है, पर मामला संज्ञान में आने से पूर्व किसी भी किसान या व्यापारी द्वारा खेत या घर से सब्जी चोरी होने का कोई मामला थाने में दर्ज नहीं कराया गया था। वहीं, ग्रामीणों के अनुसार वे खेतों से फसल चोरी की घटना से परेशान हैं।



रांची के बुढ़मू में पेड़ से बांधी गईं फसल चोरी के आरोप में पकड़ी गईं महिलाएं। जागरण

भूखे व बीमार बाघ ने कीपर पर किया हमला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : चिड़ियाघर में कई दिनों से भूखे व बीमार चल रहे रॉयल बंगाल टाइगर रामा ने मंगलवार सुबह पानी पिलाने के लिए बाड़े में पहुंचे बीट कीपर फतेह सिंह को घायल कर दिया। हमले में कीपर की उंगलियों में गंभीर चोट आई है। फतेह सिंह को उपचार के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बीमार और भूखा था बाघ : जानकारी के मुताबिक रामा बाघ बीमारी की वजह से कई दिनों से खाना नहीं खा रहा था। इस कारण वह चिड़चिड़ा भी हो गया था। बाघ की तबियत को देखते हुए चिड़ियाघर की ओर से रामा के इलाज के लिए बरेली के डॉक्टरों की स्पेशल टीम को बुलाया गया था। जो सोमवार की रात ही चिड़ियाघर में पहुंची थी। ऐसे में अल सुबह पांच बजे करीब चिड़ियाघर की निदेशक रेणु सिंह के साथ डॉक्टरों की टीम जांच के लिए पहुंची थी। इस दौरान कीपर फतेह सिंह उसे पानी देने के लिए गए तो भूखे बाघ रामा ने उन पर हमला बोल दिया। कीपर की उंगलियां बाघ के शिकंजे में फंस आ गई थीं।

तोहफे में मिला रामा : आठ वर्षीय रामा बाघ दिल्ली के चिड़ियाघर को उपहार के तौर पर मिला था। जिसको देखने के लिए दिल्ली समेत एनसीआर से पर्यटक पहुंचते हैं।

पहले भी हुआ है ऐसा हादसा : चिड़ियाघर में यह पहला मामला नहीं है जब किसी जानवर ने हमला किया हो। बल्कि एक बार एक हाथी ने आक्रमक होकर महावत पर हमला बोल दिया था।

यमुना एक्सप्रेस-वे से 30 फीट नीचे गिरी बुलेट, दो की मौत

- जीरो प्वाइंट के समीप तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर नीचे गिरी बुलेट, नॉलेज पार्क कोतवाली क्षेत्र का मामला
- निजी फैक्ट्री में प्रबंधक व सेल्स एक्जीक्यूटिव के पद पर नौकरी करते थे दोनों मृतक



यमुना एक्सप्रेस-वे पर हुए हादसे में मौत के बाद ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में शोकाकुल परिजन। जागरण

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

यमुना एक्सप्रेस वे के जीरो प्वाइंट के समीप तेज रफ्तार में बुलेट मोटरसाइकिल 30 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गई। हादसे में बुलेट सवार प्रबंधक व उनके साथी की मौत हो गई। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि तेज रफ्तार में बुलेट पहले एक्सप्रेस-वे के किनारे लगी रेलिंग से टकराई और फिर नीचे गिर गई। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में कोई लिखित शिकायत पुलिस को नहीं मिली है।

मूलरूप से आगरा के साईं सदन आवास विकास कॉलोनी सेक्टर आठ सिकंदरा के रहने वाले 46 वर्षीय पल्लव गौड़ और अलीगढ़ के रामनगर कॉलोनी आइटीआइ रोड बन्ना देवी के रहने वाले 35 वर्षीय गौरव चौहान एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे। पल्लव क्षेत्रीय प्रबंधक व गौरव क्षेत्रीय सेल्स एक्जीक्यूटिव थे। दोनों मंगलवार सुबह करीब नौ बजे बुलेट पर सवार होकर नोएडा आ रहे थे। यमुना एक्सप्रेस वे पर जीरो प्वाइंट के समीप जब दोनों पहुंचे तो तेज रफ्तार में एक्सप्रेस वे से नीचे उतरने के दौरान कर्व पर उनकी बुलेट अनियंत्रित हो गई और रेलिंग से टकराकर 30 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरी। हादसे में पल्लव व गौरव दोनों घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए कैलाश अस्पताल लाया गया, जहां डाक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

गत दिनों पांच कर्मचारियों की हुई थी मौत : तीन सप्ताह पहले यमुना एक्सप्रेस वे पर इसी जगह तेज रफ्तार में एंडेवर कार कर्व पर रेलिंग से टकरा कर 30 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरी थी। उस हादसे में युवती समेत कुल पांच की मौत हो गई थी। मामले में युवती के पिता ने कार चला रहे उसके दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उपचार के दौरान उस दोस्त की भी मौत हो गई थी।

फरीदाबाद में हत्या कर किशोरी को यमुना किनारे दफनाया, 11 दिन बाद शव बरामद

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद

एक कॉलोनी क्षेत्र से 30 अगस्त को लापता साढ़े सोलह वर्षीय किशोरी की हत्या उसके पड़ोस में दुकान करने वाले प्रदीप नाम के युवक ने उसी दिन गला घोंटकर कर दी थी। शव उसने दो साथियों संग कबूलपुर खादर कैप्टन फार्म क्षेत्र में यमुना किनारे तीन फुट गहरा गड्ढा खोदकर दफना दिया था। मंगलवार को सेक्टर-85 क्राइम ब्रांच पुलिस ने प्रदीप और उसके साथी वसीम को गिरफ्तार किया तो उन्होंने राज उगला।

वसीम की निशानदेही पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में यमुना किनारे झाड़ी के नीचे गड्ढा खोदकर शव बरामद कर लिया। खेड़ी पुल थाने में 30 अगस्त को किशोरी की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज है। अब मुकदमे में हत्या की धारा जोड़ी गई है। फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट से दुष्कर्म की बात स्पष्ट होगी तो दुष्कर्म की धारा जोड़ी जाएगी। शव का पोस्टमॉर्टम बुधवार को पीजीआइ रोहतक में होगा।

मुख्य आरोपित गांव भतौला निवासी प्रदीप की किशोरी के घर के पास सरिया की दुकान है। पुलिस पूछताछ में प्रदीप ने बताया है कि उसने किशोरी को प्रेमजाल में फंसा लिया था। प्रदीप पहले ही शादीशुदा है। ऐसे में वह किशोरी से छुटकारा पाना चाहता था। 30 अगस्त को वह किशोरी को कार में बिठाकर वजीरपुर रोड पर लेकर गया और गला घोंटकर हत्या कर दी। वसीम व अमर सिंह के साथ कार में ले जाकर शव को दफना दिया। अमर सिंह की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। पिता के मुताबिक उनकी बेटी दसवीं कक्षा की छात्रा थी। 30 अगस्त को दोपहर 12.15 बजे लापता हुई। परिजनों को शुरू से ही प्रदीप पर संदेह था। उन्होंने खेड़ी पुल पुलिस को भी बताया, मगर पुलिस ने अनसुना कर दिया था।

> गुमशुदगी के दर्ज मुकदमे में हत्या की धारा जोड़ी गई है। जबकि फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट आने के बाद दुष्कर्म की धारा जोड़ी जाएगी। मुख्य आरोपित सहित दो को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों से पूछताछ के बाद ही हत्या की असली वजह साफ होगी।
> – लोकेंद्र सिंह, डीसीपी, सेंट्रल

दिल्ली और पंजाब से एनसीबी ने पकड़ी हेरोइन, दो गिरफ्तार

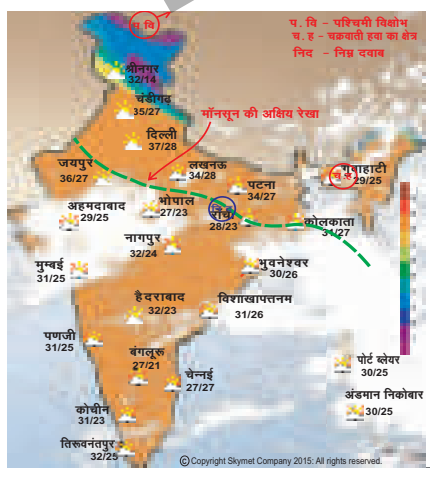
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से हेरोइन की तस्करी करके उसे दिल्ली, पंजाब और मुंबई में खपाने वाले अंतरराष्ट्रीय तस्कर गिरोह से जुड़े दो लोगों को गिरफ्तार किया है। कनाडा से भेजी गई 422 ग्राम हेरोइन के साथ जालंधर के रहने वाले योगेश कुमार धूना को पकड़ने के बाद हेरोइन को पंजाब में पहुंचाने वाले जालंधर के रहने अक्षिंदर सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके घर में हेरोइन बनाने का कच्चा माल और 112 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। फिलहाल गिरोह में शामिल अन्य तस्करों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इस कार्रवाई को दिल्ली क्षेत्रीय इकाई और अमृतसर, पंजाब की उपक्षेत्रीय इकाई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया।

एनसीबी के उप महानिदेशक एसके झा ने बताया कि अमृतसर उप क्षेत्रीय इकाई टीम को सूचना मिली कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से हेरोइन की तस्करी पंजाब, दिल्ली व मुंबई के लिए की जाने वाली है। दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने सूचना के आधार पर एक कंसाइनमेंट को पकड़ा जो कनाडा से पंजाब के लिए भेजा गया था। कंसाइनमेंट में प्रिंटिंग मशीनों के अंदर 422 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इसके बाद एक फर्जी कंसाइनमेंट बनाकर कूरियर कंपनी द्वारा उसी पते पर भेजा गया, जहां हेरोइन पहुंचनी थी। इसके बाद कंसाइनमेंट का पीछा करते हुए जालंधर में उसे लेने वाले योगेश कुमार धूना को पकड़ लिया गया। उसने पूछताछ में बताया कि वह हेरोइन को अक्षिंदर सिंह को देने वाला था।

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर में मौसम शुष्क तथा काफी गर्म रहेगा। हिमाचल प्रदेश में एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा संभव है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के शेष भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क व काफी गर्म बना रहेगा।



भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	31/25/व	अहमदाबाद	34/25/व
कोलकाता	33/26/व	बड़ोदा	31/24/व
चेन्नई	33/24/व	नागपुर	33/25/आंबा
हैदराबाद	31/24/व	इन्दौर	27/22/आंबा
बंगलूरु	28/20/व	रांची	31/24/व
विवेन्द्रम	33/25/आंबा	पटना	33/26/आंबा
गुवाहाटी	28/26/व	जमशेदपुर	33/24/व
गंगटोक	16/09/व	पुणे	23/22/व

राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

बुधवार 11 सितंबर 2019

आजकल

16

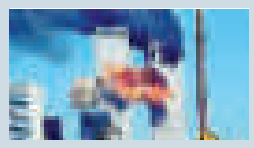
www.jagran.com

स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद को संबोधित किया



1893 में आज ही शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे स्वामी विवेकानंद ने जब भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से की तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। इस भाषण ने दुनिया में भारत की छवि मजबूत की।

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला



2001 में आज ही अमेरिका में अलकायदा के आतंकियों ने चार विमानों का अपहरण कर दो विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिया था। इस हमले में 19 आतंकी और करीब 3000 लोग मारे गए थे। यह हमला मानव इतिहास में सबसे घातक आतंकवादी हमला माना जाता है।

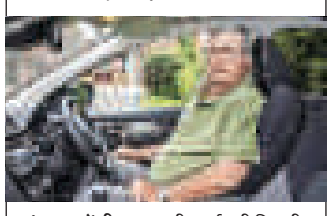
भूदान आंदोलन के जनक थे आचार्य विनोबा भावे



स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी नेता आचार्य विनोबा भावे का जन्म 1895 में आज ही महाराष्ट्र में हुआ था। उनका वास्तविक नाम विनायक नरहरी भावे था। भावे पहले शख्स थे, जिन्हें सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने चुना था। कम्युनिटी लीडरशिप के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। उन्हें संस्कृत, कन्नड़, उर्दू और मराठी समेत करीब 7 भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने भूदान आंदोलन की नींव रखी। 15 नवंबर, 1982 को उनका देहांत हो गया। 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित हुए।

इधर-उधर की

100 पाउंड जुर्माने के खिलाफ खर्च किए 30,000 पाउंड



लंदन, एजेंसी : अदालती कार्यवाही कितनी ढीली होती है ब्रिटेन में इसका एक उदाहरण सामने आया है। यहां एक सेवानिवृत्त इंजीनियर ने तेज गति से वाहन चलाने पर लगे 100 पाउंड के जुर्माने से बचने के लिए कोर्ट जाकर अपनी जीवन की कमाई के 30,000 पाउंड खर्च कर दिए। 71 वर्षीय रिचर्ड कीडवेल ने बताया कि उन्हें लगा कि कोर्ट में मामला जल्दी निपटेगा, लेकिन कानूनी दांवपेच ने उनकी जमा पूंजी खत्म कर दी। उन्होंने बताया कि 21000 पाउंड वकील की फीस, 7000 पाउंड अदालत में और बाकी आने-जाने में खर्च हो गए। कीडवेल जिस सड़क से जा रहे थे वहां, 30 मील (48 किमी) प्रति घंटा चलने की इजाजत थी और उन पर 35 मील (56किमी) प्रति घंटा चलने का आरोप लगा था। खास बात यह रही की तीन साल लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भी वह हार गए।

शोध अनुसंधान

जेब्राफिश से मिल सकता है आंखों के इलाज का रास्ता



वैज्ञानिकों ने ऐसी प्रक्रिया का पता लगाया है, जिससे जेब्राफिश अपनी क्षतिग्रस्त रेटिना की मरम्मत करती है। इस प्रक्रिया की मदद से मनुष्यों में भी रेटिना के इलाज का नया रास्ता मिल सकता है। स्तनधारी जीवों में अपने किसी क्षतिग्रस्त अंग को तुरंत सही कर लेने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन जेब्राफिश में यह क्षमता होती है कि अगर उसकी रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाए तो वह उसकी मरम्मत कर लेती है। अमेरिका की वांडरबिल्ट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया है कि वयस्क जेब्राफिश के रेटिना की म्यूलर ग्लिया (एमजी) कोशिकाएं स्टेम कोशिकाओं की तरह काम करती हैं। अभी वैज्ञानिकों ने उस प्रक्रिया को समझने में सफलता पाई है कि कैसे जेब्राफिश की रेटिना की कोशिकाएं सक्रिय होती हैं। अब वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश में हैं कि किस जीन की मदद से अन्य स्तनधारी जीवों में ऐसा करना संभव हो सकता है। - प्रेट्र

उम्र के साथ वजन बढ़ते जाने का कारण पता चला

आपने आसपास ऐसे बहुत लोगों को देखा होगा, जिनका वजन बढ़ती उम्र के साथ बढ़ता जाता है। यहां तक कि खानपान और व्यायाम में कोई बदलाव नहीं करने पर भी वजन थामने में उन्हें मुश्किल होती है। स्वीडन के वैज्ञानिकों ने इसका कारण पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने औसतन 13 साल तक 54 पुरुषों और महिलाओं की वसा कोशिकाओं पर अध्ययन किया। वैज्ञानिकों ने पाया कि बढ़ती उम्र के साथ इन लोगों के वसा ऊतकों (टिश्यू) का लिपिड टर्नओवर लगातार कम होता गया। ऐसे में जिन लोगों ने समय के साथ खाने में कैलोरी की मात्रा कम नहीं कि उनका वजन औसतन 20 फीसद ज्यादा बढ़ गया। प्रोफेसर पीटर आर्नर ने कहा कि इन नतीजों से पहली बार यह सामने आया है कि हमारे वसा ऊतकों में होने वाली प्रक्रिया यह तय करती है कि बढ़ती उम्र के साथ हमारा वजन किस तरह बढ़ेगा। इससे मोटापे के इलाज का नया रास्ता खुल सकता है। - प्रेट्र

गूगल के एकाधिकार की होगी जांच

बड़ा कदम ▶ ऑनलाइन विज्ञापन बाजार पर वर्चस्व की भी होगी जांच

अमेरिका के सभी 50 राज्य ने कहा- गूगल के बर्ताव के चलते इंटरनेट मुफ्त नहीं



वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका के सभी 50 राज्यों ने दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी गूगल के संभावित एकाधिकारवादी बर्ताव और ऑनलाइन विज्ञापन बाजार में उसके वर्चस्व की जांच करने का एलान किया है। इन राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने सोमवार को कहा कि गूगल के कुछ बर्ताव के चलते इंटरनेट मुफ्त नहीं है।

कोलंबिया के अटॉर्नी जनरल कार्ल रैसीन ने यहां कहा, 'विभिन्न राज्य और क्षेत्र गूगल के संभावित एकाधिकारवादी बर्ताव की जांच शुरू कर रहे हैं।' टेक्सास के अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन ने कहा, 'इंटरनेट पर विज्ञापन और सर्च के सभी पहलुओं पर गूगल का वर्चस्व है। कई उपभोक्ता मानते हैं कि इंटरनेट फ्री है। लेकिन हमें पता चला है कि गूगल का मुनाफा 117 अरब डॉलर (करीब आठ लाख 40 हजार करोड़ रुपये) है तो इंटरनेट कहां फ्री है।' अमेरिकी कंपनी गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है।

आरोपों को गूगल ने ठुकराया : गूगल ने आरोपों को ठुकराते हुए कहा कि अमेरिका में उसकी सेवाओं से लोगों को मदद मिलती है और ज्यादा विकल्प मिलते हैं। हजारों नौकरियों और छोटे कारोबार को समर्थन भी मिलता है। नई जांच पर गूगल के वैश्विक मामलों के उपाध्यक्ष केंट वाकर ने कहा, 'हमारे लिए यह नया नहीं है। पूर्व में अमेरिका के न्याय विभाग की ओर से की गई जांच में जो सवाल पूछे गए थे, उनके जवाब दिए गए थे। हमें उम्मीद है कि अटॉर्नी जनरल भी वही सवाल पूछेंगे। हम नियामकों के साथ हमेशा रचनात्मक काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे।'

फेसबुक भी जांच के दायरे में : अमेरिकी राज्यों के एक समूह ने गत शुक्रवार को फेसबुक के खिलाफ भी जांच का एलान किया था। ये राज्य इस बात की पड़ताल करेंगे कि क्या इस दिग्गज सोशल नेटवर्किंग साइट ने यूजर्स के डाटा की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए थे या नहीं। कड़ी प्रतिस्पर्धा को लेकर भी उसकी जांच की जाएगी।

इटली में फेसबुक ने दो दलों के एकाउंट बंद किए

रोम, एएफपी : सोशल नेटवर्क साइट फेसबुक ने इटली में दो राजनीतिक दलों के एकाउंट बंद कर दिए हैं। फेसबुक ने यह कार्रवाई इन दलों द्वारा कथित रूप से घृणा फैलाने वाले पोस्ट के कारण की है। इस कार्रवाई के बाद दोनों राजनीतिक दलों के नेताओं ने फेसबुक पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। फेसबुक ने एक बयान में कहा है, कि कासापाउंड और फोर्जा नोवा नामक दलों की ओर से नफरत फैलाने वाले पोस्ट किए गए। फेसबुक और इंस्टाग्राम सरीखे मंचों में ऐसे लोगों और संगठनों के लिए कोई जगह नहीं है जो दूसरी विचारधारा पर अपनी घृणा थोपते हैं। हमने जो एकाउंट ब्लाक किए वे नफरत फैलाने को लेकर कंपनी की नीतियों का पालन नहीं कर रहे थे।

कैंसर से जीत 11 माह, 11 दिन बाद लौटे ऋषि कपूर

- अभिनेता ने ट्वीट कर कहा - 11 महीने, 11 दिन बाद घर वापसी
- फिल्मी दुनिया की हस्तियों ने जताई खुशी, दीं शुभकामनाएं



न्यूयॉर्क में कैंसर का इलाज कराकर अभिनेता ऋषि कपूर सोमवार की देर रात मुंबई लौट आए। उनकी पत्नी नीतू सिंह भी साथ थीं। मिड-डे

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई

लगभग सालभर कैंसर से जंग लड़ने के बाद ऋषि कपूर की स्वदेश वापसी हो गई है। न्यूयॉर्क में इलाज कराने के बाद सोमवार देर रात उनकी घर वापसी हुई। अपनी सरजमीं पर कदम रखते ही ऋषि कपूर खासे उत्साहित नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर घर पहुंचने की खुशी जाहिर की और अपने शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा किया।

ऋषि ने ट्वीट किया, '11 महीने, 11 दिन बाद घर वापसी। आप सभी को धन्यवाद।' उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने कहा कि ऋषि की घर वापसी से हम सब खुश हैं। फिल्मी बिरादरी ने भी सोशल मीडिया पर उनका खुले दिल से स्वागत किया। गायक अदनान सामी ने लिखा, 'घर वापसी पर आपका स्वागत है।' अभिनेता फरहान अख्तर, शेखर कपूर और फिल्म निर्माता अतुल कासबेकर समेत कई फिल्मी हस्तियों ने उनकी वापसी पर खुशी व्यक्त की। फिल्ममेकर कुणाल कोहली ने लिखा, 'घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। घर वापसी पर आपका स्वागत है सर।' ऋषि कपूर के मित्र अनुपम खेर ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। अनुपम खेर अभी अमेरिका में हैं।

उल्लेखनीय है कि चार सितंबर को ऋषि ने न्यूयॉर्क में ही अपना 67वां जन्मदिन मनाया था। अनुभव सिन्हा ने जब उन्हें जन्मदिन की बधाई दी थी तो ऋषि ने 'मुल्क-2' में काम करने की इच्छा जताई थी। इस पर अनुभव ने कहा था कि आप वापस आएं 2, 3, 4 सब बन जाएंगी। कैंसर के इलाज के कारण लंबे समय तक अमेरिका में रुकने के चलते ऋषि कपूर को मुंबई और अपने घर की बहुत याद सता रही थी। उन्होंने अपना जन्मदिन अमेरिका के एक रेस्तरां में मनाया था, लेकिन उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा था। इसके बाद उन्होंने ट्वीट के जरिये रेस्तरां को लेकर अपनी निराशा का खुलकर प्रदर्शन किया था और लोगों से कहा था कि यहां आना ठीक नहीं।

इन्होंने भी जीती कैंसर से जंग



मनीषा कोइराला

2012 में मनीषा को ओवेरियन कैंसर होने का पता चला। मनीषा इलाज के लिए अमेरिका चली गईं। इलाज के बाद उन्होंने कैंसर पर अपनी किताब 'हील्ड : हाउ कैंसर गेव मी ए न्यू लाइफ' में उन्होंने लिखा, 'कैंसर मेरे जीवन में एक तोहफे की तरह आया। अब जीवन को देखने का मेरा नजरिया बदल गया है।'



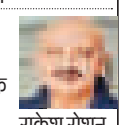
सोनाली बेंद्रे

पिछले साल सोनाली बेंद्रे ने भी सोशल मीडिया पर कैंसर होने की जानकारी दी थी। उन्होंने न्यूयॉर्क में इलाज कराया। अब वह स्वस्थ हैं।



ताहिरा कश्यप

आयुष्मान खुराना की पत्नी और डायरेक्टर ताहिरा कश्यप को पिछले साल पता चला कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। ताहिरा ने मुंबई में ही अपना इलाज कराया। अब वह अपनी पहली फिल्म के निर्देशन की तैयारी कर रही हैं।



राकेश रोशन

फिल्म निर्माता और निर्देशक राकेश रोशन के कैंसर से पीड़ित होने की जानकारी उनके पुत्र रितिक रोशन ने सोशल मीडिया के जरिये दी। राकेश का कैंसर फिलहाल पहले स्टेज पर है। वह इलाज करा रहे हैं।



इरफान खान

लंदन में एक साल तक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर का इलाज करवाने के बाद इरफान अब स्वस्थ हैं। फिलहाल अपनी फिल्म 'अंग्रेजी मीडियम' की शूटिंग में व्यस्त हैं।



लीजा रे

2009 में पता चला कि लीजा को ब्लड कैंसर है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बाद 2010 में वह कैंसर से मुक्त हो गई थीं। 2012 में उनकी शादी के आसपास उनका कैंसर फिर उभरा। लीजा ने उसका डटकर मुकाबला किया।

कोलकाता के संतोष की कृत्रिम हृदय के सहारे चल रही है जिंदगी

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- संतोष दूगड़ देश के उन गिने-चुने लोगों में शामिल हैं जो हृदय के रूप में एक डिवाइस के सहारे जी रहे हैं
- हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत वाले मरीजों में लगाई जाती है यह डिवाइस

देश में इस समय 120 लोग ऐसे हैं जो कृत्रिम हृदय की धड़कनों के साथ जी रहे हैं। ऐसे ही विरले लोगों में एक हैं कोलकाता के संतोष दूगड़ (63)। वह पिछले दस साल से मशीनी (डिवाइस) हृदय के साथ जी रहे हैं। वह कृत्रिम हृदय के साथ इतने लंबे समय तक जीवित रहने वाले गिने-चुने भारतीयों में शामिल हैं। यह मशीन हृदय की तरह ही काम करती है और उन मरीजों को लगाई जाती है जिन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। संतोष के शरीर में 2009 में कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था। संतोष को 2000 में पता चला था कि उन्हें हृदय रोग है जो अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। इसके बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा। तब संतोष ने डॉक्टरों की सलाह पर 'लेफ्ट वेंट्रीक्युलर असिस्ट डिवाइस' लगवाई।

बैग लेकर चलना जरूरी है : इस मशीन की सबसे बड़ी खामी यह है कि इसके साथ एक बैग लेकर चलना पड़ता है। इसके अलावा चूंकि यह मशीन टाइटेनियम की बनी है इसलिए मरीज कभी एमआरआइ स्कैन नहीं करा सकता है। बहरहाल, संतोष इस मशीन को धन्यवाद देते हैं, जिसकी बदौलत वह सामान्य जीवन जी रहे हैं।

एक करोड़ में मंगाई थी मशीन : कोलकाता के बिजनेसमैन संतोष ने बताया कि वैसे तो सबसे अच्छा विकल्प हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी था, लेकिन उन दिनों में ट्रांसप्लांट बहुत दुर्लभ था। इसके अलावा यह भी तय नहीं था कि हार्ट डोनर कब मिलेगा। संतोष को पहली बार 2000 में दिल का दौरा पड़ा था। उन्होंने एंजियोप्लास्टी करवाई, जो कुछ दिन कारगर रही। लेकिन उसके बाद उनका हृदय ठीक से खून की पंपिंग नहीं कर पा रहा था। इलाज के लिए वह एम्स गए जहां स्टेम सेल थेरपी हुई पर वह भी ज्यादा दिन नहीं चली। फिर उन्हें हृदय रोग विशेषज्ञ पीके हाजरा ने 'हार्ट मेट 2' यानी कृत्रिम दिल लगवाने की सलाह दी।

इस मशीनी हृदय का नाम 'हार्ट मेट 2' है, जो कमजोर दिल में खून पंप करने की क्रिया को संपन्न करता है। इसे मरीज के दिल के पास इंप्लांट किया जाता है। डॉ. हाजरा बताते हैं कि नाभि से एक पावर केबल बाहर आता है, जो एक बैग में रखे कंट्रोलर और बैट्री से जुड़ा रहता है। मरीज को समय-समय पर इसे चार्ज करते रहना पड़ता है। संतोष को यह मशीनी हृदय अमेरिका से मंगवाकर लगाया गया था।

कानपुर और आगरा के प्रदूषण के स्तर पर संयुक्त राष्ट्र की नजर

शशांक शेखर भारद्वाज, कानपुर

- वायु प्रदूषण पर पहली बार यूएन ने जताई चिंता, कानपुर में हवाओं और आगरा में ताज पर गैसों के दुष्प्रभाव की होगी जांच

विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल कानपुर और ताजमहल के सफेद होने के कारण आगरा के वायु प्रदूषण पर संयुक्त राष्ट्र की नजर है। इस विषय पर पहली बार चिंता जताते हुए उसने दोनों शहरों की प्रदूषण संबंधी मानीटरिंग रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट और मानीटरिंग के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने कानपुर आइआइटी से मदद मांगी है।

कानपुर के वायु प्रदूषण की चर्चा वैश्विक फलक पर आज से दो साल पहले शुरू हुई थी, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसे सर्वाधिक प्रदूषित शहर करार देते हुए चिंता जताई थी। तब इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि कानपुर में बाहर से आ रही हवाएं प्रदूषण फैला रही हैं और सांस व दमे के रोगी बढ़ रहे हैं। इसमें उत्तर पश्चिमी हवाओं के साथ दूसरे देशों से आने वाली हानिकारक गैसें भी शामिल हैं। वहीं, दुनिया के अजूबों में शामिल ताजमहल का सफेद संगमरमर पीला पड़ रहा है, जबकि आगरा से प्रदूषणकारी फैक्ट्रियां भी हटाई जा चुकी हैं। इस पर भी वैश्विक स्तर पर चिंता जताई जा रही है।

इन चिंताओं के बीच संयुक्त राष्ट्र ने भारत से इन दोनों शहरों की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट मांगी है। वहीं, यूनाइटेड नेशन इनवायरमेंट प्रोग्राम (यूएनईपी) के अधिकारी वैलेनटीन पिछले दिनों सीपीसीबी अफसरों से मिल भी चुके हैं। ऐसे में सीपीसीबी ने आइआइटी से कानपुर व आगरा की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट मांगी है। दोनों शहरों की रिपोर्ट में उत्तर पश्चिमी हवाओं संग आने वाले प्रदूषणकारी तत्व और गैस रिपोर्ट शामिल होगी। सीपीसीबी और कानपुर आइआइटी में 50 शहरों में प्रदूषण की मानीटरिंग के लिए पहले ही करार हो चुका है।

दिल्ली में होगी बैठक : नई दिल्ली में 15 सितंबर से पहले आइआइटी कानपुर के सिविल इंजीनियरिंग, इनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सीपीसीबी, यूपीपीसीबी और यूएनओ के अधिकारियों की बैठक प्रस्तावित है। इसमें मानीटरिंग की रणनीति तैयार होगी।

हवा की दिशा के आधार पर होगा काम : आइआइटी सिविल इंजीनियरिंग के सीनियर प्रो. मुकेश शर्मा के मुताबिक हवा की दिशा के आधार पर पता लगाया जाएगा कि कहां से सर्वाधिक प्रदूषण आ रहा है। हवा के साथ आ रहे पीएम 2.5, पीएम 10, सीओटू, एनओटू, एसओटू समेत अन्य गैसें के लिए विशेष मानीटरिंग सिस्टम और मैथमेटिकल मॉडलिंग की मदद ली जाएगी। मानीटरिंग सिस्टम कैसा होगा, यह दिल्ली की बैठक में तय होगा।



740 मीटर की ऊंचाई पर करतब

इंडोनेशिया के योग्याकार्ता में एडवेंचरस स्पोर्ट्स एथलीट एंडी आर्डी ने सांस थाम देने वाला करतब दिखाया। यहां के माउंट ग्लांगगेरन पर वह करीब 740 मीटर की ऊंचाई पर टाइटरोप पर चलते नजर आए। इसका मकसद पर्यटन के क्षेत्र में इस मनोरम स्थल को बढ़ावा देना था। एएफपी



कोयले के विरोध में मालवाहक जहाज को रोका

यूरोपीय देश पोलैंड के ग्दांस्क शहर में पर्यावरणीय समूह ग्रीनपीस के कार्यकर्ताओं ने एक नौका में सवार होकर कोयला लदे मालवाहक जहाज को अवरुद्ध कर रोकने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं ने कोयले का इस्तेमाल बंद करने की गुहार लगाई। हालांकि सुरक्षा बलों ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इसके बाद मालवाहक जहाज बंदरगाह में प्रवेश कर सका। यह मालवाहक जहाज पूर्वी अफ्रीकी देश मोजांबिक से यहां पहुंचा है। एपी

स्क्रीन शॉट

कीर्ति कुल्हारी का किरदार उपन्यास में नहीं!



फिल्म 'पिंक', 'उरी', 'मिशन मंगल' के बाद कीर्ति कुल्हारी 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' में परिणीति चोपड़ा के साथ नजर आएंगी। उसके अलावा वह वेब शो 'बार्ड ऑफ ब्लड' में बलूच की महिला का किरदार निभाती दिखेंगी। शाह रुख खान के प्रोडक्शन हाउस में बनी इस वेब सीरीज में इमरान हाशमी, विनीत कुमार सिंह और शोभिता धूलिपाला प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह शो इसी नाम के बिलाल सिद्दीकी द्वारा लिखे गए उपन्यास पर आधारित है। शो का निर्देशन रिभु दासगुप्ता ने किया है। कीर्ति के मुताबिक, उनका किरदार उपन्यास में नहीं है। उसे शो के लिए क्रिएट किया गया है। कीर्ति के मुताबिक, यह उनके लिए बेहद अलग दुनिया रही है। उन्हें बलूचिस्तान के बारे में भी ज्यादा नहीं पता था। उसके साथ जासूसी की दुनिया में कैसे काम होता है, उसे भी समझना पड़ा। कीर्ति के मुताबिक, 'डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कलाकार अपनी प्रतिभा को साबित कर सकते हैं। यह उन कलाकारों के लिए स्वर्णिम मौका है, जो अच्छे काम की तलाश में हैं। जब आप अच्छा काम कर लेते हैं तो और अच्छा करने की अपेक्षा की जाती है। छह महीने पहले जो काम मुझे सतुंष्टि देता था, अब लगता है कि अब और चैलेंजिंग किरदार निभाऊं।'

समकालीन होगी 'रैंबो' की कहानी : सिद्धार्थ आनंद



फिल्म 'बैंग बैंग' के बाद सिद्धार्थ आनंद का झुकाव एक्शन फिल्मों की ओर हो गया है। दो अक्टूबर को उनके द्वारा निर्देशित फिल्म 'वॉर' रिलीज होगी। उसमें रितिक रोशन और टाइगर श्रॉफ पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर एकसाथ नजर आएंगे। उसके बाद वह 'रैंबो' के रीमेक की तैयारियों में जुट जाएंगे। फिल्म की शूटिंग अगले साल मार्च में आरंभ होगी। यह फिल्म वर्ष 1982 में रिलीज सिल्वेस्टर स्टेलोन अभिनीत हॉलीवुड की क्लासिक फिल्म 'रैंबो' का रीमेक होगी। रीमेक में सिल्वेस्टर की भूमिका टाइगर श्रॉफ निभाते नजर आएंगे। मूल फिल्म में अमेरिकी सैन्य अधिकारी जॉन रैंबो के वियतनाम युद्ध को लेकर अनुभव कड़वे रहे हैं। जब वह सेना अधिकारी पद से सेवानिवृत्त होकर दोस्त से मिलने जाते हैं तो वहां से उनकी जिंदगी अलग मोड़ लेती है। सिद्धार्थ के मुताबिक, फिल्म की कहानी देश के समकालीन माहौल के अनुरूप प्रासंगिक होगी। उनके मुताबिक, 'वॉर' की रिलीज के बाद वह 'रैंबो' पर काम करना आरंभ कर देंगे।



'वीरे दी वेडिंग 2' पर काम शुरू...!

डांस रियलिटी शो 'डांस इंडिया डांस' में अपनी फिल्म 'जोया फैक्टर' के प्रमोशन के लिए जब सोनम कपूर पहुंची तो करीना कपूर खान खुशी से चहक उठीं। दोनों इससे पहले 'वीरे दी वेडिंग' में एकसाथ नजर आई थीं। शो से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, इस मौके सोनम ने रहस्योद्घाटन किया कि 'वीरे दी वेडिंग 2' की स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो गया है।

करण को रीमेक में नहीं देखना चाहते पापा सनी देयोल!

सनी देयोल को रीमेक पसंद नहीं है, न फिल्मों का न गानों का। उनका मानना है कि वर्तमान पीढ़ी रीमेक व रीमिक्स पर अधिक ध्यान दे रही है, जो ठीक नहीं है। सनी कहते हैं, 'मैं अपने बेटे करण को ऐसी किसी फिल्म में नहीं देखना चाहता। पहले बनी फिल्में आज से अलग हैं। लोग आज भी मुझे उन किरदारों में याद करते हैं। एक ही चीज को दोबारा अलग एक्टर के साथ और अलग परिवेश में बनाना आसान नहीं है।' सनी को गानों के रीमिक्स भी पसंद नहीं हैं। वह कहते हैं कि हर दौर के अपने गाने रहे हैं, पर अब क्या हो गया है।

'छिछोरे' के बाद नीतेश संग फिर फिल्म बनाएंगे साजिद नाडियाडवाला



'सुपर 30' और 'छिछोरे' की बैक टू बैक सफलता के साथ साजिद नाडियाडवाला ने सफल निर्माता का खिताब अपने नाम कर लिया है। दिलचस्प बात है कि दोनों ही फिल्मों ने शिक्षा के प्रति दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है। एक तरफ 'सुपर 30' में पढ़ाई की तरफ गरीब बच्चों की ललक और समाज में शिक्षक के महत्व को उजागर किया गया है, वहीं 'छिछोरे' में पढ़ाई के दबाव और हताश न होने का संदेश दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, 'छिछोरे' की सफलता को देखते हुए साजिद नाडियाडवाला ने उसके डायरेक्टर नीतेश तिवारी से साथ अपनी अगली फिल्म करने का निर्णय कर लिया है, जिसकी घोषणा वह जल्द ही करेंगे। वैसे 'किक 2' से वह खुद भी निर्देशन में कदम रख रहे हैं। वहीं वह 'हाउसफुल 4' और 'बागी 3' का भी निर्माण कर रहे हैं।

अध्ययन

शोधकर्ताओं ने चिड़ियों की चहचहाहट में छिपी बातें पता लगाईं और बताया कि चहचहाहट में मनुष्यों की भाषा की तरह अक्षर मौजूद होते हैं। इन्हें मिलाकर शब्द और वाक्य बनते हैं।

हमारी भाषा की तरह ही है चिड़ियों की चहचहाहट

लंदन, प्रेट्र: लंबे समय से इस बात पर विचार होता रहा है कि चिड़ियों की चहचहाहट, कुत्ते का भौंकना, घोड़े का हिनहिनाना यह सिर्फ एक आवाज है या कोई भाषा। अब वैज्ञानिकों ने चिड़ियों की चहचहाहट में भाषा खोज निकाली है। उनका कहना है कि चहचहाहट में हमारी भाषा की तरह ही वाक्य, शब्द और अक्षर मौजूद रहते हैं। चिड़ियाएं मनुष्यों की तरह ही बातें करती हैं और संदेश भी देती हैं।

'प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज' जर्नल में प्रकाशित शोध में इस बात की संभावना जताई गई है कि चिड़ियों की आवाज भी मनुष्यों की भाषा की तरह छोटे-छोटे अक्षरों से मिलकर बनी है, जो संगठित होने पर किसी शब्द या वाक्य की तरह पेश आते हैं।

इस तरह से लगाया पता : स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता सबरीना एंगेजर के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलियाई पक्षी 'चेस्टनट-क्राउंड-बब्लर' की आवाज का विश्लेषण किया और पाया किमानव भाषा की तरह ही उसके सुरों को तोड़ा जा सकता है। शोधकर्ताओं ने इस पक्षी के सुरों में अक्षरों को पहचाना और उन्हें 'ए' और 'बी' नाम दिया। उन्होंने बताया कि विश्लेषण करने पर पता चला कि ये पक्षी 'ए' और 'बी' को विशेष क्रम में संयोजित करके बात करते हैं। उन्होंने बताया कि जब ये पक्षी 'एबी' की आवाज निकालते हैं तो यह उड़ने वाले होते हैं और जब अपने चूजों को घोसले में खाना खिलाते हैं तो 'बीएबी' की ध्वनि निकालते हैं।



हर किसी को अच्छा लगता है चिड़ियों की चहचहाट सुनना। अब उसे समझने की कोशिश हो रही है। फाइल

खुल सकते हैं कई राज: अध्ययन में एंगेजर और उनकी टीम ने इस खोज के लिए उस तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसके माध्यम से उन्होंने मानव शिशुओं की आवाज का मतलब निकालने के लिए किया था। इस अध्ययन के सह लेखक ब्रिटेन की वारविक यूनिवर्सिटी के साइमन टाउनसेंड ने बताया कि यह पहली बार है जब किसी पक्षी की आवाज में अक्षरों की पहचान कर उससे बने वाक्य और उनका मतलब पता लगाया गया है। शोधकर्ताओं ने बताया कि इस बात से यह संभावना पैदा होती है कि इसी तरह प्रत्येक जीव की आवाज को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर उनमें छिपे अक्षरों की पहचान की जा सकती है। इसके बाद उनसे बने शब्द और वाक्य को पहचान कर उनका मतलब पता लगया जा सकता है।